ए. के. गोपालन

वी.

मद्रास राज्य।

भारत संघः इंटरवेनर।

[श्री हरिलाल कनिया सी. जे., सैयद फजल अली,

पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन,

मुखर्जी और एस. आर. दास जे. जे.*]*

निवारक निरोध अधिनियम *(1950* का चतुर्थ*)*, एस. एस. *3* , *7* , *10-14* . - वैधभारत का संविधान, *1950*, कला। *13* , *19 22,32* तक-कानूननिवारक निरोध से संबंधित-क्या यह मौलिक का उल्लंघन करता है आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार-चाहे वह न्यायपालिका के अधीन हो कला के तहत तर्कसंगतता के रूप में समीक्षा। *19 (5)* -कला का दायरा। *19* स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रकृति औरकला की घटनाएँ। *22* , क्या निवारक निरोध के दायरे और कला की प्रयोज्यता के बारे में पूर्ण संहिता है। *21-* " कानून *""*, प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित, "के अर्थ-चाहे प्राकृतिक न्याय के नियम शामिल हों-कला का निर्माण। *21* - "कानून के लिए उचित उपकर" पर अमेरिकी निर्णय, अधिकारियों की संतुष्टि के लिए वस्तुनिष्ठ मानक प्रदान करने के लिए चूक का मूल्य, मौखिक सुनवाई या साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए प्रदान करना, हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित करना, और "सी. आई. आर. अपराध" और "मामलों के वर्गों" को निर्दिष्ट करना जहां हिरासत की अवधि *3* महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार का खुलासा करने से प्रतिबंधित करना-कानून की वैधता-संविधान का निर्माण-बहस और मसौदा समिति की रिपोर्ट का संदर्भ अनुमति है।याचिकाकर्ता जिसे निवारक के तहत हिरासत में लिया गया था

निरोध अधिनियम *(1950* का अधिनियम *IV)* अनुच्छेद के तहत लागू किया गया। *32* बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए और निरोध से उनकी रिहाई के लिए, इस आधार पर कि उक्त अधिनियम कला के पक्ष में दृष्टिकोण का उल्लंघन करता है। *13* , *19* , *21* और संविधान की धारा *22* और इसके परिणामस्वरूप अधिकार से बाहर है और इसलिए उनकी नजरबंदी अवैध थीः

आयोजित, कनिया सी. जे. के अनुसार, पतंजलि शास्त्री, मुखर्जी और दास जे. जे. *(* फजल अली और महाजन जे. जे. असहमति व्यक्त करते हुए*)*-कि धारा *1950* के अपवाद के साथ, निवारक निरोध अधिनियम, *1950*। *14* इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया और भले ही सेक। *14* यह अधिकार से बाहर था क्योंकि यह कला के प्रावधानों का उल्लंघन करता था। *22 (5)* संविधान की, क्योंकि यह धारा अधिनियम की शेष धाराओं से अलग करने योग्य थी, अयोग्यता सेक. *14* इसने समग्र रूप से अधिनियम की वैधता को प्रभावित नहीं किया और याचिकाकर्ता को हिरासत में लेना अवैध नहीं था।

फजल अली और महाजन जे. जे। - अधिनियम की धारा *12* भी थी उलिरा अधिकार रखता है, और चूंकि यह बहुत ही प्रावधान का उल्लंघन करता है संविधान जिसके तहत संसद ने कानून बनाने के लिए अपनी क्षमता प्राप्त की, हिरासत अवैध थी।

पूर्ण न्यायालय द्वारा आयोजित *(*कानिया सी. जे., फजल अली, पतंजलि*)* शास्त्री, महाजन, मुखर्जी और दास जेजे।*)* - निवारक निरोध अधिनियम, *1950* की धारा *14*, कला के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। *22 (5)* जहाँ तक संविधान निषेध करता है

2 न्यायालय को उन आधारों का खुलासा करने से हिरासत में लिया गया व्यक्ति जिनके आधार पर निरोध आदेश दिया गया है या प्रतिनिधित्वउसके द्वारा निरोध के आदेश के खिलाफ किया गया, और उस हद तक अधिकार से बाहर और शून्य है।

पर कनिया सी. जे., पतंजलि शास्त्री, महाजन, मुखर्जी

और दास जे. जे. *(* फजल अली जे. असहमति*)*-संविधान के अनुच्छेद *19* का उस कानून पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जो सीधे निवारक निरोध से संबंधित है, भले ही निरोध के आदेश के परिणामस्वरूप उप-समूहों में निर्दिष्ट अधिकार हों। *(* ए*)* से *(*ई*)* और *(*जी*)* सामान्य में, और उप-सीएल। *((*घ*)* विशेष रूप से, सी. एल. *(1)* कला की। *19* पुनः संक्षिप्त या संक्षिप्त किया जा सकता है; और एक कानून की संवैधानिक वैधता

इसलिए इस तरह के निरोध को सी. एल. में निर्धारित परीक्षण के आलोक में नहीं आंका जा सकता है। *(5)* उक्त अनुच्छेद का।

डी. ए. एस. जे.-अनुच्छेद *19 (1)* प्रयोग करने की कानूनी क्षमता का प्रतिपादन करता है।

इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकार और यदि कोई नागरिक किसी अपराध के लिए विजय के परिणामस्वरूप वैध निरोध के कारण अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता खो देता है या अन्यथा वह उप-समूहों के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। *((*क*)* से *(*ङ*)* और *(*छ*)* कला। *19 (1) ;* इसी तरह यदि किसी नागरिक की संपत्ति को अनुच्छेद के तहत अनिवार्य रूप से अर्जित किया जाता है। *31 ,* वह दावा नहीं कर सकता

उप-क्ल के तहत अधिकार। *(* च*)* कला। *19 (1)* उस प्रो संपत्ति के संबंध में। संक्षेप में उप-क्लस के तहत अधिकार। *(* ए*)* से *(*ई*)* और *(*जी*)* अंत जहां वैध निरोध शुरू होता है और इसलिए एक की वैधता

निवारक निरोध अधिनियम को अनुच्छेद द्वारा नहीं आंका जा सकता है। *19 (5) .*

जे. महाजन-कला का सटीक दायरा जो भी हो। *19 (1) ((*घ*)*

और कला। *19 (5)* कला के प्रावधान। *19 (5)* निवारक निरोध से संबंधित कानून पर लागू नहीं होता है, क्योंकि *1*

कला में विशेष स्व-निहित प्रावधान। *22* इसे विनियमित करना।

फजल अली जे.-निवारक निरोध एक सीधा उल्लंघन है।

कला में गारंटीकृत अधिकार। *19. (1) (* घ*),* भले ही उक्त उपखंड पर एक संकीर्ण निर्देश दिया गया हो, और निवारक निरोध से संबंधित एक कानून इसलिए ऐसी सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है जिसकी अनुमति अनुच्छेद द्वारा दी गई है। *19 (5) .*

कनिया सी. जे., पतंजलि शास्त्री, मुखर्जी और दास जे. जे. के अनुसार।

(फज़ल अली जे. असहमति*)*। - "भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार" की अवधारणा कला. *19 (1) (* घ*)* संविधान का अनुच्छेद में निर्दिष्ट "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार की अवधारणा से पूरी तरह से अलग है। *21 ,* और कला। *19* इसलिए, इसे कला के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। *21.* उस कला का दृष्टिकोण। *19* गारंटी उप

स्थायी अधिकार और कला। *21* यह निर्धारित करता है कि प्रक्रिया गलत है। डीएएस। जे.-अनुच्छेद *19* व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्वतंत्र अधिकारों और अभिव्यक्ति के रूप में संरक्षित करता है।

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कला में किया जाता है। *21* एक संक्षिप्त शब्द के रूप में *[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

90

इसके अर्थ के भीतर सभी प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो पुरुषों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरा करते हैं।

फजल अली जे.-भले ही यह माना जाए कि कला। *19 (1) ((*घ*)* नहीं

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता" को संदर्भित करता है और यह कि यह, इसके लिए जिम्मेदार सीमित अर्थ रखता है, अर्थात, यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अधिकार को दर्शाता है, निवारक निरोध आवश्यक है।

बनो।

आवाजाही के इस सीमित अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से और अस्थायी रूप से प्रभावित करने के लिए आयोजित किया गया। निवारक निरोध के उद्देश्यों में से एक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए फिर से प्रशिक्षित करना है ताकि वह उन स्थानों पर असंतोष न फैला सके या खतरनाक गतिविधियों में लिप्त न हो। यही विचार उन व्यक्तियों के मामलों पर भी लागू होता है जिन्हें नजरबंद या बाहर रखा गया है। इसलिए, बाहरी, नजरबंदी और प्रतिबंध के कुछ अन्य रूप

पर

आंदोलन को हमेशा रिश्तेदारों के मामलों के रूप में माना गया है। एक ही समूह या परिवार के लिए, और जो नियम एक पर लागू होता है वह अनिवार्य रूप से दूसरे पर लागू होना चाहिए।

कनिया सी. जे., पतंजलि शास्त्री और डी. ए. एस. जे. जे. के अनुसार। *(* महाजन जे।

असहमति*)*। - अनुच्छेद *22* निवारक निरोध से संबंधित न्यायिक सुरक्षा उपायों की पूरी संहिता नहीं बनाता है। के लिए इस हद तक कि प्रावधान कला में किया गया है। *22* इसे कला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। *21 ;* लेकिन प्रक्रिया के उन बिंदुओं पर जिन पर स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा कला द्वारा विचार नहीं किया जाता है। *22 ,* कला. *21* लागू होगा। डी. ए. एस. जे.-कला। *21* एक प्रक्रिया और कला की आवश्यकता के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करता है। *22* समर्थन के न्यूनतम नियम निर्धारित करते हैं जिन्हें संसद भी निरस्त या नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जे. महाजन-कला। *22* निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपायों की एक स्व-निहित संहिता है और कला के प्रावधानों द्वारा इसकी जांच या नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। *21.* प्रिंसि प्लेज़ अंतर्निहित कला है। *21* हालाँकि कला में इन्हें ध्यान में रखा गया है। *22* और इन अनुच्छेदों के बीच कोई टकराव नहीं है। मुखर्जी जे।

यहाँ तक कि उस कला को मानते हुए भी। *22* निवारक निरोध और उस कला से संबंधित एक स्व-निहित संहिता नहीं है। *21* लागू होगा, कला के पूरक के लिए अनुमति नहीं है। *22* प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू करके। फजल अली जे.-कला। *22* निवारक निरोध से संबंधित अपने आप में एक पूर्ण कोड नहीं बनाता है। संसद आगे के प्रावधान कर सकती है और यदि उसने ऐसा किया है। *19 (5)* यह देखने के लिए लागू किया जा सकता है कि क्या उन प्रावधानों ने तर्कसंगतता की सीमा का उल्लंघन किया है।

पर कनिया सी. जे. मुखर्जीआ आरो दास जे. जे.। *(* फजल अली जे।

असहमति*)*। - कला में। *21* "कानून" शब्द का उपयोग किया गया है

राज्य-निर्मित कानून की भावना और अमूर्त या सामान्य अर्थों में कानून के समकक्ष के रूप में नहीं जो प्राकृतिक के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है।

न्याय; और "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से राज्य, अर्थात संघ संसद या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिप्रेत है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिकी संविधान में "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति को दिए गए अर्थ के आलोक में इस अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना उचित नहीं है। पतंजलि शास्त्री जे। - " कला में "कानून"। *21* इसका अर्थ नागरिक कानून की स्वाभाविकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

91

एस सी आर।

सकारात्मक या राज्य-निर्मित कानून। . " कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ "हालांकि कोई भी प्रक्रिया नहीं है जो एक सक्षम विधायिका द्वारा निर्धारित की जा सकती है, बल्कि सामान्य सामान्य सुस्थापित आपराधिक प्रक्रिया, यानी वे व्यवस्थित उपयोग और सामान्य तरीके हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, जो इस देश में दंड प्रक्रिया का सामान्य कानून है।

एकमात्र

इस निर्माण का विकल्प, यदि एक संवैधानिक

अतिक्रमण से बचना चाहिए, "कानून" के संदर्भ की व्याख्या करना है जो एक संवैधानिक संशोधन का संकेत देता है, क्योंकि यह केवल इस तरह के संशोधन के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो कला का उल्लंघन किए बिना एक मौलिक अधिकार को संशोधित या ओवरराइड कर सकता है। *13 (2) .*

फजल अली जे.-इस दृष्टिकोण में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है कि

" कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में "प्राथमिक न्याय के चार सिद्धांत शामिल होने चाहिए जो कानून की सभी नागरिक प्रणालियों के मूल में हैं और हैं, और जिन्हें अमेरिकी न्यायालयों और न्यायविदों द्वारा *(1)* नोटिस, *(2)* सुनवाई का अवसर, *(3)* निष्पक्ष न्यायाधिकरण और *(4)* अनुशासनात्मक प्रक्रिया में कहा गया है। ये चार

सिद्धांत वास्तव में एक ही अधिकार के अलग-अलग पहलू हैं, अर्थात्, किसी की निंदा होने से पहले सुनवाई का अधिकार। इसलिए शब्द "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया", जो भी हो

सटीक अर्थ यह होना चाहिए कि इसमें अनिवार्य रूप से यह सिद्धांत शामिल होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई किए बिना निंदा नहीं की जाएगी।

पर कनिया सी. जे., फजल अली, पतंजलि शास्त्री, महाजन

और डी. ए. एस जे. - निवारक निरोध अधिनियम, *1950* की धारा *3* किसी कार्यकारी अधिकारी को कोई विधायी शक्ति प्रदान नहीं करती है, बल्कि केवल ऐसे अधिकारी को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है, और इसलिए इस आधार पर अमान्य नहीं है। तथ्य यह है कि यह धारा यह निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानक प्रदान नहीं करती है कि क्या कानून की आवश्यकताएँ हैं

इसका अनुपालन किया गया है, यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं है कि यह अमान्य है। फज़ल अली जे.- धारा *3* हालांकि केवल पहले कदम, यानी गिरफ्तारी और प्रारंभिक निरोध के लिए एक उचित प्रावधान है और तथाकथित व्यक्तिपरक संतुष्टि का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जो केवल उन आधारों की जांच करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करके किया जा सकता है जिनके आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है और उन आधारों के संबंध में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकता है।

कनिया सी. जे. महाजन और डी. ए. एस. जे. जे. के अनुसार-धारा *7*

उक्त अधिनियम केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि यह मौखिक सुनवाई या साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। मौखिक सुनवाई का अधिकार और साक्ष्य देने का अधिकार आवश्यक रूप से अनुच्छेद *22* द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अधिकार में निहित नहीं हैं।

फेर कानिया सी. जे. और महाजन-में निहित प्रावधान

सेक. *11* कि किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है जैसे कि

12 - ए *92*

राज्य सोचता है कि फिट कला का उल्लंघन नहीं करता है। *22 (7)* और वह वहाँ नहीं है

पूर्व अमान्य है।

कनिया सी. जे., पतंजलि शास्त्री, मुखर्जी और दास जे. जे. के अनुसार।

(फजल अली और महाजन जे. जे. असहमति जताते हुए*)*। - अनुच्छेद *22 (7)* का अर्थ है -

दोनों को निर्धारित करना चाहिए। खंड *(*क*)* में निर्दिष्ट मामलेऔर *(*बी*)* उप-सेक का। *(1)* सेक. *12* ऐसी परिस्थितियों या मामलों के वर्गों का पर्याप्त वर्णन करता है और धारा *12* है -

इसलिए इस आपत्ति के लिए खुला नहीं है कि यह कला का अनुपालन नहीं करता है। *22 (7)* . जे. दास-संसद ने वास्तव में और सार रूप में अध्यक्षता की है। उप-खंड के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)* दोनों में लिखा गया है। *(1)* सेक. *12* .

फजल अली और महाजन जज-अनुच्छेद *22 (7)* का अर्थ है कि दोनों

परिस्थितियों और मामलों के वर्ग या वर्गों *(*जो अलग-अलग अर्थों और अर्थों के साथ दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं*)* को निर्धारित किया जाना चाहिए, और एक के बिना दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन पर्याप्त नहीं होगा। जिन कारणों से निवारक निरोध का कानून बनाया जा सकता है, उनके लिए विषयों की गणना सी. एल. एस. में निहित है। *(* क*)* और *(*ख*)* उप-सेक। *(1)* सेक. *12* यह उन परिस्थितियों को निर्धारित करने के बराबर नहीं है जिनके तहत,

या मामलों का वह वर्ग या वर्ग जिसमें किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

केनिया सी. जे. के अनुसार-जबकि सहमति में लेना उचित नहीं है

संसद के सदस्यों की व्यक्तिगत राय का अपमान करना या

किसी विशेष खंड के अर्थ का अर्थ निकालने के लिए कन्वेंशन, जब कोई प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई निश्चित वाक्यांश या अभिव्यक्ति विचार के लिए थी या नहीं, तो बहस के संदर्भ की अनुमति दी जा सकती है। जे. पतंजलि शास्त्री-किसी अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाने में, विधेयक पर बहस के दौरान दिए गए भाषणों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। मुखर्जी जे.-इन

संविधान का अर्थ लगाते हुए संविधान सभा में बहस को ध्यान में नहीं रखना बेहतर है, लेकिन मसौदा समिति की रिपोर्ट को अधिक महत्व दिया जा सकता है।

मौलिक न्यायनिर्णयः याचिका सं। *1950* का *XIII*।

कला के तहत आवेदन। *32 (1)* संविधान का

बंदी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए भारत का

मद्रास जेल में अपीलार्थी का आदेश

निवारक के तहत किए गए निरोध के आदेश का

निरोध अधिनियम, *1950*। मामले के भौतिक तथ्य और वकील के तर्कों को विस्तार से निर्धारित किया गया है

निर्णय। निवारक के प्रासंगिक प्रावधान

निरोध अधिनियम, *1950*, नीचे मुद्रित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

93

एस सी आर।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और अवधि। इस अधिनियम को कहा जा सकता है

निवारक निरोध अधिनियम, *1950*।

(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है। *(3) 1* अप्रैल, *1951* से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

उस तारीख से पहले की गई या छोड़ी गई चीजों के संबंध में बचत करें।

2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ हैं।

(क*)* "राज्य सरकार" से भाग ग के संबंध में अभिप्रेत है।

राज्य का मुख्य आयुक्त; और

(ख*)* "निरोध आदेश" का अर्थ है इसके तहत किया गया आदेश।

खंड *3.*

3. पोवार को कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देना। - *(1)* द.

केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती है

(क*)* यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है जो एक दृष्टिकोण के साथ है

उसे किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए

((i) भारत की रक्षा, भारत के साथ संबंध

विदेशी शक्तियाँ, या भारत की सुरक्षा, या

((ii) राज्य की सुरक्षा या राज्य का रखरखाव।

सार्वजनिक व्यवस्था, या

((iii) आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव।

समुदाय के लिए, या

(ख*)* यदि किसी विदेशी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है

विदेशी अधिनियम, *1946 (1946* का *XXXI)* के अर्थ के भीतर, कि भारत में उनकी निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने या भारत से उनके निष्कासन की व्यवस्था करने की दृष्टि से

ऐसा करना आवश्यक है, यह निर्देश देते हुए आदेश दें कि

व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

(2) कोई जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या

प्रेसीडेंसी-नगर में, पुलिस आयुक्त, यदि धारा *(1)* के खंड *(ए)* के उपखंड *(ii)* और *(iii)* में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हो जाता है, तो उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(3) जब किसी जिले द्वारा इस धारा के तहत कोई आदेश दिया जाता है।

मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, वह तुरंत राज्य सरकार को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

को

जिसे वह उन आधारों के साथ अधीनस्थ करता है जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण जो उसकी राय में आदेश की आवश्यकता पर असर डालते हैं।

7. हिरासत के आदेश के आधार व्यक्तियों को बताए जाएँगे

आदेश से प्रभावित। *(1)* जब किसी व्यक्ति को निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे उन आधारों से अवगत कराएगा जिनके आधार पर आदेश दिया गया है, और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा, उस मामले में जहां ऐसा आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, उस सरकार को, और उस मामले में जहां यह राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया गया है, राज्य सरकार को।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

94

1950

11. निरोध आदेश की पुष्टि। जहां किसी भी मामले में

सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में पर्याप्त है

ए. के. गोपालन

संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो,

राज्य

संबंधित व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझता है।— *12.* `कुछ मामलों में निरोध की अवधि। *- (1)* निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग के मामलों में या किसी के तहत हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति

निम्नलिखित परिस्थितियों को प्राप्त किए बिना हिरासत में लिया जा सकता हैः

महीनों, लेकिन उसकी नजरबंदी की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं, अर्थात्, जहां ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हैउसे किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकना।

((क) भारत की रक्षा, विदेश के साथ भारत के संबंध।

भारत की शक्तियाँ या सुरक्षा; या

((ख) किसी राज्य की सुरक्षा या जनता का रखरखाव।

*

आदेश दें।

14. निरोध आदि के आधारों का प्रकटीकरण। - *(1)* कोई भी अदालत, किसी अपराध के लिए अभियोजन के उद्देश्य के अलावा नहीं करेगी।

उप-धारा *(2)* के तहत दंडनीय, किसी भी कथन की अनुमति दें

के सार के बारे में उसके सामने किया गया, या कोई साक्ष्य दिया जाना है

आधार की धारा *7* के तहत किया गया कोई भी संचार

जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति के विरुद्ध निरोध आदेश दिया गया है।

ऐसे आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कोई अभ्यावेदन; और नहींकिसी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने पर, कोई भी अदालत

किसी भी लोक अधिकारी को उसके सामने पेश करने का अधिकार होगा, याः ऐसे किसी संचार या प्रतिनिधि के सार का खुलासा करना -

(2) यह एक ऐसा अपराध होगा जो किसी व्यक्ति के लिए एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा, ताकि वह पूर्ववर्ती के बिना खुलासा या प्रकाशन कर सके।केंद्र सरकार या राज्य सरकार का प्राधिकरण

जैसा भी मामला हो, कोई भी सामग्री या विषय जिसका तात्पर्य हो इस तरह के किसी भी संचार या प्रतिनिधित्व की सामग्री हो जो है

उप-धारा *(1)* में निर्दिष्टः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा

एक व्यक्ति द्वारा अपने कानूनी सलाहकार को किया गया खुलासा जो उप है

एक निरोध आदेश का जेक्ट।

एम. के. नाम्बियार *(*एस. के. अय्यर और वी. जी. राव,

उसके साथ*)* याचिकाकर्ता के लिए।

के. राजा अय्यर,

अधिवक्ता-मद्रास के महाधिवक्ता

(सी. आर. पट्टाभि रमन और आर. गणपति, उनके साथ*)*

मद्रास राज्य के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी *(*जिन्द्रा---*)*

लाल, उनके साथ*)* भारत संघ के लिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

95

1950 .

19 मई। निम्नलिखित निर्णय थे -

वितरित किया गया।

कानिया सी. जे. -- यह आवेदक की याचिका है।

मद्रास जेल में उनकी नजरबंदी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद *32 (1)* के तहत। याचिका में उन्होंने विभिन्न तिथियां दी हैं जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वे दिसंबर, *1947* से हिरासत में हैं। साधारण आपराधिक कानून के तहत

उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन उन दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया था। जबकि वे इस प्रकार मद्रास राज्य के एक आदेश के तहत हिरासत में थे सरकार ने *1* मार्च, *1950* को उन्हें *1950* के निवारक निरोध अधिनियम, *IV* की धारा *3 (1)* के तहत एक आदेश दिया था। वह चुनौती देता है

1950 अनुच्छेद *13,19* के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और *21* और उस अधिनियम के प्रावधान अनुरूप नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद *22* के साथ। उनके पास चाल भी है।

आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह

दुर्भावनापूर्ण रूप से जारी किया जाता है। यह साबित करने का बोझ कि सभी

गेशन आवेदक पर है। दंडात्मक प्रो के कारण

आक्षेपित अधिनियम की धारा *14* के दर्शन आवेदकउसे दिए गए आधारों का खुलासा नहीं किया है, उसके लिए

नजरबंदी और आदेश की दुर्भावना का सवाल

इसलिए इस याचिका के तहत नहीं लिया जा सकता है।

1950 के अधिनियम *IV* की वैधता का प्रश्न

हमारे सामने काफी देर तक बहस की गई। यह पहला है।

मामला जिसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेद

मौलिक पर अध्याय में निहित भारत का

अधिकार हमारे सामने चर्चा के लिए आए हैं। अदालत नेआवेदक के विद्वान वकील का ऋणी है और

व्याख्या में उनकी सहायता के लिए महान्यायवादी

के प्रासंगिक खंडों का सही अर्थ निकालना

संविधान।

प्रतिद्वंद्वी विवादों की सराहना करने के लिए यह है

की सामान्य योजना को ध्यान में रखने के लिए पहले उपयोगी

संविधान। संविधान के अनुच्छेद *53* के तहत

संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

और उसके द्वारा *96* के अनुसार प्रयोग किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

संविधान या तो प्रत्यक्ष रूप से या अधिकारियों के माध्यम से उसके अधीनस्थ होता है। संघ की विधायी शक्तियाँ संसद और विधानमंडलों के बीच विभाजित हैं।

राज्यों को। उनकी निर्दिष्ट शक्तियों की सीमाएं संविधान के अनुच्छेद *245*, अनुसूची *VII*, सूची *1,2* और *3* के साथ पठित अनुच्छेद *246* में पाई जाती हैं। भारत संघ के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है

शेड और इसकी शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद *124* से *147* में निर्धारित किए गए हैं। यह भारत सरकार अधिनियम, *1935* के पैटर्न का अनुसरण करता है, जो भारत सरकार का पूर्व संविधान था। अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारत संघ की न्यायिक शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में निहित करने वाला कोई अनुच्छेद नहीं है। इमारत को काफी हद तक बदलने वाले महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले प्रस्तावना में हैं जो भारत को अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने और उन सभी के बीच भाईचारे को बढ़ावा

देने के लिए एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संविधान का भाग *III* एक महत्वपूर्ण नवाचार है। इसका नेतृत्व किया जाता है

"फंड

मानसिक अधिकार "। उस भाग में

"राज्य "

वह शब्द

संघ की सरकार दोनों शामिल हैं

और

राज्यों की सरकार। अनुच्छेद *13* द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के पक्ष में दृष्टिकोण से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक, शून्य हैं। इसलिए, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन भारत में लागू होने वाले सभी कानून, जब तक कि अन्य ज्ञानों के अनुसार, मौलिक अधिकारों पर इस अध्याय के साथ इस हद तक असंगत न हों, स्वतः बन जाते हैं।

भौतिक रूप से शून्य। अनुच्छेद *13 (2)* के तहत संविधान लागू होने के बाद कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्राप्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। इसलिए, जहां तक भविष्य के विधान का संबंध है, भाग *III* में मौलिक अधिकारों को फिर से शामिल किया जाना चाहिए और जब तक कि प्रावधानों द्वारा अन्यथा संरक्षित नहीं किया जाता है।

संविधान के अनुसार, वे इस हद तक अमान्य होंगे कि वे भाग *III* के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

के तहत

अनुच्छेद *245 (1)* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत प्रदत्त विधायी शक्तियाँ

97

एस सी आर।

अनुच्छेद *246* भी "के प्रावधानों के अधीन" बनाया गया हैयह संविधान ", जिसमें निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग *III* शामिल है। कानून शब्द

अनुच्छेद *13* में, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, उप-कानूनों, नियमों, विनियमों और यहां तक कि प्रथा या उपयोग को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक होने के लिए व्यक्त किया गया है।

भारत, कानून की शक्ति। इस भाग के शेष भाग को सात भागों में विभाजित किया गया है। समानता का अधिकार "में पाया जाता है

लेख *14-18,* लेख *19-22* में "स्वतंत्रता का अधिकार", " अनुच्छेद *23* और *24* में शोषण के खिलाफ अधिकार,

" अनुच्छेद *25-28* में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,

" अनुच्छेद *29* और *30* में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद *31* में "संपत्ति" और "संपत्ति का अधिकार"

संवैधानिक

आर्टसिल *32-35 32-35* में उपचार। . इसमें

हम सीधे तौर पर केवल लेखों से संबंधित हैं

"स्वतंत्रता का अधिकार" *(19-22)* शीर्षक के तहत और अनुच्छेद *32* जो अधिकारों को लागू करने के लिए एक उपाय प्रदान करता है

इस भाग द्वारा प्रदत्त। बाकी लेख हो सकते हैं

केवल व्याख्या में सहायता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए

उपर्युक्त लेखों का उल्लेख।

यह स्पष्ट है कि इस भाग को सम्मिलित करने से

मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकारभाग *III* उच्चतम न्यायालय में सीधे आवेदन द्वारा

विधायी नियंत्रण से हटा दिया जाता है। शब्दरचना.

अनुच्छेद *32* से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय हो सकता हैलेख में उल्लिखित एक उपयुक्त राहत देने के लिए प्रेरित किया गया

32 (2) , केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में

संविधान के भाग *III* में उल्लिखित है।

याचिकाकर्ता को एक निवारक कानून के तहत हिरासत में लिया गया है

1950 के अधिनियम *IV* के तहत बनाया गया आदेश, जिसमें

भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। में

संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची *I* में शामिल हैं -

उन वस्तुओं को निर्दिष्ट करने वाली प्रविष्टियाँ जिनके संबंध में संसद उनके पास अनन्य विधायी शक्तियाँ हैं। प्रविष्टि *9* में है

ये शब्द हैं: " कारणों के लिए निवारक हिरासत

रक्षा, विदेशी मामलों या सुरक्षा के साथ संबंधित

भारत; इस तरह की नजरबंदी के अधीन व्यक्ति। सूची *III*

उस अनुसूची में ऐसे विषयों की गणना की गई है जिन पर दोनों

संघ और राज्यों के समवर्ती विधान हैं *98*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

उस सूची की प्रविष्टि *3* इन शब्दों में हैः

शक्तियाँ "। किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव; ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति। यह विवादित नहीं है कि *1950* का अधिनियम *IV* सातवीं अनुसूची की सूची *I* और सूची *III* में इन दो प्रविष्टियों के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि विवादित विधान अनुच्छेद *1* द्वारा दिए गए अधिकारों को कम करता है या उनका उल्लंघन करता है और यह अनुच्छेद *22 (4)* और *(7)* के तहत अनुमत निवारक निरोध पर अनुमेय विधान के अनुसार भी नहीं है और विशेष रूप से अनुच्छेद *22 (5)* के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए इन लेखों में से प्रत्येक और इसके संबंध में दिए गए तर्कों पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है।

अनुच्छेद *19* कुछ अधिकारों के संरक्षण के लिए है।

नागरिकों को स्वतंत्रता। यह इस प्रकार चलता हैः --

" 19. (1) -सभी नागरिकों को होगा अधिकार

(ख) शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;*(ग)* संघों या संघों का गठन करना;

((घ) पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना

भारतः

(ई) देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए

भारत का क्षेत्र;

(च) संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करना;

और

(छ) किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या आगे बढ़ना।

कोई भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय।

" (2) खंड *(1)* के उपखंड *(क)* में कुछ भी नहीं होगा।

जहां तक उसका संबंध है, किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करना या राज्य को मानहानि, बदनामी, मानहानि, अदालत की अवमानना या किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई कानून बनाने से रोकना जो शालीनता या नैतिकता के खिलाफ है या जो राज्य की सुरक्षा को कम करता है या उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है।

(3) उक्त खंड के उपखंड *(ख)* में कुछ भी नहीं है।

सार्वजनिक व्यवस्था एस. सी. आर. के हित में किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99

पर उचित प्रतिबंध

का अभ्यास

सही है।

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त।

(4) उक्त खंड के उपखंड *(ग)* में कुछ भी नहीं

सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है, यानैतिकता, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध।

(5) उपखंड *(घ), (ङ)* और *(च)* में कुछ भी नहीं

उक्त खंड किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा जहां तक वह राज्य पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

उक्त द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग

उपखंड या तो आम जनता के हित में

या किसी अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए

जनजाति।

(6) उक्त खंड के उपखंड *(छ)* में कुछ भी नहीं

अब तक के किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगाजैसा कि यह अधिरोपित करता है, या राज्य को ऐसा करने से रोकता है

आम जनता के हित में कानून लागू करना,

अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त, और, विशेष रूप से,

उक्त उपखंड में कुछ भी संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। किसी विद्यमान विधि का जहाँ तक वह विहित करता है या करता है

किसी भी प्राधिकारी को निर्धारित करने या रोकने की शक्ति देता है

राज्य द्वारा निर्धारित या सशक्त बनाने वाला कोई भी कानून बनाने से

निर्धारित करने के लिए कोई भी प्राधिकारी, पेशेवर या तकनीकी

किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यताएँया कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना।

खंड *(2)* उन सीमाओं को निर्दिष्ट करता है जिन तक

*19 (1) (*क*)* में निहित अधिकार का संक्षिप्तकरणअनुमति दी जाए। यह एक अपवाद है। इसी तरह खंड

(3) 19 में अधिकार के संक्षिप्त होने की सीमा निर्धारित करता है। *(1) (* ख*)* और खंड *(4)* के संबंध में ऐसी सीमाएँ निर्दिष्ट करती हैं -

*19 (1) (*सी*)* में अधिकार। खंड *(5)*। के संबंध में है

*19 (1) (*घ*), (*ङ*)* और *(*च*)* और खंड में उल्लिखित अधिकार

(6) यह *19 (1) (*छ*)* में निहित अधिकारों के संबंध में है।

यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि संग्रहित वस्तुएँ,

मौलिक की सीमा की सराहना करने के लिए एक साथअधिकार। सबसे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि

2-3 एस. सी. इंडिया*/58*

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100

नागरिकों और व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों के बीच अंतर है। यह प्रावधान के अवलोकन पर स्पष्ट है।

संविधान में अनुच्छेद *13 (1)* और *(2)* बहुत सावधानी बरतने का विषय प्रतीत होता है। उनकी अनुपस्थिति में भी, यदि किसी विधायी अधिनियम द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था, तो न्यायालय के पास हमेशा उस अधिनियम को अमान्य घोषित करने की शक्ति होती है, जिस हद तक वह सीमाओं का उल्लंघन करता है। इसलिए संविधान में अनुच्छेद *13 (1)* और *(2)* का अस्तित्व इसके लिए सामग्री नहीं है - इस सवाल का निर्णय कि कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है और संविधान द्वारा ही इसे किस हद तक संक्षिप्त करने की अनुमति है।

निवारक निरोध आदेश के परिणामस्वरूप

उसकी ओर से कि अनुच्छेद *19 (1) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई)* और *(जी)* में निर्दिष्ट अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यह.यह तर्क दिया गया था कि उनकी नजरबंदी के कारण उन्हें जहां चाहें बोलने का स्वतंत्र अधिकार नहीं हो सकता है

और उसी तर्क का आग्रह किया गया थाउपखंड *(ख), (ग), (घ)* में उल्लिखित शेष अधिकार,

(ई) और *(जी)*। यद्यपि यह तर्क ए में आगे बढ़ाया गया है

निवारक निरोध से संबंधित मामला, यदि सही है, तो यह दंडात्मक निरोध के मामले में लागू होना चाहिएभारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति को भी

कोड। इसलिए विचार करने पर, तर्क स्पष्ट रूप से होना चाहिए

अस्वीकार कर दिया। बचत खंड *(2)* से *(6)* के बावजूद, संबंधित अधिकारों के संक्षिप्त होने की अनुमति देना

उनमें से प्रत्येक, कई धाराओं के तहत दंडात्मक निरोध

दंड संहिता, उदाहरण के लिए, चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और यहां तक कि सामान्य हमले के लिए, अवैध होगा। जब तक कि ऐसा न हो।

निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लेख से आता है, यह स्पष्ट है कि इस तरह के निर्माण से बचा जाना चाहिए। मेरी राय में, ऐसा परिणाम स्पष्ट रूप से इसका परिणाम नहीं है

संविधान। लेख बिना पढ़े ही पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी पूर्व-परिकल्पित धारणाएँ। तो पढ़िए, इसका स्पष्ट अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

एस सी आर।

101

कि जिस विधान की जांच की जानी है, वह सीधे उपखंडों में उल्लिखित अधिकारों में से एक के संबंध में होना चाहिए। यदि कोई ऐसा कानून है जो किसी नागरिक की बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है,

या शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का उसका अधिकार,

आदि, सवाल यह है कि क्या उस कानून को संरक्षित किया गया है

अनुच्छेद *19* का सुसंगत बचत खंड उत्पन्न होगा। अगर,

हालाँकि, कानून सीधे संबंध में नहीं है

इनमें से कोई भी विषय, लेकिन ऑपरेशन के परिणामस्वरूप

अन्य विधान, उदाहरण के लिए, दंडात्मक या

निवारक निरोध, इनमें से किसी भी उप के तहत उसका अधिकार

अनुच्छेद *19* उत्पन्न नहीं होता है। सही तरीका केवल यह हैकानून की प्रत्यक्षता पर विचार करना और नहीं

अन्यथा नजरबंदी का क्या परिणाम होगा

वैध, बंदी के जीवन के मोड पर। उस परसंक्षिप्त आधार, मेरी राय में, इस तर्क के बारे में

अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन

आम तौर पर असफल होना चाहिए। कोई अन्य निर्माण

मुझे लगता है कि लेख अनुचित होगा।

इसके बाद यह आग्रह किया गया कि जबकि यह व्याख्या

अधिकारों के संबंध में विवाद को पूरा कर सकते हैं

अनुच्छेद *19 (1) (ए), (बी), (सी), (ई)* और *(जी),* द्वारा दिया गया अधिकार

अनुच्छेद *19 (1), (घ)* को अछूता छोड़ दिया गया है। वह उपखंडस्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है

भारत का क्षेत्र "। यह तर्क दिया गया था कि

निवारक के तहत याचिकाकर्ता का कारावासनज़रबंदी आदेश देता है कि उसे स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है

भारत का क्षेत्र सीधे संक्षिप्त है और इसलिएराज्य को यह दिखाना चाहिए कि विवादित कानून

के अभ्यास पर केवल उचित प्रतिबंध लगाता है

वह अधिकार आम जनता के हित में या

अनुच्छेद *19 (5)* के अधीन। इस प्रकार न्यायालय को आदेश दिया गया है कि -जाँच करें कि क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं

हिरासत में लिया गया व्यक्ति के हितों में उचित है

आम जनता। संविधान का अनुच्छेद *14* देता है -

इन शर्तों में समानता का अधिकारः

"राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित नहीं करेगा।

कानून या कानूनों के समान संरक्षण से पहले

भारत के क्षेत्र के भीतर। *"[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

102

यह तर्क दिया गया था कि शब्द "क्षेत्र के भीतर"

स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। मेरी राय में, निर्माण का यह नियम अपने आप में दोषपूर्ण है। क्योंकि कुछ शब्दों को अनावश्यक माना जा सकता है *(*उन्हें वर्तमान चर्चा के लिए अनुच्छेद *14* में ऐसा मानते हुए*)* यह मान लेना काफी अनुचित है कि वे संविधान के बाकी हिस्सों में जहां भी पाए जाते हैं, वहां अनावश्यक हैं। इसके विपरीत, मेरी राय में, उपखंड *(*घ*)* को समग्र रूप से पढ़ने पर "भारत का क्षेत्र" शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस उपखंड द्वारा जिसे संरक्षित करने की मांग की गई है, वह आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात इसके बिना

भारत के पूरे क्षेत्र में प्रतिबंध। उनके स्वाभाविक व्याकरणिक अर्थ के साथ पढ़ें, उपखंड का केवल यह अर्थ है कि यदि किसी नागरिक की एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाती है, तो ऐसे प्रतिबंधों को उस अनुच्छेद के खंड *(5)* में निर्धारित अनुमेय सीमाओं द्वारा जांचना होगा। उपखंड *(*घ*)* का निरोध, निवारक या दंडात्मक हिरासत से कोई लेना-देना नहीं है। संविधान

भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करता है। उस खंड के प्रत्येक शब्द को उसका सही और वैध अर्थ दिया जाना चाहिए और एक क़ानून, विशेष रूप से एक संविधान के निर्माण में, किसी भी शब्द को छोड़ना अनुचित है जिसमें

इसमें उचित और उचित स्थान या बचना

इसके अर्थ को प्रभाव देने से। यह स्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब खंड *(5)* को इस उपखंड के साथ पढ़ा जाता है। यह आम जनता के हित में या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण में ऐसे अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। यह मुश्किल है

किसी व्यक्ति को कोठरी में सीमित करने के लिए आम जनता के हित में आवश्यक उचित प्रतिबंध की कल्पना करना। इस तरह का प्रतिबंध किसी व्यक्ति को एक प्रांत से दूसरे प्रांत या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में जाने से रोकने के लिए उचित हो सकता है।

103

एस सी आर।

विकल्प द्वारा प्रचुर मात्रा में स्पष्ट किया गया है, अर्थात। , किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। अनुसूचित जनजाति के हितों की किस सुरक्षा के लिए एक आदमी को कोठरी में कैद करने की आवश्यकता होती है*?* दूसरी ओर, भारत के क्षेत्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में किसी व्यक्ति की आवाजाही को रोकना और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए लगाए गए उचित प्रतिबंध का सवाल स्पष्ट रूप से विवेकपूर्ण है और अक्सर देश के प्रशासन के दौरान देखा जाता है। अनुसूचित जनजाति जनजातियों के कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और अक्षमताएँ भी हैं। उनके पास है

उनकी अपनी सभ्यता, रीति-रिवाज और जीवन शैली और किसी विशेष अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों या समूहों के साथ संपर्क की रोकथाम

माना जा सकता है

एक निश्चित अवधि के दौरान अवांछनीय

समय या निश्चित रूप से

भारत का विधायी इतिहास दर्शाता है

शर्तें। कि इन आधारों पर अनुसूचित जनजातियों को एक अलग स्थान दिया गया है। इसलिए, अनुच्छेद *19* को समग्र रूप से पढ़ने पर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है।

कि याचिकाकर्ता के तर्क की स्वीकृति इस खंड की व्याख्या के परिणामस्वरूप

न्यायालय को उचित निर्णय लेने के लिए बुलाया जा रहा है

भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधान

और इस अधिकार को संक्षिप्त करने वाले कई अन्य दंडात्मक कानून। खंड *(5)* के तहत भी न्यायालय को अनुमति है। प्रतिबंधों या सीमाओं की तर्कसंगतता के परीक्षण को आम तौर पर नहीं, बल्कि केवल उस हद तक लागू करना जब तक वे

किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए। मुझमेंराय, यह संविधान का इरादा नहीं है।

इसलिए अनुच्छेद *19* के संबंध में तर्क का आग्रह किया गया

असफल हो जाता है।

अनुच्छेद *19* और अनुच्छेद *21*

यह तर्क दिया गया था कि

एक साथ पढ़ा जाना चाहिए

एक-दूसरे को लागू करें।

नागरिकों के अधिकार, जबकि

अनुच्छेद *19* ने ठोस आधार प्रदान कियाअनुच्छेद *21* में कहा गया है कि नहीं

व्यक्ति वंचित हो सकता है

प्रक्रिया *104* को छोड़कर उसका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अनुच्छेद *19* के अनुसार, मुझे ऐसा लगता है कि निवारक और दंडात्मक निरोध अनुच्छेद *19* के दायरे से बाहर हैं।

अनुच्छेद *19* के वास्तविक दायरे को समझने के लिए

इसे स्वयं पढ़ना और फिर विचार करना उपयोगी है। भाग *III* के अन्य अनुच्छेद नियंत्रण को कितनी दूर तक प्रभावित करते हैं

इसका अर्थ है। यह शीर्षक के तहत पहला लेख है।"स्वतंत्रता का अधिकार "।

यह उल्लिखित अधिकार देता है।

19 (1) (ए) से *(जी)* भारत के सभी नागरिकों के लिए। ये हैं अधिकार

स्वयं पढ़िए और पाए गए नियंत्रणों के अलावा उसी अनुच्छेद के खंड *(2)* से खंड *(6)* में, निर्दिष्ट करें -

विभिन्न सामान्य अधिकार जो एक स्वतंत्र नागरिक मेंलोकतांत्रिक देश में आम तौर पर ऐसा होता है। निर्दिष्ट किया गया है

उन अधिकारों में से प्रत्येक को अलग से माना जाता है

दूसरे में समान अधिकार के दृष्टिकोण से

नागरिक, और ध्यान में रखने के बाद भी

सिद्धांत कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रास्ता देना चाहिए,

जिस हद तक यह आवश्यक है, जब वस्तु या सुरक्षा

लोग सामान्य रूप से चिंतित हैं। इस प्रकार मुक्त होने का अधिकार

वाणी और अभिव्यक्ति का गुंबद *19 (1) (ए)* द्वारा दिया जाता है।

लेकिन खंड *(2)* में प्रावधान है कि ऐसा अधिकार नहीं होगा मानहानि से संबंधित कानून के संचालन को रोकें *",*

बदनामी, मानहानि, न्यायालय की अवमानना या कोई भी मामला

जो शालीनता या नैतिकता के खिलाफ है या जो

सुरक्षा को कमजोर करता है, या उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है, राज्य। खंड *(2)* इस प्रकार केवल इस बात पर जोर देता है कि जबकि

व्यक्तिगत नागरिक को बोलने का स्वतंत्र अधिकार है या

अभिव्यक्ति, उसे उसी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

किसी अन्य नागरिक में समान अधिकार का नुकसान या

राज्य के नुकसान के लिए। इस प्रकार, मानहानि के सभी कानून,

मानहानि, न्यायालय की अवमानना या मामलों के संबंध में कानून

शालीनता या नैतिकता के खिलाफ अपराध की पुष्टि की जाती है के इस व्यक्तिगत अधिकार के बावजूद सक्रिय होने के लिए

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नागरिक। इसी तरह, वह अधिकार उन कानूनों के अधीन भी है जो एक को रोकते हैं

राज्य की सुरक्षा को बाधित करना या गतिविधियों के खिलाफ जो राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी तरह का विश्लेषण

खंड *(3)* और *(4)* में समान प्रतिबंध लगाए गए हैं।

समान आधार। इसी तरह खंड *(5)* भी अनुमति देता है।

अधिकार के प्रयोग में उचित प्रतिबंध

पूरे देश में आवाजाही की स्वतंत्रता

का क्षेत्र

भारत, किसी भी देश में रहने और बसने का अधिकार

105 का हिस्सा

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का राज्यक्षेत्र या कानून द्वारा अधिरोपित संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार, बशर्ते कि ऐसे अधिकार के प्रयोग पर ऐसे उचित प्रतिबंध आम जनता के हित में हों। संविधान में इसी खंड द्वारा आगे प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए उन अधिकारों के प्रयोग पर इसी तरह के उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से इस तर्क को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए है कि हालांकि इस तरह के प्रतिबंध आम जनता के हित में लगाए जा सकते हैं, लेकिन संविधान के संविधान में हितों की रक्षा के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं था

केवल लोगों का एक छोटा समूह। अनुच्छेद *19* को इस तरह से समग्र रूप से पढ़ने पर एकमात्र अवधारणा यह प्रतीत होती है कि एक स्वतंत्र नागरिक के निर्दिष्ट अधिकारों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है जो संविधान के उल्लंघनकर्ताओं ने सोचा था कि बाकी नागरिकों के हित में आवश्यक प्रतिबंध थे।

अनुच्छेद *19* को इस तरह पढ़ना मुझे प्रतीत होता है

कि भारत के क्षेत्र से बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की अवधारणा अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार से पूरी तरह से अलग अवधारणा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता "कवर

एक अर्थ में कई और अधिकार हैं और दूसरे अर्थ में इसका सीमित अर्थ है। उदाहरण के लिए, जबकि रहने या रहने का अधिकार "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जा सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार।

भाषण का *[*अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* में उल्लिखित*]* या संपत्ति के अधिग्रहण, धारण या निपटान का अधिकार *(*में उल्लिखित*)*

19 (1) (च*)* इसे किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। वे स्वतंत्रता का हिस्सा हैं

नागरिक लेकिन शब्द द्वारा लगाई गई सीमा

" व्यक्तिगत "मुझे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि वे अधिकार अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। इसलिए पढ़ें कि अनुच्छेद *19* और *21* के बीच कोई टकराव नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद *19* और *21* की सामग्री और विषय वस्तुएँ समान नहीं हैं और वे अपने-अपने शब्दों में शामिल अधिकारों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

बिल्कुल अलग कोणों से। जैसा कि पहले से ही पुरुषों ने अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंडों में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकार के संबंध में प्रत्येक के संबंध में विशिष्ट सीमाएं प्रदान की हैं, जबकि अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत *106*"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अनुच्छेद *21* में स्वतंत्रता को आम तौर पर नियंत्रित किया जाता है -

अभिव्यक्ति "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रक्रिया"।

जनरल द.

संविधान में

लेख

19 , और इसमें भी

भाग *III* के अन्य अनुच्छेद, इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामान्य हित के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। विधायी शक्तियों या राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण पर संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंध इस प्रकार व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में कार्य करते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित *(*कुल हानि*),* जो

अन्य बातों के साथ-साथ खाने या सोने का अधिकार जब कोई चाहे या काम करने का अधिकार या जब चाहे काम न करने का अधिकार शामिल है और ऐसे कई अधिकार जिन्हें अनुच्छेद *21* में *"*व्यक्तिगत स्वतंत्रता*"* अभिव्यक्ति द्वारा संरक्षित करने की मांग की गई है*,* स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार के प्रतिबंध *(*जो केवल एक आंशिक नियंत्रण है*)* से काफी अलग है।

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* द्वारा संरक्षित एक नागरिक का एक छोटा अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया गया है

में मुक्त आवाजाही के प्रतिबंध के रूप में एक ही अर्थ

भारत का क्षेत्र। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब

शांति की सुरक्षा या शांति बनाए रखने से संबंधित अध्याय *VIII* में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान

सार्वजनिक आदेश पढ़ा जाता है। इसलिए अनुच्छेद *19 (5)* ऐसा नहीं कर सकता है।

एक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले मूल कानून पर लागू होता है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।

कि *"*अभाव*"* शब्द अपने दायरे में शामिल है*"* अनुच्छेद *21* की व्याख्या करते समय *"*प्रतिबंध*"*। अनुच्छेद *22*

निवारक निरोध के कानून की परिकल्पना की गई है। ऐसा भी होता है।

अनुसूची सात*,* सूची *I,* प्रविष्टि *9* के साथ पठित अनुच्छेद *246*

और सूची *III,* प्रविष्टि *3*। इसलिए जब विषय

निवारक निरोध विशेष रूप से निपटाया जाता है

मौलिक अधिकारों के अध्याय में मुझे नहीं लगता

अनुमति देने वाले कानून पर विचार करने के लिए

यह उचित है

अधिकारों के साथ टकराव के रूप में निवारक निरोध

अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित है। अनुच्छेद *19 (1)* में ऐसा नहीं है

स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी पहलुओं को शामिल करने का उद्देश्यस्वतंत्रता। उस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के केवल कुछ चरण हैं

उनका इलाज किया जाता है "। व्यक्तिगत स्वतंत्रता "मुख्य रूप से

इसका अर्थ है भौतिक शरीर की स्वतंत्रता। दिए गए अधिकार

वर्णन करें। वे अधिकार हैं जो इसके साथ आते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता।

उनकी सर्वोच्च अदालत की रिपोर्टों से

एस सी आर।

107

प्रकृति वे एक व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ हैं जो माना जाता है

का अधिकार

पूरी तरह से

स्वतंत्रता। अगर

उसका

व्यक्तिगत

अनुच्छेद *19 19* है

माना जाता है

एकमात्र बनो

को

लेख

रक्षा करना

स्वतंत्रता कई

व्यक्तिगत

या शराब पीना, काम करने, खेलने, तैरने का अधिकार और कईअन्य अधिकार और गतिविधियाँ और यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी

संविधान के तहत संरक्षित नहीं माना जाएगा।

मुझे नहीं लगता कि यह इरादा है। मुझे ऐसा लगता है

अनुच्छेद *19* को उसी से संबंधित पढ़ने के लिए अनुचित है

अनुच्छेद *21* के रूप में विषय। अनुच्छेद *19* केवल भारत के नागरिकों को उसमें निर्दिष्ट अधिकार देता है, जबकि

अनुच्छेद *21* सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। वह शब्द।

संविधान में नागरिक को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हैके निवासियों के केवल एक निश्चित वर्ग को इंगित करें

सायन की व्याख्या अर्थ में की जाती है। विधायी प्रतिबंध विधायिका की कानून बनाने की शक्तियों पर नहीं हैं

यहाँ अधिकारों के मामले में विस्तार से निर्धारित किया गया है

अनुच्छेद *19* में विनिर्दिष्ट। इसलिए मेरी राय में लेख

19 इसे एक अलग पूर्ण लेख के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

अनुच्छेद *21* जो इसके तहत भाग *III* में भी है

शीर्षक "स्वतंत्रता का अधिकार" इस प्रकार हैः

अपने जीवन से वंचित या

"कोई भी व्यक्ति नहीं होगा

व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिवाय

प्रक्रिया के अनुसार

कानून द्वारा स्थापित "।

यह लेख है

दृढ़ता से निर्भर करता है

याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कहा कि

विवादित अधिनियम संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह

इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए अधिकार का हनन करता है। यह तर्क दिया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तहत संबंधित *5* वें और *14* वें संशोधनों में प्रावधान पाया गया है जहां प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि भारतीय संविधान देता है

भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान सुरक्षा, सिवाय इसके कि संयुक्त राज्य अमेरिका में "कानून की उचित प्रक्रिया" को इसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कवर करने के लिए समझा गया है।

दोनों *108*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मूल और प्रक्रियात्मक कानून, जबकि भारत में केवल प्रक्रियात्मक कानून के संरक्षण की गारंटी है। यह तर्क दिया गया कि "देय" शब्द को हटाने से अनुच्छेद *21* में शब्दों की व्याख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। "स्थापित" शब्द "निर्धारित" के बराबर नहीं था। इसका एक व्यापक अर्थ था। "कानून" शब्द का अर्थ अधिनियमित कानून नहीं था क्योंकि वह कोई विधायी संरक्षण नहीं होगा। यदि ऐसा समझा जाता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी अधिनियम, जो अन्यथा इसकी विधायी शक्ति के भीतर था,

इस अधिकार को नष्ट या कम करें। उसी तर्क पर, यह तर्क दिया गया था कि अगर यही इरादा था

भाग *III* में इसे मौलिक अधिकार के रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। "कानून" शब्द के अर्थ के बारे में यह तर्क दिया गया था कि इसका अर्थ है

सिद्धांत

में से

प्राकृतिक न्याय। इसका मतलब था

" जस ", अर्थात,

कानून

सिद्धांतों का

प्राकृतिक

अमूर्त अर्थ में न्याय, जैसा कि न्यायशास्त्र के मानक कार्यों में उल्लेख किया गया है, न कि "लेक्स", यानी अधिनियमित कानून। इस तर्क के खिलाफ कि इस तरह के निर्माण से अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा, यह तर्क दिया गया था कि चार सिद्धांत

सभी सभ्य देशों में मान्यता प्राप्त प्राकृतिक न्याय

किसी भी स्थिति में, "कानून" शब्द द्वारा कवर किया गया था। वे इस प्रकार हैं: *(1)* एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अर्थात। , उल्लंघन के लिए मानव आचरण का एक निश्चित, निश्चित और सुनिश्चित नियम

जिनमे से किसी को हिरासत में लिया जा सकता है; *(2)* ऐसे निरोध के आधारों की सूचना; *(3)* एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण, प्रशासनिक, न्यायिक या सलाहकार, यह तय करने के लिए कि क्या निरोध उचित है; और *(4)* मौखिक रूप से सुनवाई का अवसर *(*केवल लिखित अभ्यावेदन करके नहीं*)* सहित व्यवस्थित प्रक्रिया, साक्ष्य देने और गवाहों को बुलाने के अधिकार के साथ।

मेरी राय में, यह दृष्टिकोण उचित नहीं है

और वास्तव में यह भ्रामक है। जहां तक अमेरिकी संविधान का संबंध है, इसकी सामान्य संरचना पृष्ठ *53* पर मुनरो *(5* वें संस्करण*)* द्वारा "संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार" में इन शब्दों में देखी गई है: *" 1787* के वास्तुकारों ने केवल तहखाने का निर्माण किया। उनके वंशजों ने दीवारों और खिड़कियों, पंखों और गैबल्स, खंभों और बरामदों को जोड़कर एक शानदार शिल्प निर्माण किया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। या, रूपक को बदलने के लिए, इसमें एक कपड़ा होता है, जो एस. सी. आर. के शब्दों का उपयोग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

109

जेम्स रसेल लोवेल को अभी भी 'समय के गर्जन करघे पर बुना जा रहा है'। मूल संविधान के निर्माताओं का यही इरादा था। उनके दिमाग में यह कभी नहीं था कि वे देश की सरकार के लिए एक अंतिम योजना तैयार करें और इसे हमेशा के लिए रूढ़िबद्ध करें। वे केवल एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करना चाहते थे। संवैधानिक कानून पर प्रोफेसर विलिस की पुस्तक में भी इसी पहलू पर जोर दिया गया है।

कूली का

संवैधानिक सीमाएँ।

द.

इसके विपरीत

अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान बहुत विस्तृत है। संविधान स्वयं संसद की विधायी शक्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

वैसा ही।

विधायिकाएँ।

विशेषता है

और

राज्य

न्यायपालिका के मामले में ध्यान देने योग्य,

वित्त, व्यापार,

विस्तृत और

वाणिज्य और सेवाएँ।

इस प्रकार यह काफी है

भाग *III* या लेख को अनुचित महत्व दिए बिना, इसे पूरी तरह से एक ही पवित्रता के साथ पढ़ना होगा।

246 , सिवाय उस सीमा के जो एक दूसरे द्वारा वैध और स्पष्ट रूप से सीमित है।

के बीच अंतर के चार चिह्नित बिंदु

अमेरिकी संविधान के खंड और भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* को इस स्तर पर देखा जा सकता है। पहला यह है कि अमेरिकी संविधान में यह शब्द है

"स्वतंत्रता का उपयोग सरलता से किया जाता है जबकि भारत में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक ही सीमित है। *(2)* यू. एस. ए. संविधान में संपत्ति को समान सुरक्षा दी गई है, जबकि भारत में संपत्ति के संबंध में मौलिक अधिकार है।

यह अनुच्छेद *31* में निहित है। *(3)* "देय" शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है और "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का उपयोग जानबूझकर नहीं किया गया है। *(4)* "स्थापना शेड" शब्द का उपयोग किया जाता है और यह हमारे अनुच्छेद *21* में "प्रक्रिया" तक सीमित है।

याचिकाकर्ता का पूरा तर्क आधारित है।

द्वारा दिए गए "कानून" शब्द का अर्थ

यू. एस. ए. के सर्वोच्च न्यायालय और वे कैसे कानून के अर्थ को बढ़ाने या कम करने के लिए आए अभिव्यक्ति "कानून की उचित प्रक्रिया" विवरण में गए बिना, मुझे लगता है कि इसे अपनाने का कोई औचित्य नहीं है

"कानून" शब्द का अर्थ जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई है

यू. एस. ए. का सर्वोच्च न्यायालय "देय *110*" अभिव्यक्ति में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

विधि की प्रक्रिया "केवल इसलिए कि" विधि "शब्द का उपयोग अनुच्छेद *21* में किया गया है। संवैधानिक कानून और कूली की संवैधानिक सीमाओं पर विलिस में पाए गए "कानून की उचित प्रक्रिया" के अर्थ की चर्चा उस अभिव्यक्ति को अलग-अलग समय पर और अलग-अलग परिस्थितियों में दिए गए विविध अर्थों को दर्शाती है।

यू. एस. ए. का सर्वोच्च न्यायालय, इतना कि इन लेखकों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभिव्यक्ति का अर्थ उचित कानून है। किसी विशेष समय पर पद धारण करने वाले उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों के विचार के अनुसार। यह यह भी दर्शाता है कि कैसे कुछ दशकों में अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक या संक्षिप्त किया गया था। इसके अलावा, समय-समय पर उस अभिव्यक्ति को दिए गए अर्थ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस शक्तियों के सिद्धांत को लागू किया गया था। यह सिद्धांत, संक्षेप में कहा जाए तो, यह है कि कानून आम तौर पर लोगों की भलाई के लिए है, और जिसमें व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता को कुछ हद तक आत्मसमर्पण करना पड़ता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर लोगों के लाभ के लिए है, इसका परीक्षण "कानून की उचित प्रक्रिया" सूत्र की कसौटी से नहीं किया जाना चाहिए।

हमारा ध्यान बहसों की ओर खींचा गया और

इस खंड के शब्दों के संबंध में संविधान सभा की मसौदा समिति की रिपोर्ट।

रिपोर्ट को लेख के अर्थ को नियंत्रित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन अस्पष्टता के मामले में देखा जा सकता है। सिडनी की नगर परिषद बनाम। सामान्य धन *()*, यह माना जाता था कि व्यक्तिगत राय। बहस में व्यक्त कन्वेंशन के सदस्यों को संविधान का अर्थ लगाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है। यही राय संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम में व्यक्त की गई थी। वोंग किम आर्क *()*। परिणाम यह प्रतीत होता है कि यद्यपि विशेष खंड के अर्थ का अर्थ निकालने के लिए संसद या सम्मेलन के सदस्यों की व्यक्तिगत राय पर विचार करना उचित नहीं है, जब कोई प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई निश्चित वाक्यांश या अभिव्यक्ति विचार के लिए थी या नहीं, तो बहस के संदर्भ की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान मामले में बहसों को यह दिखाने के लिए संदर्भित किया गया था कि अभिव्यक्ति "की उचित प्रक्रिया"

कानून "अमेरिकी संविधान *(1) (1904) 1* कॉम, एल. आर. *208* में मौजूद था।

(1) (169) 699 पर यू. एस. *649*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

111

एस सी आर।

और एक चर्चा के बाद हमारे संविधान में कॉन्स्टी ट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया नहीं गया था। बंगाल के प्रशासक जनरल बनाम। प्रेमलाल मलिक *(1)*, विधानमंडल की कार्यवाही का एक संदर्भ जिसके परिणामस्वरूप

अधिनियम के पारित होने को किसी विशेष धारा के निर्माण में वैध सहायता नहीं माना जाता था। द.

एक को बाहर करने के लिए ठोस के रूप में आयोजित

एक ही कारण थे

भारतीय क़ानून के अर्थ में इस तरह की बहसों का संदर्भ। इन स्रोतों को बड़ी सावधानी के साथ रिसॉर्ट करना पड़ सकता है और केवल तभी जब अव्यक्त अस्पष्टताओं को हल किया जाना हो। क्रेइज़ क़ानून देखें। *(4* संस्करण*)* पृष्ठ *122*, मैक्सवेल

क़ानूनों की व्याख्या

पर

(9 संस्करण*)* पीपी। *28-29* और सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड *(1940* संस्करण*)* पी। *379* , अनुच्छेद *214*। मसौदा समिति की रिपोर्ट, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, उसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संविधान सभा के समक्ष अमेरिकी संविधान था। अनुच्छेद और अभिव्यक्ति "कानून की उचित प्रक्रिया" लेकिन

उन्होंने जानबूझकर हमारे संविधान से उस अभिव्यक्ति के उपयोग को हटा दिया।

शब्दों की व्याख्या करने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद *21*, जो मेरी राय में अस्पष्ट नहीं है।

अन्य का

सोच-विचार में

आम तौर पर पढ़ें, और

बिना

" प्रक्रिया की अवधि

संविधान,

अभिव्यक्ति

कानून द्वारा ब्लिश किया जाना चाहिए

निर्धारित प्रक्रिया

मतलब

राज्य के कानून द्वारा। अगर भारतीय संघ

ट्यूशन प्रत्येक व्यक्ति को अमेरिकी संविधान के उचित प्रक्रिया खंड द्वारा दिए गए संरक्षण को संरक्षित करना चाहता था, विधानसभा को इस वाक्यांश को अपनाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, या यदि वे इसे केवल प्रक्रिया तक सीमित रखना चाहते थे, तो उस अभिव्यक्ति को केवल "प्रक्रिया" शब्द के साथ "कानून" के लिए पूर्व निर्धारित करना चाहते थे। लेकिन, सही सवाल यह है कि अनुच्छेद *21* द्वारा दिया गया अधिकार क्या है*?* एकमात्र अधिकार है

कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक बड़े क्षेत्र को कवर करने का अधिकार पसंद हो सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार देना न्यायालय का कार्य नहीं है*;* यह संविधान का कार्य है। "कानून" शब्द को प्राकृतिक न्याय के नियमों के अर्थ के रूप में पढ़ने से एक व्यक्ति प्रभावित होगा।

(1) (1895) एल. आर. *22* आई. ए. *107.*

कठिनाइयाँ क्योंकि प्रक्रिया के संबंध में प्राकृतिक न्याय के नियम कहीं भी परिभाषित नहीं हैं और मेरी राय में संविधान को एक अस्पष्ट मानक निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब "कानून की उचित प्रक्रिया" को अपनाने से बचने के लिए यह माना जाता था कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति मानक को विशिष्ट बनाती है। यह विधायिका द्वारा निर्धारित अभिव्यक्ति को अर्थ प्रक्रिया के रूप में पढ़ने के अलावा विशिष्ट नहीं हो सकता है। इस भाग में उपयोग किए गए "कानून" शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं, लेकिन किसी अन्य अनुच्छेद में यह प्राकृतिक न्याय का अनिश्चित अर्थ नहीं रखता है। अगर ऐसा है तो

इस लेख में इस विशिष्ट अर्थ को प्राप्त करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अनुच्छेद *31* जो भाग *III* में भी है और मौलिक अधिकारों से संबंधित है

संपत्ति का सम्मान इस प्रकार है -

"किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि

कानून के अधिकार से "।

यह स्पष्ट है कि उस खंड में "कानून" का अर्थ होना चाहिए

अधिनियमित कानून। एक अलग अनुच्छेद के तहत संपत्ति से निपटने का उद्देश्य अनुच्छेद *31 (2)* से *(6)* में पाए गए अपवादों को प्रदान करने के लिए अधिक प्रतीत होता है, बजाय इसके कि "कानून" शब्द को अनुच्छेद *21* में दिए गए अर्थ से अलग अर्थ दिया जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "स्थापित" शब्द का अर्थ है "ठीक करना, बसाना, स्थापित करना"।

या अधिनियम या समझौते द्वारा आदेश। वह शब्द।

"स्थापित "स्वयं एक एजेंसी का सुझाव देता है जो इसे ठीक करती है

सीमाएँ। शब्दकोश के अनुसार यह एजेंसी कर सकती है

या तो विधायिका या दोनों के बीच एक समझौता हो

पार्टियाँ। इसलिए देने का कोई औचित्य नहीं है

अनुच्छेद *21* में "न्याय" से "कानून" का अर्थ है।

वाक्यांश "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" प्रतीत होता है।

जापानी संविधान के अनुच्छेद *31* से उधार लिया जाना ट्यूशन। लेकिन उस संविधान के अन्य अनुच्छेद

जो स्पष्ट रूप से अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को संरक्षित करते हैं

निर्धारित करने के लिए विभिन्न खंडों को एक साथ पढ़ना होगा।

"प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में "कानून" का अर्थ

कानून द्वारा स्थापित "। जापानियों के ये लेख

संविधान में शामिल नहीं किया गया है

उसी भाषा में भारत का संविधान। यह नहीं है।

यह दिखाया गया है कि जापा में "कानून" शब्द का अर्थ "जस" है।अपना संविधान। जापानी संविधान में ये *113*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर। प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत दावा किए गए अधिकार शब्दों की व्याख्या द्वारा नहीं दिए जाते हैं।

" उनके अनुच्छेद *31* में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान में "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में "देय" शब्द की व्याख्या का अर्थ है

" यू. एस. ए. के सर्वोच्च न्यायालय की राय के अनुसार यह शब्द न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। कानून के अनुसार, अन्यथा से "देय" का उच्चारण करना। अनुच्छेद *21* से "देय" शब्द को जानबूझकर हटाना इस तर्क को बल देता है कि "कानून" का न्यायोचित पहलू, यानी यह विचार करना कि यह न्यायालय द्वारा उचित है या नहीं, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। "देय" शब्द को छोड़ना, "प्रक्रिया" शब्द द्वारा लगाई गई सीमा और "स्थापित" शब्द को सम्मिलित करना इस प्रकार विधायी के विचार को अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाता है।

अनुच्छेद *21* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति में प्रिस्क्रिप्शन। के द्वारा "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" वाक्यांश को अपनाना

संविधान ने विधायिका को कानून निर्धारित करने के लिए अंतिम शब्द दिया।

हमारा ध्यान द किंग वी की ओर खींचा गया था। द.

हेयर पार्क कैम्प *(1)* के सैन्य गवर्नर, जहाँ आयरिश संविधान के अनुच्छेद *6* और *70* हैं

व्यक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा "कानून के अनुसार" को छोड़कर इस तरह से वंचित।

अनुच्छेद *70* में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

" कानून के उचित पाठ्यक्रम और असाधारण न्यायालयों को छोड़कर स्थापित करने की अनुमति नहीं थी सिवाय इसके कि

सैन्य अपराधों की सुनवाई के लिए सैन्य न्यायालय। भूतपूर्व

"कानून के अनुसार" दबाव की व्याख्या की गई थी

इसका अर्थ प्राकृतिक न्याय के नियम नहीं बल्कि कानून के रूप में है

लार्ड एटकिन द्वारा एशुगबायी एलेको वी में देखा गया। अधिकारी नाइजीरिया सरकार का प्रशासन *(2),* कि

ब्रिटिश न्यायशास्त्र सं। कार्यपालिका का सदस्य स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है

या किसी ब्रिटिश प्रजा की संपत्ति सिवाय जब वह कर सकता है

न्याय के न्यायालय के समक्ष उसके कार्य की वैधता का समर्थन करें।

(1) [1931] ए. सी. *662 670* पर।

(1) [1924] 2 आयरिश रिपोर्ट के. बी. *104*।

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

114

द किंग वी. गृह मामलों के राज्य सचिव *()* स्क्रूटन एल. जे. ने कहाः हत्या के संदिग्ध रूप से दोषी व्यक्ति को अभी तक रिहा किया जाना चाहिए यदि उसकी सजा में कानून के उचित रूपों का पालन नहीं किया गया है। *27* यह बहुत तर्कपूर्ण लगता है कि पूरे सेट में

हमारे संविधान का भाग *III* केवल ये सिद्धांत हैं

अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटीकृत रहें।

लेख की वास्तविक सीमाओं की विस्तृत चर्चा

21 यदि अनुच्छेद *22* को उस हद तक एक संहिता माना जाता है, जिसमें निवारक निरोध के प्रावधान हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि भाग *III* के लेख विभिन्न विषयों से संबंधित हैं।

और अलग अधिकार। शीर्षक के तहत "स्वतंत्रता का अधिकार" लेख *19-22* को समूहीकृत किया गया है लेकिन प्रत्येक के साथ एक

अलग सीमांत नोटः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *22 (1)* और *(2)* अनुच्छेद *21* द्वारा दिए गए अधिकार पर सीमाएं निर्धारित करते हैं। यदि उन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो अनुच्छेद *22 (1)* और *(2)* द्वारा अनुध्यात गिरफ्तारी और निरोध, हालांकि वे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते

हैं, कानूनी होगा, क्योंकि यह गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में स्थापित कानूनी प्रक्रिया बन जाती है। अनुच्छेद *22* कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा के लिए है, और निम्नानुसार चलता हैः

" 22. (1) गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति नहीं होगा।

बिना सूचित किए हिरासत में लिया गया, जल्द से जल्द

ऐसी गिरफ्तारी के लिए जो भी आधार हो, और न ही उसे परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अपनी पसंद का एक कानूनी व्यवसायी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है

अभिरक्षा को ऐसे बीस-चार घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी

मजिस्ट्रेट और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

(3) खंड *(1)* और *(2)* में कुछ भी लागू नहीं होगा।

(क*)* किसी भी व्यक्ति के लिए जो कुछ समय के लिए एक है

दुश्मन विदेशी*;* या

(1) [1923] से के. बी. *361 382 115* पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

(ख*)* गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत।

(4) निवारक निरोध के लिए कोई कानून नहीं

किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करेगा। तीन महीने से अधिक की अवधि जब तक कि

(क*)* एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो

के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हैं, या रहे हैं, या हैं

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने पूर्व के समक्ष रिपोर्ट की हैतीन महीने की उक्त अवधि का पायरेशन कि वहाँ

उसकी राय में इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण हैः

बशर्ते कि इस उपखंड में कुछ भी नहीं होगा

इससे परे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करना

द्वारा बनाई गई किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि खंड *(1)* के उपखंड *(*बी*)* के तहत संसद*;* या

(ख*)* ऐसे व्यक्ति को इसके अनुसार हिरासत में लिया जाता है -

संसद द्वारा उप के अधीन बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानखंड *(7)* के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)*।

(5) जब किसी व्यक्ति को अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है

पूर्व प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किए गए आदेश का

वेंटिव हिरासत, आदेश देने वाला प्राधिकरण

जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा।

जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और उसे एक बनाने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा

आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व।

(6) खंड *(5)* की किसी भी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि -

ऐसा कोई आदेश देने वाला प्राधिकारी जिसे निर्दिष्ट किया गया है

वह खंड तथ्यों को प्रकट करने के लिए जो ऐसा प्राधिकारी

खुलासा करना लोक हित के खिलाफ माना जाता है।

(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क*)* जिन परिस्थितियों में, और वर्ग

या ऐसे मामलों के वर्ग जिनमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है

किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए

बिना प्राप्त किए निवारक निरोध का प्रावधान करनाके अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय

खंड *(4)* के उपखंड *(*क*)* के प्रावधान*;*

(ख*)* अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति

किसी भी वर्ग या मामलों के वर्गों के तहत हिरासत में लिया जा सकता है निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई कानून*;* और

(ग*)* एक सलाहकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

खंड *(4)* के उपखंड *(*ए*)* के तहत एक जांच में बोर्ड।

विद्वान अत्तोर्नेव-जनरल ने तर्क दिया कि

निवारक निरोध का विषय इसके अंतर्गत नहीं आता है

3-3 एस. सी. इंडिया*/58*

116

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अनुच्छेद *21* और पूरी तरह से अनुच्छेद *22* द्वारा कवर किया गया है।

गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अनुच्छेद *22 (1)* और *(2)* सुरक्षा प्रदान करें। इन सुरक्षा उपायों को बाहर रखा गया है

अनुच्छेद *22 (3)* द्वारा निवारक निरोध का मामला, लेकिन इस तरह के निरोध के संबंध में सुरक्षा उपाय अनुकूल हैं।

उसी अनुच्छेद के खंड *(4)* से खंड *(7)* द्वारा निर्दिष्ट। इसलिए यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *21* को अनुच्छेद *22* द्वारा दिए गए पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह से पढ़ना सही है

निर्माण का तरीका इस हद तक होगा कि

प्रक्रिया अनुच्छेद *22* द्वारा निर्धारित की गई है वही होनी है देखा गया*;* अन्यथा अनुच्छेद *21* लागू होगा। लेकिन अगर

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं बताया गया है, या प्रक्रिया के कुछ बिंदुओं पर विशिष्ट नियम हैं।

ड्यूरे निर्धारित किए गए हैं, व्याख्या करना अनुचित लगता है

ये बिंदु अनुच्छेद *22* में शामिल नहीं हैं और इन्हें खुला छोड़ दिया गया है

अनुच्छेद *21* के अधीन विचार के लिए। जिस हद तक बिंदुओं से निपटा जाता है, और शामिल या बहिष्कृत किया जाता है, अनुच्छेद *22* एक पूर्ण संहिता है। प्रक्रिया के बिंदुओं पर

जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनुच्छेद *22*, अनुच्छेद *21* के संचालन द्वारा नहीं निपटा गया है।

रहेगा। अप्रभावित। अतः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अधिनियम या इनमें से कोई भी है, पहले आक्षेपित अधिनियम के अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* और उसके बाद के प्रावधानों को देखना आवश्यक है।

निवारक निरोध की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं, इस तरह के अधिकार पर बहुत कम सीमाएँ निर्धारित करना

हिरासत, सामान्य समय में, यानी आपातकाल की घोषणा के बिना। सामान्य समय में निवारक निरोध, यानी युद्ध जैसे आपातकाल के अस्तित्व के बिना,

इसे सातवीं योजना युगल की सूची *I*, प्रविष्टि *9* और सूची *III*, प्रविष्टि *3* में कानून के एक सामान्य विषय के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के अध्याय में भी

अनुच्छेद *22* सामान्य समय में निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने की परिकल्पना करता है। अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* के प्रावधान अपने शब्दों से इस मुद्दे पर विधान की बड़ी शक्तियों को अप्रभावित छोड़ते हैं और विशेष रूप से अनुच्छेद *22 (7)* द्वारा किसी व्यक्ति को अपने मामले पर सलाहकार मंडल द्वारा विचार करने के अधिकार से वंचित करने की संसद की शक्ति पर जोर देते हैं। भाग *III* और एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

117

विशेष रूप से अनुच्छेद *22* उस शक्ति पर केवल प्रतिबंध हैं और लेकिन उन प्रावधानों के लिए इस विषय पर देर से कानून बनाने की शक्ति काफी अप्रतिबंधित होती। संसद निवारक निरोध के लिए बिना किसी सुरक्षा या किसी प्रक्रिया के कानून बना सकती थी। विधायिका की इस तरह की निरंकुश सर्वोच्चता को अनुच्छेद *21* द्वारा निश्चित रूप से कम कर दिया गया है। इसलिए, यदि कानून किसी वैध रूप से अधिनियमित कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित करता है और निवारक निरोध के मामले में ऐसी प्रक्रिया भाग *III* या अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* के स्पष्ट प्रावधानों के साथ टकराव में नहीं आती है, तो निवारक दंड अधिनियम को वैध माना जाना चाहिए, इसके बावजूद कि -

न्यायालय ऐसे अधिनियम के तहत प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुमोदित नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद *22 (4)* दोहरी नकारात्मकता के साथ शुरू होता है। लगायें।

सकारात्मक रूप में इसका अर्थ यह होगा कि एक कानून जो तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निवारक निरोध का पक्ष लेता है, उसमें एक सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान होगा, *(*जिसमें उपखंड *(ए)* में उल्लिखित योग्यता वाले व्यक्ति शामिल होंगे, और जिसे तीन महीने की समाप्ति से पहले रिपोर्ट करनी होगी यदि

राय है कि इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण था। यह खंड, यदि यह अपने आप में और अनुच्छेद *22* के पुनर्निर्धारण प्रावधानों के बिना खड़ा है, तो दोनों पर लागू होगा -

संसद और राज्य विधानमंडल। प्रावधान

इस खंड में आगे यह आदेश दिया गया है कि भले ही विज्ञापन दृश्य बोर्ड की राय हो कि वहाँ थाऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण, अर्थात तीन महीने की अवधि के बाद निरोध, फिर भी अधिकतम अवधि से अधिक निरोध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि

अनुच्छेद *22 (7) (*बी*)* के तहत संसद द्वारा विहित कोई भी,पुनः इस पूरे उपखंड को निष्क्रिय कर दिया गया है।

निवारक अधिनियम के संबंध में अनुच्छेद *22 (4) (*बी*)* द्वारा

खंड *(7) (*ए*)* के तहत संसद द्वारा पारित निरोधऔर *(*बी*)*। क्योंकि आक्षेपित अधिनियम एक अधिनियम है

संसद जिसे इस प्रकार बनाया जाना अपेक्षित है, खंड *22 (4)*

इसका कोई संचालन नहीं है और वर्तमान चर्चा के लिए हो सकता है

अलग रखें। अनुच्छेद *22 (5)* में निर्धारित किया गया है कि जब कोई

आदेश देने वाला प्राधिकारी जितनी जल्दी हो सके हो, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करें जिनके आधार पर

आदेश दिया गया है और उसे *[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

118

आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर। यह. खंड किसी भी विधि अनुमति के तहत किए गए प्रत्येक निरोध आदेश के संबंध में सामान्य रूप से लागू होता है।

टिंग हिरासत। अनुच्छेद *22 22 ((6))* अनुमति देता है कि प्राधिकरण तथ्यों के प्रकटीकरण को रोकने का आदेश दे जो

ऐसा प्राधिकारी खुलासा करना लोक हित के खिलाफ मानता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह खंड केवल तथ्यों का खुलासा न करने और खंड *(5)* और *(6)* को एक साथ पढ़ने पर तथ्यों और निरोध के आधारों के बीच अंतर करता है। अनुच्छेद *22 (4)* और *(7)* केवल निरोध की अवधि से संबंधित नहीं है, बल्कि

निवारक निरोध के मामले में अन्य आवश्यकताएँ भी। वे एक सलाहकार मंडल की स्थापना, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता और उसे प्रतिनिधि बनाने का अधिकार देने का भी प्रावधान करते हैं।

प्रेषण। अनुच्छेद *22* खंड *(4)* और *(7)* को पढ़नाऐसा प्रतीत होता है कि निवारक निरोध

बिना किसी सलाह के तीन महीने से कम समय के लिए

बोर्ड, मौलिक पर अध्याय के तहत अनुमति है

अधिकार, बशर्ते कि ऐसा विधान विधान के भीतर होसंसद या राज्य विधानमंडल की क्षमता

प्रकृति, जैसा भी मामला हो सकता है।

अनुच्छेद *22 (5)* हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है

एक प्रतिनिधित्व। संविधान इस बारे में चुप है जिस व्यक्ति के लिए इसे बनाया जाना है, या इसे कैसे बनाया जाना है

निपटा लिया। लेकिन यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है

संविधान। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदिनिवारक के संबंध में संसद द्वारा बनाया गया कानून

नजरबंदी उन दो बिंदुओं पर प्रावधान नहीं करती है।

यह अमान्य है। इन बिंदुओं पर चुप रहने से कुछ नहीं होता।

संविधान के उल्लंघन में विवादित अधिनियम

क्योंकि पहला सवाल यह है कि क्या अधिकार दिए गए हैं*?*

निवारक निरोध के मामले में संविधान द्वारा।

यह तर्क कि प्रतिनिधित्व एक होना चाहिए

बाहरी निकाय को कानून में कोई समर्थन नहीं है। यहां तक कि

लिवर्जिज मामले में प्रतिनिधित्व किया जाना था

राज्य सचिव और किसी अन्य निकाय के लिए नहीं। इसके बाद ऐसा प्रतिनिधित्व किया गया था, एक और सलाहकार बोर्ड

इस पर विचार करना था, लेकिन यह करना आवश्यक नहीं था

किसी तीसरे पक्ष को स्वयं का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद *22*

(4) और *(7)* परामर्श की स्थापना न करने की अनुमति दें।

एक संसदीय विधान एस. सी. आर. में स्पष्ट रूप से बोर्ड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

119

निवारक का प्रावधान

तीन से अधिक हिरासत

महीनों तक। यदि ऐसा है, तो यह कैसे आग्रह किया जा सकता है कि

सलाहकार बोर्ड की स्थापना में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उल्लंघन किया गया एक मौलिक अधिकार है

संसद द्वारा पारित अधिनियम*?*

महत्वपूर्ण खंड जिस पर विचार किया जाना है वह है अनुच्छेद।

22 (7) . उपखंड *(ए)* इस मामले के लिए महत्वपूर्ण है। द्वारा पारित निवारक निरोध अधिनियम के मामले में

संसद मौलिक अधिकारों पर अध्याय में निहित इस खंड को इस प्रकार निरोध की अनुमति देती है

तीन महीने की अवधि के बाद और एक सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने की आवश्यकता को शामिल नहीं करता है, यदि उद्घाटन

उपखंड के शब्दों का पालन किया जाता है। उपखंड *(बी)* अनुमेय है। यह संसद पर अनिवार्य नहीं है।

किसी भी अधिकतम अवधि को निर्धारित करने के लिए। यह तर्क दिया गया था कि यह संसद को किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देने का अधिकार देता है। अगर वह निर्माण है सही है, यह उपखंड *(7)* के शब्दों से ही निकलता है और न्यायालय इस मामले में मदद नहीं कर सकता है। उप.

खंड *(ग)* संसद को खंड *(4)* के उपखंड *(क)* के तहत जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुमति देता है। मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि अनुच्छेद *22 (4) (ए)* नियम है और अनुच्छेद *22 (7)* अपवाद है। मैंने उन्हें दो विकल्पों के रूप में पढ़ा, जिनके लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया है

कानून बनाना-निवारक निरोध पर।

अनुच्छेद *22* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें

अनुच्छेद *246* और अनुसूची *VII,* सूची *I,* प्रविष्टि *9* और सूची *III,* प्रविष्टि *3* के साथ, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसद को निवारक निरोध का कानून बनाने का अधिकार है *(ए)* रक्षा से जुड़े कारणों के लिए, *(बी)* विदेशी मामलों से जुड़े कारणों के लिए, *(सी)* भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए; और *(*सूची *III* के तहत*), (डी)* किसी राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए, *(ई)* सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कारणों के लिए, या *(एफ)* समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए। याचिकाकर्ता के वकील ने अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी है। जेम्स बनाम में एक संविधान के निर्माण के संबंध में लॉर्ड राइट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल *(1),*

(1) (1936) ए. सी. *578 614* पर।

उन्होंने कहा कि "संविधान का अर्थ किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए"। अटॉर्नी में श्री जस्टिस हिगिंस-न्यू साउथ वेल्स के जनरल बनाम। शराब उद्योग कर्मचारी संघ *(1)* ने कहाः हालाँकि हमें संविधान के शब्दों की व्याख्या एक ही प्रिंट पर करनी है

व्याख्या के सिद्धांत जैसा कि हम किसी भी सामान्य कानून पर लागू करते हैं, व्याख्या के ये सिद्धांत ही हमें अधिनियम की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखने के लिए मजबूर करते हैं

व्याख्या कर रहे हैं-याद रखने के लिए कि यह एक है

कि हम संविधान, एक तंत्र जिसके तहत कानून बनाए जाने हैं, न कि केवल एक अधिनियम जो घोषणा करता है कि कानून क्या होना है। *1938 (2)* के केंद्रीय प्रांत और बरार अधिनियम *XIV* में, सर मौरिस ग्वायर सी. जे. ने इन टिप्पणियों को अपनाने के बाद कहाः विशेष रूप से यह न्यायशास्त्र के अच्छे संतुलन के साथ एक संघीय संविधान के बारे में सच है। मेरा मानना है कि एक व्यापक और उदार भावना को उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जिनका कर्तव्य इसकी व्याख्या करना है, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि वे खिंचाव करने या टालने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी कानूनी या संवैधानिक सिद्धांत के हित में या यहां तक कि चूक की आपूर्ति करने या कथित सुधार के उद्देश्य से अधिनियम की भाषा

त्रुटियाँ "। इस कथन के लिए काफी अधिकार है कि न्यायालय घोषणा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं

भावना संविधान में व्याप्त होनी चाहिए लेकिन नहीं शब्दों में व्यक्त किया। जहाँ मौलिक कानून है

सीमित नहीं, या तो शर्तों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा

विधानमंडल को प्रदत्त सामान्य शक्तियों को हम इस धारणा के तहत एक सीमा घोषित नहीं कर सकते हैं कि

संविधान जिसका उल्लेख संविधान में भी नहीं है।यंत्र। यह किसी भी सामान्य सिद्धांत पर मुश्किल है।

लिखित संविधान के व्यक्त शब्द देते हैं कि प्राधिकरण। यह भी कहा जाता है, अगर शब्द सकारात्मक हों

और अस्पष्टता के बिना, एक के लिए कोई अधिकार नहीं है

उस आधार पर किसी क़ानून को खाली करने या निरस्त करने के लिए न्यायालय

अकेले। लेकिन यह केवल व्यक्त संवैधानिक प्रावधान में है।

शासन विधायी शक्ति को सीमित करता है और नियंत्रित करता है एक स्थायी और द्वारा बहुमत की अस्थायी इच्छा

(2) (1939) 37 में एफ. सी. आर. *18*

(1) (1908) 6 कॉम। एल. आर. *469 611-12* पर।

जानबूझकर ज्ञान द्वारा तय किया गया कानून

सर्वोपरि

वह राष्ट्र जिसे कोई पा सकता है

सुरक्षित और ठोस जमीन

न्यायालयों के अधिकार के लिए

न्याय को अमान्य घोषित करने के लिए

कोई भी विधायी अधिनियम। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मौलिक मान्यता की धारणा को हाथों में लेना होगा।

न्यायपालिका की शक्तियाँ बहुत अधिक और बहुत अनिश्चित हैं

या तो अपनी सुरक्षा के लिए या निजी सुरक्षा के लिए

अधिकार।

सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि धारा *3* द्वारा

संसद ने अपनी विधायी शक्ति को सौंप दिया था

एक व्यक्ति को उसके होने पर हिरासत में लेने में कार्यकारी अधिकारी

अपनी आवश्यकता से संतुष्ट। यह आग्रह किया गया था कि सती

गुट विधायी निकाय का होना चाहिए। यह सामग्री

ऐसे मामलों में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन

कई मामलों में माना और अस्वीकार किया गया है

हमारे संघीय न्यायालय और अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा। यह है।उन सभी मामलों को संदर्भित करना अनावश्यक है। एक वाचन

लिवर्जिज बनाम में विभिन्न भाषण। एंडरसन *(1)*

यह स्पष्ट रूप से इस तर्क को नकारता है। धारा *3*

विवादित अधिनियम विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हैकानून बनाएँ। यह केवल अधिकारी को विवेक प्रदान करता है कि

विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। धारा *3* है

यह निर्धारित करना कि क्या कानून की आवश्यकताएँ हैं अनुपालन किया गया। यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।

आचरण का मानक निर्धारित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि

एक को प्राप्त करने या उससे बचने की प्रवृत्ति रखने वाले आचरण को निर्धारित करना विशेष वस्तु। निवारक निरोध कार्रवाई के लिए

इसे अच्छे संदेह पर लिया जाना चाहिए। यह एक व्यक्तिपरक है

विभिन्न क्रियाओं के संचयी प्रभाव के आधार पर परीक्षण, शायद काफी समय तक फैला हुआ। जैसा कि देखा गया है।

द किंग वी. में लॉर्ड फिनले द्वारा होलीडे *(1)*, एक अदालत

जाँच के लिए सबसे कम उपयुक्त न्यायाधिकरण है

सवाल यह है कि क्या परिस्थितियाँ

संदेह मौजूद है

विवाद

एक व्यक्ति पर संयम की गारंटी देना।

निवारक निरोध के संबंध में आग्रह किया जाता है और नहीं

दंडात्मक हिरासत। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकेएक अपराध के लिए यह स्पष्ट है कि उसे एक में होना चाहिए

यह जानने की स्थिति कि वह क्या कर सकता है या नहीं, और

करने या न करने में चूक का परिणाम राज्य में होगा

(1) (1942) ए. सी. *206*

(2) (1917) 269 पर *A.C.260*।

दंडात्मक अधिनियम के अनुसार उसे दोषी मानते हुए

मन में। लेकिन जब निवारक हिरासत की बात आती है,

बहुत ही उद्देश्य व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं है

केवल एक विशेष तरीके से कार्य करने से लेकिन, के रूप मेंउप-शीर्ष ऊपर संक्षेप में दिखाया गया है, एक प्राप्त करने से

उन सभी कार्यों को पूरी तरह से सारणीबद्ध करें जो एक विशेष वस्तु। इसलिए यह माना गया है कि

कि एक दंडात्मक निरोध अधिनियम जो पर्याप्त रूप से

वे उद्देश्य निर्धारित करता है जिन पर विधायिका विचार करती है

एक पर्याप्त मानक तक काम नहीं करना है

कानून को अस्पष्ट होने से रोकें। मेरी राय में,

इसलिए, एस के खिलाफ याचिकाकर्ता का तर्क

कि धारा *3* के लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है निरोध और इसलिए कानून अधिकार से बाहर है।

इसका उत्तर अनुच्छेद *22 (7) (*ख*)* में मिलता है। एक अवलोकन

इसके अलावा विवादित अधिनियम के प्रावधानों से पता चलता है

कि धारा *12* में निरोध के लिए प्रावधान किया गया है

तीन महीने से अधिक लेकिन अधिक नहीं

उसके खंड *(*क*)* और *(*ख*)* के संबंध में एक वर्ष

अनुभाग। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि

धारा *3 (1) (*क*)* में उल्लिखित शेष खंडलंबे समय तक हिरासत में रखने पर विचार नहीं किया जाता है।

तीन महीने से अधिक, और ऐसे मामलों में एक संदर्भ धारा *9* के तहत सलाहकार बोर्ड पर विचार किया जाता है।

अधिनियम की धारा *7* जिसे अगली बार चुनौती दी गई है,

उसी पर दौड़ता है। अनुच्छेद *22 (5)* और *(6)* की पंक्तियाँमेरी राय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।

यह तर्क दिया गया था कि यह केवल बनाने का अधिकार देता है

मौखिक रूप से या साथ सुने बिना एक अभ्यावेदन साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना और

इसलिए प्रक्रिया का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं था, क्योंकि

प्राकृतिक न्याय के नियमों द्वारा आवश्यक। द पार्लिया

अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया है

निवारक निरोध आदेश के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति

निरोध के लिए आधार प्राप्त करें और यह भी दिया है

उसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अधिनियम में है

इस प्रकार अनुच्छेद *22 (5)* की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया।

वह खंड, जो यह निर्धारित करता है कि किस प्रक्रिया को करना है

मौलिक अधिकार के मामले के रूप में पालन किया जाए, चुप है,

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में जिसे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सुनने का अधिकार है

एस सी आर।

123

मौखिक रूप से या किसी वकील द्वारा। संविधान सभा ने उनके समक्ष उसी के खंड *(1)* के प्रावधान

लेख। सभा ने आवश्यकता से निपटा लिया

आधार प्राप्त करने और एक अवसर देने का विचार

एक प्रतिनिधित्व करने के लिए जानबूझकर परहेज किया हैमौखिक रूप से सुने जाने का अधिकार प्रदान करने से। अगर ऐसा है तो मैं

अनुच्छेद *22 (5)*। एक "प्रक्रिया का व्यवस्थित पाठ्यक्रम" हैप्रक्रिया तक सीमित नहीं है जिसे मंजूरी दी गई है

व्यवस्थित उपयोग। प्रक्रिया के नए रूप उतने ही हैं,

यहां तक कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित, कारण

पुराने रूपों के रूप में कानून की प्रक्रिया, बशर्ते वे एक

व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर। यह था।

तर्क दिया कि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

अनुच्छेद *22 (5)* के साथ सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए।

एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण; अन्यथा एक का निर्माण प्रतिनिधित्व का कोई सार नहीं है क्योंकि यह एक नहीं है

प्रभावी उपचार। मैं खंड *(5)* को पढ़ने में असमर्थ हूँ।

अनुच्छेद *22* सुनवाई का मौलिक अधिकार देता है

एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा। संविधान का विवरण

बेरेटली पश्चाताप का अधिकार देना बंद कर देता है।

यह स्वाभाविक है क्योंकि अनुच्छेद *22 (7)* के तहत,

संविधान एक कानून बनाने की अनुमति देता है

संसद जिसमें एक सलाहकार बोर्ड का संदर्भ छोड़ दिया जा सकता है। बनाने के अधिकार पर विचार करने के लिए

होने का अधिकार सहित आवश्यक रूप से प्रतिनिधित्व

इस प्रकार एक स्वतंत्र न्यायिक, प्रशासनिक या सलाहकार न्यायाधिकरण द्वारा सुनी गई सुनवाई सीधे तौर पर उनके साथ टकराव में होगी।

अनुच्छेद *22 (7)* के स्पष्ट शब्द।

यहां तक कि यू. एस. ए. के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ए

न्यायिक विचारण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। जू टॉय *(1),* राज्यों में प्रवेश से एक चीनी के एक्सक्लू सायन के बारे में एक सवाल उठा जोसंयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने का दावा किया। पृष्ठ *263* पर बहुमत के फैसले में निम्नलिखित शामिल हैं -

परिच्छेदः - "यदि तर्क के उद्देश्य से, हम मानते हैं कि पाँचवाँ संशोधन उन पर लागू होता है, और

कि किसी नागरिक को प्रवेश से वंचित करना उसे स्वतंत्रता से वंचित करना है, फिर भी हमारी राय है कि उसके संबंध में कानून की उचित प्रक्रिया के लिए न्यायिक मुकदमे की आवश्यकता नहीं हैः यह उन मामलों का परिणाम है जो हमने उद्धृत किया है, और इसका लगभग आवश्यक परिणाम

(1) (198) 263 पर यू. एस. *253*।

124

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

बहिष्करण कानून पारित करने की कांग्रेस की शक्ति। यह कि निर्णय एक कार्यकारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है, और यह कि उसका निर्णय कानून की उचित प्रक्रिया है, कई मामलों में पुष्टि की गई और समझाया गया। यह अनावश्यक है।

को

डेन एक्सडेन मुर्रे बनाम में पूरे न्यायालय के लिए बोलते हुए श्री जस्टिस क्यूरिट्स की अक्सर उद्धृत टिप्पणियों को दोहराएँ। होबोकेन लैंड एंड इम्प्रूवमेंट कंपनी *(1)*यह दर्शाता है कि प्रत्येक मामले में न्यायिक परीक्षण की आवश्यकता प्रबल नहीं होती है।

एक बार फिर, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

यह कि मौखिक रूप से सुने जाने का अधिकार प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार भी प्रक्रिया का एक आवश्यक अधिकार है। बचाव करने का अधिकार स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस तर्क का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मौखिक साक्षात्कार अनिवार्य है। में।

स्थानीय सरकार बोर्ड *v.* आर्लिज *(1),* जवाब सदन के तहत गठित बोर्ड पर लागू किया गया डेंट

उच्च न्यायालय की राय के लिए एक विशेष मामला स्थापित करने के लिए अधिनियम, यह तर्क देते हुए कि आदेश अमान्य था क्योंकि *(1)* निरीक्षक की रिपोर्ट को एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में माना गया था और प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया गया था, और *(2)* क्योंकि बोर्ड ने प्रतिवादी को उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर दिया था जिसके द्वारा अपील का अंत में निर्णय लिया गया था। बोर्ड ने आवेदन को खारिज कर दिया। अपील पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष दोनों बिंदुओं का आग्रह किया गया था। विस्काउंट हाल्डेन

एल. सी. ने अपने भाषण में मौखिक सुनवाई की आवश्यकता के बारे में तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण की प्रक्रिया समान होनी चाहिए। इस देश में विधि परंपरा के न्यायालय के मामले में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए मुख्य रूप से प्रक्रिया का गठन होना चाहिए। लेकिन वह प्रक्रिया विस्तार से क्या होनी चाहिए, यह न्यायाधिकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। निरीक्षक की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के बारे में तर्क को अस्वीकार करते हुए, लॉर्ड चांसलर ने कहाः इस रिपोर्ट का खुलासा करना उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोर्ड ऐसा करने के लिए बाध्य था

यह खुलासा करने के लिए बाध्य था

इससे पहले कार्यालय में कागज पर बनाए गए सभी मिनट

(2) (1915) ए. सी. *120*

(1) 18 एच. ओ. डब्ल्यू. *272 280* पर।

125

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

एक निर्णय आया था। मुझे जो लगता है कि अपील न्यायालय में बहुमत के फैसले की भ्रांति यह है कि यह प्रक्रिया के परीक्षण को स्थापित करके शुरुआत में सवाल उठाता है।

अन्य मानक के बजाय न्याय के न्यायालय का

जो शिक्षा मंडल में ऐसे मामलों के लिए निर्धारित किया गया था

कैशन वी। चावल *(1)*। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड बाध्य था

प्रत्यर्थी को मौखिक रूप से सुनने के लिए बशर्ते वह उसे दे।

वास्तव में उनके पास अवसर थे। इसके बावजूद

तथ्य यह है कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है मैं हूँ

मान्यता प्राप्त लोगों के खिलाफ कानून बनाना, कानून बनानाप्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सभी में स्वीकार किया गया

सभ्य देश। एक ही दृष्टिकोण में स्वीकार किया जाता है

संघीय संचार आयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका

वी. डब्ल्यूजेआर द गुडविल स्टेशन *(1)*।

संदिग्ध तथ्यों के विरुद्ध साक्ष्य देने का अधिकार

निवारक डी के मामले में भी मौजूद होना आवश्यक नहीं है

उल्लेख। अनुच्छेद *22 (6)* गैर-प्रकटीकरण की अनुमति देता है

तथ्य। यह संविधान के खंडों में से एक है

मौलिक अधिकारों से निपटना। अगर गैर-भी तथ्यों को बंद करने की अनुमति है, मैं यह देखने में विफल हूं कि यह कैसे हो सकता है

साक्ष्य द्वारा तथ्यों को चुनौती देने का अधिकार मौजूद है और गैर इस तरह के प्रक्रियात्मक अधिकार को शामिल करने से यह अधिनियम बन सकता है

अमान्य है।

धारा *10 (3)* को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि

यह व्यक्तिगत रूप से या किसी के द्वारा उपस्थित होने के अधिकार को बाहर करता है।

सलाहकार मंडल के समक्ष वकील और यह तर्क दिया गया था

कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद *22 (1)* जो एक डी देता है

जंजीरबंद व्यक्ति को उसके द्वारा परामर्श करने या उसकी रक्षा करने का अधिकार

द्वारा बहिष्कृत

अपना कानूनी व्यवसायी विशेष रूप से है विधान के मामले में अनुच्छेद *22 (3)*

से निपटना

निवारक निरोध। इसके अलावा,

संसद है

अनुच्छेद *22 (7) (*सी*)* के तहत स्पष्ट रूप से शक्ति दी गई हैएक सलाहकार बोर्ड द्वारा जांच में प्रक्रिया को नीचे करें।

यह भी अनुच्छेद *22* का ही एक हिस्सा है। यदि ऐसा है तो कैसे*?*

दर्शकों को अधिकार देने की चूक पर विचार किया जाना चाहिए संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ*?* यह बताया गया था

कि धारा *10 (3)* एक के प्रकटीकरण को भी रोकती है

(1) (1911) ए. सी. *17.*

(2) 337 276 126 पर यू. एस. *265*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

रिपोर्ट का हिस्सा और सलाहकार मंडल की राय। यह तर्क दिया गया था कि यदि ऐसा है तो हिरासत में लिया गया व्यक्ति अदालत के समक्ष अपना मामला कैसे रख सकता है और भ्रम को चुनौती कैसे दे सकता है*?* यह तर्क इसी तरह स्थानीय सरकार बोर्ड बनाम में आगे बढ़ाया गया था। आर्लिज *(1)* और अस्वीकार कर दिया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। मेरी राय में, इसका उत्तर भारत के संविधान के अनुच्छेद *22 (7) (*सी*)* में पाए जाने वाले प्रावधान में है।

यह तर्क दिया गया था कि विवादित अधिनियम की धारा *11*

यह अमान्य था क्योंकि इसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार को उचित लगने वाली अवधि के लिए प्रतिबंध जारी रखने की अनुमति दी थी। इसका मतलब अनिश्चित काल हो सकता है। मेरी राय में इस तर्क में कोई सार नहीं है क्योंकि अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम का पूरा जीवन एक वर्ष के लिए है और इसलिए यह तर्क कि निरोध एक निश्चित अवधि के लिए हो सकता है, निराधार है। पुनः, अनुच्छेद *22 (7) (*बी*)* के आधार पर, संसद ऐसे निरोध की अधिकतम अवधि निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है। इसने धारा *12* के अलावा इसे इस तरह से तय नहीं किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा *11* अनुच्छेद का उल्लंघन है। *22 (7) .*

विवादित अधिनियम की धारा *12* को चुनौती दी गई है

इस आधार पर कि यह अनुच्छेद *22 (7)* के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद *22 (7)* में तीन महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है, जब संसद किसी व्यक्ति को "किन परिस्थितियों में, और किन वर्गों या मामलों में" हिरासत में लिया जा सकता है, यह निर्धारित करती है। यह तर्क दिया गया था कि इन दोनों शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। मेरी राय में, यह तर्क अनुचित है, क्योंकि अनुच्छेद *22 (7)* में उपयोग किए गए शब्द स्वयं इस तरह की व्याख्या के खिलाफ हैं। पहले भाग में दो बार "जो" शब्द का उपयोग

उपखंड, जिसे प्रत्येक के बाद अल्पविराम के साथ पढ़ा जाता है, से पता चलता है कि विधायिका चाहती थी कि इन्हें इस रूप में पढ़ा जाए

संयुग्म और संयुग्म नहीं। इस तरह का तर्क संभव हो सकता था *(*हालांकि आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं किया गया*)* यदि संविधान का अनुच्छेद "परिस्थितियों और मामलों के वर्ग या वर्गों में था।" मुझे कोई संदेह नहीं है कि खंड द्वारा, जैसा कि कहा गया है, विधायिका

(1) (1915) ए. सी. *120*

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

127

इरादा था कि निवारक निरोध की शक्ति

इससे परे

तीन महीने का प्रयोग या तो किया जा सकता है यदि परिधि का रुख जिसमें, या मामलों के वर्ग या वर्ग जिसमें, किसी व्यक्ति पर संदेह है या उसे ऐसा करने के लिए पकड़ा जाता है

अनुभाग में उल्लिखित आपत्तिजनक बातें। इसलिए यह तर्क विफल हो जाता है।

अगला

तर्क दिया कि धारा *12* द्वारा

यह था।

व्यक्ति हो सकता है

संसद ने

बशर्ते कि ए

एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना, उसे *(*ए*)* भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, उसकी नजरबंदी की तारीख से तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया*;*

या *(*ख*)* किसी राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा *3 (1) (*ए*) (iii)* में प्रदान की गई आकस्मिकता। , रखरखाव

धारा *12* में समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को हटा दिया गया है। धारा *12* में इन दो उप-धाराओं के शब्दों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित अधिनियम में अंतिम भाग को छोड़कर

अनुसूची *VII* सूची *I,* प्रविष्टि *9* और सूची *III,* प्रविष्टि *3* के शब्दों की केवल प्रतिलिपि बनाई गई है। यह परिस्थितियों या मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है जैसा कि किया जाना आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद *22 (7)* के तहत।

सर्कम

रुख का अर्थ आम तौर पर संबंधित व्यक्ति के कार्यों के लिए बाहरी घटनाएं या स्थिति होता है, जबकिमामलों के वर्ग का अर्थ है एक समान उद्देश्य या विचार वाले व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर निर्धारित करने योग्य समूह। निर्धारित करना वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि वर्गीकरण लोगों की गतिविधियों को समूहीकृत करके या प्राप्त करने या टालने के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करके किया जा सकता है। द.

अनुसूची *VII* सूची *I,* प्रविष्टि *9* और सूची के शब्द *III,* प्रविष्टि *3* पर कभी भी विचार नहीं किया जा सकता है

परिस्थितियों या मामलों के वर्गों के रूप में। मेरी राय में,

यह धारणा उचित नहीं है, विशेष रूप से जब हम

निवारक *[1950]* के मामलों को ध्यान में रखना होगा

128

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निरोध और न कि दोषसिद्धि और दंडात्मक निरोध

यह। उन प्रविष्टियों में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति पुरुषों की आवश्यकता का पालन करने में सक्षम है।

परिस्थितियों या मामलों के वर्गों का निर्धारण। मामलों का वर्गीकरण, किसी वस्तु को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों के विवरण के बराबर हो सकता है। यह विवादित नहीं है कि विधान में प्रत्येक प्रविष्टि सातवीं अनुसूची की सूचियों का एक विशिष्ट अर्थ है जो कानून में अच्छी तरह से समझा और सुनिश्चित किया जा सकता है।

यदि ऐसा है तो

ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि जब आक्षेप अधिनियम की धारा *12 (1) (ए)* और *(बी)* में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है तो इसका ऐसा विशिष्ट अर्थ नहीं माना जाना चाहिए।

और इस प्रकार परिस्थितियों या मामलों के वर्गों को निर्धारित करने की आवश्यकता का पालन करना। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

धारा *13 (2)* पर इस आधार पर हमला किया गया कि

भले ही किसी निरोध आदेश को निरस्त कर दिया गया हो, उसी आधार पर उसी व्यक्ति के खिलाफ धारा *3* के तहत एक और निरोध आदेश दिया जा सकता है। यह खंड

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को रिहा होने से रोकने के लिए डाला गया है यदि किसी हिरासत आदेश को किसी तकनीकी आधार पर अमान्य ठहराया गया था। मौलिक अधिकारों के अध्याय में और अनुच्छेद *21* या *22* में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद में इस तरह के खंड को शामिल करने से रोक सके।

निवारक निरोध की अनुमति देने वाला कानून। अनुच्छेद *20 (2)* को इस मुद्दे पर एक विरोधाभास के रूप में पढ़ा जा सकता है।

के चार बुनियादी सिद्धांतों से निपटना

याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निवारक निरोध के संबंध में मानव नलिका के वस्तुनिष्ठ मानक का कोई प्रश्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि हिरासत से पहले किसी भी नोटिस का दावा इस तरह की हिरासत की प्रकृति से नहीं किया जा सकता है। यह तर्क कि निरोध के बाद आधारों की सूचना दी जानी चाहिए, अनुच्छेद *22 (5)* में मान्यता दी गई है और विवादित अधिनियम में शामिल किया गया है। जहाँ तक निष्पक्षता की बात है

न्यायाधिकरण, अनुच्छेद *22-22 (4)* और *(7)* को एक साथ पढ़ने पर संसद को पर्याप्त विवेकाधिकार मिलता है। जब विशिष्ट परिस्थितियों और मामलों के वर्गों में

हिरासत से अधिक

तीन

महीनों,

निवारक सलाहकार मंडल की अनुपस्थिति की स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की अनुमति है।

129

एस सी आर।

अनुच्छेद *22 (7)* द्वारा। अनुच्छेद *22 (4)* के तहत यह निहित प्रतीत होता है कि ऐसे न्यायाधिकरण के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

यदि नजरबंदी तीन महीने से कम समय के लिए है। जहाँ तक सुनवाई के अवसर का संबंध है, मौखिक प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई पूर्ण प्राकृतिक अधिकार मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे न्यायाधिकरण की प्रकृति पर निर्भर माना गया है। प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की पुष्टि संविधान द्वारा अनुच्छेद *22 (5)* में की गई है और इसे विवादित अधिनियम में जगह मिली है। प्रक्रिया के एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद *22 (7) (*सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *22 (4)* द्वारा दी गई है।

और अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)* और *(*बी*)* द्वारा भी

इस प्रकार

प्रदान किया गया

में

अधिनियम।

मुझे ऐसा लगता है

इसलिए

कि

याचिकाकर्ता का

यहां तक कि विवाद

ये बिंदु विफल हो जाते हैं।

धारा *14* पर जमीन पर जोरदार हमला किया गया था

कि इसने प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया और

यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद *22 (5)* द्वारा दिए गए अधिकार का भी उल्लंघन किया है।

संविधान। यह इस प्रकार चलता हैः

" 14. (1) उद्देश्यों के अलावा कोई भी न्यायालय नहीं करेगा

उप के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन काधारा *(2),* किसी भी कथन को किए जाने की अनुमति देता है, या कोई

व्यक्ति या उसके विरुद्ध उसके द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन काऐसा आदेश; और, कुछ भी निहित होने के बावजूद

किसी अन्य कानून में, कोई भी न्यायालय माँग करने का हकदार नहीं होगा।

किसी लोक अधिकारी को उसके सामने पेश करना, या खुलासा करना

ऐसे किसी संचार या प्रतिनिधि का सार

किया गया, या एक सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही

या किसी सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का वह भाग जो गोपनीय है।

(2) यह दंडनीय अपराध होगा।

जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, किसी भी व्यक्ति को खुलासा करने के लिए यापूर्व प्राधिकरण के बिना प्रकाशित करें

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के रूप में

होने का अनुमान

मामला हो सकता है, कोई भी सामग्री या मामलाइस तरह के किसी भी संचार या प्रतिनिधित्व की सामग्री

जैसा कि उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट किया गया हैः

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

130

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी नहीं होगा

एक व्यक्ति द्वारा अपने कानूनी सलाहकार को किए गए प्रकटीकरण पर आवेदन करें जो निरोध आदेश का विषय है।

उस धारा द्वारा न्यायालय को रोका जाता है (सिवाय इसके कि -

(ख) धारा *7* के अधीन, जिस पर आदेश दिया गया था, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए गए आधारों के सार के बारे में, या ऐसे आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन के बारे में, किसी बयान द्वारा या प्रमुख साक्ष्य द्वारा सूचित किए जाने से। यह न्यायालय को भी रोकता है

किसी भी लोक अधिकारी से उन आधारों के सार का खुलासा करने या सलाहकार मंडल की कार्यवाही या रिपोर्ट पेश करने के लिए कहना जिसे गोपनीय घोषित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि इस प्रावधान को कायम रखने की अनुमति दी जाती है तो न्यायालय के समक्ष यह निर्धारित करने के लिए कोई सामग्री नहीं हो सकती है कि निरोध उचित है या नहीं। मेरा मतलब यह नहीं है कि आधार पर्याप्त हैं या नहीं। यह न्यायालय को यह पता लगाने से भी रोकता है कि क्या निरोध के कथित आधार का धारा *12 (1) (ए)* या *(*बी*)* में उल्लिखित परिस्थितियों या मामलों के वर्ग या वर्गों से कोई लेना-देना है। मछिंदर शिवाजी महार बनाम। राजा *(1)*

संघीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय सरकार द्वारा दिए गए आधारों की जांच कर सकता है कि क्या वे उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जो कानून के विचार में है। अनुच्छेद *22 (5)* के प्रावधान न्यायालय के उस अधिकार को बाहर नहीं करते हैं। विवादित अधिनियम की धारा *14* एक कठोर प्रावधान प्रतीत होती है जिसे निवारक रूप से बनाए रखने के लिए काफी समर्थन की आवश्यकता होती है।

निरोध अधिनियम। विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया कि इस धारा का पूरा उद्देश्य सार्वजनिक रूप से हवा के प्रवाह को रोकना था और यह कि यह केवल साक्ष्य का नियम था जिसे संसद निर्धारित कर सकती थी।

में सहमत नहीं हूँ।

यह

के शब्द

अनुच्छेद *22* खंड *(5)* और *(6)* पर तर्क स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। सरकार को अनुच्छेद *22 (6)* के तहत उन तथ्यों का खुलासा नहीं करने का अधिकार है जिन्हें वह जनहित में प्रकट करना अवांछनीय समझती है। यह सरकार को खंड *(5)* के तहत आने वाले आधारों का खुलासा करने से बचने की अनुमति नहीं देता है।

(1) [1949-50] एफ. सी. आर. *827*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

131

एस सी आर।

इसलिए, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि

आधारों का खुलासा न्यायालय से रोका जा सकता है

जनहित में, साक्ष्य के नियम के रूप में। इसके अलावा,

अनुच्छेद *22* के शब्दों से

स्थिति स्पष्ट की गई है

(5) . इसमें कहा गया है कि

हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी

हिरासत में लिया गया व्यक्ति आधार

ऐसे लोगों से संवाद करें

जिस पर आदेश दिया गया है। इसलिए यह

आवश्यक है कि आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए

निवारक निरोध का आदेश। अगर वे नहीं हैं

संबंधित अनुच्छेद *22 (5)* की आवश्यकताएँ नहीं हैं

अनुपालन किया जाएगा और निरोध आदेश होगा

अमान्य है। इसलिए, यह प्रति बंदी के लिए खुला हैबेटा एक अदालत के सामने तर्क देता है कि

आधार

जिस पर आदेश दिया गया है, उसका कोई संबंध नहीं है।

आदेश के साथ, या इसका कोई संबंध नहीं है

परिस्थितियों या वर्ग या वर्गों, मामलों के साथ

जिसके तहत एक निवारक निरोध आदेश हो सकता है

धारा *12* के तहत समर्थित। इस तर्क पर जोर देने के लिए

पीड़ित पक्ष को सूचित करने का अधिकार होना चाहिए

कथित निरोध के लिए दिए गए आधारों को न्यायालय में प्रस्तुत करें और उसके द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए,

ए

व्यक्ति को एक कागज दिया जाता है जिस पर लिखा होता है

एक कविता की तीन पंक्तियाँ या तीन वर्णमालाएँ

तीन अलग-अलग तरीके नजरबंदी की वैधता के लिए

आदेश यह आवश्यक है कि आधार वे होने चाहिए जिस पर आदेश दिया गया है। अगर *1* को हिरासत में लिया जाता है

इस पर अदालत करें

व्यक्ति के सामने रखने की स्थिति में नहीं है

कागज, अदालत को विचार करने से रोका जाएगा

क्या अनुच्छेद *22 (5)* की अपेक्षाओं का पालन किया जाता है

के साथ और वह एक ऐसा अधिकार है जिसकी गारंटी हर किसी को दी जाती है

व्यक्ति। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रावधान

धारा *14* का अनुच्छेद *22 (5)* के तहत दिए गए अधिकार को कम करता है।

और इसलिए अल्ट्रा वायर्स हैं।

इसके बाद यह विचार किया जाना बाकी है कि यह कितनी दूर है।

इस धारा की वैधता शेष आक्षेप को प्रभावित करती है।

एक्ट करें। इस धारा को घटाकर विवादित अधिनियम बना रह सकता है।अप्रभावित। इस धारा को नहीं छोड़ा जाएगा।

प्रकृति या संरचना या वस्तु को बदलें

कानून। अतः यह निर्णय कि धारा *14* है

अल्ट्रा वायर्स बाकी की वैधता को प्रभावित नहीं करता है

एक्ट करें। इसलिए मेरी राय में *1950* का अधिनियम *IV*, सिवाय इसके कि

धारा *14*, अधिकार से परे नहीं है। यह किसी का उल्लंघन नहीं करता है।

4-3 एस. सी. इंडिया/*58 132*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

संविधान के भाग *III* के प्रावधान और

उस की वैधता के विरुद्ध आवेदक का उल्लेख

धारा *14* के विस्तार को छोड़कर अधिनियम विफल हो जाता है। द.

इसलिए याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

फजल अली जे.-इसमें तय किया जाने वाला प्रश्न

मामला यह है कि क्या निवारक निरोध अधिनियम, *1950*

(1950 का अधिनियम *IV)*, पूरी तरह से या आंशिक रूप से अमान्य है और

क्या याचिकाकर्ता जिसे हिरासत में लिया गया है

वह अधिनियम बंदी की प्रकृति में एक रिट का हकदार है

तथ्यों की एक लंबी श्रृंखला का उल्लेख किए बिना जो हैं इस न्यायालय में याचिकाकर्ता के आवेदन में वर्णित

और जिनका उन्हें हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की कथित दुर्भावनाओं पर अधिक सीधा असर पड़ता है

अधिनियम की वैधता पर।

जिस अधिनियम का विरोध किया गया है, उसे अधिनियमित किया गया था -

26 फरवरी, *1950* को संसद, और उस तारीख से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, *1* अप्रैल, *1951* को इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान धाराओं में दिए गए हैं।

3 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 और *14.* धारा *3 (1)* प्रदान करती है

कि "केंद्र सरकार या राज्य सरकार

हो सकता है

(क*)* यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि

उसे किसी भी कार्य में अभिनय करने से रोकने के लिए प्रतिकूल तरीका

((i) भारत की रक्षा, भारत के संबंध

विदेशी शक्तियों या भारत की सुरक्षा के साथ, या

((ii) राज्य या रखरखाव की सुरक्षा।

सार्वजनिक व्यवस्था, या

*((*ग*)* आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव

समुदाय के लिए आवश्यक, या

(ख*)* यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है जो

विदेशी अधिनियम, *1946 (1946* का *XXXI)* के अर्थ के भीतर एक विदेशी, जो भारत में अपनी निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने की दृष्टि से या

एक दृश्य

उसके लिए व्यवस्था करना

से निष्कासन

भारत, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

133

एस सी आर।

ऐसा करना आवश्यक है, निर्देश देने का आदेश दें

कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

इस खंड की उप-धाराएँ *(2)* और *(3)* एक

जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या

प्रेसीडेंसी टाउन टाउन में पुलिस आयुक्त को

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करें और आदेश दें

उप-धारा *(1)* में विचार किया गया है, लेकिन योग्यता के साथ

यह कि इसके तहत किए गए किसी भी आदेश की सूचना दी जानी चाहिए

राज्य सरकार को जिसका

विचाराधीन अधिकारी आधारों के साथ अधीनस्थ है

जिसे आदेश दिया गया है और इस तरह के अन्य पक्ष

जैसा कि उनकी राय में कहा गया है, आवश्यकता पर असर डालता है

आदेश के लिए। अधिनियम की धारा *7* में प्रावधान है कि

नजरबंदी का आदेश देने वाला प्राधिकारी जल्द से जल्द हिरासत में लिए गए व्यक्ति से संवाद किया जा सकता है

जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और

उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करें, ऐसे मामले में जहां

केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि -

उस सरकार, और एक मामले में जहां यह किया गया हैराज्य सरकार या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बनाया गया

इसके लिए, राज्य सरकार को। धारा *8* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, एक या अधिक का गठन करेगी।

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सलाहकार मंडल। और

बोर्ड में किन व्यक्तियों की योग्यताएँ होनी चाहिए, उनका उल्लेख करें। धारा *9* में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से कोई निरोध आदेश दिया गया है या यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया गया है जो भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने या उसके निष्कासन की व्यवस्था करने की दृष्टि से विदेशी अधिनियम के अर्थ के भीतर एक विदेशी है।

भारत से, जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, हिरासत की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

कि यह खंड प्रदान नहीं करता है

यह देखा जाएगा

कि व्यक्तियों के मामले जो हैं

हिरासत में लिया गया

के तहत

धारा *3 (1) (ए) (आई)* और *(आई)* को भी सलाहकार मंडल के समक्ष रखा जाएगा। धारा *10 134* को निर्धारित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और धारा *11* में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां -

द.

सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण है, हिरासत आदेश की पुष्टि की जा सकती है और व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है

संबंधित इस तरह के लिए जारी रखा जा सकता है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त समझती है। . धारा *12*, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जैसा कि हम अनिवार्य रूप से देखेंगे, इस प्रकार हैः

" 12 (1) निम्नलिखित में से किसी में भी हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति

मामलों के किसी भी वर्ग या निम्नलिखित मामलों में से किसी के तहत सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना अधिक समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

तीन महीने से अधिक,

लेकिन अधिक नहीं

एक साल से

उसकी नजरबंदी की तारीख,

अर्थात्, जहाँ ऐसा व्यक्ति

उसे किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है

((a) भारत की रक्षा, भारत के संबंध

विदेशी शक्तियों या भारत की सुरक्षा के साथ; या

(ख*)* किसी राज्य की सुरक्षा या रखरखाव

सार्वजनिक व्यवस्था।

(2) ए के तहत हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला

निरोध आदेश, जिस पर उप-धारा *(1)* के प्रावधान लागू होते हैं, उसकी निरोध की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी, जहां केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिया गया था।

राज्य

सरकार, ऐसी सरकार द्वारा और जहां आदेश धारा *3* की उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जिसके लिए ऐसा अधिकारी अधीनस्थ है, उस व्यक्ति के परामर्श से जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस ओर से नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है या है।

धारा *14*, जो इसके लिए एक सामग्री खंड भी है

इस मामले का उद्देश्य निम्नलिखित हैः --

" (1) कोई भी न्यायालय, निम्नलिखित उद्देश्यों के अलावा नहीं करेगाः

उप के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन

धारा *(2)*, किसी भी कथन को किए जाने की अनुमति देता है,

या कोई *1*

135

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर। धारा *7* के तहत किए गए किसी भी संचार के सार के बारे में उसके समक्ष दिया जाने वाला साक्ष्य, जिसके आधार पर उसके खिलाफ निरोध आदेश का आदेश दिया गया है।

उनके द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व

किसी भी व्यक्ति या किसी के

और, और, कुछ भी होने के बावजूद

इस तरह के आदेश के खिलाफ;

किसी अन्य में निहित

कानून,

कोई न्यायालय हकदार नहीं होगा।

इससे पहले उत्पादन करना, या

किसी भी लोक अधिकारी की आवश्यकता

ऐसा कोई संचार

पदार्थ का खुलासा करने के लिए,या किया गया प्रतिनिधित्व, या

एक की कार्यवाही

सलाहकार मंडल या उसका वह भाग

एक की रिपोर्ट

सलाहकार बोर्ड जो गोपनीय है।

(2) यह दंडनीय अपराध होगा -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व प्राधिकरण के बिना, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसे संचार या प्रतिनिधि प्रेषण की सामग्री होने का तात्पर्य रखने वाली किसी भी सामग्री या विषय का खुलासा या प्रकाशन करने के लिए कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, जैसा कि उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट किया गया हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी नहीं होगा

एक व्यक्ति द्वारा अपने कानूनी सलाहकार को किए गए प्रकटीकरण पर आवेदन करें जो निरोध आदेश का विषय है।

हमारे सामने जिस बिंदु को दबाया गया है वह है

कि अधिनियम अमान्य है, क्योंकि यह भाग द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है।

III का

भारत का संविधान, और समर्थन में

इनमें से

सामान्य प्रस्ताव, निर्भरता लेख पर रखी गई है

13 (2)

जो इस प्रकार चलता हैः

" राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी।

भाग *III* के तहत गारंटीकृत अधिकार

संविधान को सात व्यापक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैंः

(1) समानता का अधिकार*;*

(2) स्वतंत्रता का अधिकार*; (3)* शोषण के खिलाफ अधिकार*;*

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार*;(5)* सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार*;*

(6) संपत्ति का अधिकार*;* और

ई. सी.

संवैधानिक उपचार का अधिकार।

136

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अधिकांश लेख जिनके बारे में कहा जाता है कि

उपेक्षा की गई

"राइट टू" शीर्षक के तहत होता है

स्वतंत्रता *",* ये अनुच्छेद अनुच्छेद *19 (1) (*डी*), 21* हैं।

और *22.*

एक अन्य लेख जिसके बारे में भी कहा जाता है कि

जिसका उल्लंघन किया गया है वह अनुच्छेद *32* है*,* जिसके तहत वर्तमान

एक रिट के लिए आवेदन

बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य है

बनाए गए हैं।

अनुच्छेद *19 (1)* सात उपखंडों में विभाजित है।

और इस प्रकार चलता हैः

" सभी नागरिकों को होगा अधिकार

*((*क*)* बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता*;*

(ख*)* शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना*;*

*(*ग*)* संघों या संघों का गठन करना*;*

*(*घ*)* पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए

भारत*;*

*(*ई*)* किसी भी स्थान पर रहने और बसने के लिए

इसका हिस्सा

भारत का क्षेत्र*;*

*(*च*)* संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करना*;* और

*(*छ*)* किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या आगे बढ़ना।

कोई भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय।

इस अनुच्छेद के खंड *(2), (3), (4), (5)* और *(6)*

बशर्ते कि खंड *(1)* में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

उस खंड के तहत अधिकारों के संबंध में किसी भी मौजूदा कानून का संचालन, कुछ शर्तों के तहत जो उसमें उल्लेख किया गया है।

खंड *(5)*, जिसके साथ हम हैं

प्रत्यक्ष रूप से संबंधित और जो इन प्रावधानों की प्रकृति को दिखाने के लिए एक नमूने के रूप में काम करेगा, निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" उपखंड *(*घ*), (*ङ*)* और *(*च*)* में कुछ भी नहीं

कहा।

खंड किसी भी मौजूदा के संचालन को प्रभावित करेगा

जहाँ तक कानून राज्य पर उचित प्रतिबंध लगाता है या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग या तो आम जनता के हित में या किसी अनुसूची के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है।

:

शासित जनजाति "।

पेटी की ओर से आगे की गई दलीलें

इस लेख के संदर्भ में मुख्य लेखक हैंः *-(1)* कि वह अधिनियम जिसके तहत उसे हिरासत में लिया गया है, उसे जो भारत गणराज्य का नागरिक है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से वंचित करता है, जिसकी गारंटी अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत दी गई है, और *(2)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

137

एस सी आर।

वह खंड के तहत। *(5)* अनुच्छेद *19* के अनुसार, इस न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार है कि अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या अन्यथा। सौदा करने से पहले

इस तर्क के साथ, अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है, और

वास्तविक प्रकृति के बारे में स्पष्ट समझ होना

उसके अधीन प्रदत्त अधिकार का। विवाद

याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि स्वतंत्रता

आवाजाही की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिएव्यक्तिगत के संक्षिप्त या वंचित करने के लिए राशि

स्वतंत्रता, जैसा भी मामला हो, प्रकृति के अनुसार

संयम से। बहुत सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद,

आई.

इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह तर्क है

कानून में अच्छी तरह से स्थापित। ब्लैकस्टोन ने अपने "कॉमेन" में

इंग्लैंड के कानूनों पर लेख *"(*चौथा संस्करण, खंड*)*

1 , पृष्ठ *134)* में कहा गया है कि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल हैं

गति की शक्ति, बदलती स्थिति या

अपने व्यक्ति को किसी भी स्थान पर ले जाना

बिना कारावास या

झुकाव निर्देशित हो सकता है,

जब तक कानून के उचित पाठ्यक्रम द्वारा नहीं "। लेखक

इस कथन की वास्तविकता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया है, और

इसे एच. जे. स्टीफन द्वारा शारीरिक रूप से शामिल किया गया है।

कूली द्वारा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में पुनः प्रस्तुत किया गया"संवैधानिक सीमाओं" पर *(8* वां संस्करण, खंड*)*

1 , पृष्ठ *710),* जिसे दोनों ने व्यापक रूप से उद्धृत किया था।

अपने तर्कों के दौरान पक्षकार। यह दृश्य

कि आंदोलन की स्वतंत्रता व्यक्तिगत का सार है

स्वतंत्रता की पुष्टि किसी के संदर्भ में भी की जाएगी। इंग्लैंड के आपराधिक कानून पर पुस्तक

झूठे कारावास का अपराध या इस पर कोई टिप्पणी के अपराधों से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता

गलत संयम या कारावास। रसेल अपनी पुस्तक में

"अपराध और दुराचार" पर *(8* वां संस्करण, खंड*)*

1 , पृष्ठ *861),* झूठे अभिकरण के अपराध से संबंधित

सोनमेंट इस प्रकार कहता हैः

" झूठा कारावास गैरकानूनी और पूर्ण है।

दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिबंध, चाहे

उसे विवश करना या उसे जाने के लिए मजबूर करना

विशेष स्थान पर या उसे जेल में बंद करके या *[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

138

पुलिस थाना या निजी स्थान, या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर हिरासत में लेना. अपराध में आवश्यक तत्व व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखना या उसकी स्वतंत्रता पर गैरकानूनी प्रतिबंध है। दूसरे की गतिविधियों की स्वतंत्रता में इस तरह का हस्तक्षेप गैरकानूनी है, जब तक कि यह उचित न हो।

अपराध के साथ

फिर से, डॉ. गौर व्यवहार में

के दंड कानून पर

अपनी पुस्तक में गलत संयम

पृष्ठ *1144)* टिप्पणी करता है

ब्रिटिश इंडिया "*(5* वाँ संस्करण,

इस प्रकार हैः

"इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि हर आदमी का व्यक्ति

यह पवित्र है और यह स्वतंत्र है, कानून अपने दंडात्मक संबंधों के साथ उन लोगों का दौरा करता है जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करते हैं, हालांकि उसका अपने व्यक्ति पर कोई इरादा नहीं हो सकता है। लेकिन यह तथ्य कि वह इतने कम समय के लिए इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, राजा की शांति के खिलाफ एक अपराध है, क्योंकि किसी को भी अपने स्वतंत्र आंदोलनों में दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।

अनुचित कारावास के अपराध से निपटना,

वही विद्वान लेखक अपनी पुस्तक के पृष्ठ *1148* पर इस प्रकार टिप्पणी करता हैः ---

"गलत तरीके से कैद 'गलत तरीके से कैद' की एक प्रजाति है।

'संयम' जैसा कि अंतिम खंड में परिभाषित किया गया है। गलत तरीके से रोकने में, किसी की चलने-फिरने की स्वतंत्रता का केवल आंशिक निलंबन होता है, जबकि गलत तरीके से कैद में 'कुछ सीमित सीमाओं से परे' स्वतंत्रता का पूर्ण निलंबन होता है।

ये दोनों लेखक व्यक्तिगत संयम की बात करते हैं।

स्वतंत्रता और किसी के चलने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या स्वतंत्रता या गति का निलंबन अंतर-परिवर्तनीय शब्दों के रूप में। बर्ड वी में। जोन्स *(1),* जे. कॉलरिज ने कहा कि "यह स्वतंत्रता की परिभाषा का एक हिस्सा है कि वह जहाँ चाहे वहाँ जाने में सक्षम हो"। सर अल्फ्रेड डेनिंग सहित कई लेखकों ने अपनी पुस्तक "" में इसी तरह की राय व्यक्त की है। कानून के तहत स्वतंत्रता "। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आंदोलन की स्वतंत्रता अंतिम विश्लेषण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार है, और जिस तरह एक आदमी की संपत्ति है

आम तौर पर इस देश में रुपये, अन्न और पाई के संदर्भ में मापा जाता है, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता की सीमा पर निर्भर करती है। लेकिन राज्य की ओर से यह माना जाता है कि आवाजाही की स्वतंत्रता

(1) 7 क्यू. बी. *742*।

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में जिस संदर्भ का उल्लेख किया गया है, वह आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं है जिसका उल्लेख काले पत्थर और अन्य लेखकों ने किया है, बल्कि स्वतंत्रता की एक अलग प्रजाति है जो शब्दों द्वारा योग्य है।

" भारत के पूरे क्षेत्र में "। "भारत के पूरे क्षेत्र में" अभिव्यक्ति का उपयोग लेख में उपयोग किए गए बाकी शब्दों के अर्थ को कैसे योग्य बना सकता है, यह मेरी समझ से परे है। मेरी राय में, "भारत के पूरे क्षेत्र में" शब्दों का उपयोग आवाजाही की स्वतंत्रता के दायरे को उस हद तक बढ़ाने के लिए किया गया था, जिस हद तक हमारे संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी जा सकती थी। संविधान भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आवाजाही की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता था, और इसलिए उन शब्दों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि एक नागरिक का अधिकार था

देश के एक कोने से दूसरे कोने में स्वतंत्र रूप से जानाऔर बिना किसी बाधा के। . " सब जगह एक

और एक सीमित अभिव्यक्ति नहीं, और मैं

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि "भारत के पूरे क्षेत्र में" अभिव्यक्ति, जिसका उपयोग आंदोलन की स्वतंत्रता को व्यापक संभव गुंजाइश देने के लिए किया जाता था, को स्वतंत्रता के दायरे और प्रकृति को सीमित करने वाली अभिव्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश की जाती है। मेरी राय में, "भारत के पूरे क्षेत्र में" शब्द, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें उनका उपयोग किया गया है।

बल और अर्थ के रूप में

यहाँ,

एक ही बात है

ब्लैकस्टोन द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "किसी भी स्थान पर किसी का अपना झुकाव निर्देशित हो सकता है", या अभिव्यक्ति

" कॉलरिज जे. इन द्वारा उपयोग की गई स्वतंत्रता कि वह जहाँ चाहे वहाँ जाने में सक्षम हो।

बर्ड वी। जोन्स *(1)*।

मैं हूँ।

निश्चित है कि इनमें से कोई भी अधिकारी

विचार किया।

कि आंदोलन की स्वतंत्रता जो एक ब्रिटिश नागरिक को प्रदान की जाती है, ब्रिटिश क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं से परे की गारंटी है।

सवाल यह है कि क्या निवारक हिरासत

*19 (1) ((*घ*)* नागपुर, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है। वह दृश्य जो अंततः इन उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है कि

निवारक निरोध अधिकार का उल्लंघन नहीं हैअनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* द्वारा प्रत्याभूत, लेकिन, कलकत्ता में

(1) 7 क्यू. बी. *742*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

140

उच्च न्यायालय, जहाँ मामले को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है

चर्चा की गई, कम से कम पाँच न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि यह करता है,

और अंतिम विश्लेषण में न्यायाधीशों की संख्या

जिन्होंने विपरीत दृष्टिकोण रखा है, वे प्रतीत होते हैं

एक ही। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व दृश्य

इतने विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दबाए जाने का विरोध है

देखने के लिए मैं लेने के लिए इच्छुक हूँ, मैं इसे आवश्यक मानता हूँ मुख्य आपत्तियों के साथ संक्षेप में निपटें जो

संकीर्ण अर्थ के समर्थन में उठाया गया

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* के शब्दों के साथ संलग्न।

आई.

पहले से ही उनमें से एक के साथ निपटा है जो है

अभिव्यक्ति के आधार पर "पूरे क्षेत्र में

भारत "। और अब मैं इससे निपटने के लिए आगे बढ़ूंगा

अन्य श्रेणी।

I. यह स्मरण किया जाएगा कि अनुच्छेद *19* का खंड *(5),*

जिनका मैं पहले ही पूर्ण रूप से उल्लेख कर चुका हूँ

अन्य चीजें जो खंड *(1) (*घ*)* में कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगी

किसी भी कानून का संचालन, वर्तमान या भविष्य, लागू करना

के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

आम जनता या के हितों की रक्षा के लिए कोई भी अनुसूचित जनजाति। यह तर्क दिया गया है कि उपयोग

इसमें "किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित" शब्द हैं। खंड से पता चलता है कि अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा गारंटीकृत अधिकार

(घ*)* आवाजाही का एक सीमित अधिकार है, जैसे कि

विभिन्न इलाकों में जाएँ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ दूसरा और अभिव्यक्ति "स्वतंत्रता" से अलग है।

आंदोलन का "जो ब्लैकस्टोन द्वारा कहा गया है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दूसरा नाम होना। . यह इंगित किया गया है कि यहाँ चिंतन चिंतन में प्रतिबंध हैं

मुख्य रूप से अवांछनीय बाहरी लोगों को रोकने वाले प्रतिबंध अनुसूचित क्षेत्रों का दौरा करने और अनुसूचित क्षेत्रों का दोहन करने से

जनजातियाँ, और अगर "आंदोलन की स्वतंत्रता" शब्दों का उपयोग बड़े अर्थों में किया गया था, तो इतना छोटा

बात।

अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* में कोई स्थान नहीं मिला होगा।

मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं

इस तर्क का समर्थन करना और यह मानना कि अनुसूचित जनजातियों का केवल एक संदर्भ अनुच्छेद *19* के खंड *(1) (*डी*)* में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ को प्रभावित करता है। अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* में प्रयुक्त शब्द बहुत व्यापक हैं और उनका अर्थ है कि

अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में जा सकता है

एक व्यक्ति का इलाका और किसी भी दूरी पर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

141

एस सी आर।

इतने व्यापक दायरे और विस्तार में विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं और इसमें किसी व्यक्ति को नजरबंद करना या बाहर निकालना, किसी विशेष इलाके में या जेल की दीवारों में उसे कैद करना, उसे किसी विशेष क्षेत्र में जाने या रहने से रोकना आदि शामिल हो सकते हैं। संविधान के निर्माता आंदोलन की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले सभी प्रतिबंधात्मक कानूनों को बचाना चाहते थे।

आम जनता के हित *(*जो अभिव्यक्ति का अर्थ है

रूचि *")* और मुझे लगता है

समान बात यह है कि निवारक निरोध के संबंध में कानून पूरी तरह से "सार्वजनिक हितों में लगाए गए प्रतिबंध" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया है।

"सार्वजनिक

लेकिन उन्हें यह भी याद था कि

एक महत्वपूर्ण समुदाय के हित में प्रतिबंधात्मक कानून बनाए गए थे और भविष्य में इसी तरह के कानून बनाने पड़ सकते हैं और इसलिए उन्होंने "किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए" शब्द जोड़े। संविधान की पाँचवीं अनुसूची और भारत सरकार अधिनियम, *1935* के संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ छोटा नागपुर, संथाल परगना और अन्य इलाकों के लिए बनाए गए कुछ कानूनों के संदर्भ से पता चलेगा कि इस देश में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने को बहुत महत्व दिया गया है और यह, मेरी राय में, खंड *(5)* में अनुसूचित जनजातियों के विशेष उल्लेख के लिए पर्याप्त है। यह, पहली नज़र में, एक अपेक्षाकृत छोटी बात प्रतीत हो सकती है, लेकिन प्रतिबंध के पूरे क्षेत्र को कवर करने की उनकी चिंता में

चाहे वे लोक हित में हों या किसी विशेष समुदाय के हित में और छोटी से छोटी खामियों को छोड़ने के लिए नहीं, संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से वर्तमान रूप में खंड का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी भी समुदाय के हित में कोई प्रतिबंधात्मक कानून नहीं बनाए गए हैं और मुझे लगता है कि खंड *(5)* अनुसूचित जनजातियों की स्वतंत्रता पर सबसे छोटे और साथ ही सबसे पूर्ण प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है।

मुझे इस बात का भी संतोष है कि केवल उल्लेख

आंदोलन।

खंड *(5)* में अनुसूचित जनजातियों के मुख्य प्रावधान के शब्दों के स्पष्ट अर्थ को नहीं बदला जा सकता है जो हम अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में पाते हैं और इसे किसी प्रकार की विशिष्ट और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की संक्षिप्त स्वतंत्रता तक सीमित नहीं कर सकते हैं।

आंदोलन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से असंबद्ध हैऔर जो किसी भी संविधान के लिए अज्ञात है

हम परिचित हैं।

शायद इसका उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा।

1943 के अध्यादेश *XIV* के संबंध में, जो एक हैवे अध्यादेश जिनके द्वारा भारत की रक्षा अधिनियम,

1939 , आंशिक रूप से संशोधित किया गया। यह अध्यादेश प्रदान करता है

के लिए

"हिरासत में आशंका और हिरासत

कोई भी व्यक्ति जिसे प्राधिकरण द्वारा सशक्त किया गया हो

मामला चाहे जैसा भी हो, उसे पकड़ने या हिरासत में लेने के नियम

संदिग्ध, ऐसे प्राधिकरण को दिखाई देने वाले आधारों पर

उचित होना, शत्रुतापूर्ण मूल का होना, या कार्य करना, कार्य करना, कार्य करने वाला होना, या कार्य करने की संभावना होना

सार्वजनिक सुरक्षा या हित के लिए प्रतिकूल तरीके से, ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी शक्तियों या भारतीय राज्यों के साथ महामहिम के संबंध, आदिवासी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थितियों को बनाए रखना या युद्ध का कुशल अभियोजन, या जिनके संबंध में ऐसे प्राधिकरण को संतुष्ट किया जाता है कि उसे किसी भी पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से उसकी आशंका और हिरासत आवश्यक है, इस तरह के प्रतिबंध

व्यक्ति

किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने या रहने से, और ऐसे व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में रहने और रहने के लिए मजबूर करना, या कुछ भी करने या करने से बचना।

के संबंध में ध्यान देने योग्य बिंदु

अध्यादेश इस प्रकार हैः

(1) कि यह विशेष रूप से प्रदान करने वाला एक अध्यादेश है

आशंका और हिरासत के लिए;

(2) इस तथ्य के बावजूद कि एक

इसमें सार्वजनिक सुरक्षा या हितों और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्यों के लिए सामान्य संदर्भ आदिवासी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थितियों के रखरखाव के लिए भी एक विशिष्ट संदर्भ है।

(3) कि जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ हैं

आत्मीय विषय जो पाँचवें से दिखाई देंगे

संविधान में संलग्न अनुसूची; और

(4) शांति बनाए रखने के लिए

स्थितियों में

जनजातीय क्षेत्र उतने ही लोक हित में हो सकते हैं जितने उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के हित में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

143

एस सी आर।

यह अध्यादेश कम से कम इतना तो दिखाता है कि कुछ

कई बार निवारक निरोध का कानून अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित क्षेत्रों के हितों में भी बनाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप खंड *(5)* में अनुसूचित जनजातियों का केवल उल्लेख किया जा सकता है।

आवश्यक रूप से संबंधित कानूनों को बाहर नहीं करता है

अनुच्छेद *19 (5)* के दायरे से निवारक निरोध। यही टिप्पणी "प्रतिबंध और निरोध अध्यादेश, *1944"* नामक अध्यादेश पर भी लागू होती है। *1944* का तीसरा*)*

जो

सशक्त किया गया

केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के मुख्य अधिकार के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थितियों के रखरखाव आदि के हित में कुछ व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और आदेश देने के लिए।

II. यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि निवारक हिरासत

यह स्वतंत्रता के पूर्ण अभाव के बराबर है

इस प्रकार, यह अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन नहीं है, जिसके संबंध में खंड *(5)* में "प्रतिबंध" शब्द का उपयोग किया गया है न कि "अभाव" का। यह तर्क भी मुझे पसंद नहीं आता। वास्तव में दो प्रश्न हैं जिनका इस मामले में निर्णय लिया जाना है। , *(* क*)* क्या निवारक निरोध अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* द्वारा गारंटीकृत अधिकार को छीन लेता है*? ;* और *(*ख*)* यदि हां, तो इसके क्या परिणाम होंगे*?*

यह मुझे स्पष्ट लगता है कि निवारक निरोध

यह अनुच्छेद *(19) (*घ*)* द्वारा सही ग्वारन को पूरी तरह से वंचित करने के बराबर है। शब्द का अर्थ

प्रतिबंध के संदर्भ में विचार किया जाना है

दूसरा सवाल और मुझे लगता है कि यह अत्यधिक होगा

यह तर्क देने के लिए तकनीकी कि किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है

के अभ्यास पर प्रतिबंध शामिल करने के लिए कहा जा

सही है। मेरी राय में, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए

जिस शब्द "प्रतिबंध" का उपयोग किया गया है, उस शब्द और "वंचित" शब्द के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

वैशन "। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पर संयम

स्थानांतरित करने का अधिकार विभिन्न रूपों और प्रतिबंधों को ग्रहण कर सकता है।

यह सबसे उपयुक्त अभिव्यक्ति होगी

खंड *(5)* में उपयोग किया गया है ताकि उन सभी रूपों को शामिल किया जा सके

आवागमन की स्वतंत्रता। लेकिन मुझे विज्ञापन देना होगा।इस विषय पर बाद में और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि *144*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मैंने जो निर्माण का सुझाव दिया है वह अच्छे द्वारा समर्थित है

प्राधिकरण।

III. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न्यायाधीश जिन्होंने

हमारे सामने जो सवाल है, उससे निपटने के लिए

इस तर्क से बहुत प्रभावित थे कि यदि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना वंचित करने के बराबर है।

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* के अधीन प्रदत्त अधिकार का*;*

भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए विजय

कारावास की सजा का विषय होगा

की तर्कसंगतता के आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए

संहिता के प्रावधान जिनके तहत दोषसिद्धि

दर्ज किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय के मेरिडिथ सी. जे.

स्थिति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है

जो इन शब्दों में उत्पन्न होगा -

"यह देखा जाएगा कि किया गया दावा बहुत है

वास्तव में झाड़ू। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक कानून जिसके तहत किसी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, जिसमें दंड संहिता के सभी प्रावधान शामिल हैं, अदालतों द्वारा तर्कसंगतता के आधार पर जांच के लिए खुला है। यह किसी भी मामले में न्यायालय को सर्वोच्च मध्यस्थ बनाता है।

ऐसा विधान, और वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार कर सकते हैं

उनके विचारों के अनुसार कि क्या यह अपील करता है

उनके कारण। लेकिन तर्कसंगतता या अन्यथा के विचार व्यापक रूप से भिन्न होने के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, निषेध से संबंधित कानूनों को लें या व्यभिचार जैसे मामले को लें।

जिसे भारतीय कानून कारावास से दंडनीय अपराध मानता है लेकिन अंग्रेजी कानून ऐसा नहीं करता है।

यह.

यह विश्वास करना कठिन है कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी न्यायालयों के हाथों में इतनी विशाल शक्ति रखने का इरादा किया था। राज्य

बिहार के*]*।

इस तर्क का स्पष्ट और सख्ती से कानूनी जवाब

विचार यह है कि जिस विचार ने विद्वान मुख्य न्यायाधीश को इतना प्रभावित किया है, वह संविधान के अनुच्छेद *19 (5)* में उपयोग किए गए सामान्य शब्दों के स्पष्ट अर्थ को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि एक संख्या में बताया गया है

" निर्माण में

मामलों में,

अधिनियमित शब्द, हम नहीं हैं

नीति के बारे में

सम्मिलित या परिणामों के साथ

हानिकारक या अन्यथा

जो देने के बाद आ सकता है

उच्च न्यायालय की भाषा रिपोर्टों पर प्रभाव

145

एस सी आर।

उपयोग किया गया *"[[*राजा राजा सम्राट बनाम। बेनोआरी लाल शर्मा और अन्य। *(1)]*।

सहमत हैं।

मामले के इस पहलू के अलावा, मैं

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने अपनी टिप्पणी में कहा कि "कोई भी विनाशकारी या अप्रिय परिणाम नहीं आएगा, भले ही दंड संहिता के प्रावधान न्यायसंगत हों।" मुझे यकीन है कि कोई भी न्यायालय उस संहिता में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो लगभग एक सदी से देश का कानून रहा है और जिसके प्रावधान किसी भी कानून के मूल सिद्धांतों के साथ टकराव में नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यायालय को संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने से केवल एक अस्पष्ट और निराधार डर के कारण नहीं रोका जाना चाहिए कि कुछ विनाशकारी हो सकता है।

मैं अब तक इस धारणा पर आगे बढ़ा हूँ कि

मेरेडिथ सी. जे. द्वारा उठाई गई आपत्ति का आधार है कानून में सही है, लेकिन, मेरी राय में, ऐसा नहीं है। अपराध को उन कृत्यों या चूक में शामिल होने के लिए परिभाषित किया गया है

सार्वजनिक हित में दंड। *(* रसेल की "अपराध और दुराचार" देखें।*)* भारतीय दंड की धारा *2* संहिता, *1860* में प्रावधान है कि "प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा और अन्यथा इसके लिए नहीं।

उसके प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक, जिसके लिए वह ब्रिटिश भारत के भीतर दोषी होगा। द.

भारतीय दंड संहिता मुख्य रूप से या आवश्यक रूप से नहीं है।

आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, और यह कहना सही नहीं है कि यह प्रतिबंध लगाने वाला कानून है

स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर। इसका मुख्य उद्देश्य

अपराध को दंडित करना है न कि आवाजाही को प्रतिबंधित करना। सजा में कारावास या सजा शामिल हो सकती है। यदि इसमें आर्थिक दंड शामिल है, तो यह

स्पष्ट रूप से आंदोलन पर कोई प्रतिबंध शामिल नहीं है; लेकिन यदि

इसमें कारावास शामिल है, आवाजाही पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध किसी कानून के तहत नहीं लगाया गया है। आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना लेकिन अपराध को परिभाषित करने वाले कानून के तहत और इसे दंडनीय बनाना। दंड का संबंध सीधे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन से है न कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन से।

(1) (1945) एफ. सी. आर. *161* पी. *177 .*

[1950]

146

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं अपराधी के कब्जे में।

मुझमें

आंदोलनराय,

इसलिए, भारतीय दंड

कोड नहीं है

"लागू करने वाला कानून

शब्दों के दायरे में आएं

स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर प्रतिबंध "।

अभिव्यक्ति

तर्कों के दौरान,

"दंडात्मक निरोध का अक्सर उपयोग किया जाता था और इसे कुछ उद्देश्यों के लिए पूर्वनिर्धारित निरोध के समान आधार पर रखने की प्रवृत्ति थी।

तर्क।

अनिवार्य रूप से अलग

दंडात्मक निरोध हालांकि निवारक निरोध से है। एक व्यक्ति को अपराध करने के लिए मुकदमे के बाद और एक सक्षम न्यायालय में उसका अपराध स्थापित होने के बाद ही दंडात्मक रूप से दंडित किया जाता है। इस तरह से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उसकी सजा हो सकती है।

राज्य उच्च न्यायालय में मामला चलाया जाता है और कभी-कभी इसे इस न्यायालय में भी लाया जाता है; और वह अपने मुकदमे से जुड़े पक्षकारों के दौरान अपने लिए उपलब्ध सभी याचिकाओं को ले सकता है, जिसमें मुकदमे के न्यायालय की अधिकारिता का अभाव और उस कानून की अयोग्यता शामिल है जिसके तहत उस पर मुकदमा चलाया गया है। इस प्रकार आपराधिक मुकदमे में अंतिम निर्णय उसके रास्ते में एक गंभीर बाधा का गठन करेगा यदि वह अपनी जीत के बाद भी यह दावा करने का विकल्प चुनता है कि अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है। लेकिन एक व्यक्ति जिसे एहतियातन हिरासत में लिया गया है

इस तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है चाहे उसके रास्ते में कोई अन्य बाधा हो।

IV. यह इंगित किया गया था

इसे बाहर निकालें।

अनुच्छेद *19* कोन है

नागरिकों पर जुर्माना,

विसंगत स्थिति का पालन किया जाएगा

कि निवारक निरोध के मामलों में, एक नागरिक को एक गैर-नागरिक की तुलना में बेहतर स्थिति में रखा जाएगा, क्योंकि यदि किसी नागरिक को हिरासत में लिया जाता है तो उसकी नजरबंदी अनुच्छेद *19 (5)* के

तहत किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होगी, लेकिन यदि एक गैर-नागरिक को हिरासत में लिया गया है तो उसका मामला इस तरह की समीक्षा के लिए खुला नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से, यह कहा जाता है कि निवारक निरोध से संबंधित पूरे अधिनियम को अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि यह अनुचित है, हालांकियह नागरिकों के साथ-साथ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी संबंधित है। मुझे स्पष्ट रूप से कहना होगा कि मैं इस तर्क से बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं। यह एक पेटेंट तथ्य है कि संविधान ने लेख में उल्लिखित सभी अधिकारों को सीमित कर दिया है।

यह भी उतना ही स्पष्ट है कि प्रतिबंध

19 (1) नागरिकों के लिए। उन अधिकारों पर एक सीमित सीमा तक कम से कम न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है। वही सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

147

अधिकांश अन्य उपखंडों का ध्यान रखें। एक नागरिकशांतिपूर्वक और बिना एकत्रित होने का अधिकार है

हथियार, संघ या संघ बनाने के लिए और इसी तरह। अगर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून है

इनमें से कोई भी अधिकार, वह कानून नहीं होगा

परजहाँ तक नागरिकों का संबंध है, अच्छा कानून है, लेकिन

जहाँ तक गैर-नागरिक हैं, यह अच्छा कानून हो सकता है।

सुनिश्चित किया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है।

उपखंड *(घ)* के अधीन प्रदत्त अधिकार के संबंध में

इसे विसंगत कहा जाना चाहिए। जहाँ तक सही है

मुक्त आवाजाही का संबंध है, एक गैर-नागरिक रहा है

अनुच्छेद *21* और *22* में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। यदि ए.

नागरिक को कुछ अन्य अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं।

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत कोई विसंगति नहीं है।

कि एक निश्चित कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता है एक नागरिक के खिलाफ लेकिन एक गैर-नागरिक के खिलाफ नहीं।

लेकिन इस तरह के परिणाम से हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

स्पष्ट रूप से चिंतन के भीतर पाया गया है संविधान के निर्माताओं में से।

V. यह तर्क दिया गया था कि द्वारा घोषित अधिकार

पहले से ही परिधि में अपनी स्वतंत्रता से वंचित था अनुच्छेद *20,21* और *22* में निर्दिष्ट रुख, फिर यह

यह कहना व्यर्थ होगा कि उन्हें अभी भी अनुच्छेद *19* में निर्दिष्ट अधिकार प्राप्त है। इस तर्क पर अपना पूरा पक्ष रखने के बाद, मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ

इस मामले में यह कैसे उत्पन्न होता है, इसकी सराहना करें। कुछ नहीं है।

अनुच्छेद *19* में यह सुझाव देने के लिए कि यह केवल उन पर लागू होता है ऐसे मामले जो अनुच्छेद *20,21* और *22* के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्वयं को निवारक निरोध तक सीमित रखते हुए, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि एक व्यक्ति जिसे निवारक रूप से हिरासत में लिया गया है, वह अपनी स्वतंत्रता खोने से पहले, एक स्वतंत्र व्यक्ति रहा होगा। वह उन्हें हिरासत में लेने वालों से क्यों नहीं कह सकतेः "एक नागरिक के रूप में मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और आप मेरी सीमाओं से परे मेरे अधिकार को कम या छीन नहीं सकते हैं।

अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* द्वारा प्रस्तुत। यह एकमात्र सवाल है जो मामले में उत्पन्न होता है और इसे किसी भी अमूर्त या आध्यात्मिक विचारों द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह सच है कि यदि आप किसी व्यक्ति को हिरासत में रखते हैं, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है और इसलिए वह *5-3* एस. सी. की स्थिति में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत गारंटीकृत अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन यह केवल मामले का भौतिक पहलू है और एक व्यक्ति जो बीमारी के कारण बिस्तर पर है, वह इसी तरह की अक्षमता से पीड़ित है। कानून में, हालांकि, शारीरिक दबाव किसी व्यक्ति को आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करता है। यदि उसे आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के किसी प्रावधान के तहत हिरासत में लिया गया है, तो सवाल उठेगा कि क्या प्रतिबंध उचित हैं। अगर उसके पास कानून के किसी भी प्रावधान के तहत या किसी ऐसे कानून के तहत हिरासत में लिया गया है जो अमान्य है, उसे रिहा किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से, अध्याय की योजना

मौलिक अधिकारों के साथ विचार नहीं करता है इसका क्या श्रेय दिया जाता है। अर्थात्, प्रत्येक लेख अपने आप में एक कोड है और दूसरों से स्वतंत्र है। मेरी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *19,20,21* और *22* कुछ हद तक एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति का मामला अनुच्छेद *20* और *21* के तहत और अनुच्छेद *22* के तहत भी आएगा, जहां तक उसकी गिरफ्तारी और मुकदमे से पहले हिरासत में हिरासत का संबंध है। निवारक निरोध, जिसके बारे में अनुच्छेद *22* में बताया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है जिसका उल्लेख अनुच्छेद *21* में किया गया है और यह अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में बताए गए आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यह कि संविधान में अनुच्छेदों के ओवरलैप होने के अन्य उदाहरण हैं, अनुच्छेद *19 (1) (*च*)* और अनुच्छेद *31* के संदर्भ से स्पष्ट

किया जा सकता है, जो दोनों संपत्ति के अधिकार से संबंधित हैं और कुछ हद तक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के कुछ विद्वान न्यायाधीश, जिन्हें हमारे सामने इसी प्रश्न से निपटना था, ड्राफ्टिंग कॉम की रिपोर्ट में दिए गए बयान से बहुत प्रभावित हुए थे

संविधान सभा की समिति ने अनुच्छेद *15 (*वर्तमान अनुच्छेद *21* का जवाब देते हुए*)* पर कहा कि *"*स्वतंत्रता*"* शब्द को उसके समक्ष *"*व्यक्तिगत*"* शब्द को अंतःस्थापित करके योग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा इसका बहुत व्यापक रूप से अर्थ लगाया जा सकता है ताकि अनुच्छेद *13 (*वर्तमान अनुच्छेद *19* के अनुरूप*)* में वर्णित स्वतंत्रताओं को शामिल किया जा सके। हालाँकि, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह कथन अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में उपयोग किए गए शब्दों के निर्माण के प्रश्न पर निर्णायक है जो काफी स्पष्ट हैं और जिनका बिना किसी *149* के अर्थ लगाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

बाहरी मदद। क्या प्रारूप समिति की रिपोर्ट और सदन के पटल पर बहस का उपयोग किसी सामान्य और सामान्य उपयोग के शब्दों, जो सामान्य और सामान्य उपयोग के शब्द हैं और जो किसी भी तकनीकी या विशिष्ट अर्थ में उपयोग नहीं किए जाते हैं, के अर्थ में किया जाना चाहिए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है; और क्या उनका उपयोग किसी ऐसे निर्माण की सहायता के लिए किया जा सकता है जो सदन पर दबाव डालने वाला हो।

व्याख्या किए जाने वाले खंड में उपयोग की गई भाषा अभी भी अधिक संदिग्ध मामला है। लेकिन, इन कानूनी के अलावा विचार, मुझे लगता है, हमारे लिए इस कथन का विश्लेषण करने और यह देखने के लिए खुला है कि क्या यह कुछ हद तक प्रशंसनीय कारण जोड़ने से परे है-अनुच्छेद *21* में मामूली मौखिक परिवर्तन के लिए एक सतही रूप से प्रशंसनीय कारण। यह.

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनुच्छेद *21* में *"*स्वतंत्रता*"* से पहले *"*व्यक्तिगत*"* शब्द का जोड़ा जाना अनुच्छेद *19* में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को नहीं बदल सकता है, और न ही यह अनुच्छेद *19* में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को बदल सकता है।

ऐसा मामला जो व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है अपनी जगह से परे स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत

स्वतंत्रता, *"*व्यक्तिगत*"* शब्द के उपयोग के बावजूद,

जैसा कि हम कई पुस्तकों में पाते हैं, कभी-कभी एक में उपयोग किया जाता है

व्यापक भावना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता को गले लगाएं

संगठन आदि। ये अधिकार सबसे अधिक हैं।मूल्यवान चरण या स्वतंत्रता के तत्व और वे नहीं करते हैं

*"*व्यक्तिगत*"* शब्द को जोड़ने से ऐसा होना बंद हो जाता है।

प्रारूपण समिति का एक सामान्य वक्तव्य संदर्भित करता है

बहुवचन में स्वतंत्रता की अंगूठी एक की जगह नहीं ले सकती हैशब्दों के अर्थ की आधिकारिक व्याख्या

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में उपयोग किया गया है, जो विशेष रूप से नहीं किया गया है

संदर्भित किया गया है और इस तरह के एक ओवरराइडिंग कॉन नहीं हो सकता हैहमें एक अर्थ रखने के लिए मजबूर करने के रूप में पक्ष लेना

तर्क और अधिकार के लिए। अनुच्छेद *19* में प्रयुक्त शब्द

(1) (घ*)* जैसा वे खड़े हैं वैसा ही समझा जाना चाहिए, और हमारे पास है

शब्दों पर स्वयं निर्णय लेने के लिए कि क्या

निवारक निरोध का मामला अनुच्छेद *19* के तहत अधिकार

(1) (घ*)* उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन, जैसा कि मैं बताऊंगा

हालाँकि, बाद में, शाब्दिक रूप से हम उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ लगा सकते हैं

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* में और हालांकि प्रतिबंधित हो सकता है

इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि निवारक हिरासत अधिनियम में गारंटीकृत अधिकार का सीधा उल्लंघन है

क्ले *19 (1) (*डी*)*।

150

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मुख्य आपत्तियों से निपटने के बाद, मैं चाहता हूं

एक बार फिर मुख्य विषय पर लौटने के लिए। अभिव्यक्तियाँ

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता "और" व्यक्तिगत स्वतंत्रता "के रूप में है

हम कई पुस्तकों में एक व्यापक अर्थ पाते हैं और एक

संकीर्ण अर्थ। व्यापक अर्थ में, वे शामिल हैं

न केवल गिरफ्तारी और नजरबंदी से प्रतिरक्षा बल्कि

बोलने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, आदि। में

संकीर्ण भावना, उनका मतलब गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा है और

नजरबंदी। मैंने दिखाया है कि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की न्यायिक अवधारणा, जब इन शब्दों का उपयोग गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा के अर्थ में किया जाता है, तो यह है कि इसमें आवाजाही और चलने-फिरने की स्वतंत्रता शामिल है। मैंने यह भी बताया है कि यह अवधारणा इंग्लैंड और इस देश के आपराधिक कानून के मूल में है, जहां तक झूठे कारावास और गलत तरीके से कारावास के अपराधों का संबंध है। इन अपराधों की गंभीरता आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैंने यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या इंग्लैंड में गिरफ्तारी और निरोध से प्रतिरक्षा के अर्थ में उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा आवाजाही की कोई स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे ऐसी किसी भी स्वतंत्रता का कोई निशान नहीं मिलता है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड *(*दूसरा संस्करण, खंड *6*, पृष्ठ *391)* में, उल्लिखित स्वतंत्रताएँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार *(*या निरोध या कारावास से प्रतिरक्षा*)*, संपत्ति का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक सभा का अधिकार, संगठन का अधिकार, आदि हैं। इसी तरह के वर्गीकरण डाइसी की "संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय" और कीथ की "संवैधानिक कानून" और संवैधानिक विषयों पर अन्य पुस्तकों में पाए जाएंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी स्वतंत्रता या आंदोलन के अधिकार का कोई संदर्भ नहीं है।

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निकालें। अमेरिका, आयरलैंड के संविधान में। और कई अन्य

जिन देशों में स्वतंत्रता मूल्यवान है, वहां गिरफ्तारी और कारावास से प्रतिरक्षा के अर्थ में उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग कुछ के रूप में स्वतंत्रता या आवाजाही के अधिकार का कोई संदर्भ नहीं है। स्पष्ट व्याख्या यह है कि कानूनी अवधारणा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा कोई स्वतंत्रता या स्थानांतरण का अधिकार मौजूद नहीं है और इसलिए इस स्वतंत्रता का एक अलग उपचार आवश्यक नहीं था। यह केवल फ्री *151* के संविधान में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर। डैनजिग शहर, जिसका क्षेत्रफल *791* वर्ग किलोमीटर है।

कि हम ये शब्द अनुच्छेद *75* में पाते हैं: - "सभी नागरिकों को देश के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा।शहर "। हालांकि ऐसा नहीं है

आधिकारिक राय

इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उपलब्ध है कि यह स्वतंत्रता कोई भी है

जिसे अन्यथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है, उससे कुछ अलग है। डैनजिग के संविधान में इस विशेष अधिकार के संबंध में निर्माण की समस्या वही है जो हमारे संविधान में है। इस तरह की सामान्य स्थिति होने के कारण, मेरे विचार में इस बात की पुष्टि होती है कि कानूनी अवधारणा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चलने की स्वतंत्रता एक ही बात को दर्शाती है, सही और सच्ची अवधारणा है, और अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में उपयोग किए गए शब्द।

इस सार्वभौमिक प्राप्ति के अनुसार समझा जाना चाहिए टेड कानूनी अवधारणा।

इस निष्कर्ष का समर्थन संदर्भ द्वारा किया जाता है।

इंग्लैंड और भारत में युद्ध कानून, जिस पर निवारक निरोध का कानून, जो युद्ध के बाद से इस देश में लागू है, आधारित है। में

युद्ध, ब्रिटिश संसद ने पारित किया

साम्राज्य समेकन अधिनियम का प्रथम विश्व रक्षा, *1914* में, और इसके तहत विनियमन *14*-बी सहित कई विनियम बनाए गए थे, जो राज्य सचिव को किसी भी व्यक्ति को "ऐसे दायित्वों और प्रतिबंधों के अधीन करने की अनुमति देता था जो उसके शत्रुतापूर्ण मूल या संघों को देखते हुए इसके बाद उल्लिखित हैं।" लॉर्ड एटकिन ने इस विनियमन को फिर से लागू करते हुए कहा कि लिवर्जिज बनाम। सर जॉन एंडरसन *(1)*, "कि विनियमन निर्विवाद रूप से एक राज्य सचिव को एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की अप्रतिबंधित शक्ति देता है।" जाहिरा तौर पर, लॉर्ड एटकिन का मतलब था कि अधिनियम में निर्दिष्ट प्रतिबंध में पूर्व वेंटिव हिरासत शामिल थी। इस विनियमन के तहत, एक आर्थर जैडिग को नजरबंद कर दिया गया था, और उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए राजा की पीठ में आवेदन किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। मामला अंततः रेक्स बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष आया। हैलिडे *(2)*, और मामले से निपटने में कुलीन लॉर्ड्स इस धारणा पर आगे बढ़े कि नजरबंदी और इनकार समर्पण या कारावास के बीच कोई अंतर नहीं था। लॉर्ड शॉ ने मामले के तथ्यों का वर्णन करते हुए कहाः

(1) [19 : 2] ए. सी. *238*

(2) [1917] ए. सी. *260.*

"उसके व्यक्ति को जब्त कर लिया गया है, उसे नजरबंद कर दिया गया है।

अपीलार्थी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उसे नजरबंद कर दिया गया।

फिर उन्होंने आगे कहा कि कोई नहीं था

नजरबंदी और कारावास के बीच अंतर और

ब्लैकस्टोन से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया गया हैः ---

"व्यक्ति का कारावास, किसी भी तरह से, एक है

कारावास। ताकि एक आदमी को उसके खिलाफ रखा जा सके

एक निजी घर में, उसे स्टॉक में डाल देंगे,

उसे सड़क पर गिरफ्तार करना या जबरन हिरासत में रखना, एक

कारावास "।

इस आधार पर आगे बढ़ना *(*जो मुझे लगता है

मामले में दिए गए अन्य सभी भाषणों में सामान्य आधार,

हालाँकि लॉर्ड शॉ ने एक असहमत निर्णय दिया था*),*

लॉर्ड फिनले ने विनियमों के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहाः

"पूर्व लेने के सबसे स्पष्ट साधनों में से एक

खतरों के खिलाफ चेतावनी जैसे कि गिने गए हैं आवाजाही की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाएं

जिन व्यक्तियों पर संदेह करने का कोई कारण हो सकता हैदुश्मन की मदद करने के लिए तैयार किया जाना *"(1)*।

फेरसँ, लॉर्ड एटकिंसन मेरसँ निपटैत काल

इस मामले में उसने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"यदि विधायिका यह अधिनियमित करने का विकल्प चुनती है कि वह हो सकता है

अपनी स्वतंत्रता से वंचित और कैद या नजरबंद

कुछ चीजें जिनके लिए वह यहाँ नहीं हो सकते थे

कारावास में या नजरबंद होने से पहले, उस अधिनियम और उसके तहत किए गए आदेश यदि अंतर-अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं

बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियमों पर या कोई अधिकार छीन लेना

मैग्ना चार्टा द्वारा प्रदान किया गया। *"(1)*

यह परिच्छेद पिछले परिच्छेद के साथ पढ़ा गया

मार्ग

नजरबंदी

और

मेरे द्वारा उद्धृत यह दिखाएगा कि दोनों कारावास को "प्रतिबंधों के रूप में माना जाता था

आंदोलन की स्वतंत्रता "और स्वतंत्रता से वंचित और आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का उपयोग समान अर्थ रखने वाली वैकल्पिक अभिव्यक्तियों के रूप में किया गया था।

यही निष्कर्ष संदर्भ द्वारा भी निकाला जाना है।

आपातकालीन शक्तियां *(रक्षा)* अधिनियम, *1939* के तहत पिछले विश्व युद्ध में बनाए गए विनियमों के लिए। वह विनियम जो सीधे निरोध आदेशों से संबंधित था, *18*-बी था। इस विनियमन और कई अन्य विनियमों को भाग *I* में *"*प्रतिबंध*"* शीर्षक के तहत रखा गया है।

(2) [1917] ए. सी. *272,*

(1) [1917] ए. सी. *269*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

153

व्यक्तियों की गतिविधियों और गतिविधियों पर। क्लासी फिक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस कैस्क में उन्नत दो प्रमुख तर्कों को पूरा करता है, यह सबसे पहले दर्शाता है कि निरोध प्रतिबंध का एक रूप है और दूसरा यह कि यह आवाजाही पर प्रतिबंध है। मैंने देखा है कि *"*आंदोलन*"* का उपयोग बहुवचन में किया जाता है, और शीर्षक गतिविधियों पर प्रतिबंधों को भी संदर्भित करता है, लेकिन, इस शीर्ष के तहत वर्गीकृत विषयों को ध्यान में रखते हुए, कदम-। मेंट निस्संदेह शारीरिक गति को संदर्भित करता है और

इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे कि किसी विशेष स्थान में प्रवेश करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आदि, यानी वही चीजें जिनके बारे में कहा जाता है कि अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* का संदर्भ है। लिवर्जिज के मामले में, *1939* के अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, विस्काउंट मॉम ने इस प्रकार कहाः

" 1939 के अधिनियम की भाषा *(*ऊपर उद्धृत*)*

यह संदेह से परे दर्शाता है कि रक्षा विनियम बनाए जा सकते हैं जो उस विषय को वंचित कर सकते हैं *"*जिसकी नजरबंदी राज्य सचिव को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में समीचीन लगती है*"* जब तक कि विनियम लागू रहते हैं *"(1)*।

इस प्रकार विस्काउंट मॉम ने भी हिरासत पर विचार किया।

स्वतंत्रता से वंचित होने का पर्याय होना

आंदोलन।

वर्गीकरण जो हम रक्षा में पाते हैं

राज्य विनियम भारत के रक्षा नियमों में अपनाए गए एक छोटे से मौखिक संशोधन के साथ थे, और हम पाते हैं कि यहाँ नियम *26* भी है, जो

निवारक निरोध को *"*आंदोलनों और गतिविधियों पर प्रतिबंध*"* शीर्षक के तहत रखा गया है।

लोग। प्रांतीय अधिनियमों और ओरडी की एक श्रृंखला में भी कुछ हद तक इसी तरह के वर्गीकरण को अपनाया गया है।व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित नियम *[*बिहार लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, *1949* की धारा *2,* पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, *1948* की धारा *16* देखें।

पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, *1949* की धारा *4,*

मद्रास लोक व्यवस्था के रखरखाव की धारा *2*

अधिनियम, *1947,* यू की धारा *3:* पी. लोक व्यवस्था अस्थायी अधिनियम, *1947* का रखरखाव और बम बे सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम, *1947* की धारा *2]*। इन अधिनियमों और अध्यादेशों में निवारक निरोध और कुछ

(1) [1942] ए. सी. *219.*

154

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

आवाजाही पर प्रतिबंध के अन्य रूप जैसे इंटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट, आदि को एक साथ वर्गीकृत किया गया है और

कमोबेश एक ही आधार पर निपटा गया, और कुछ

कई बार उन्हें विभिन्न खंडों में निपटाया गया है

एक ही खंड। एक अधिनियम में, वही सलाह

एक बाहरी व्यक्ति का, और वहाँ भी समान हैं उन्हें अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देने वाले प्रावधान

सरकार के लिए।

1 अब तर्क के लिए मान लेंगे कि

आंदोलन की स्वतंत्रता जिसका संदर्भ दिया जाता है

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* का व्यक्तिगत से कोई लेना-देना नहीं है।

स्वतंत्रता और वे शब्द जो लेख में पाए जाते हैं

उनके द्वारा दिए गए सीमित अर्थ को सहन करें विद्वान महान्यायवादी और मेरे कुछ सहयोगी।

मुझे ऐसा लगता है कि इस धारणा पर भी, यह हैइसके अलावा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है

मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निवारक निरोध प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक आवाजाही की इस सीमित स्वतंत्रता को भी छीन लेता है, और यदि ऐसा है, तो मुझे नहीं लगता कि यह कैसे तर्क दिया जा सकता है कि अधिकार

यदि वैकल्पिक व्याख्या स्वीकार की जाती है तो अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत उल्लंघन नहीं किया जाता है। हमें केवल खुद से पूछना हैः क्या हिरासत में लिया गया व्यक्ति अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता का एक अंश भी

अपने पास रखता है, चाहे इस शब्द का उपयोग किसी भी सीमित अर्थ में किया जा सके और क्या वह अपनी नजरबंदी के परिणामस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से जाने या किसी भी स्थान पर जाने का अपना अधिकार नहीं खोता है? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ एक बार फिर इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए कि राज्य विनियमों की रक्षा और भारत की रक्षा नियमों में, निवारक निरोध को "गतिविधियों और गतिविधियों का प्रतिबंध" शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। " यहाँ "आंदोलन" का उपयोग बहुवचन में किया जाता है और यह उसी प्रकार के आंदोलन को संदर्भित करता है जिसे कहा जाता है।

अनुच्छेद *19° (1) (*घ*)* द्वारा संरक्षित किया जाना, एक राज्य या स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विभिन्न इलाकों का दौरा करना,

आदि। निवारक निरोध के उद्देश्यों में से एक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना है ताकि वह उन स्थानों पर असंतोष न फैला सके या खतरनाक गतिविधियों में लिप्त न हो। यही विचार व्यक्तियों के मामलों पर भी लागू होता है।

जिन्हें नजरबंद या बहिष्कृत किया गया है।

इसलिए, बाहरी, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

155

एस सी आर।

नजरबंदी और प्रतिबंध के कुछ अन्य रूप

आंदोलन को हमेशा एक ही समूह या परिवार और नियम से संबंधित रिश्तेदार मामलों के रूप में माना गया है।

जो एक पर लागू होता है वह अनिवार्य रूप से दूसरे पर लागू होना चाहिए। यह मानना मुश्किल है कि बाहरी मामले को संभवतः निवारक निरोध के मामले से अलग आधार पर निपटाया जा सकता है। हालाँकि मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि पटना और बॉम्बे उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक व्यक्ति जिसे बाहर कर दिया गया है, वह सफलतापूर्वक यह दावा कर सकता है कि अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत उसे दिए गए अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इस दृष्टिकोण को हमारे सामने गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है, और अगर यह सही है, तो मैं वास्तव में यह नहीं समझता कि यह कैसे माना जा सकता है कि निवारक निरोध भी अधिकार पर सीधा आक्रमण नहीं है।

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* में गारंटी। शायद, कोई यहाँ यह पूछने के लिए रुक सकता है कि संविधान निर्माताओं के विचार में किस तरह के कानून थे जब वेअनुच्छेद *19 (5)* में जनहित में प्रतिबंध लगाने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि युद्ध के कानून और

प्रांतीय अधिनियम और अध्यादेश जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, उनमें से होने चाहिए, ये ऐसे कानून हैं जो स्पष्ट रूप से इन पर प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य रखते हैं। आंदोलनों। यदि ऐसा है, तो हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि निवारक निरोध इन कानूनों का एक अविभाज्य हिस्सा था और इसे स्थानांतरण पर प्रतिबंध के रूप में माना जाता था और इस तरह से वर्गीकृत किया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मामले पर गंभीरता से विचार किया जाता है, तो यह पाया जाएगा कि विद्वान महान्यायवादी की

व्याख्या अनुच्छेद *13 (2)* के संचालन को मेरे द्वारा सुझाए गए स्पष्टीकरण की तुलना में कम दृढ़ता से और सीधे रूप से आकर्षित करती है, और मैं बाद वाले को केवल इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जो अविभाज्य रूप से बाध्य है, उसके साथ व्यवहार करना कानूनी रूप से अनुचित है।

एक पूरी तरह से अलग और असंबद्ध इकाई के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कानूनी अवधारणा में आवश्यक तत्व है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, यह इस मामले के उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में सब कुछ भूल जाएं और केवल यह याद रखें कि हिरासत, जैसा कि स्वयं स्पष्ट है और जैसा कि विस्काउंट मॉम और अन्य प्रतिष्ठित न्यायाधीशों द्वारा इंगित किया गया है,

किसी व्यक्ति को उसकी सभी "आवाजाही की स्वतंत्रता" से वंचित करने के लिए एक और नाम। •

यह तर्कों के दौरान इंगित किया गया था *156*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

कि निवारक निरोध न केवल अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* में दिए गए अधिकार को छीन लेता है, बल्कि अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा गारंटीकृत अन्य सभी अधिकारों को भी छीन लेता है, सिवाय संपत्ति रखने, प्राप्त करने और निपटाने के अधिकार के। वास्तव में इस तर्क का उद्देश्य हमें कहाँ ले जाना है, मैं पूरी तरह से समझ नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक स्पष्ट भ्रांति शामिल है, क्योंकि यह उन तरीकों में अंतर को नजरअंदाज करता है जिनमें निवारक निरोध उपखंड *(*डी*)* और अनुच्छेद *19 (1)* के अन्य उपखंडों में निर्दिष्ट अधिकार पर काम करता है। अंतर यह है कि निवारक निरोध प्रत्यक्ष और अनिवार्य रूप से आवाजाही की स्वतंत्रता पर काम करता है, अन्य अधिकारों पर इसका संचालन अप्रत्यक्ष और परिणामी है और अक्सर केवल काल्पनिक होता है। जिस व्यक्ति को निवारक रूप से हिरासत में लिया जाता है, वह अपनी हिरासत के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में सीधे अपने आंदोलन के अधिकार से वंचित हो जाता है, लेकिन वह केवल अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता खोने के परिणामस्वरूप अन्य अधिकार खो देता है। इसके अलावा, जबकि स्वतंत्रता

आंदोलन है

सभी वास्तविकता और सार में उसके द्वारा खोए गए, कुछ अन्य अधिकार तब तक नहीं खो सकते जब तक कि वह उनका प्रयोग नहीं करना चाहता या उनका प्रयोग करने में रुचि नहीं रखता। हिरासत में लिया गया व्यक्ति संगठन की स्वतंत्रता में रुचि नहीं रख सकता है या किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ऐसे मामले में, संदर्भित अधिकार केवल सिद्धांत रूप में खो जाते हैं, न कि सार के रूप में। मैं केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि जब मैंने कहा कि मैं उस तर्क की पूरी ताकत को समझने में सक्षम नहीं था जिससे निपटने का मैंने प्रयास किया है, तो मेरे दिमाग में जो था वह यह था कि यदि निवारक निरोध अनुच्छेद *(19) (1)* में गारंटीकृत लगभग सभी अधिकारों को छीन लेता है या प्रभावित करता है, तो मामला बहुत गंभीर विचार का पात्र है और हम हल्के में यह नहीं कह सकते कि अनुच्छेद *13 (2)* लागू नहीं होता है।

इस तथ्य के लिए पूरी तरह से जीवित होना कि यह एक गंभीर बात है

पार्लिया द्वारा अधिनियमित कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कहे जाने के मामले में, मैंने बार-बार खुद से सवाल पूछा हैः हम उस निर्माण के खिलाफ क्या तराजू लगा सकते हैं जिसे मैं अपनाने के लिए इच्छुक हूं और इस दृष्टिकोण के पक्ष में कि निवारक निरोध अनुच्छेद *19 19 ((1 1)) (*डी*)* में गारंटीकृत आवाजाही की स्वतंत्रता को नहीं छीनता है*?* इसका अपरिहार्य उत्तर हमेशा यह रहा है कि जबकि एक तराजू में *157*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

हमारे पास स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा है, प्रख्यात न्यायविदों की राय, उच्च प्राधिकारी का न्यायिक आदेश, इस अर्थ में संवैधानिक अभ्यास है कि कोई भी संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा किसी भी आंदोलन की स्वतंत्रता को संदर्भित नहीं करता है, और जिस तरह से निवारक निरोध के साथ व्यवहार किया गया है, उसी कानून में जिसके आधार पर इस विषय पर हमारा कानून आधारित है, हम विपरीत स्थल पैमाने पर जो कुछ भी रख सकते हैं वह एक अस्पष्ट और निराधार आशंका है कि दंड संहिता के संशोधन जैसे कुछ भयानक उद्देश्य दूर, क्षितिज में अस्पष्ट रूप से उभर रहे हैं, यह विशिष्ट आपत्ति कि केवल षड्यंत्रकारी जनजातियों का उल्लेख कुछ स्पष्ट अर्थ को बदल देगा।

शब्द, अत्यधिक तकनीकी और अवास्तविक अंतर प्रतिबंध और अभाव और धारणा पर दांव लगाते हैं

किसी व्यक्त प्रावधान द्वारा वारंट नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति

जिसे निवारक रूप से हिरासत में लिया गया है वह अधिकार का दावा नहीं कर सकता है आवाजाही की स्वतंत्रता क्योंकि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है और

कुछ अन्य चीजें जो, चाहे अकेले ली गई हों या

सामूहिक रूप से, किसी भी वजन को ले जाने के लिए बहुत असंगत हैं।

इन परिस्थितियों में, मेरा दृढ़ मत है किअनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार होने के नाते, अधिकार लेख के तहत गारंटी वास्तव में प्रति का अधिकार है

सोनल स्वतंत्रता और यह कि निवारक निरोध एक वंचित है

उस अधिकार का हनन। मेरा यह भी मानना है कि

विद्वान एटर द्वारा सुझाई गई व्याख्या पर

नी-सामान्य, निवारक हिरासत आयोजित किए बिना नहीं रखा जा सकता है

अनुच्छेद *19* द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन होना

(1) (डी*)*। किसी भी दृष्टिकोण से, इसलिए, पूर्ववत का कानून

हिरासत इस तरह की सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

समीक्षा केवल यह देखने के लिए है कि क्या कोई विशेष कानून लागू है।कोई भी अनुचित प्रतिबंध लगाता है। इसे ध्यान में रखते हुए

उच्चतम न्यायालय को यह जांचने के लिए कि क्या कोई अधिनियम हैजो उस अधिकार का उल्लंघन करता है वह इन सीमाओं के भीतर है -

कारण।

अब मैं लेख पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

21 , जो इस प्रकार चलता हैः

" *158* किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर स्वतंत्रता

स्थापित किया गया

कानून के अनुसार "।

यहाँ फिर से, हमारा पहला कदम एक पर पहुंचना होना चाहिए

प्रावधान का स्पष्ट अर्थ। केवल शब्द जो

के उचित निर्माण में कुछ कठिनाई पैदा करें

लेख "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" हैं।

विद्वान महान्यायवादी ने पहले तर्क दिया

"कानून" शब्द जिसका अनुच्छेद *21* में उपयोग किया गया है।

इसका अर्थ है राज्य द्वारा बनाई गई विधि या राज्य द्वारा अधिनियमित विधि।

दूसरी ओर, के लिए विद्वान वकीलयाचिकाकर्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि अभिव्यक्ति

" कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग बहुत कुछ में किया जाता है

व्यापक अर्थ और अर्थ में अनुमानित

द्वारा व्याख्या के अनुसार "कानून की उचित प्रक्रिया"

प्रारंभिक समय में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय और, यदि

यही है, इसका मतलब है कि कुछ अमेरिकीलेखकों का अर्थ "प्रक्रियात्मक" अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करना है।

उचित प्रक्रिया "।

तर्क, विद्वान

इस दौरान

महान्यायवादी ने हमें कार्यवाही के लिए संदर्भित किया

संविधान सभा यह दिखाने के उद्देश्य से कि

मूल रूप से तैयार किए गए लेख में शब्द थे

" कानून की उचित प्रक्रिया के बिना "लेकिन ये शब्द

थे।

बाद में शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया "सिवाय इसके कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए। मेरी राय में, यद्यपि विधानसभा में कार्यवाही या चर्चा

का अर्थ लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैंअनुच्छेद *21* में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ, विशेष रूप से

जब वे स्पष्ट और असंदिग्ध होते हैं, तो वे हैं यह दिखाने के लिए प्रासंगिक है कि सभा से बचने का इरादा था

"कानून की उचित प्रक्रिया के बिना" अभिव्यक्ति का उपयोग। उस अभिव्यक्ति की जड़ें *1215* में मैग्ना चार्टा में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "पर लेगेम टेरे" *(*देश का कानून*)* में थीं। हालाँकि, एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में, "कानून की उचित प्रक्रिया" शब्दों का उपयोग एक क़ानून में किया गया था जो यह गारंटी देता था कि कोई भी व्यक्ति उसके अधिकार से वंचित नहीं होगा।

कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा जवाब देने के लिए लाए बिना संपत्ति या कैद या अभ्यारोपित या मौत की सजा *(28,* एडवर्ड *III, Ch. III)*। इस अभिव्यक्ति को बाद में अमेरिकी संविधान और कुछ घटक राज्यों के संविधानों में भी अपनाया गया था, हालांकि कुछ राज्यों ने एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का उपयोग करना पसंद किया।

159

"कानून के उचित पाठ्यक्रम में" या "देश के कानून के अनुसार" शब्द। *[* कूली को "संवैधानिक सीमाएँ", *8* वीं संस्करण पर देखें। खण्ड. *II,* पृष्ठ *734-5]*। प्रारंभिक समय में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून की उचित प्रक्रिया" का अर्थ केवल प्रक्रिया के मामलों को शामिल करने के लिए किया था, लेकिन धीरे-धीरे अभिव्यक्ति के

अर्थ का विस्तार किया गया ताकि "देय" शब्द पर जोर देकर मूल कानून को भी शामिल किया जा सके। इस अभिव्यक्ति का उपयोग इतने व्यापक अर्थों में किया गया था कि न्यायाधीशों को इसे परिभाषित करना मुश्किल हो गया और एक मामले में यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" यह मुश्किल और शायद असंभव होगा

उन शब्दों को एक परिभाषा दें, जो एक बार में सटीक और हर मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक हो। यह कठिनाई और

शायद श्री जस्टिस ने असंभवता का उल्लेख किया थाः डेविडसन बनाम में मिलर। न्यू ऑरलियन्स, जहाँ राय

व्यक्त किया गया था कि उनके इरादे का पता लगाना बुद्धिमानी है

और न्यायिक प्रक्रिया की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा आवेदन

संलयन और बहिष्करण, 'जैसा कि निर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए मामले

सायन को इस तर्क की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं: *?* मिसौरी प्रशांत रेलवे।

को. वी. हमस *(1)*।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संविधान सभा ने किया था

बहुत लोचदार होने के कारण इस अभिव्यक्ति को न अपनाएँ

इसका अर्थ दिया गया है, लेकिन शब्दों का उपयोग करना पसंद किया" प्रक्रिया के अनुसार। कानून द्वारा स्थापित "जो

यह *1946* में बनाए गए जापानी संविधान में आता है।

यहाँ कुछ में यह कहना अनुचित नहीं होगा।

शब्द कैसे जापानी संविधान अस्तित्व में आयाटेंस। ऐसा प्रतीत होता है कि *11* अक्टूबर, *1945* को,

जापानियों की तैयारी के लिए उपाय शुरू करें संविधान, लेकिन, क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी, यह था

फरवरी, *1946* में निर्णय लिया गया कि कॉन्स्टी की समस्या

न्यायिक सुधार सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए

सर्वोच्च कमांडर के प्रमुख का खंड

क्वार्टर। तत्पश्चात इस अनुभाग के प्रमुख और

कर्मचारियों ने संविधान का मसौदा तैयार किया

अमेरिकी संवैधानिक वकील जिन्हें बुलाया गया था

इस कार्य में सरकारी अनुभाग की सहायता करें। यह

संविधान, जैसा कि एक विद्वान लेखक ने टिप्पणी की है,

(1) 115 पृष्ठ *518* पर यू. एस. *512*।

21 आई।

160 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[1950]*

समझ भी सकते हैं। *" [* ओग और ज़िंक की "आधुनिक विदेशी सरकारें" देखें*]*। संविधान की विशेषताओं में से एक जो निस्संदेह प्रत्यक्ष अमेरिकी प्रभाव की बात करती है, एक में पाई जाती है लंबा अध्याय, जिसमें लोगों के अधिकार और कर्तव्य नामक *31* अनुच्छेद शामिल हैं, जो पहली बार जापानी लोगों के लिए एक प्रभावी "अधिकार विधेयक" प्रदान करता है। बिना वारंट के आशंका के खिलाफ और आरोपों के बारे में सूचित किए बिना या पर्याप्त कारण के बिना गिरफ्तारी या हिरासत के खिलाफ सामान्य सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। *(* अनुच्छेद *33* और *34)*।

अब दो मामले हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः *-(1)* कि जापानी संविधान था

पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव के तहत तैयार किया गया*;* और *(2)* कि जिस समय इसे तैयार किया गया था, उस समय अमेरिका में न्यायिक राय की प्रवृत्ति "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति के अर्थ को सीमित करने के पक्ष में थी, जिसे कुछ अमेरिकी लेखकों द्वारा कुछ हद तक विचित्र लेकिन उपयोगी अभिव्यक्ति द्वारा दबाव डाला जाता है। यह कि ऐसी प्रवृत्ति थी, निम्नलिखित अंश से स्पष्ट होगा जिसे मैं कार्ल ब्रेंट से उद्धृत करता हूं।

स्विशर की "संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक शक्ति का विकास" *(*पृष्ठ *107):*

" इसकी व्याख्या का अमेरिकी इतिहास तीन अवधियों में आता है। पहली अवधि के दौरान, आवरण

संविधान के तहत सरकार की लगभग पहली शताब्दी में, उचित प्रक्रिया की व्याख्या मुख्य रूप से प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में की गई थी-और मुख्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया-जिसके द्वारा सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी।शक्तियाँ। दूसरी अवधि के दौरान, जिसे फिर से मोटे तौर पर *1936* तक बढ़ाया गया था, उचित प्रक्रिया को केवल प्रतिबंध के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रतिबंध के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था।

प्रक्रिया लेकिन उन गतिविधियों के सार पर जिसमें सरकार संलग्न हो सकती है। तीसरी अवधि के दौरान, *1936* से आज तक, देय *161* का उपयोग

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

एक मूल प्रतिबंध के रूप में प्रक्रिया को काफी हद तक निलंबित या त्याग दिया गया है, जिससे इसे मुख्य रूप से प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में अपनी मूल स्थिति में छोड़ दिया गया है।

इन परिस्थितियों में

उल्लेख किया गया है, यह परमिस लगता है

यह अनुमान लगाने के लिए कि जापानी संविधान में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "कानून द्वारा ब्लिश की गई प्रक्रिया" वर्तमान प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। "कानून की उचित प्रक्रिया" के संबंध में अमेरिकी न्यायिक राय, और, यदि ऐसा है, तो हमारे संविधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का अर्थ वह सब है जिसे अमेरिकी लेखकों ने "प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया" शब्दों में पढ़ा है। लेकिन मैं किसी भी निष्कर्ष को केवल अनुमान पर आधारित नहीं करना चाहता और इसके गुण-दोष के आधार पर पूरे प्रश्न की जांच करने का प्रयास करूंगा।

"कानून" शब्द का उपयोग सार में किया जा सकता है या

ठोस भावना। कभी-कभी इसके पहले "ए" या "द" जैसे लेख या "कोई भी" "सभी" आदि जैसे शब्द होते हैं, और कभी-कभी इसका उपयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है। लेकिन, आम तौर पर, "कानून" शब्द का व्यापक अर्थ होता है जब इसका उपयोग अमूर्त अर्थों में किया जाता है।

एक लेख से पहले। तय किया जाने वाला सवाल यह है कि क्या शब्द

"कानून का मतलब कुछ भी नहीं है।

कानून से अधिक।

अब जो भी पूर्व का अर्थ हो सकता है

दबाव "कानून की उचित प्रक्रिया", शब्द "कानून" है

उस अभिव्यक्ति के साथ-साथ "प्रक्रिया" के लिए सामान्य

कानून द्वारा स्थापित "और हालांकि हम बाध्य नहीं हैं

"कानून" या "उचित प्रक्रिया" पर रखे गए निर्माण को अपनाना

अमेरिका में कानून का ", फिर भी कई प्रतिष्ठित लोगों के बाद से

अमेरिकी न्यायाधीशों ने इस पर बहुत विचार किया है

विषय, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम प्राप्त कर सकते हैं

उनकी राय से कोई मदद नहीं मिलती और हमें पूरी तरह से

उनकी उपेक्षा करें। इसलिए मैं पहली बार में सेट करूँगा के कुछ निर्णयों से कुछ उद्धरण निकालें

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इस शब्द का अर्थ लगाया" "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में प्रयुक्त कानून,

जहाँ तक यह कानूनी प्रक्रिया के प्रश्न से संबंधित है।

(1) "यद्यपि विधायिका अपनी इच्छानुसार

नए उपचार प्रदान करें या पुराने को बदलें, शक्ति है

फिर भी इस शर्त के अधीन कि यह नहीं कर सकता

कुछ प्राचीन भूमि-चिह्नों को हटा दें,

या ले जाएँ

कुछ मौलिक अधिकार जो हमेशा से रहे हैं *[1950]*

162

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक प्रक्रियाओं में मान्यता प्राप्त और अवलोकन किया गयाः बार्ड

ठीक है वी। कोलिन *(1)*।

(2) "देश के कानून के अनुसार सबसे स्पष्ट रूप से इरादा है

सामान्य कानूनः एक कानून जो उसके सामने सुनता है निंदा करता है, जो जांच पर आगे बढ़ता है और प्रस्तुत करता है

परीक्षण के बाद ही निर्णय। मतलब यह है कि हर

नागरिक अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को बनाए रखेगा, और

सामान्य नियमों के संरक्षण के तहत प्रतिरक्षाएँ

जो समाज को नियंत्रित करता हैः "डार्टमाउथ कॉलेज मामला *(2)*

(3) "क्या इस बात पर संदेह किया जा सकता है कि कानून की उचित प्रक्रिया

अपने बचाव में सुने जाने के अधिकार को दर्शाता है*?* अगर

सरकार के विधायी विभाग को अधिनियम बनाना था

एक कानून जो नागरिक की निंदा करने का अधिकार प्रदान करता है

बिना किसी अवसर के, जो कुछ भी सुना जा रहा है, क्या यह नाटक किया जाएगा कि इस तरह का एक अधिनियम होगा

संविधान का उल्लंघन नहीं? अगर यह सच है,

जैसा कि निस्संदेह है, यह कैसे कहा जा सकता है कि न्यायिक विभाग, जो स्वयं न्याय का स्रोत और स्रोत है, के पास अभी भी उस कार्य को विधिसम्मत बनाने का अधिकार है जो यदि व्यक्त विधायी मंजूरी के तहत किया जाता है तो संविधान का उल्लंघन होगा? यदि ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, तो संविधान को बनाए रखने और लागू करने के लिए बैठे सरकार के न्यायिक विभाग के पास इसकी अवहेलना करने की शक्ति है। यदि ऐसा अधिकार मौजूद है तो उनकी स्थापना के परिणामस्वरूप, कानून के प्रति आज्ञाकारिता को मजबूर करने और न्याय को लागू करने के लिए, न्यायालयों को उन गलतियों को लागू करने का अधिकार है जिन्हें रोकने के लिए उन्हें बनाया गया थाः होवी वी। इलियट *(*)*।

(4) "यह एक ऐसा नियम है जो कानून जितना ही पुराना है, और इससे अधिक कभी नहीं।

अब से अधिक सम्मानित होने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि वह न्यायालय में अपनी बात नहीं कहता है, जिसके द्वारा वह अभिप्रेत है, जब तक कि उसे उपस्थित होने के लिए विधिवत उद्धृत नहीं किया गया है, और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस तरह के उद्धरण और अवसर के बिना निर्णय न्यायिक निर्धारण के सभी गुणों को चाहता है; यह न्यायिक हड़प और उत्पीड़न है, और जहां न्याय न्यायपूर्ण रूप से प्रशासित किया जाता है, वहां इसे कभी भी बरकरार नहीं रखा जा सकता हैः गैटपिन वी. पृष्ठ *(*)*।

इस प्रकार, अमेरिका में "कानून" शब्द का अर्थ नहीं है

केवल राज्य द्वारा अधिनियमित राज्य-निर्मित कानून या कानून और इसके कुछ मौलिक सिद्धांतों को बाहर नहीं करता है -

(1) 44 मिन। *97 ; 9* एल. आर. ए *152*

167 पृष्ठ *417* पर यू. एस. *409*।

(क*) 85* यू. एस. *18.*

(1) 17 अमेरिका *4.*

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

163

न्याय जो कानून की हर सभ्य प्रणाली में निहित है

और जो इसकी जड़ में हैं। अमेरिका में कई निर्णयों के परिणाम का सारांश प्रोफेसर विलिस ने पृष्ठ *662* पर "संवैधानिक कानून" पर अपनी पुस्तक में इस कथन में दिया है कि उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएँ हैंः *(1)* नोटिस, *(2)* सुनवाई का अवसर, *(3)* एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण, और *(4)* प्रक्रिया का व्यवस्थित पाठ्यक्रम। यह विद्वान द्वारा इंगित किया गया है

अलग मान सकते हैं

लेखक ने कहा कि ये आवश्यक हैं विभिन्न परिस्थितियों में प्रपत्र, और जब तक उन्हें सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है, कानून की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को किसी विशेष रूप या सुनने की विधि की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन उसे केवल सुनने के लिए एक उचित अवसर की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह, एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण का मतलब जरूरी नहीं कि हर मामले में एक न्यायिक न्यायाधिकरण हो।

जहाँ तक

प्रक्रिया के व्यवस्थित पाठ्यक्रम का संबंध है, वे बताते हैं कि इसके लिए किसी न्यायालय को साक्ष्य को सख्ती से तौलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है।

मुद्दों का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड करें, यह पता लगाने के लिए कि क्या तथ्यों की सूचना नहीं दी गई है और यह देखने के लिए कि तथ्यों पर कानून को सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं। अन्य लेखकों द्वारा व्यक्त किया गया विचार व्यावहारिक रूप से वही है जो प्रोफेसर विलिस द्वारा व्यक्त किया गया था, हालांकि कुछ लेखकों ने

वे स्पष्ट रूप से चौथे तत्व का उल्लेख नहीं करते हैं। , प्रक्रिया का व्यवस्थित पाठ्यक्रम। लेकिन असली बात यह है कि यह कि ये चार तत्व वास्तव में अलग-अलग पहलू हैं

उसी अधिकार का, अर्थात किसी के समक्ष सुने जाने के अधिकार की निंदा की जाती है। जहाँ तक इस अधिकार का संबंध है, इंग्लैंड में न्यायिक राय अमेरिका में समान प्रतीत होती है। इंग्लैंड में, यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई या सुनवाई के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ऐसा मामला तभी हो सकता है जब संसद आपात स्थिति में प्रश्नगत अधिकार को स्पष्ट रूप से छीन ले जैसा कि ब्रिटिश संसद ने पिछले दो विश्व युद्धों के दौरान सीमित संख्या में मामलों में किया था। मैं यहाँ कुछ मामलों का उल्लेख करूँगा जो दर्शाते हैं कि

मौलिक सिद्धांत कि एक व्यक्ति जिसका अधिकार प्रभावित होता है, उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में बल्कि अन्य अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्यवाही में भी देखी गई है, भले ही उनके पास हो।

6-3 एस. सी. इंडिया*/58 164*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष आएं। कूपर वी। वाड्सवर्थ बोर्ड ऑफ वर्क्स *(1)* एक अधिनियम के तहत एक मामला था जिसने जिला बोर्ड को एक ऐसे घर को बदलने या ध्वस्त करने का अधिकार दिया था जहां बिल्डर ने नींव रखने या खुदाई करने के लिए सात दिन पहले अपने इरादे की सूचना देने में लापरवाही की थी। इस शक्ति पर कार्रवाई करते हुए, बोर्ड ने विध्वंस का निर्देश दिया

बिल्डर को बिना किसी सूचना के एक इमारत, लेकिन इसे अवैध माना गया। मामले से निपटने में जे. बाइल्स ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"मुझे लगता है कि उन्होंने न्यायिक रूप से काम किया क्योंकि उन्होंने

अपराध का निर्धारण करना था, और उन्हें सजा के साथ-साथ उपचार भी देना था। ऐसा होने पर, डॉ. बेंटले के मामले से शुरू होने वाले और कुछ हाल के मामलों के साथ समाप्त होने वाले निर्णयों का एक लंबा क्रम, यह स्थापित करता है कि हालांकि कोई सकारात्मक नहीं हैं।

एक कानून में शब्दों की आवश्यकता होती है कि पार्टी को सुना जाएगा, फिर भी सामान्य कानून का न्याय विधायिका को हटाने की आपूर्ति करेगा। डॉ. बेंटले के मामले में मिस्टर जस्टिस फोर्टेस्क्यू का फैसला कुछ अनोखा है, लेकिन यह बहुत लागू होता है, और उस समय से लेकर आज तक कानून रहा है। वे कहते हैं, "नोटिस के अभाव में आपत्ति कभी खत्म नहीं की जा सकती।

ईश्वर और मनुष्य दोनों के कानून पक्ष को अपना बचाव करने का अवसर देते हैं, यदि उसके पास कोई है।

इसी मामले में एर्ले सी. जे. ने कहाः

"यह कहा गया है कि सिद्धांत है कि कोई आदमी नहीं

सुनवाई के अवसर के बिना अपनी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, यह न्यायिक कार्यवाही तक सीमित है। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं;. कानून, मेरे विचार में, शक्ति के कई प्रयोगों पर लागू किया गया है जो आम समझ में न्यायिक कार्यवाही से अधिक नहीं होगी।

कार्य करें

जिला बोर्ड ने एक घर को गिराने का आदेश दिया।

एर्ले सी. जे. द्वारा की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया गया था।

और सर रॉबर्ट कोलियर द्वारा स्मिथ बनाम में आवेदन किया गया। रानी *(1)*, और रेजिना वी में लॉर्ड कैंपबेल की टिप्पणियाँ। कैंटरबरी के आर्कबिशप *()* का भी यही प्रभाव था।

(1) 3 ए. सी. *614*।

(1) 14 सी. बी. *(*एन. एस.*) 180*

(3) 1 ई. और ई. *559*।

165

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर जॉर्ज ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की थी।

फिशर बनाम में जेसल। कीन *(1),* लाबौचेर बनाम। अर्ल ऑफ वार्नक्लिफ, *((2 2))* और

रसेल बनाम। रसेल *(3)*। में

अंतिम उल्लिखित मामले में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" यह *[*वुड बनाम। लोड *(4)]* में एक मूल्यवान क्रिया होती है

न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा न्याय प्रशासित करने के तरीके के बारे में लॉर्ड चीफ बैरन का बयान, जिनके पास करने के लिए न्यायिक कार्य हैं, जो मुझे उन दोनों क्लब मामलों पर मेरे सामने होने पर बहुत खुशी होनी चाहिए थी, जिन्हें मैंने हाल ही में सुना था, अर्थात्, फिशर बनाम का मामला। कीन और लाबौचेर बनाम का मामला। अर्ल ऑफ वार्नक्लिफ। एक समिति का उल्लेख करते हुए मेरा मतलब यह हैः " वे "ऑडी अल्टरम पार्टेम" उक्ति में व्यक्त नियम द्वारा अपने कार्यों के अभ्यास में बाध्य हैं, कि किसी भी व्यक्ति को अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना परिणाम भुगतने की निंदा नहीं की जानी चाहिए। यह नियम सख्ती से कानूनी आचरण तक ही सीमित नहीं है।

प्रत्येक न्यायाधिकरण या निकाय

न्यायाधिकरण, लेकिन लागू होता है

निवेशित व्यक्तियों का

निर्णय लेने का अधिकार

के साथ

भारतीय व्यक्तियों के लिए नागरिक परिणामों से जुड़े मामलों पर '। *33*

इस राय को लॉर्ड द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

मैक्नाघटेन इन

लापोइंटे वी। संगठन आदि

मॉन्ट्रियल *(5)*।

इस मामले में

के लिए आवेदन

बाध्य किया गया

अपीलार्थी द्वारा पेंशन, जिसके पास निदेशक मंडल ने इस्तीफा देने के लिए, परिस्थितियों की किसी भी न्यायिक जांच के बिना, इस आधार पर दावे को अस्वीकार करने का संकल्प लिया कि वह अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य थे। इस प्रक्रिया की निंदा की गई थी

लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा "नियमों के विपरीत" होने के रूप में समाज और सबसे बढ़कर प्राथमिक के विपरीत

न्याय के सिद्धांत "। लॉर्ड मैकनाघटेन की इन टिप्पणियों का उल्लेख द किंग में किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था।वी. आवास अधिनियम, *1919 (*)* के तहत अपील न्यायाधिकरण। उस स्थिति में, एक कंपनी ने एक चित्र बनाने का प्रस्ताव रखा

घर और स्थानीय प्राधिकरण ने प्रतिबंधित किया है

इमारत, कंपनी ने आवास के तहत अपील की

(1) [1874] एल. आर. *9*

पूर्व, *190*।

(1) 11 च। डी. *353.*

(6) [1906] ए. सी. *535*

*(*) 13* च. डी. *346.*

*(*) [1920]* टी. बी. *334.*

(1) 14 च। डी. *471.*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

166

[1950]

(अतिरिक्त शक्तियाँ*)* अधिनियम, *1919,* जिसमें एक प्रावधान था कि अपील को कुछ मामलों में सुनवाई के बिना ठीक से निर्धारित किया जा सकता है और अपीलीय न्यायालय सुनवाई को समाप्त कर सकता है और अपील को संक्षेप में निर्धारित कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम *7* का अर्थ यह था कि अपील पर न्यायाधिकरण मौखिक सुनवाई को समाप्त कर सकता है, यह नहीं कि वे किसी भी प्रकार की सुनवाई को समाप्त कर सकते हैं, और यह कि वे अपीलार्थियों को सुनवाई देने के लिए बाध्य हैं। द अर्ल ऑफ रीडिंग ने निर्णय देते हुए कहाः

" ऐसे मामले में लागू कानून का सिद्धांत है -

वुड बनाम में केली सी. बी. द्वारा अच्छी तरह से कहा गया। ए में लोड करें

जिस परिच्छेद का उल्लेख किया गया है

प्रभु की स्वीकृति के साथ

लापोइंटे बनाम में मैकनाघटेन। एल 'एसोसिएशन आदि डी मॉन्ट्रियल।

स्थानीय सरकार बोर्ड *v.* आर्लिज *(1),* स्थानीय

सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ आवास, नगर योजना और ग के तहत समापन आदेश दिया गया था। मौखिक सुनवाई के बिना और बोर्ड के निरीक्षक द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई रिपोर्ट को देखने की अनुमति दिए बिना कार्य करें।

स्थानीय

पूछताछ की। द.

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस आधार पर आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया कि अपील को एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा निपटाया गया था जिसका कर्तव्य समुदाय के हित में व्यक्ति पर दायित्वों को लागू करना था और जिसका चरित्र एक संगठन का था।

सिद्धांत

कार्यकारी कार्यों के साथ एकीकरण। हालाँकि स्वीकार किया गया था और स्पष्ट रूप से सेट किया गया था

कि कब

अपील पर निर्णय लेने का कर्तव्य लगाया जाता है, जोयह तय करना किसका कर्तव्य है कि उसे न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए, और उन्हें इस प्रश्न से निपटना चाहिए

उन्हें संदर्भित किया

उनमें से प्रत्येक

पक्षपात के बिना और देना चाहिए

को

मामला, और वह

दलों को प्रस्तुत करने का अवसर

निर्णय में आना चाहिए

आत्मा और उसके साथ

एक न्यायाधिकरण की जिम्मेदारी की भावना जिसका कर्तव्य है

इस मामले में

न्याय पाने के लिए। टिप्पणी करते हुए

आम तौर पर एक चरम माना जाता है

मामला, श्री गेविन

के सदस्य

साइमंड्स, जो बाद में एक बन गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कहना हैः

(1) [1915] ए. सी. *120*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

167

"मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि अगर विषय

ऐसी कार्यवाहियों का मामला जो यहाँ इंगित किया गया है कि विषय की स्वतंत्रता थी, या वास्तव में उसका जीवन था, आप ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को अपमानजनक मानेंगे। *(* सी. के. एलन की *"*लॉ एंड ऑर्डर्स*"*, पृष्ठ *167* देखें*)*।

मैंने विशेष रूप से उन मामलों का उल्लेख किया है जो थे

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सामने, क्योंकि मुझे करना है

कहा जाता है कि यह एक कार्यकारी कार्य है और क्योंकि मैं चाहता हूँ इंगित करें कि कार्यकारी अधिकारियों के सामने भी और

प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक आदेश आम तौर पर नहीं हो सकता है

ऐसा दिए बिना किसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाला पारित

परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सुनवाई मामला। मुझे केवल उस के बाद हैल्सबरी को जोड़ना है

सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की गणना करना जो हैं -इंग्लैंड में मान्यता प्राप्त, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जनता का अधिकार

बैठक, आदि, जोड़ती है:

"मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जोड़ा जाना चाहिए

इस सूची में निम्नलिखित अधिकार हैं जो प्रतीत होते हैं

अच्छी तरह से स्थापित हो-विषय का अधिकार

उसे प्रभावित करने वाले किसी भी मामले में उसके अनुसार मुकदमा चलाया गया है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विशेष रूप से

सिद्धांत कि एक आदमी अपने आप में न्यायाधीश नहीं हो सकता हैकारण, और कि किसी भी पक्ष की निंदा नहीं की जानी चाहिए

अनसुना, या उसके खिलाफ निर्णय दिया जाना

जब तक उसे एक उचित अवसर नहीं दिया गया है

अपना मामला आगे बढ़ाएँ। *(* हैल्सबरी के नियम

इंग्लैंड, दूसरा संस्करण, खंड *6,* पृष्ठ *392)*।

सवाल यह है कि क्या सिद्धांत है कि नहीं

सुनवाई के बिना व्यक्ति की निंदा की जा सकती है

निष्पक्ष न्यायाधिकरण जो सभी में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कानून की आधुनिक सभ्य प्रणालियाँ और कौन सी हैल्सबरी

मौलिक

अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त के बराबर रखता है

इस कानून का हिस्सा माना जाता है

अधिकार नहीं हो सकते

देश। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे यह मुश्किल लगता है

राजकुमार

सवाल करते हैं।

इसका नकारात्मक जवाब दें।

शिष्य अंग्रेजों का हिस्सा होना

विधि प्रणाली और

प्रक्रिया जो हमें विरासत में मिली है,

देखा गया

इस देश में बहुत लंबे समय से और गहराई से भी है

हमारे प्राचीन इतिहास में निहित, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का आधार होने के नाते

[1950]

168

प्रारंभिक काल से ही पंचायत प्रणाली। द.

पूरी आपराधिक प्रक्रिया

कोड, क्या यह सौदा करता है

अपराधों के मुकदमे के साथ या

निवारक या अर्ध

प्रशासनिक उपाय जैसे -

हैं।

में विचार किया गया

धारा *107,108,109,110* और *145* इस पर आधारित है -

इस सिद्धांत की नींव, और यह मुश्किल है

देखें कि यह कानून का हिस्सा नहीं बन गया है।भूमि "और हमारी कानून प्रणाली में नहीं है।

यदि ऐसा है, तो "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया"

इस सिद्धांत को शामिल करना चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है या

शामिल नहीं हो सकता है। कि लेख में प्रयुक्त "कानून" शब्द

21 इसका मतलब यह नहीं है कि केवल राज्य द्वारा बनाई गई कानून इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि अदालत की अवमानना के मामलों में अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं है, जब अवमानना के विचार में नहीं है।

न्यायालय की, फिर भी ऐसी प्रक्रिया जो अब इन मामलों में प्रचलित है, हमारे कानून का हिस्सा है।

द.

कानून-जो

सी. आर. आई. में परीक्षणों और पूछताछ की प्रक्रिया को विनियमित करता है

गौण मामले विशेष रूप से कुछ मामलों में तर्क के लिए प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यह हमेशा माना गया है कि तर्कों को सुने बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। कई मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हालांकि क़ानून में नोटिस के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हो सकता है, लेकिन प्रावधान को कानून में पढ़ा जाना चाहिए।

मुझे पता है कि कुछ न्यायाधीशों ने "प्राकृतिक न्याय" की अभिव्यक्ति के लिए तीव्र नापसंद व्यक्त किया है।

यह आधार है कि यह बहुत अस्पष्ट और लोचदार है, लेकिन जहां इसके साथ प्रसिद्ध सिद्धांत हैं

नहीं।

के बारे में अस्पष्टता

जिनका सभी विधियों ने सम्मान किया है और

केवल इसलिए त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि

संज्ञान में, वे प्राकृतिक न्याय पर आधारित पाए जाने वाले अंतिम विश्लेषण में हैं। यह कि "प्राकृतिक न्याय" शब्द हमारे कानून के लिए अज्ञात नहीं है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रिवी काउंसिल ने इस देश की कई आपराधिक अपीलों में निर्धारित किया है कि वह इस देश में आपराधिक न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या न्याय की आवश्यकता से विचलन हुआ है। *[* अब्राहम मैलोरी डिलेट *(1),* तबा सिंह बनाम देखें। राजा सम्राट*),* जॉर्ज गफेलर बनाम। द.

(1) आई. एल. आर. *48* बम। *515 .*

(1) 12 ए. सी. *459*।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

169

राजा *(1),* और बुग्गा और अन्य बनाम। सम्राट *(2)]*। वर्तमान मामले में, दावा किए गए अधिकार के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है जो किसी के अपराध को स्वीकार करने का अधिकार है या एक निष्पक्ष निकाय द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उस अधिकार को अनुच्छेद *21* के शब्दों में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का तात्पर्य रखता है, और यह एक अनिश्चित संरक्षण और संरक्षण के लायक नहीं होगा, यदि चर्चा के तहत कानून के प्राथमिक सिद्धांत, जो हैल्सबरी के अनुसार मौलिक अधिकारों के बराबर है, को नजरअंदाज किया जाना है और बाहर रखा जाना है। अपनी दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बार-बार पूछा कि क्या संविधान

किसी कानून को अधिनियमित करने की अनुमति देगा, मौजूदा कानून द्वारा अनुमत परीक्षण के तरीके को समाप्त कर देगा और युद्ध या परीक्षण द्वारा परीक्षण की प्रक्रिया स्थापित करेगा जो इंग्लैंड में पुराने समय में प्रचलित थी। इस प्रश्न में कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है जिसके होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह एक कानूनी समस्या को जन्म देता है जिसे शायद केवल इस तरह से पूरा किया जा सकता है कि यदि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी प्रक्रिया प्रक्रिया कानून द्वारा समाप्त या अधिनियमित की गई है तो इसे हल करना मुश्किल होगा। प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दें, लेकिन यदि "कानून" शब्द में वह शामिल है जो मैंने उसे दिखाने का प्रयास किया है, तो ऐसा उत्तर उचित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है कि "कानून कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्दों में प्रोफेसर विलिस की पुस्तक में निर्धारित चार सिद्धांत शामिल होने चाहिए, जो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, एक ही सिद्धांत के अलग-अलग पहलू हैं और जिनके बारे में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है। ये सिद्धांत, जैसा कि विद्वान लेखक बताते हैं और जैसा कि अधिकारी बताते हैं

दिखाएँ, बिल्कुल कठोर सिद्धांत नहीं हैं लेकिन कुछ निश्चित मामलों के भीतर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम हैं।

सीमाएँ। मुझे केवल यह जोड़ना है कि इस बात का गंभीरता से विरोध नहीं किया गया है कि इस अनुच्छेद में "कानून" का अर्थ वैध कानून है और "प्रक्रिया" का अर्थ कार्यवाही के कुछ निश्चित नियम हैं, न कि कुछ ऐसा जो प्रक्रिया के लिए केवल ढोंग है।

अब मैं अनुच्छेद *22* की जांच करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

संविधान जो विशेष रूप से विषय से संबंधित है

(1) ए. आई. आर. *1919* पी. सी. *108*।

(1) ए. आई. आर. *1943*, पी. सी. *211*।

170

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निवारक निरोध। इस अनुच्छेद के संबंध में ध्यान देने योग्य पहला बिंदु यह है कि यह अनुच्छेद *19* और *21* के संचालन को बाहर नहीं करता है, और इसे उन दो लेखों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, उसी तरह जैसे अनुच्छेद *19* और *21* को अनुच्छेद *22* के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। सही स्थिति यह है कि जहां तक निवारक निरोध के संबंध में उसमें विशिष्ट प्रावधान हैं, अनुच्छेद *22* को प्रबल होना चाहिए, लेकिन जहां उस अनुच्छेद में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं, वहां अनुच्छेद *19* और *21* के संचालन को बाहर नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि एक ही अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर तीन अलग-अलग अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, उन्हें पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं बनाएगा, सिवाय इसके कि मैंने जितना संकेत दिया है।

अब मैं लेख और सौदे का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

एक सलाहकार बोर्ड *[*खंड *4 (*ए*)]; (2)* कि संसद उन परिस्थितियों और मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्धारित कर सकती है जिनमें किसी व्यक्ति को राय प्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। एक सलाहकार बोर्ड का *[*खंड *7 (*ए*)]; (3)* कि जब किसी व्यक्ति को निवारक रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो प्राधिकरण

उसे आदेश *[*खंड *(5)]* के खिलाफ प्रतिनिधि भेजने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करें; और *(4)* कि संसद इसके लिए अधिकतम अवधि निर्धारित कर सकती है - जिसे किसी भी वर्ग या मामलों के वर्गों में किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध *[*खंड *7 (*बी*)]* का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इस मामले में अंतिम बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले तीन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

पहले बिंदु के संबंध में, प्रश्न

खंड *4 (*क*)* के अंत में आने वाले "इस तरह के उल्लेख" शब्दों के सटीक अर्थ के बारे में उत्पन्न होता है। दो वैकल्पिक व्याख्याएँ सामने रखी गईं: *(1)* " "ऐसे निरोध" का अर्थ है निवारक निरोध; *(2)* "इस तरह के समर्पण" का अर्थ है इससे अधिक अवधि के लिए निरोध।

तीन महीने। यदि पहली व्याख्या सही है, तो सलाहकार मंडल का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के मामले के गुण-दोष पर गौर करना और केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

171

एस सी आर।

रिपोर्ट करें कि क्या उनकी नजरबंदी का पर्याप्त कारण था

यह। दूसरी व्याख्या के अनुसार, सलाहकार बोर्ड का कार्य सरकार को यह रिपोर्ट करना होगा कि क्या इसके लिए पर्याप्त कारण है।

तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया व्यक्ति। कुल मिलाकर, मैं दूसरी व्याख्या से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं। प्रथम दृष्टया यह एक गंभीर मामला है कि

किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखें *(*तीन से अधिक*)*

महीनों*)* बिना किसी जांच या मुकदमे के। लेकिन अनुच्छेद *22*

(4) (क*)* प्रावधान करता है कि इस तरह की नजरबंदी का आदेश दिया जा सकता है

सलाहकार मंडल की रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद से सीधे उस वस्तु से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए

यह आवश्यक है, लेख द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा,

अर्थात्। , सलाहकार मंडल से रिपोर्ट मांगना, हार जाता है

इसका मूल्य, यदि सलाहकार बोर्ड को अपना दिमाग नहीं लगाना है सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात्,

लंबे समय तक हिरासत *(*तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत*)* उचित है या नहीं। अनुच्छेद *22 (4)* के अधीन

(क*)* सलाहकार बोर्ड को इससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

तीन महीने की समाप्ति और इसलिए ऐसा कर सकते हैं

प्रदान करने के लिए, कि एक आदमी के लिए हिरासत में लिया गया है अस्सी-नौ दिन, एक सलाहकार मंडल को यह कहना है कि क्या

उनकी प्रारंभिक नजरबंदी उचित थी। दूसरी ओर,

सवाल का निर्धारण कि क्या लंबा है

निरोध *(*तीन से अधिक धाराओं के लिए निरोध*)* उचित है, इसमें आवश्यक रूप से इस सवाल का निर्धारण शामिल होना चाहिए कि क्या निरोध बिल्कुल भी उचित था, और ऐसी व्याख्या केवल प्रावधान को वास्तविक

अर्थ और प्रभावशीलता दे सकती है। प्रावधान प्रकृति में, संरक्षण या सुरक्षा का होने के कारण, मुझे स्वाभाविक रूप से उस व्याख्या की ओर झुकना चाहिए जो विषय के लिए अनुकूल है और जो विचार में उद्देश्य के अनुरूप भी है।

अगला प्रश्न जिस पर हमें चर्चा करनी है

अनुच्छेद *22 (7) (ए)* का अर्थ और दायरा इस प्रकार हैः ——

"संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क) जिन परिस्थितियों में, और वर्ग

या ऐसे मामलों के वर्ग जिनमें किसी व्यक्ति को *172* प्राप्त किए बिना निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय

खंड *(4)* के उपखंड *(क)* के प्रावधान।

सवाल यह है कि "परिस्थितियों" का क्या अर्थ है*?*

और इस प्रावधान में "मामलों के वर्ग या वर्ग" का उपयोग किया गया है।

यह सवाल इस वजह से उठा है कि किस तरह से

ऐसा प्रतीत होता है कि इन अभिव्यक्तियों की व्याख्या संसद के अधिनियम में की गई है और उन्हें लागू किया गया है, जिससे हम संबंधित हैं। चूंकि मामला महत्वपूर्ण है और कुछ हद तक

जटिल, मैं अपने अर्थ को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा

स्पष्ट रूप से कुछ पुनरावृत्ति के जोखिम पर भी, और ऐसा करते समय, मुझे अनिवार्य रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *I* और *III* का उल्लेख करना चाहिए, जिसके तहत संसद को इसे अधिनियमित करने का अधिकार था। सूची *I*-संघ सूची की मद *9* से पता चलता है कि संसद के पास *(1)* रक्षा, *(2)* विदेश मामलों और *(3)* भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों से निवारक निरोध पर देर से कानून बनाने की शक्ति है। सूची *III*-समवर्ती सूची के तहत -

उपयुक्त मद मद *3* है जो दर्शाता है कि कानून निवारक निरोध *(1)* राज्य की सुरक्षा, *(2)* सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और *(3)* समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के मुख्य किराये से जुड़े कारणों से किया जा सकता है। विवादित अधिनियम सभी को संदर्भित करता है

सूची *I* और *III* में उल्लिखित विषयनिवारक निरोध का कौन सा कानून बनाया जा सकता है।

अधिनियम की धारा *3 (1),* जिसका सार पहले ही उल्लिखित किया जा चुका है, महत्वपूर्ण है और मैं इसे शब्दशः दोहराऊंगा।

"केंद्र सरकार या राज्य सरकार

हो सकता है

(क*)* यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि

उसे किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए

((i) भारत की रक्षा, भारत के संबंध

विदेशी शक्तियों या भारत की सुरक्षा के साथ, या

((ii) राज्य या मुख्य राज्य की सुरक्षा

सार्वजनिक व्यवस्था का अधिभोग, या

*((*ग*)* आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव

समुदाय के लिए आवश्यक, या *173*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

(ख*)* यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है जो

विदेशी अधिनियम, *1946 (1946* का *XXXI)* के अर्थ के भीतर एक विदेशी है, जो भारत में अपनी निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने या भारत से उसके निष्कासन की व्यवस्था करने की दृष्टि से,

ऐसा करना आवश्यक है, निर्देश देने का आदेश दें

कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

यह ध्यान दिया जाएगा कि विधान के सभी विषय

सूची *I* की मद *9* में होने वाले निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान खंड *(*ए*)* के उपखंड *(1)* में वर्गीकृत किए गए हैं।

इस समूह में विषय संख्या में तीन हैं और,

संदर्भ की सुविधा के लिए, मैं इसके बाद उल्लेख करूंगा

ग. उपखंड *(ii)* में हम पाते हैं कि

ए, बी और

मद *3* में संदर्भित

मामले

समूह में दो

राज्य और

सुरक्षा

सूची *III,* ये हैं

आदेश दें।

ये दो विषय, मैं

जनता का रखरखावडी और ई के रूप में संदर्भित किया जाएगा। उपखंड *(iii)* में, संदर्भ

सूची की मद *3* में तीसरी बात की गई है।

III, और मैं इस विषय को एफ के रूप में संदर्भित करूंगा।

वर्गीकरण, आइए अब हम संविधान की ओर मुड़ें

स्वयं।

अनुच्छेद *22 (4)* और *22 (7)* को एक साथ पढ़ने पर, यह

यह स्पष्ट होगा कि जब तक अनुच्छेद *22 (4) (ए)* लागू होता है

क्षेत्र और संसद खंड *(7)* के तहत कार्य नहीं करती है।

(क*)* अनुच्छेद *22* में एक सलाहकार मंडल होना चाहिए।

प्रत्येक मामला, अर्थात, यदि विधान समूह ए से संबंधित है

एफ, जैसा कि यह यहाँ करता है, के लिए एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए

इन सभी समूहों।

अनुच्छेद *22 (7)* हालांकि व्यावहारिक रूप से एक

अपवाद। यह सार में कहता है कि संसद

बोर्ड, लेकिन ऐसे मामलों में यह बाध्यकारी होगा संसद द्वारा *(1)* परिस्थितियाँ निर्धारित करना और

(2) ऐसे मामलों का वर्ग या वर्ग जिसमें ऐसा पाठ्यक्रम है

आवश्यक पाया गया। यदि मामले में विचार किया जाता है

और मामलों का वर्ग या वर्ग एक विशेष या वर्ग का होना चाहिए। असाधारण प्रकृति, ताकि मामले को बाहर निकाला जा सके

शासन करें और इसे अपवाद के दायरे में लाएं। यह हमेशा *174* है।

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामान्य या सामान्य के बीच रेखा खींचना संभव है

और असामान्य या असाधारण

नैरी

मामले,

और यह वही है, मेरी राय में, संसद खंड *(7) (क)* के तहत ऐसा करने की अपेक्षा की गई थी। मुझे नहीं लगता कि यह कभी इरादा था कि संसद

अपनी इच्छा से सामान्य को असामान्य या नियम को अपवाद के रूप में मान सकते हैं। लेकिन इस मामले में ठीक यही किया गया है। ए से ई को छोड़कर जिन सभी वस्तुओं पर निवारक कानून बनाना संभव है, उन्हें अपवाद के दायरे में रखा गया है और केवल एक, एफ, जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित है, को नियम के तहत रहने की अनुमति दी गई है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान किया गया है कि केवल अंतिम श्रेणी, एफ के लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा, लेकिन अन्य श्रेणियों, ए से ई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यह माना जा सकता है कि उन मामलों में सलाहकार बोर्ड को हटा दिया गया है। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि एफ श्रेणी के लिए भी सलाहकार मंडल को समाप्त करना संसद के लिए खुला होता और यदि इस तरह का पाठ्यक्रम अपनाया जाता तो यह अधिनियम की वैधता को प्रभावित नहीं करता। यह निस्संदेह इस अर्थ में एक तार्किक स्थिति है कि उनके लिए अपने रुख को सही ठहराने के लिए इस हद तक जाना आवश्यक था; लेकिन, मेरी राय में, विवादित अधिनियम की धारा *12* को लागू करने में संसद द्वारा अपनाया गया मार्ग है

अनुच्छेद *22 (7) (ए)* के तहत क्या विचार किया गया है या इसके द्वारा अनुमति दी गई है। द.

परिस्थितियाँ

होना।

निर्धारित विशेष और असाधारण परिधि वाले रुख होने चाहिए और मामलों के वर्ग या वर्ग एक ही प्रकृति के होने चाहिए। मेरी राय में, संविधान ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि संसद को सभी या अधिकांश श्रेणियों ए से एफ को लगभग शाब्दिक रूप से दोहराना चाहिए और यह तय करने के लिए अपना दिमाग नहीं

लगाना चाहिए कि क्या करना है। परिस्थितियों और किन वर्गों या वर्गों के मामलों में एक सलाहकार मंडल की सुरक्षा को समाप्त किया जाना है।

मैं यहां बता सकता हूं कि दो विचार सामने रखे गए हैं।

अनुच्छेद *22* के खंड *(4) (ए)* और *7 (ए)* को कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में हमारे सामनेः *-(1)* वह खंड *(4) (ए)* यह नियम निर्धारित करता है कि उन सभी मामलों में जहां अधिक समय के लिए निरोध

तीन महीने से अधिक का आदेश दिया जाता है, यह परामर्श के साथ और सलाहकार *175* की रिपोर्ट पर किया जाना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

बोर्ड, और खंड *(7) (ए)* इस नियम के लिए एक अपवाद प्रदान करता है कि संसद एक पारित कर सकती है एक सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के बिना तीन महीने से अधिक के लिए निरोध की अनुमति देने वाला अधिनियम*; (2)* कि खंड *(4) (ए)* और *(7) (ए)* स्वतंत्र खंड हैं जो दो अलग-अलग और वैकल्पिक प्रावधान बनाते हैं।

तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखना, एक मामले में सलाहकार मंडल की रिपोर्ट पर और दूसरे मामले में सलाहकार मंडल के संदर्भ के बिना। पदार्थ को देखना और केवल शब्दों को नहीं; मैं हूँ

यह अभिनिर्धारित करने के लिए इच्छुक है कि खंड *(7) (ए)* व्यावहारिक रूप से इस नियम पर एक अपवाद है कि तीन महीने से अधिक के लिए निवारक निरोध का आदेश केवल एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर दिया जा सकता है, और अब तक मेरे पास है

उस पायदान पर आगे बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे अंतिम निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से जो भी विचार हम अपनाएँ। बाद के दृष्टिकोण पर भी, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह कानून जो संविधान संसद को अनुच्छेद *22 (7) (ए)* के तहत बनाने के लिए सक्षम बनाता है, वह एक अपवादात्मक रूप से कठोर कानून होगा, और इस सिद्धांत पर कि एक असाधारण रूप से कठोर कानून का उद्देश्य एक विशेष उद्देश्य के लिए होना चाहिए।

असाधारण स्थिति में, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है, उसका हर शब्द कायम रहना चाहिए। खंड *(7) (ए)* केवल एक सक्षम प्रावधान है, और यह इस बात का ध्यान रखता है कि संसद उस चरम सीमा तक नहीं जा सकती है जिस तक उसे मामलों के वर्ग या वर्गों और उन परिस्थितियों को निर्धारित किए बिना जाने की अनुमति है जिन पर चरम कानून लागू होगा। यह इस प्रकार है कि मामलों के वर्ग या वर्ग और परिस्थितियाँ इस तरह के विधान की आवश्यकता के लिए एक विशेष प्रकृति की होनी चाहिए।

यह आग्रह किया गया था कि "और" शब्द जो आता है

"परिस्थितियों" और "वर्ग या मामलों के वर्गों" के बीच का उपयोग असंगत अर्थों में किया जाता है और इसे "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और चित्रण के माध्यम से यह कहा गया था कि जब यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है और इसका मतलब है कि वह यह या वह करने के लिए स्वतंत्र है। मुझे नहीं

लगता कि यह तर्क उचित है। मेरा मानना है कि खंड *(7) (ए)* को कुछ हद तक निम्नानुसार सटीक रूप से व्याख्या की जा सकती हैः - " संसद एक सलाहकार मंडल का गठन कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में वह परिस्थितियों और वर्ग या *176* को निर्धारित करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मामलों के वर्ग। "यदि यह अर्थ है, तो" और "को" और "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और" या "के रूप में नहीं; और" हो सकता है "को" होगा "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए मान लीजिए कि यह कहा गया था कि

संसद किसी कार्य को करने के लिए समय और स्थान निर्धारित कर सकती है, तो क्या यह सुझाव दिया जा सकता है कि समय और स्थान दोनों निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए? मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामलों के वर्ग या वर्गों में हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्तियों या उनकी गतिविधियों और गतिविधियों या दोनों के बारे में कुछ संदर्भ होना चाहिए। दूसरी ओर "परिस्थितियाँ" कुछ अतिरिक्त नीरस को संदर्भित करती हैं, जैसे कि

परिवेश, पृष्ठभूमि, प्रचलित के रूप में

ऐसी स्थितियाँ, आदि, जो खतरनाक व्यक्तियों की खतरनाक गतिविधियों के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र साबित हो सकती हैं। वहाँ प्रावधान के सामने स्पष्ट रूप से अर्थ है कि परिधीय रुख और मामलों के वर्ग या वर्ग *(*जो अलग-अलग अर्थों और संकेतों के साथ दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और जिन्हें पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है*)* दोनों को निर्धारित किया जाना चाहिए, और दूसरे को निर्धारित किए बिना एक का प्रिस्क्रिप्शन पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अनुच्छेद *22 (7) (ए)* के तहत अधिनियमित की जा सकने वाली ऐसी कानून में, जिस चरम सीमा तक यह जा सकती है, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए गंभीर परिणाम शामिल होने चाहिए। इसका अर्थ होगा *(1)* लंबे समय तक हिरासत में रखना, यानी तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखना, और *(2)* सलाहकार मंडल की सुरक्षा से वंचित होना।

इसलिए अनुच्छेद *22 (7) (ए)*, जो एक संरक्षणात्मक प्रावधान होने का तात्पर्य रखता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसकी उचित व्याख्या नहीं की जाती है। मेरे विचार से, यह विचार करता है कि विचाराधीन कानून बहुत सामान्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका दायरा निर्धारित करके सीमित किया जाना चाहिए।

मामलों के वर्ग या वर्ग और परिस्थितियाँ दोनों।

अभिव्यक्ति "वर्ग या

यह तर्क दिया गया था कि

मामलों के वर्ग काफी व्यापक हैं जो सूची में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का इलाज करने में सक्षम बनाते हैं।

I और *III*, क्रमशः आइटम *9* और *3, (*यानी, किसी भी

वर्ग। सबसे पहले

ए का गठन

श्रेणी ए से एफ*)* के रूप में

मुझे यह एक प्रशंसनीय तर्क लग रहा था, लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, मुझे यह उतना ही अनुचित लगता है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि मैं पहले भी एक से अधिक बार इस पर जोर दे चुका हूं। , कि एक विशेष या चरम प्रकार का कानून इन तक सीमित होना चाहिए

मामलों और परिस्थितियों के विशेष वर्ग।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के तहत

177

एस सी आर।

संविधान, संसद को निर्धारित करना है "वर्ग या वर्ग ", सूची *I* और *III* के तहत उसे दी गई शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करते हुए। वर्ग या

वर्गों का अपना प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उनकी इस तरह से कल्पना की जानी चाहिए कि उनकी सामग्री द्वारा संविधान द्वारा प्रदान किए गए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा को हटाने को उचित ठहराया जा सके। निर्धारित करना केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक है।

इसमें उस वस्तु को चुनने और अनुकूलित करने का एक मानसिक प्रयास शामिल है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है।निर्धारित किया गया। हम यहाँ पाते हैं कि जो निर्धारित किया जाना है वह "वर्ग या वर्ग" *(*और "परिस्थितियाँ" भी*)* है। हम यह भी पाते हैं कि कानून जो प्रदान करने का इरादा रखता है वह अनुकूल है।

लंबे समय तक नजरबंदी *(*जिन शब्दों से मैं आगे चलूँगा*)*

मतलब तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहना*)* और एली

सलाहकार बोर्ड का खनन। वर्ग या वर्ग

इसलिए निर्धारित किए जाने का सीधा असर होना चाहिए इन मामलों पर और इस तरह से चुना जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए

ताकि कोई भी उन्हें देखकर कहेः " "वह यह है कि

कारण कि कानून ने लंबे समय तक नजरबंदी निर्धारित की हैएक सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के बिना "। अन्य में

शब्दों में, कक्षा बनाने के लिए कुछ होना चाहिए या

निर्धारित वर्ग एक चरम प्रकार के कानून के साथ फिट होते हैं

लेशन-असाधारण गुरुत्वाकर्षण या खतरे का कुछ तत्व जिसे आसानी से और तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है और

इसलिए लंबे समय तक हिरासत की आवश्यकता होती है; और वहाँ

उस संदर्भ को दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, एक विज्ञापन के लिए

विसरी बोर्ड एक अवांछनीय और बोझिल होगा।

प्रक्रिया और असाधारण के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त

ऐसी स्थिति जिसमें कानून लागू होता है। शायद एक साधारण

चित्रण स्थिति को और भी स्पष्ट कर सकता है।

सूचियों के तहत, उन विषयों में से एक जिस पर

संसद निवारक निरोध का कानून बना सकती है

के रखरखाव से जुड़ा मामला है सार्वजनिक आदेश "। अधिनियम बस इस वाक्यांश को दोहराता है

भूविज्ञान और धारा *3* में स्थितियाँः "उसे *(*हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को*)* रोकने की दृष्टि से

रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करनासार्वजनिक आदेश "। यह धारा *3* के लिए ठीक हो सकता है,

लेकिन धारा *12* को आगे बढ़ना चाहिए। के लिए एक पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य

सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव एक सामान्य बात हो सकती है

कार्य या यह विशेष गुरुत्वाकर्षण का कार्य हो सकता है। मुझे लगता है।

उस अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)* में विचार किया गया है कि गंभीर और *178*

[1950 एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस श्रेणी में आने वाले अधिक जघन्य प्रकार के कार्यसार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कृत्यों का

(या अन्य शीर्ष*)* निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि परिभाषित किया जा सके और एक असाधारण टुकड़े के क्षेत्र को घेरें

कानून।

कि किसी प्रकार का उप-वर्गीकरण *(*यदि मैं हो सकता हूँ*)*

इस शब्द का उपयोग करने की अनुमति*)* श्रेणियों ए से एफ तकक्या संभव था कि रेगुला के संदर्भ से चित्रित किया जा सकता है

राज्य विनियमन की ब्रिटिश रक्षा की धारा *18*-बी

टियोन। यह विनियमन *1939* के एक अधिनियम के तहत बनाया गया था।

जिसके लिए विनियम बनाने को अधिकृत किया गया था

उन व्यक्तियों को हिरासत में लेना जिनकी नजरबंदी प्रतीत होती है

राज्य सचिव के हितों में समीचीन होना सार्वजनिक सुरक्षा या क्षेत्र की रक्षा "। इन दोनों

"सार्वजनिक सुरक्षा" और "क्षेत्र की रक्षा" के मामले

सूची *I* में बताए गए कुछ शीर्षों के अनुरूप हैंऔर *III*। यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद होगा कि इनके तहत

दो शीर्ष, विनियम *18*-बी ने कई उप-खंड निर्धारित किए हैं। मामलों के प्रमुख या वर्ग या वर्ग जिनमें निवारक

नजरबंदी का आदेश दिया जा सकता है। ये कक्षाएँ बहुत हैं

हम धारा *3* में जो पाते हैं उससे अधिक विशिष्ट

विवादित अधिनियम और इसलिए इसकी संभावना कम है

कार्यपालिका द्वारा पूर्व आदेश देने की शक्ति का दुरुपयोग कड़ी नजरबंदी। निर्धारित कक्षाएँ इस प्रकार हैंः - *(1)* अगर

राज्य सचिव के पास विश्वास करने का उचित कारण है

शत्रुतापूर्ण मूल या संघों का कोई व्यक्ति, *(2)* यदि राज्य सचिव के पास विश्वास करने का उचित कारण है

कोई भी व्यक्ति जो हाल ही में कृत्यों में शामिल रहा हो

सार्वजनिक सुरक्षा या रक्षा के लिए हानिकारक

क्षेत्र में या ऐसे कार्यों की तैयारी या उकसावे में,

(3) यदि राज्य सचिव के पास उचित कारण है

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसका सदस्य रहा है या रहा है या आगे बढ़ने में सक्रिय रहा है या होना है

इसके बाद के किसी भी संगठन के उद्देश्य

उल्लिखित। *(*क*)* संगठन विदेशी के अधीन है।

प्रभाव या नियंत्रण *(*बी*)* के नियंत्रण में व्यक्ति

संगठन के साथ संबंध हैं या रहे हैं

सरकार या सहानुभूति में संबंधित व्यक्ति

सरकार की प्रणाली के साथ, किसी भी शक्ति के साथ

जिसे महामहिम युद्ध में हैं, और दोनों ही मामलों में

उद्देश्यों के लिए संगठन के उपयोग का खतरा

सार्वजनिक सुरक्षा आदि के लिए प्रतिकूल, *(4)* यदि सचिव

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि किसी क्षेत्र में कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति का हालिया आचरण या ऐसे व्यक्ति द्वारा दुश्मन के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हाल ही में लिखे गए या बोले गए कोई भी शब्द इंगित करते हैं या संकेत देते हैं कि उस व्यक्ति के दुश्मन की सहायता करने की संभावना है। मुझे केवल यह इंगित करना है कि इस मामले में निवारक निरोध को किस दायरे में कानून बनाया जा सकता है।

देश ब्रिटिश अधिनियम में इंगित दायरे से बहुत बड़ा है जिसके तहत विनियमन *18*-बी बनाया गया था। और इसलिए विवादित अधिनियम के तहत परिस्थितियों के साथ-साथ मामलों के वर्ग या वर्गों के विनिर्देशन के लिए अधिक गुंजाइश है। लेकिन जो कुछ किया गया है वह यह है कि विधायी सूचियों में आने वाले शब्दों को ले लिया गया है और अधिनियम में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कक्षा या कक्षाओं के संबंध में मैंने क्या कहा है

मामले उन परिस्थितियों पर भी लागू होते हैं जो अनुच्छेद *22 (7) (ए)* के तहत निर्धारित की जानी हैं। इन परिस्थितियों का उद्देश्य उस पृष्ठभूमि या परिवेश की आपूर्ति करना है जिसमें क्रूर व्यक्तियों की खतरनाक गतिविधियाँ विशेष रूप से हानिकारक साबित हो सकती हैं। वे विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो एक विशेष आवश्यकता की मांग करती हैं।

एक कठोर उपाय और जिसके तहत एक सलाहकार बोर्ड का संदर्भ पूर्व के उद्देश्य को विफल कर सकता है

तीखी कार्रवाई। अनुच्छेद *22 (7) (ए)* का स्पष्ट अर्थ यह प्रतीत होता है कि दोनों वर्गों और परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना तस्वीर पूरी नहीं होगी। बार में कुछ चर्चा हुई कि किस तरह की परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया गया होगा। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए नहीं है, लेकिन मुझे आशंका है कि एक आसन्न विद्रोह या युद्ध, एक विशेष क्षेत्र में गंभीर अव्यवस्था ने पंजाब को प्रेरित किया है।

सरकार कुछ क्षेत्रों को घोषित करेगी

"परेशान करती हैं।

क्षेत्रों, तनावपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति, तोड़फोड़ या व्यापक राजनीतिक डकैती की व्यापकता और कई अन्य मामले संविधान के उद्देश्य का जवाब दे सकते हैं।

अब मैं कुछ हद तक परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा।

लंबी चर्चा जिसमें मुझे केवल संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रवेश करना पड़ा, जिसे मेरी राय में, संविधान के निर्माताओं द्वारा पूरी तरह से गलत समझा गया है।

विवादित अधिनियम। मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद *22* निवारक निरोध के तीन वर्गों से संबंधित हैः

(1) तीन महीने के लिए निवारक हिरासत*;*

(2) तीन से अधिक लोगों के लिए निवारक हिरासत

सलाहकार मंडल की रिपोर्ट पर महीनों*;* और

(3) तीन से अधिक लोगों के लिए निवारक हिरासत

सलाहकार मंडल के संदर्भ के बिना महीनों।

अगर किसी को इनके लिए किसी प्रकार का लेबल ढूंढना है

विषय की स्पष्ट समझ के लिए, कोई उन्हें "खतरनाक", अधिक खतरनाक और "सबसे खतरनाक" के रूप में लेबल कर सकता है। अब तक पहले दोकक्षाओं का संबंध है, निर्धारित करने के लिए कुछ भी नहीं है। संविधान के तहत। जाहिरा तौर पर, संविधान के लेखक वर्ग संख्या *(1)* के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि जहाँ तक वर्ग संख्या *(2)* का संबंध इस प्रावधान से है कि

सलाहकार बोर्ड इस प्रावधान के साथ आवश्यक था कि निरोध अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए।

अवधि जो संसद द्वारा तय की जा सकती थी

काफी है। लेकिन उन्होंने एक विशेष बनाने का ध्यान रखा। वर्ग सं. *(3)* के लिए प्रावधान, और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह प्रावधान विषय की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान के सुचारू रूप से काम करने के लिए है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन एक अच्छी तरह से विचार और उचित निर्माण प्राप्त करना चाहिए। यह वह है

यह सलाह दी जाती है कि किसी कानून की कठोरता बुराई या खतरे की गंभीरता के अनुरूप या फिट होनी चाहिए जिसका उद्देश्य *at.com*-है।

बैटिंग, और यह भी स्पष्ट है कि कानून जो

संसद को अनुच्छेद के तहत अधिनियम बनाने की अनुमति दी गई है।

22 (7) (क*)* जहाँ तक कठोरता का संबंध है, वह सबसे दूर की सीमा तक जा सकता है। यह इस प्रकार है कि कानून होना चाहिए था।

असाधारण रूप से गंभीर स्थितियों और बहिर्गमन के लिए इरादा

सीज़। इसलिए संविधान के लेखकों नेयह आवश्यक है कि संसद निश्चित करे कि

अधिनियम में विनिर्देश जो इसके लिए सशक्त हैं

अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)* के तहत पारित करें, ताकि इन के माध्यम से

इतना कठोर कानून बनाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है इसके चेहरे पर और इसके अनुप्रयोग पर स्पष्ट होना चाहिए।

इसे वर्गों और परिस्थितियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

निर्दिष्ट किया गया। अधिनियम को *(1)* "वर्ग या वर्ग" निर्धारित करना चाहिए।

जिनका संदर्भ व्यक्तियों के लिए होना चाहिए।

मामलों की संख्या *181*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

जिनके खिलाफ कानून संचालित करना है और उनकी गतिविधियाँ और गतिविधियाँ और *(2)* "परिस्थितियाँ" जो स्थितियों और पीठ को प्रमुखता में लाएंगी।

जिनके खिलाफ खतरनाक गतिविधियों के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह के दो-गुना प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से, कानून को लागू करने का क्षेत्र केवल एक विशेष प्रकार के मामलों तक ही सीमित रहेगा -

यह कम अस्पष्ट होगा, दुरुपयोग के लिए कम खुला होगा और जिन लोगों को इसे प्रशासित करना है, उन्हें कानून द्वारा निहित शक्ति के उपयोग को उचित ठहराने के लिए एक शर्त उत्पन्न होने पर इसे निष्पक्ष रूप से निर्धारित करने में सक्षम बनाएगा। यही, मेरी राय में, लेख का सही अर्थ और महत्व है।

22 (7) (क*)* और इसे कम करने का कोई भी प्रयास निंदनीय परिणाम देगा।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के निर्माण के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के बाद

अनुच्छेद *22 (7) (*ए*),* मैं तुरंत विचार करने का प्रस्ताव करता हूं कि क्या विवादित अधिनियम की धारा *12* के अनुरूप है

द.

उस प्रावधान की आवश्यकताएँ। मेरी राय में, यहऐसा नहीं है, क्योंकि यह संविधान द्वारा अपेक्षित तरीके से मामलों के परिक्षेत्र रुख या वर्ग या वर्गों को निर्धारित करने में विफल रहता है। यह परिस्थितियों को बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करता है, और हालांकि इसका उद्देश्य वर्ग या वर्गों का प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन यह इस तरह से करता है कि जिस प्रावधान से संसद ने अपनी शक्ति प्राप्त की है, उसका सही अर्थ समझ में नहीं आया है। मैंने मामले के इस हिस्से पर पर्याप्त रूप से विचार किया है और जो मैंने पहले ही कहा है उसे दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मुझे यह बताना चाहिए कि भले ही यह माना जाए कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिया गया दृष्टिकोण सही है और सूची *I* और *III* की मद *9* और *3* में उल्लिखित किसी भी श्रेणी को एक वर्ग के रूप में मानना और बिना किसी योग्यता या परिवर्तन के इसे शामिल करना संसद की क्षमता के भीतर था, फिर भी

दो गुना त्रुटि के कारण खंड को सहेजा नहीं जा सकता हैः *(1)* अनुच्छेद *22 (7) (*क*)* में "वर्ग या वर्गों" को "परिस्थितियों" से जोड़ने वाले शब्द "और" का गलत अर्थ लगाया गया है और *(2)* "परिस्थितियों" और "वर्ग या वर्गों" के बीच के अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और उनका उपयोग विनिमेय शब्दों के रूप में किया जाता है। सबसे पहले

त्रुटि दिखाई देती है

मैं काफी गंभीर हूं, क्योंकि हालांकि संविधान दो आवश्यकताओं को निर्धारित करता है और जोर देता है

[1950]

182

परिस्थितियों के निर्देश पर भी

के रूप में

यह अधिनियम में माना गया है

वर्ग या वर्ग, धारा *12* कि

केवल उनमें से

एक का प्रिस्क्रिप्शन

और मामले की जड़ तक जाता है। हो सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिस्थितियाँ और वर्ग या वर्ग

दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और उनका अलग-अलग अर्थ है

लेकिन अधिनियम इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि

परिस्थितियाँ वर्ग या वर्गों के साथ समान हैं, जैसा कि होगा

"किसी भी मामले में हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति" शब्दों से प्रकट होता है।निम्नलिखित वर्गों के मामलों में से या इनमें से किसी के अधीन

अनुभाग में निम्नलिखित परिस्थितियों का उपयोग किया गया है। मैंने पहले ही दिखा दिया है कि इस तरह के चरम के कानून में परिस्थितियों का विनिर्देशन कितना महत्वपूर्ण है और

कठोर चरित्र। इसलिए, "वर्गों" के साथ भ्रमित करने के लिए" परिस्थितियाँ "और" परिधि "का उल्लेख करना छोड़ देना।

मेरी राय में "रुख" गंभीर त्रुटियाँ हैं। वहाँ

मेरी राय में, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि अधिनियम की धारा *12* जिसके द्वारा संविधान द्वारा इस विषय को प्रदान किया गया सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण या सुरक्षा छीन ली गई है, एक वैध प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह संविधान के उसी प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके तहत संसद ने इसे अधिनियमित करने की अपनी क्षमता प्राप्त की थी।

अब मैं अनुच्छेद *22 (5)* के बारे में संक्षेप में बताऊंगा जो

व्यक्ति से संवाद करने के लिए निवारक निरोध का आदेश देना प्राधिकरण पर अनिवार्य बनाता है। जिन आधारों पर आदेश दिया गया है उन्हें हिरासत में लिया गया है बनाया और उसे जल्द से जल्द मौका देने के लिए

आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करना। यह याद रखना चाहिए कि इस प्रावधान का उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और उसके पक्ष में सुरक्षा प्रदान करना है और इसे सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

कानून या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसके पास कोई अधिकार हैं। यदि अनुच्छेद *21* यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले उसे एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी बेगुनाही स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, तो वह अधिकार अभी भी बना हुआ है। वास्तव में, संविधान में उस अधिकार का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है और इसके खिलाफ कोई निषेध नहीं है।

एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन करना। दूसरी ओर, ऐसा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जिसके पास सर्वोच्च है

के तहत दिया गया है

संविधान का पालन करना चाहिए

यह अधिकार है

प्रतिनिधित्व हो रहा है

ठीक से

एक निष्पक्ष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा माना जाता है।

वहाँ

इसलिए कुछ मशीनरी ठीक से हो

बंदी के मामलों की जांच करनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि उन्हें बिना किसी कारण के हिरासत में नहीं लिया गया है। यदि संविधान द्वारा इस अधिकार को स्पष्ट रूप से छीन लिया गया होता, तो इस मामले का अंत हो जाता, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नहीं छीन लिया गया है, और मैं किसी भी अंतर्निहित अभाव को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं।

इस तरह के एक मूल्यवान अधिकार। अनुच्छेद *22 (4) (ए)* में एक सलाहकार बोर्ड का मात्र संदर्भ, यदि प्रावधान की मेरी व्याख्या सही है, तो इसमें शामिल नहीं है -

गुण-दोष के आधार पर बंदियों के मामलों की जांच करने के उद्देश्य से एक उचित तंत्र का गठन। द.

किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए या नहीं, यह रिपोर्ट करने के उद्देश्य से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए हिरासत में रखने के बारे में रिपोर्ट करने के उद्देश्य से एक बोर्ड का गठन करने से बहुत अलग बात है। मेरे विचार में, संसद अनुच्छेद *22* के खंड *(7) (ए)* के तहत जो कुछ भी कर सकती थी, वह उस अनुच्छेद के खंड *(4) (ए)* में विचार किए गए उद्देश्य के लिए एक विज्ञापन विज़री बोर्ड को समाप्त करना था और अधिकार को समाप्त नहीं करना था।

किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले के गुण-दोष की जांच करने के उद्देश्य से तंत्र, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए।

यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद *22* अपने आप में एक संहिता है

और निवारक निरोध का पूरा कानून इसके चार कोनों के भीतर पाया जाना चाहिएः हालांकि मैं इस व्यापक बयान को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। लेख प्रक्रिया के कुछ मामलों के लिए प्रदान करता है, लेकिन यह उनके लिए पूरी तरह से प्रदान नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह नोटिस के पक्ष में है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना मामला वापस करने का अवसर देता है, एक सलाहकार बोर्ड जो उसके मामले से निपट सकता है, और अधिकतम अवधि के लिए जिसके बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। इन बिंदुओं को बिना किसी संदेह के छुआ गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका पूरा इलाज किया गया है। प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह विधायिका पर छोड़ दिया गया है कि वह प्रतिनिधि से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करे। सलाहकार मंडल का उल्लेख किया गया है, लेकिन *184*

[1950]

यह केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत की सुरक्षा के लिए है। संसद के पास अभी भी पर्याप्त अक्षांश बचा है, और यदि संसद उस अक्षांश का अनुचित रूप से उपयोग करती है, तो अनुच्छेद *19 (5)* न्यायालय को यह देखने में सक्षम बना सकता है कि क्या उसने तर्कसंगतता की सीमाओं का उल्लंघन किया है।

मैं अब अधिनियम से निपटने के लिए आगे बढ़ूंगा

जिन निष्कर्षों पर मैं पहुँचा हूँ उनका प्रकाश। जहाँ तक अधिनियम की धारा *3* का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि यह सबसे अधिक अनुचित है, क्योंकि यह कुछ अधिकारियों की दया पर निर्भर करता है, जो अपने दम पर उनकी नजरबंदी का आदेश दे सकते हैं और जिनके दिमाग में हम यह देखने के लिए जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए कोई आधार है जिस पर उनकी कार्रवाई टिकी हुई है। लेकिन मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। जिन प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, उन्हें त्वरित निर्णय लेने होते हैं और अनिवार्य रूप से उन्हें अपने निर्णय पर कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत किसी भी तरह से अनुचित नहीं है और यह सभी निवारक या अर्ध अंतर्निहित है। प्रशासनिक उपाय जो दंड प्रक्रिया संहिता में पाए जाते हैं। उस संहिता की धारा *107* के तहत, यह निर्धारित करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि क्या उनकी राय में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है जिसके कारण शांति भंग होने की संभावना है। धारा *145* के तहत भी, उसकी प्रारंभिक कार्रवाई उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि पर निर्भर करती है। इसलिए मुझे अधिनियम की धारा *3* में कुछ भी गलत या असंवैधानिक नहीं लगता है। लेकिन मुझे यह बताना चाहिए कि यह केवल पहले कदम के लिए एक उचित प्रावधान है, यानी गिरफ्तारी और प्रारंभिक निरोध के लिए, और तथाकथित व्यक्तिपरक संतुष्टि संतुष्टि का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जो केवल एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करके किया जा सकता है।

जिन आधारों पर निरोध का आदेश दिया जाता है और उन आधारों के संबंध में प्रति पुत्र के अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है।

मुझे इसमें कुछ भी मौलिक रूप से गलत नहीं लगता है।

अधिनियम की धारा *7*, जो संबंधित प्राधिकारी पर यह दायित्व बनाती है कि वह किसी बंदी को उन आधारों के बारे में सूचित करे जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और *185*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

उसे आदेश के खिलाफ प्रतिनिधि भेजने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करें। धारा *10* में यह प्रावधान है कि सलाहकार मंडल निरोध आदेश की तारीख से दस सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। संविधान के अनुच्छेद *22 (4) (ए)* के अनुरूप, और केवल एक ही टिप्पणी जो कोई कर सकता है वह यह है कि

संसद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इतनी लंबी अवधि तय करने के लिए बाध्य नहीं थी और सामान्य मामलों में इसे छोटा किया जा सकता था। वास्तविक धाराएँ जो मुझे संविधान का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं, वे

धारा *12* और *14* हैं। मैं पहले ही अनुच्छेद *22 (7) (ए)* के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए धारा *12* के सिद्धांत पर चर्चा कर चुका हूं और मेरी राय है कि धारा

12 संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है

यह और इसलिए अल्ट्रा वायर्स है। मुझे यह भी लगता है कि

संसद ने अनुच्छेद *22 (7) (ए)* की आवश्यकताओं पर कार्य किया है।अपनी विवेकाधीन शक्ति का अनुचित रूप से प्रयोग करना

इस प्रकार बंदी को सुरक्षा से वंचित करनासलाहकार बोर्ड जिसे संविधान में प्रदान किया गया है

मैं अपने फैसले को दोहराना चाहता हूं अपने स्वयं के शब्द जो इतने स्पष्ट रूप से कहा गया है

उनके द्वारा। धारा *14* से अलग की जा सकती है - अधिनियम के अन्य प्रावधान और यह नहीं हो सकता है

याचिकाकर्ता को कोई राहत देना संभव है

यह आधार बनाते हुए कि धारा *14* अमान्य है। लेकिन मुझे लगता है कि

धारा *12* विधान की जड़ तक जाती है।

क्योंकि यह एक आवश्यक के निरोध से वंचित करता हैबचाव, और मेरी राय में याचिकाकर्ता का अधिकार है

बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए इस आधार पर कि एक

संविधान का आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है अनुपालन किया। यह रिट निश्चित रूप से बिना

किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह जो अधिकारी कर सकते हैं

याचिकाकर्ता के खिलाफ लिया है या उसके बाद ले सकता है

दंडात्मक कानून के तहत। मुझे इस योग्यता को जोड़ना है।

क्योंकि उसके शामिल होने के आरोप थे

कुछ आपराधिक आपराधिक मामले लेकिन वास्तविक तथ्य नहीं थे

स्पष्ट रूप से हमारे सामने लाया गया।

मुझे केवल कुछ जोड़ना है

समापन टिप्पणियाँ

मेरा निर्णय। के प्रावधानों का अध्ययन करते हुए

विवादित अधिनियम, मैं एक तुलना स्थापित करने में मदद नहीं कर सका

पिछले दो विश्व युद्धों के दौरान इंग्लैंड में। मैं कर सकता था।यह भी ध्यान देने में मदद नहीं करता है कि विवादित अधिनियम का उद्देश्य है

एक शांतिकाल अधिनियम होने के लिए, जबकि कानून

जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह युद्ध के दौरान लागू किया गया था। पहले और दूसरे युद्ध के दौरान, एक संख्या

कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई मामले थे

उनकी नजरबंदी के संबंध में अदालत में लाया गया,

लेकिन दो प्रमुख मामले जिन्हें फिर से उद्धृत किया जाएगाऔर फिर से रेक्स वी हैं। हैलिडे *(1)* और लिवर्जिज बनाम। साहब।

जॉन एंडरसन *(2)*। हम जानते हैं कि अमेरिका में कुछ मानक जो सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं और युद्ध की अवधि के दौरान न्यायाधीशों द्वारा सामान्य कानून लागू किया गया है और कभी-कभी उन्हें समग्र रूप से "युद्ध शक्ति" में शामिल किया जाता है। द.

दो अंग्रेजी मामले जिनके लिए मेरे पास है

उसी सिद्धांत को स्पष्ट करें, जैसा कि होगा

जिसे कुछ हद तक कानूनी अधिनियम, अर्थात् युद्ध में राष्ट्रीय सफलता द्वारा बलिदान किया जा सकता है। या राष्ट्रीय लूट या गुलामी से बचना।

लिवर्जिज वी. सर जॉन एंडरसन *(1)*, लॉर्ड

मैकमिलन ने इन शब्दों में वही टिप्पणी कीः

"जिस स्वतंत्रता की हम न्यायसंगत रूप से प्रशंसा करते हैं, वही स्वतंत्रता है

कानून का उपहार और जैसा कि मैग्ना चार्टा मान्यता देता है, कानून द्वारा जब्त या संक्षिप्त किया जा सकता है। ऐसे समय में जब यह देश का निर्विवाद कानून है कि एक नागरिक को जबरन भर्ती या माँग द्वारा अपने जीवन और अपने देश के हित के लिए जो कुछ भी उसके पास है, उसे त्यागने के लिए मजबूर किया जा सकता है, यह आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है कि राज्य सचिव को अपेक्षाकृत हल्के नियमों को लागू करने की विवेकाधीन शक्ति दी जानी चाहिए।

सावधानी बरतें

में से

हिरासत "।

(1) [1917] ए. सी. *260.*

(3) [1917] ए. सी. *260* पी. *271 .*

(2) [1942] ए. सी. *206*।

(4) [1942] ए. सी. *206* पी. *257 .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

187

ये परिच्छेद बहुमत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं

दो मामले, लेकिन रेक्स बनाम में लॉर्ड शॉ के बहुत विस्तृत निर्णय। हैलिडे एंड लॉर्ड एटकिन इन लिवर साइड *v.* सर जॉन एंडरसन ने दिखाया कि मतभेद के साथ-साथ मामले और उसमें निहित बिंदुओं के प्रति अधिक भावुक व्यवहार की गुंजाइश थी। यह कहना मुश्किल है कि लॉर्ड एटकिन के प्रसिद्ध उक्ति में ध्वनि कानून का एक अच्छा आधार नहीं है कि हथियारों के टकराव के बीच भी कानून चुप नहीं हैं और वे युद्ध में उसी तरह बोलते हैं जैसे शांति में बोलते हैं। हालाँकि ऐसा हो सकता है, मुझे जो पता चलता है वह इंग्लैंड में बनाए गए नियमों में है

पहले और दूसरे युद्ध के दौरान

वहाँ एक विस्तृत था

प्रावधान

एक सलाह के लिए

बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में बोर्ड, जो

वंचित व्यक्तियों के लिए युद्धकालीन सुरक्षा प्रदान की गई

उनकी स्वतंत्रता। अधिनियम में भी एक प्रावधान था

1939 कि राज्य सचिव को कम से कम रिपोर्ट करनी चाहिए

इसके तहत की गई कार्रवाई के बारे में हर महीने एक बार

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या सहित विनियमन उसके तहत दिए गए आदेशों के तहत। मुझे पता चलता है कि ये रिपोर्ट

इन्हें मुद्रित किया गया और जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। मैं यह भी पाता हूँ कि राज्य सचिव ने सदन में कहा

28 जनवरी, *1943* को कॉमन्स, कि जनरल

ब्रिटिश प्रजा को हिरासत में लेने की अनुमति देने का आदेश होगाउनके साथ परामर्श करने के लिए विनियमन के तहत

एक अधिकारी की सुनवाई से बाहर कानूनी सलाहकार। यह

बैरिस्टरों के साथ परामर्श पर लागू आदेश और

सॉलिसिटर लेकिन उन मामलों में नहीं जहां सॉलिसिटरों को इंटर भेजा जाता है

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक क्लर्क के रूप में देखें जो एक अधिकारी नहीं था उच्च न्यायालय से। विवादित अधिनियम को नुकसान होता है

हालाँकि, ऐसे प्रावधानों के अभाव के कारण,जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं थी

एक मशीनरी की स्थापना के कारण हुआ था

परीक्षा के लिए प्रशासनिक या न्यायिक प्राधिकरण

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मामलों में, ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके निष्पक्षता और न्याय की अनिवार्यताएँ। अधिनियम भी

बाद के कुछ प्रांतों की तुलना में पीड़ित

ऐसे अधिनियम जिनमें सलाहकार मंडल की सुरक्षा की जाती है

अधिनियम की धारा *12 (2)* में मामलों की समीक्षा के लिए छह महीने के बाद हिरासत में लिया गया, लेकिन यह काफी अलग सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

188

[1950]

परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन का बेटा, की समीक्षामूल आदेश की आवश्यकता है।

मुझे उम्मीद है कि कमियों की ओर इशारा करते हुए

एक्ट आई को गलत नहीं समझा जाएगा। मुझे पता है कि

इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में और कई देशों में भी

अन्य देशों में, पुराने का पुनर्निर्धारण किया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणाएँ जो धीरे-धीरे प्राप्त हो रही हैं

कई मामलों में सामाजिक नियंत्रण। मैं भी समझता हूँ।

जिम्मेदारियाँ, और यह कहना सही नहीं है कि उभर रहा है इससे स्थितियाँ पूरी तरह से गायब हो गई हैं।

देश। यह मानते हुए कि निजी अधिकारों को अक्सर सार्वजनिक भलाई के अधीन किया जाना चाहिए, क्या एक स्वतंत्र समुदाय में इस मामले में न्यायपूर्ण संतुलन बनाना आवश्यक नहीं है? कि एक व्यक्ति को उससे वंचित किया जाना चाहिए

बिना किसी परीक्षण के व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक गंभीर मामला है, लेकिन समाज की ज़रूरतें इसकी मांग कर सकती हैं और व्यक्ति को अक्सर उन जरूरतों को पूरा करना पड़ सकता है। . फिर भी व्यक्तिगत अधिकारों के रखरखाव के बीच संतुलन

और सार्वजनिक भलाई तभी हो सकती है जब अपनी स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति को अपनी बेगुनाही स्थापित करने का उचित मौका दिया जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे एक उपयुक्त तंत्र का आशीर्वाद उसे ऐसा मौका देना अच्छे और न्याय के लिए एक बाधा हो सकती है।

सरकार

पतंजलि शास्त्री जे.-यह एक आवेदन है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत

जेल में बंदी

जारी किया जाता है

से

याचिकाकर्ता

होने का अनुमान

दिशा-निर्देश

के तहत

बिना मुकदमे केमद्रास सरकार द्वारा जारी किया गया

निवारक निरोध अधिनियम, *1950* और इसे याचिकाकर्ता के आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार के कथित उल्लंघन के खिलाफ मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इस न्यायालय के गारंटीकृत संरक्षण का आह्वान करने वाला पहला आवेदन होने का गौरव प्राप्त है। चूंकि इस मामले में बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दे शामिल थे और नए आधार को तोड़ना शामिल था, इसलिए दोनों पक्षों पर पूरी तरह से और क्षमता के साथ बहस की गई, जिसका संदर्भ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के संविधान के कमोबेश समान प्रावधानों के लिए दिया गया था।

189

एस सी आर।

अन्य देश और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।

याचिकाकर्ता पहले से ही हिरासत में था

उक्त सरकार द्वारा पारित आदेशों के तहतमद्रास सार्वजनिक रखरखाव के तहत

आदेश अधिनियम,

1947 , लेकिन उस अधिनियम और अन्य सभी की वैधता के रूप में

इसी तरह के स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम थे

भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में पूछताछ के बाद

नया संविधान लागू हुआ, संसद ने निवारक नामक एक व्यापक उपाय लागू किया

आक्षेपित अधिनियम*)* का विस्तार पूरे भारत में एककुछ अपवाद यहाँ सामग्री नहीं हैं।

यह अधिनियम *25* फरवरी *1950* को लागू हुआ।

और, *27* फरवरी को, मद्रास सरकार ने विवादित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का कथित प्रयोग करते हुए और पहले के आदेशों को निरस्त करते हुए, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, और आदेश दिया। उन्हें *1* मार्च को सेवा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने

यह तर्क देता है कि विवादित अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा *3,7,10,11,12,13* और *14* आवागमन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को छीन लेती है या कम करती है

संविधान के अनुच्छेद *13 (2)* के उल्लंघन में और इसलिए, शून्य है जैसा कि उसमें घोषित किया गया है।

अनुच्छेद *13* उन लेखों में से एक है जो

भारतीय संविधान के भाग *III* में "मौलिक अधिकार" शामिल हैं।

यह भाग एक

संविधान की नई विशेषता और भारतीय है

" बिल ऑफ राइट्स "। यह पहले दस के मॉडल पर बनाया गया है।

अमेरिकी संविधान में संशोधन जो

अमेरिकी नागरिक के मौलिक अधिकारों की घोषणा करें। अनुच्छेद *12*, जो इस भाग का पहला अनुच्छेद है, "राज्य" को संघ और राज्यों के शासन और विधानमंडलों के साथ-साथ उन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों को शामिल करने के रूप में परिभाषित करता है जिनके खिलाफ मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं,

और अनुच्छेद *13 (1)* घोषित करता है कि सभी मौजूदा कानून संघ और राज्यों के शासन और विधानमंडलों के साथ असंगत हैं।भाग *III* के प्रावधान, की सीमा तक

असंगतता, शून्य हो। अनुच्छेद का खंड *(2)*, जिस पर याचिकाकर्ता का तर्क मुख्य रूप से आधारित है, निम्नानुसार हैः

" राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त या कम करता है और

इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई भी विधि, - उल्लंघन की सीमा, शून्य हो "।

डेप्रिवा के खिलाफ संवैधानिक निषेध के रूप में

यह या संक्षिप्तकरण केवल अधिकारों से संबंधित है।

इस भाग के अनुसार, "पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि

अधिकार की प्रकृति और विस्तार, जिसके अनुसार

याचिकाकर्ता, भाग *III* ने उसे सम्मानित किया है, और,

दूसरा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अधिकार इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है

विवादित अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है या संक्षिप्त कर दिया गया है

या इसके किसी भी प्रावधान द्वारा। पहला सवाल बदल जाता है।संबंधित लेखों की उचित व्याख्या पर

संविधान, और दूसरे में विचार शामिल है

आक्षेपित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता की ओर से पेश श्री नांबियार

तर्क की तीन मुख्य पंक्तियाँ। सबसे पहले,पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

अनुच्छेद *19 (1) (घ)* में निर्दिष्ट भारत का

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार, और जैसे ही हिरासत में लिया गया

आक्षेपित अधिनियम द्वारा प्राधिकृत एक नहीं था

"उचित प्रतिबंध "जिसे संसद लागू कर सकती थी

के खंड *(5)* के तहत ऐसे अधिकार पर अधिरोपित करना

याचिकाकर्ता को अनुच्छेद *21* के तहत मौलिक अधिकार था अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए सिवाय इसके कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, और इसके अलावा हिरासत को अधिकृत करके विवादित अधिनियम

उचित प्रक्रिया के अनुसार उस अधिकार को छीन लिया गया और इसलिए यह अमान्य था। और. अंत में, पहले से संदर्भित विवादित अधिनियम के प्रावधान अधिकार से बाहर और निष्क्रिय थे क्योंकि उन्हें लागू करने में संसद ने अनुच्छेद *22* खंड *(4)* से *(7)* द्वारा अपनी विधायी शक्ति पर रखी गई सीमाओं को पार कर लिया है।

विचारणीय है

तदनुसार, पहला प्रश्न

क्या अनुच्छेद *19 (1) (घ)* और *(5)* है

लागू होता है

"जॉन स्टुअर्ट कहते हैं, "स्वतंत्रता।"

मिल,

वर्तमान मामलाः

"इसमें वह करना शामिल है जो कोई चाहता है।

लेकिन स्वतंत्रता

व्यक्ति को इस हद तक सीमित होना चाहिए-उसे खुद को दूसरों के लिए उपद्रव नहीं बनाना चाहिए।

एक आदमी के रूप में

तर्कसंगत व्यक्ति, कई चीजें करने की इच्छा रखता है, लेकिन एक नागरिक समाज में उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को विनियमित करना पड़ता है

191

एस सी आर।

और द्वारा समान इच्छाओं के अभ्यास के साथ सुलह

अन्य व्यक्ति। इसलिए स्वतंत्रता होनी चाहिएप्रभावी रूप से कब्जे में रखने के लिए सीमित। समझौता

विशेष रूप से, अनुच्छेद *19,* जबकि कुछ सबसे अधिक की गारंटी देता हैप्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण चरण या तत्व

नागरिक अधिकारों के रूप में, उनके विनियमन के लिए प्रावधान करता है

राज्य द्वारा कुछ लागू करने वाले आम अच्छे

"उनके व्यायाम पर प्रतिबंध। लोको की शक्ति

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गति व्यक्तिगत क्रिया का एक अनिवार्य तत्व है।

स्वतंत्रता जिसका अर्थ है शारीरिक संयम से मुक्ति,

और जेल में नज़रबंदी उस पर एक कठोर आक्रमण है

स्वतंत्रता। लेकिन सवाल यह हैः क्या अनुच्छेद *19* में कहा गया है कि

संविधान के भाग *III* में स्थापित करते हुए,

इंकार के अर्थ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना

पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकारभारत "। उपखंड *(ई)* इसी तरह अधिकार की गारंटी देता है

राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में रहना और बसना

अधिरोपित करने के लिए अधिकृत करता है

भारत। और खंड *(5)*

इन अधिकारों में

"उचित प्रतिबंध "

द.

पर

आम जनता के हितों या उनकी सुरक्षा के लिए

किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वे

मुख्य रूप से तथ्यात्मक एकता पर जोर देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे भारत के क्षेत्र का और एक के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए

भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए स्वतंत्र नागरिक

किसी भी बाधा से बाधित

जो

संकीर्ण मानसिकता वाले

प्रांतीयवाद हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है।

का उपयोग

विभिन्न *1* में शब्द "प्रतिबंध"

उपखंड प्रतीत होते हैं

यह इंगित करने के लिए कि लेख द्वारा गारंटीकृत अधिकार अभी भी प्रयोग किए जाने में सक्षम हैं, और कारावास के विचार को बाहर करने के लिए, हालांकि "प्रतिबंध" और "अभाव" शब्दों का उपयोग कभी-कभी विनिमेय शब्दों के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रतिबंध एक ऐसे बिंदु तक पहुंच सकता है जहां यह वंचित होने के बराबर हो सकता है। समग्र रूप से पढ़ें और समूह के बीच इसकी सेटिंग में देखें

"स्वतंत्रता के अधिकार" से संबंधित प्रावधानों *(*अनुच्छेद *19-22)* के संबंध में, अनुच्छेद *19* मेरे दिमाग में पहले से ही यह मानता है कि जिस नागरिक को इन मौलिक अधिकारों का अधिकार सुरक्षित है, वह आधार *192* को बरकरार रखता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिस पर ही इन अधिकारों का आनंद अनिवार्य रूप से निर्भर करता है। यह कहा गया था कि उपखंड *(*च*)* इस दृष्टिकोण के खिलाफ विद्रोह करेगा, क्योंकि "संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान" के अधिकार का आनंद मालिक की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने पर निर्भर नहीं करता है। चल संपत्तियों के संबंध में यह धारणा स्पष्ट रूप से गलत है, और यहां तक कि अचल वस्तुओं के संबंध में भी वह उन्हें जेल की सलाखों के पीछे से प्राप्त या निपटान नहीं कर सकता था; न ही वह उन पर अधिकार और नियंत्रण के अधिकारों का प्रयोग करने के अर्थ में उन्हें "पकड़" सकता था जो इस संदर्भ में शब्द का अर्थ प्रतीत होता है। लेकिन जहां अपराध करने या अन्यथा करने के लिए दंड के रूप में, नागरिक को कानूनी रूप से अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, वहां अब खंड *(1)* में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग या उन्हें लागू करने का कोई सवाल नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना, मेरी राय में, अनुच्छेद *19* के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाद के अनुच्छेद *20* और *21* द्वारा निपटा गया है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *19* नागरिकों को कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं का आनंद लेने की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद सभी व्यक्तियों-नागरिकों और गैर-नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं-दंड और अपराध की रोकथाम के लिए कुछ संवैधानिक गारंटी। अलग-अलग मानदंड प्रदान किए गए हैं जिनके द्वारा दोनों क्षेत्रों में विधायी निर्णयों को मापना है, और एक निर्माण जो

किए गए अपराध के दंड में या अपराध की रोकथाम में अनुच्छेद *19* के भीतर कारावास लाएगा।

धमकी देना, जैसा कि मुझे लगता है, उस प्रावधान को बेतुका बना देगा। यदि कारावास को अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में उल्लिखित अधिकारों का "प्रतिबंध" माना जाता है, तो यह समान रूप से अन्य उप-धाराओं द्वारा उल्लिखित अधिकारों पर भी प्रतिबंध होगा।

खंड। खंड *(1)* के अनुसार, जिसके परिणामस्वरूप सभी दंडात्मक कानून सजा के रूप में कारावास का प्रावधान करते हैं। खंड *(2)* से खंड *(6)* की वैधता स्वीकार किए जाने से पहले उन्हें लागू करना होगा। उदाहरण के लिए,

चोरी के लिए कैद करने वाली विधि, उस दृष्टिकोण पर, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध को मंजूरी देने वाली विधि के रूप में खंड *(2)* के तहत न्यायसंगत होगी। में।

विलेख, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, हाल ही में हमारे संज्ञान में लाए गए एक गैर-सूचित निर्णय में, एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

193

सुरक्षा को कम करने का परीक्षण लागू किया

राज्य या निर्धारण में इसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति

द.

आक्षेपित अधिनियम की वैधता या अन्य ज्ञान। सीखना।

न्यायाधीशों ने अनुच्छेद *19* का अर्थ इन मामलों को शामिल करने के रूप में लगाया -

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित और तार्किक रूप से आयोजित

पर्याप्त है कि लेखक द्वारा आक्षेपित अधिनियम के रूप में

निवारक निरोध, मुक्त होने के अधिकार का उल्लंघन

वाणी और अभिव्यक्ति के आधार पर इसकी वैधता होनी चाहिएखंड *(2)* में आरक्षण द्वारा न्याय किया गया, और जैसा कि यह

उस कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहा, यह असंवैधानिक और अमान्य था।

श्री नाम्बियार ने इतनी दूर जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चित्र बनाए।

उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के बीच अंतर

*((*घ*)* और अन्य उपखंडों द्वारा प्रदत्त।

वह.

ब्लैकस्टोन की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए आग्रह किया कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता में "किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करना" शामिल है।

किसी का झुकाव किसी भी स्थान की ओर हो,

और कि कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति को वंचित करता है

गति की ऐसी शक्ति का सीधा आक्रमण था

उपखंड *(घ)* में उल्लिखित अधिकार, जबकि यह अंतर

केवल अप्रत्यक्ष रूप से और इसके परिणामस्वरूप

अन्य उपखंडों में उल्लिखित अधिकार। वहाँ है।

सुझाए गए भेद में कोई सार नहीं है। यह होगा

अतार्किक, अनुच्छेद *19* के अर्थ में, विशेषता के लिए। इनमें से एक

उपखंड एक दायरा

और प्रभाव पूरी तरह से अलग है

दूसरों का दायरा और प्रभाव या एक अंतर आकर्षित करने के लिए

समूह में एक अधिकार और दूसरे के बीच संबंध। सभी

खंड *(1)* में उल्लिखित अधिकार समान रूप से आवश्यक हैं।

किसी भी व्यक्ति में

सभ्य और लोकतांत्रिक समुदाय की स्वतंत्रता में तत्व, और कैद उन सभी के समान रूप से विलुप्त होने के रूप में काम करते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होना केवल उपखंड *(घ)* द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन दूसरों का नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह महसूस किया और

यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से तर्कसंगत थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या कारावास से वंचित करने के लिए प्रावधान करने वाली कानून की संवैधानिक वैधता का निर्णय न केवल अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* में बल्कि खंड *(2)* सहित अन्य खंडों में भी निर्धारित परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, हालांकि उनका प्रमुख आधार कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना एक

" अनुच्छेद *19* के अर्थ के भीतर "प्रतिबंध" है,

मेरा निर्णय, गलत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

यह कहा जाता था कि निवारक निरोध एक द्रास है

स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का प्रतिबंध, इसके "सार और सार" में, अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के भीतर पढ़ा गया था।खंड के साथ। *(5)* और अनुच्छेद *21* के भीतर नहीं जो अपराध और इसकी सजा और रोकथाम से संबंधित है। वहाँ

यहाँ, मेरी राय में, "पीठ और पदार्थ" के नियम को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम में बताया है। बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, खुलना *(1)*, सुब्रमण्यन में संघीय न्यायालय की टिप्पणियों को मंजूरी देते हुए

चेट्टियार वी. मुत्तुस्वामी गौंडन *(1)*, नियम था बोर्ड द्वारा यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया कि क्या एक इम्पू है

जी. एन. डी. क़ानून, अपने वास्तविक चरित्र में, इसके साथ कानून था

एक कानून के अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों के संबंध में

विभाजित विधायी की योजना में लैचर या कोई अन्य

अदालत ने क्या कहा

शक्ति। यहाँ इस तरह का कोई सवाल नहीं है।

यह पता लगाना है कि क्या वास्तविक दायरा है

और इसका अर्थ

भाग *III* के संदर्भ में अनुच्छेद *19*

संविधान का,

यह तय करने के लिए कि क्या व्यक्तिगत अभाव स्वतंत्रता उस अनुच्छेद के भीतर आती है, और पीठ और

पदार्थ नियम सहायक से अधिक भ्रामक होगाउस मुद्दे का निर्णय। अनुच्छेद *19*, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, अधिक आयात के लिए सुरक्षा की गारंटी देता है।

आनंद में रहने वाले नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रताएँ

उनकी स्वतंत्रता की, जबकि एक ही समय में प्रतिबंधों को निर्धारित करते हुए जो विधायिका ठीक से कर सकती है

ऐसे अधिकारों के प्रयोग पर अधिरोपित करना, और इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता या कारावास से वंचित होने से कोई लेना-देना नहीं है, जिसके बारे में बाद के तीन अनुच्छेदों में बताया गया है।

एक और विचार भी है जो इंगित करता है

उसी निष्कर्ष पर। संविधान सभा की मसौदा समिति, जिसकी रिपोर्ट का संदर्भ तर्क के दौरान दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था, ने सिफारिश की कि "स्वतंत्रता शब्द को इसके सामने 'व्यक्तिगत' शब्द को सम्मिलित करके जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा इसका बहुत व्यापक रूप से अर्थ लगाया जा सकता है ताकि अनुच्छेद *13 (*अब अनुच्छेद *19)* में पहले से ही वर्णित स्वतंत्रताओं को भी शामिल किया जा सके। इस सुझाव की स्वीकृति से पता चलता है कि जो कुछ भी आम तौर पर स्वीकार किया जा सकता है

(2) [1940] एफ. सी. आर. *188*

(1) 74 आई. ए. *23.*

195

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की, यह

अर्थ

जिसमें शामिल नहीं है

अनुच्छेद *21* में एक अर्थ में उपयोग किया गया था

अनुच्छेद *19* के साथ, अर्थात,

स्वतंत्रताओं का निपटारा किया गया

भाग *III* के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता

संविधान भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता से कुछ अलग है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद *19* घोषित किया गया था

अनुच्छेद के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार

उनके खिलाफ

प्रक्रिया प्रदान की गई

सुरक्षा

21

के बीच संबंध का यह दृष्टिकोण

अभाव।

दो अनुच्छेदों को कुछ न्यायाधीशों का समर्थन मिला है

एक्ट करें। तथापि, यह देखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद *19* उसमें केवल नागरिकों को निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है।

और सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता-नागरिक और गैर-नागरिक नागरिक भी। इस प्रकार, दोनों लेख में काम नहीं करते हैं

एक अंतहीन क्षेत्र, और यह अस्वीकार करने का एक कारण हैसहसंबंध का सुझाव दिया गया। फिर से, यदि अनुच्छेद *21* होना है

केवल प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने के रूप में समझा जाता है,

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहाँ है

संविधान में गैर-नागरिक पाए जाएँगे*?* क्या वे हैं*?*

इस तरह के अधिकार से पूरी तरह से इनकार किया गया*?* अगर वे

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, क्यों है

नहीं है।

अनुच्छेद *21* में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई है*?*

और वह सबसे मौलिक अधिकार कहाँ है,

संविधान में प्रदत्त जीवन का अधिकार*?* द.

सच्चाई यह है कि अनुच्छेद *21,* अपने अमेरिकी प्रोटोटाइप की तरह

संविधान के पाँचवें और चौदहवें संशोधन

संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्यूशन, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है

उसी में प्रक्रियात्मक और मूल अधिकारों का संलयन

प्रावधान। जीने का अधिकार, हालांकि सबसे बुनियादी

और इसकी सुरक्षा आम तौर पर एक घोषणा का रूप लेती हैराशन कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा

कानून की उचित प्रक्रिया या कानून के अधिकार द्वारा। प्रक्रिया

या इस संदर्भ में "प्रक्रिया" दोनों अधिनियम को दर्शाती है।

और एक आदमी को ले जाने के लिए आगे बढ़ने का तरीका

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और पहला और आवश्यक

ऐसे वंचितों के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कदम

परिवर्तन एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया कानून होना चाहिए।

8-3 एस. सी. इंडिया/*58 196*

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के अभाव को अधिकृत करना। यह मुझे अनुच्छेद *21* और *22* पर विचार करने के लिए लाता है, जिसके लिए बार में बहस का अधिकांश भाग मतदान किया गया था।

ये लेख इस प्रकार हैं:

" 21. किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा या

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

22. (1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

बिना सूचित किए हिरासत में रखा गया,

जितनी जल्दी हो

ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार हो सकते हैं। न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसकी रक्षा करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है

अभिरक्षा को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और

ऐसे व्यक्ति को हिरासत से परे हिरासत में रखा जाएगा

मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना कहा गया अवधि।

(3) खंड *(1)* और *(2)* में कुछ भी लागू नहीं होगा।

(क*)* किसी भी व्यक्ति के लिए जो कुछ समय के लिए एक है

दुश्मन विदेशी; या

(ख*)* गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत।

(4) निवारक निरोध के लिए कोई कानून नहीं

किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करेगा।

तीन महीने से अधिक की अवधि जब तक कि

(क*)* एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो

या के रूप में नियुक्त किए गए हैं, या नियुक्त होने के लिए योग्य हैं,

हैं,

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले सूचित किया है कि उनकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैः

बशर्ते कि इस उपखंड में कुछ भी नहीं होगा

इससे परे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करना

द्वारा बनाई गई किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि

खंड *(7)* के उपखंड *(*बी*)* के तहत संसद*;* या

(ख*)* ऐसे व्यक्ति को इसके अनुसार हिरासत में लिया जाता है -

संसद द्वारा उप के अधीन बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान

खंड *(7)* के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)*।

197

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

(5 *)* जब किसी व्यक्ति को अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत किया गया आदेश, आदेश देने वाला प्राधिकारी,

के रूप में

ऐसे व्यक्ति से संवाद करें

जितनी जल्दी हो सके,

आदेश दिया गया है और होगा

जिसके आधार पर

एक बनाने का सबसे पहला अवसर

उसे दे दोआदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व।

(6) खंड *(5)* की किसी भी बात के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

तथ्यों को प्रकट करने के लिए ऐसा कोई आदेश देना जिसे उस खंड में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है।

(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क*)* जिन परिस्थितियों में, और वर्ग

एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है

या उन मामलों के वर्ग जिनमें,

किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बिना प्राप्त किए निवारक निरोध का प्रावधान करना

ए की राय। सलाहकार बोर्ड के अनुसार

खंड *(4)* के उपखंड *(*क*)* के प्रावधानः

(ख*)* अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई भी व्यक्ति

किसी भी वर्ग या मामलों के वर्गों के तहत हिरासत में लिया जा सकता हैनिवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई कानून*;* और

(ग*)* एक सलाहकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

खंड *(4)* के उपखंड *(*ए*)* के तहत एक जांच में बोर्ड। ”

श्री नाम्बियार ने आग्रह किया कि *"*कानून*"* शब्द में

अनुच्छेद *21* को समझा जाना चाहिए*,* न कि एक के अर्थ में अधिनियमन लेकिन अपरिवर्तनीय और अविभाज्य के प्रतीक के रूप में

प्राकृतिक न्याय के साल सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय

नागरिक कानून-और यह कि अभिव्यक्ति

" प्रक्रिया

कानून द्वारा स्थापित *"*का अर्थ है

एक ही बात

जैसी चीज़

वह प्रसिद्ध वाक्यांश

" देय

कानून में

प्रक्रिया

प्रक्रियात्मक पहलू।

अमेरिकी संविधान में

अमेरिका के कई फैसले

यह दिखाने के लिए उद्धृत किया गया था कि

वाक्यांश ने मूल को निहित किया

(1) की आवश्यकताएँ

आचरण का मानक

उद्देश्यपूर्ण और सुनिश्चित करने योग्य

जिसके अनुरूप होना संभव है, *(2)* पक्ष को नोटिस

उसके खिलाफ आरोप, *(3)* एक उचित अवसर

उसके लिए अपनी बेगुनाही स्थापित करने के लिए, और *(4)* एक

निष्पक्ष न्यायाधिकरण निष्पक्ष निर्णय देने में सक्षम है। मन में। श्री नाम्बियार ने स्वीकार किया कि ये आवश्यकताएँ

प्रकृति के अनुरूप संशोधित या अनुकूलित करना पड़ सकता है

विशेष कार्यवाही और उसका उद्देश्य

YE [1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

198

उदाहरण के लिए, निवारक निरोध के मामले में, पूर्व सूचना, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति भूमिगत हो सकता है, को हटा दिया जा सकता है।विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का मूल होने के नाते इन आवश्यकताओं का राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानूनों से परे होने के कारण, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून द्वारा काफी हद तक पालन किया जाना चाहिए।

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना, विषय,

बेशक, संविधान में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के लिए उन्हें किसी भी स्थिति में छूट या छूट देने की मंजूरी देना।

मामलों का मामला या वर्ग। उन्होंने मुखपत्र से भी अपील की अपने अंतर में मार्गदर्शक सितारे के रूप में संविधान का मिश्रण

अपने शोध प्रबंध का समर्थन करने का नाटक कि,

लोकतांत्रिक संविधान जिसे भारत के लोगों ने खुद को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए दिया है जो न्यायसंगत हैं, भाग *III* के प्रावधानों को इस रूप में माना जाना चाहिए:

विधायी इच्छा के लिए सर्वोपरि,

अन्यथा ऐसा ही

जिसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहा जाता है, उसे विधायी कार्रवाई के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं होगी और अनुच्छेद *13 (2)* को निरर्थक बना दिया जाएगा।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत के लोग

प्रस्तावना में व्यक्त अपनी संप्रभु इच्छा का प्रयोग करते हुए, लोकतांत्रिक आदर्श को अपनाया है जो नागरिक को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और अभिव्यक्ति के साधन के रूप में व्यक्ति की गरिमा और अन्य पोषित मानवीय मूल्यों का आश्वासन देता है, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान में अपनी-अपनी शक्तियां सौंपते हुए, कुछ मौलिक अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें मैं मानता हूं, क्योंकि उन्हें बरकरार रखा गया है।

लोगों द्वारा और प्रत्यायोजित शक्तियों को सर्वोपरि बनाया गया, जैसा कि अमेरिकी मॉडल में है। मैडिसन *(*जिन्होंने प्रथम संशोधन को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई*)*

अमेरिकी संविधान*)* ऐतिहासिक कारणों से, "लोगों के महान और अनिवार्य अधिकारों" को सुरक्षित करने के अमेरिकी और ब्रिटिश तरीकों के बीच अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि "यहां वे विशेषाधिकार के लिए सर्वोपरि कानूनों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि

कानून के लिए संविधान सर्वोपरि है: रिपोर्ट करें।

उस पर

वर्जीनिया संकल्प, नियर वी में उद्धृत। मिनेसोटा *(1)*।

(1) 283 U.S.697।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

199

एस सी आर। भारतीय संविधान के भाग *III* में इसका सकारात्मक कानून में अनुवाद किया गया है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि इन प्रावधानों को सही ठहराते हुए प्रस्तावना के उच्च उद्देश्य और भावना के साथ-साथ

मौलिक अधिकारों की घोषणा के संवैधानिक महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, इसका यह कहना नहीं है कि प्रावधानों की भाषा का विस्तार किया जाना चाहिए

इस या उस के साथ वर्ग

संविधान में संवैधानिक सिद्धांत

किसी भी अधिनियम, संवैधानिक या अन्य अन्य अधिनियम की व्याख्या के मूल नियम के संबंध में, कि उसकी भावना,

नहीं।

इसके आशय से कम को मुख्य रूप से उपयोग किए गए शब्दों के प्राकृतिक अर्थ से एकत्र किया जाना चाहिए।

हालाँकि, इन सिद्धांतों को पूरा प्रभाव देते हुए, मैं

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुच्छेद *21* में "कानून" शब्द का अर्थ प्राकृतिक न्याय के अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए लिया जाना चाहिए जिसकी एक वैधानिक उत्पत्ति है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया ज्ञात नहीं है या ऐसी अस्पष्ट और अनिश्चित द्वारा स्थापित की गई है।

" अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक सिद्धांत

अवधारणाएँ

प्राकृतिक न्याय "। मेरी राय में, अनुच्छेद *21* में "कानून" का अर्थ है "सकारात्मक या राज्य द्वारा निर्मित कानून"।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी न्यायाधीशों ने अपनाया है

देय की उनकी व्याख्या में अन्य अर्थ

संशोधन करें।

पाँचवीं और चौदहवीं में प्रक्रिया खंड

अमेरिकी संविधान के विचार *("*न

क्या कोई

व्यक्ति जीवन से वंचित हो जाता है। कानून की उचित प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता या संपत्ति। लेकिन उस खंड के पीछे एक विकासवादी इतिहास है। इस वाक्यांश का पता *28* एडब्ल्यू से लगाया गया है। *III* च। *3* , और कोक ने अपने संस्थानों में जॉन के महान चार्टर में "देश का कानून" अभिव्यक्ति के साथ इस शब्द की पहचान की। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी जहाँ संसद की विधायी सर्वशक्तिमानता है

है।

अब दृढ़ता से स्थापित। .

कोक इन शब्दों को समझता था

एक अंतर्निहित अर्थ के रूप में

सभी विधानों पर सीमा,

और डॉ. बोनहैम में शासन किया

मामला *(1)* कि "सामान्य

कानून अधिनियमों को नियंत्रित करेगा

संसद और कभी-कभी

उन्हें पूरी तरह से निर्णय दें

शून्य जब वे खिलाफ हैं

सामान्य अधिकार और

कारण "। हालांकि यह सिद्धांत

बाद में इंग्लैंड में एक चेतावनी के रूप में खारिज कर दिया गया था

(1) 8 प्रतिनिधि। *118 (* ए*)*।

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

200

इसके बजाय एक प्राधिकरण का पालन किया जाना चाहिए *"[*ली बनाम में जे. विल्स के अनुसार। दोस्त और टॉरिंगटन रे। *(1)* इसने अमेरिका में शुरुआत में क्रांतिकारियों के हाथों में एक हथियार के रूप में आधार प्राप्त किया, जिसके साथ संसद के कानूनों का विरोध किया जा सकता था, और बाद में न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए न्यायाधीशों के हाथों में एक उपकरण के रूप में। बैल *(*)]*। *19* वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, एक दिव्य सामान्य कानून या प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को पांचवें और चौदहवें संशोधनों में आने वाले वाक्यांश "कानून की उचित प्रक्रिया" के अर्थ में अवशोषित किया गया था। उन्हें बिछाकर

"देय" शब्द पर चरण, प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के रूप में "कानून" की व्याख्या करना और देना "स्वतंत्रता" और "संपत्ति" शब्दों का व्यापक अर्थ है, न्यायाधीशों ने उचित प्रक्रिया खंड को सभी विधायी शक्तियों पर एक सामान्य प्रतिबंध बना दिया है। और जब उस शक्ति को उचित प्रक्रिया की ज्यादतियों से झुकने का खतरा था, तो "पुलिस शक्ति" का समान रूप से अस्पष्ट और व्यापक सिद्धांत, यानी सार्वजनिक रूप से निजी अधिकारों को विनियमित करने की सरकार की शक्ति।

ज्यादतियाँ। सभी

ब्याज, इस तरह का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था

इसकी आलोचना महान अनसर को पेश करने के रूप में की गई है।उस देश में कानून की स्थिति में कमी, नहीं

यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कानून की उचित प्रक्रिया कैसे प्रभावित करेगी

एक विशेष अधिनियम। वाक्यांश के एक सदी बाद

न्यायिक व्याख्या का विषय रहा था

विद्वान न्यायाधीश ने *1877* में कहा कि यह अक्षम थासटीक परिभाषा और इसका आशय और अनुप्रयोग

केवल क्रमिक प्रक्रिया से पता लगाया जा सकता है

समावेशन और बहिष्करण *"[*डेविडसन बनाम। न्यू ऑरलियन्स *(3)]*

और, हाल ही में *1948* में, एक अन्य न्यायाधीश ने

अस्पष्ट आकृति को निश्चितता देने में कठिनाई

उचित प्रक्रिया "और" पर निर्णय कताई

उस गॉसमर अवधारणा से कार्रवाई का वर्णन कीजिए: "हेली वी.ओहायो राज्य *(ए)*।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है।

कि

द्वारा नियुक्त प्रारूपण समिति

संविधान

प्रतिस्थापन की सिफारिश की गई

भारत की सभा

अभिव्यक्ति का "। प्रक्रिया को छोड़कर

(1) (1871) एल. आर. *6* सी. पी. *576*। *582*।

(3) 96 यू. एस. *97*

(3) (1798) 3 दलहास *'86*।

*(*) 332 U.S.596*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

201

एस सी आर।

"उचित प्रक्रिया के बिना" शब्दों के लिए जापानी संविधान, *1946* से लिए गए कानून द्वारा स्थापित

जो हुआ

मूल मसौदा, "के रूप में

कानून का "

पहला अधिक विशिष्ट है। "

अपनी रिपोर्ट में

समिति ने कहा कि वे

कोशिश की है

(मौलिक

अधिकार*)* और

इन अधिकारों को बनाएँ

जिन सीमाओं के लिए वे आवश्यक रूप से यथासंभव निश्चित होने चाहिए, क्योंकि न्यायालयों को उन पर निर्णय देना पड़ सकता है *"(*पैरा। *5)*। इन सभी विचारों के बावजूद, इस सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है कि

" अनुच्छेद *21* में "कानून" का अर्थ है न्याय प्राकृतिक।

सिविल विधि का, और यह कि "विधि द्वारा स्थापित समर्थन के अनुसार" वाक्यांश अपने प्रक्रियात्मक पहलू में विधि की उचित प्रक्रिया के समतुल्य है,

इसके लिए

हमारे संविधान में उन "सूक्ष्म और मायावी मानदंडों" को शामिल करने का प्रभाव जो उस वाक्यांश में निहित थे, जिनसे बचना हमारे संविधान निर्माताओं का जानबूझकर उद्देश्य था।

सुझाए गए

दूसरी ओर, व्याख्या

मध्यस्थ की ओर से महान्यायवादी द्वारा कि अभिव्यक्ति का अर्थ है

प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं

बनाए गए किसी भी कानून द्वारा निर्धारित

एक सक्षम विधायिका द्वारा

" " स्थापित "" के अनुसार

शायद ही अधिक स्वीकार्य है।

अर्थात् विहित, और यदि संसद या

उसे,

किसी राज्य के विधानमंडल ने एक प्रक्रिया अधिनियमित की, हालांकि, आरोपी व्यक्ति को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए नई और अप्रभावी, यह किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविधान सभा ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को निश्चित रूप से खारिज कर दिया जब उसने "कानून की उचित प्रक्रिया" वाक्यांश को खारिज कर दिया और विधायी इच्छा को अपरिवर्तनीय बना दिया, बशर्ते कि केवल "कुछ प्रक्रिया" निर्धारित की गई हो। द इंडियन

इस प्रकार अंग्रेजी को प्राथमिकता दी

संविधान

संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, वाक्यांश

" कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में अंग्रेजी दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, अर्थात कोई भी प्रक्रिया जिसे संसद निर्धारित करने के लिए चुन सकती है। विद्वान वकील ने "ऐतिहासिक पृष्ठभूमि" को समझाने के लिए सदन के पटल पर विधानसभा के कई सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक भाषण *[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

202

किसी विधेयक पर बहस के दौरान किया गया कार्य सबसे अच्छा इसके व्यक्तिपरक इरादे का संकेत हो सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह विधेयक को ले जाने वाले बहुमत के मत के पीछे पड़ी निष्क्रिय मानसिक प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सका। न ही यह मान लेना उचित है कि उन सभी विधायकों के मन सहमत थे। न्यायालय केवल मुख्य रूप से अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों में विधायिका के वस्तुनिष्ठ इरादे की खोज कर सकता है, जो वैधानिक समितियों की रिपोर्ट, प्रस्तावना आदि जैसी ऐतिहासिक सामग्री द्वारा सहायता प्राप्त है। मैं कोई आई. एम. संलग्न नहीं करता

इसलिए, अनुच्छेद *15 (*अब अनुच्छेद *21)* पर बहस के दौरान संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों का उल्लेख करें।

मुख्य कठिनाई जो मुझे स्वीकार करने में महसूस होती है

महान्यायवादी द्वारा सुझाया गया निर्देश यह है कि यह अनुच्छेद *13 (2)* और वास्तव में मौलिक अधिकार की अवधारणा को पूरी तरह से बाधित करता है। यह उस अवधारणा का सार है कि यह सामान्य विधान द्वारा उल्लंघन के खिलाफ संविधान के मानसिक कानून द्वारा संरक्षित है। यह कहना सही नहीं है कि संविधान ने

पार्लिया मानसिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। जहाँ तक, किसी भी तरह से, जैसा कि भाग *III* का संबंध है, संविधान, जैसा कि मैं पहले ही देख चुका हूँ, ने मौलिक अधिकारों के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। अनुच्छेद *13* और *32* के प्रावधान इसे उचित रूप से स्पष्ट करते हैं। क्या तब यह संविधान निर्माताओं का इरादा हो सकता था कि जीवन और व्यक्तिगत जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता विधायी बहुमत की दया पर होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में, यदि "स्थापित" का अर्थ केवल "निर्धारित" होता तो वे होतीं? . दूसरे शब्दों में, जैसा कि एक अमेरिकी न्यायाधीश ने इसी तरह के संदर्भ में कहा, क्या अनुच्छेद *13 (2)* में संवैधानिक निषेध "आप जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीनेंगे जब तक कि आप इसे छीनने का विकल्प नहीं चुनते हैं", जो केवल शब्दशः है। यह कहना कोई ठोस जवाब नहीं है कि यदि अनुच्छेद *21* विधायी आक्रमण से सुरक्षित कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं होगा।

अनुच्छेद *13 (2)*। यह तर्क, मेरे विचार से, सवाल उठाने के लिए प्रतीत होता है, क्योंकि यह मानता है कि लेख में ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद *21* प्रदान करता है

में सक्षम विधायी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण

कोई सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट नहीं

203

एस सी आर। मूल दांडिक विधि का क्षेत्र, क्योंकि ऐसी विधियों की, जैसा कि अनुच्छेद *19* में प्रगणित अधिकारों के मामले में है, तर्कसंगतता या अन्यथा के आधार पर न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह मानते हुए भी कि विद्वान महान्यायवादी का निर्माण पूरी तरह से अप्रभावी और भ्रामक होने का प्रभाव डालेगा, यहां तक कि प्रक्रियात्मक संरक्षण भी जिसे लेख निस्संदेह वहन करने के लिए बनाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद *31* में "कानून" जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को "कानून के अधिकार के अलावा" उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका अर्थ अधिनियमित कानून होना चाहिए और यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है।

लैटिव एक्शन, उसके जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी अधिक प्रतिरक्षा का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। उपमा यह है कि

गुमराह कर रहे हैं। अनुच्छेद *31* के खंड *(2)* में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है और यह अधिकार न्यायसंगत है।

खंड *(4)* और *(6)* में उल्लिखित दो मामलों को छोड़कर जो एक अस्थायी चरित्र के हैं। संविधान अतः उक्त अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार की राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी भ्रामक या अप्रभावी नहीं है।

के रूप में

खंड *(1)* अपने आप में इसे प्रकट कर सकता है, यह मानते हुए भी कि "विधि" का अर्थ सामान्य विधान है।

आयरिश मामले पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी

राजा वी। हरे पार्क कैम्प *(1)* के सैन्य गवर्नर, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *1922* के आयरिश संविधान के अनुच्छेद *6* में "कानून" शब्द जो यह प्रावधान करता है कि "व्यक्ति की स्वतंत्रता अलंघनीय है और किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि उसके अनुसार

संसद द्वारा अधिनियमित

एक कानून का मतलब है

और इसलिए *1924* का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने इसका पालन किया

राजा वी। हैलिडे *(2)* जहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि राज्य की रक्षा *(*एकीकरण*)* अधिनियम, *1914* और उसके तहत बनाए गए विनियम बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियमों और मैग्ना कार्टा का उल्लंघन नहीं करते हैं "इस साधारण कारण से कि अधिनियम और आदेश देश के कानून का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि, जैसा कि लॉर्ड डुनेडिन ने बताया था, "ब्रिटिश संविधान ने संसद के दोनों सदनों को मंजूरी के अधीन सौंपा है।

*(*) [1917]* ए. सी. *260*

(1) [1924] 2 आई. आर.*: 104 .*

204

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

राजा की, एक पूर्ण शक्ति जो किसी के द्वारा सीमित नहीं है

लिखित उपकरण आज्ञाकारिता जिसके प्रति आज्ञाकारिता हो सकती है

किसी न्यायिक निकाय द्वारा खदेड़ा गया ", जबकि आयरिश

संविधान ने विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित किया

मानसिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करके संविधान का उल्लंघन करने वाला कानून

(अनुच्छेद *65)*।

इस मौलिक भेद को नजरअंदाज कर दिया गया था।

महान्यायवादी ने आगे कहा कि, यहाँ तक कि

उनकी व्याख्या पर, अनुच्छेद *21* एक संरक्षण होगा।

कार्यपालिका द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध औरव्यक्तियों, और यह पर्याप्त औचित्य होगा

मौलिक सुरक्षा के रूप में लेख की श्रेणीकरण। वहाँ

सुझाव में कोई सार नहीं है। जैसा कि बताया गया है।

एशुगबायी एलेको बनाम। नाइजीरिया की सरकार *(*अधिकारी*)*प्रशासन*) (1),* कार्यपालिका केवल इसमें कार्य कर सकती थी

कानून द्वारा दी गई शक्तियों का पालन और कोई स्थायी नहीं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक सुरक्षा की वास्तव में आवश्यकता है।

यहाँ तक कि राजतंत्रीय ब्रिटेन ब्रिटेन में भी दोनों के बीच संघर्ष

विशेषाधिकार और कानून लंबे समय से इसके पक्ष में समाप्त हो गया है

" ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार "

बाद वाला।

ऊपर बताए गए मामले में लॉर्ड एटकिन ने कहा, "कोई सदस्य नहीं है।

कार्यपालिका स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है या

शर्त को छोड़कर विषय

एक अंग्रेज की संपत्ति

कि वह समर्थन कर सकता है

एक से पहले उसकी कार्रवाई की वैधता

न्याय की अदालत "।

जहां तक इंडिवी के खिलाफ सुरक्षा की बात है

युगल, यह सोचना एक गलत धारणा है कि संवैधानिक

व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा उपाय निर्देशित किए जाते हैं।

वे हैं।

एक नियम के रूप में राज्य और उसके अंगों के खिलाफ निर्देशित। व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग सामान्य कानून में की जानी चाहिए। इसलिए यह

इस सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है कि वह अनुच्छेद *21* केवल उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था

कार्यपालक या व्यक्तियों द्वारा। दूसरी ओर, संविधान के अग्रभाग में मौलिक अधिकारों की घोषणा को शामिल करने के साथ-साथ इन अधिकारों में विधायी हस्तक्षेप के खिलाफ एक स्पष्ट निषेध *(*अनुच्छेद *13)* और न्यायिक समीक्षा *(*अनुच्छेद *32)* के माध्यम से इस तरह के निषेध को लागू करने के लिए एक संवैधानिक मंजूरी का प्रावधान है।

(1) [1931] ए. सी. *662*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

205

एस सी आर।

अधिकार सामान्य राज्य के लिए सर्वोपरि होने चाहिएकानून।

इस मामले को मेरी सबसे सावधानी से देने के बाद और

चिंता से विचार करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्या के केवल दो संभावित समाधान हैं। सबसे पहले, दोनों पक्षों के लिए विवादित दो चरम स्थितियों के बीच मीडिया के माध्यम से एक संतोषजनक स्थिति "एस्ता ब्लिश्ड" शब्द पर जोर देने से पाई जा सकती है, जो कुछ हद तक दृढ़ता, स्थायित्व और सामान्य स्वीकृति का तात्पर्य है, जबकि यह क़ानून द्वारा उत्पत्ति को बाहर नहीं करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "

यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि क्या विशेषाधिकार है

राजा सम्राट बनाम में संदर्भित परिषद। बेनोआरी लाल शर्मा *(1)*

"सामान्य और

सुस्थापित

वे व्यवस्थित उपयोग

आपराधिक प्रक्रिया ", अर्थात,

और द्वारा स्वीकृत कार्यवाही के सामान्य तरीके

दंड प्रक्रिया संहिता जो सामान्य कानून है

उनकी प्रभुताएँ

देश में आपराधिक प्रक्रिया।

द्वारा परीक्षण के बीच अंतर का उल्लेख कर रहे थे

सरकार के एक अध्यादेश द्वारा प्रदान किए गए विशेष न्यायालय

न-सामान्य और सामान्य न्यायालयों द्वारा मुकदमा

दंड प्रक्रिया संहिता। इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती

यह दृष्टिकोण कि संहिता कोई एकल और एकल निर्धारित नहीं करती है

सभी प्रकार के मामलों के लिए प्रपत्र प्रक्रिया लेकिन प्रदान करता है

विभिन्न वर्गों के मामलों के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएँ।कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थिर कारकों के रूप में उभरते हैं।

उन सभी प्रक्रियाओं के लिए सामान्य, और वे बनाते हैं

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल। मैं समझता हूँ कि

इस दृष्टिकोण पर भी, व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता

विधायी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि

एक सक्षम विधायिका प्रक्रिया को बदल सकती है ताकि

यदि ऐसा मन हो तो सुरक्षा को कम करने के लिए। लेकिन,

जिस दृष्टिकोण से मैंने संकेत दिया है, वह परिवर्तन नहीं होना चाहिए

किसी विशेष उद्देश्य या अवसर के लिए तदर्थ,

लेकिन ए

प्रक्रिया के सामान्य कानून में परिवर्तन

कोड। जब तक ऐसा परिवर्तन प्रभावी नहीं होता है।

द.

अनुच्छेद *21* के तहत संरक्षण उपलब्ध होगा। द.

संवैधानिक संरक्षण के विभिन्न उपाय जो

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

अनुच्छेद *21* के तहत तीन तरीकों से व्याख्या की गई है

(1) [1945] एफ. सी. आर. *161,175*।

206

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

ऊपर उल्लिखित शायद एक ठोस उदाहरण द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया जाएगा। मान लीजिए कि अनुच्छेद *22 (1)* नहीं था और संसद ने एक अस्थायी उपाय के रूप में एक अधिनियम पारित किया, जिसमें कुछ मामलों में एक अभियुक्त व्यक्ति के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव के अधिकार को छीन लिया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार अधिनियम अनुच्छेद *21* में सन्निहित प्राकृतिक न्याय के अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अमान्य होगा, जबकि महान्यायवादी द्वारा तर्क दिए गए निर्माण पर, अधिनियम पूरी तरह से वैध होगा, जबकि, मैंने ऊपर संकेत दिया है कि अधिनियम यह बुरा होगा, लेकिन अगर रक्षा के इस तरह के अधिकार से इनकार को सामान्य कानून की एक सामान्य विशेषता बना दिया जाता है

संहिता की धारा *340 (1)* को निरस्त करके आपराधिक प्रक्रिया, अनुच्छेद *21* का संरक्षण करने के लिए शक्तिहीन होगा।

ऐसी विधायी कार्रवाई के खिलाफ। लेकिन एक मुफ्त में

लोकतांत्रिक गणराज्य प्रक्रिया के सामान्य कानून में इतना बड़ा बदलाव, हालांकि सैद्धांतिक रूप से संभव है, लाना मुश्किल होगा और यह व्यावहारिक होगा।

संरक्षण का

कठिनाई

यह होगा उपाय

अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त।

यह कहा गया था कि प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद *22* के खंड *(1)* और *(2)* कमोबेश

प्रावधान

अपराधी का

प्रक्रिया

कोड, और

यह

ओवरलैपिंग

होगा।

हो चुके हैं।

यदि अनुच्छेद *21* को लागू करने का इरादा था तो इससे बचा जा सकता है

जैसा कि ऊपर बताया गया है निर्माण। इस पर तर्क यह दिखता है कि,

जबकि संहिता के प्रावधान होंगे

सक्षम विधायी कार्रवाई द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, अनुच्छेद *22* के खंड *(1)* और *(2)* में सुरक्षा उपायों को, संवैधानिक होने के कारण, इसी तरह से निपटा नहीं जा सकता था और यह पर्याप्त रूप से बताता है कि उन सुरक्षा उपायों को क्यों माना जाता है

संविधान में जगह।

मेरे पास निर्माण का एकमात्र विकल्प है

ऊपर इंगित किया गया है कि, यदि किसी संवैधानिक उल्लंघन से बचना है, तो "कानून" के संदर्भ की व्याख्या एक संवैधानिक संशोधन के रूप में की जाएगी, क्योंकि यह केवल ऐसे संशोधन *(*अनुच्छेद *368)* के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो उल्लंघन किए बिना किसी मौलिक अधिकार को संशोधित या ओवरराइड कर सकता है।

अनुच्छेद *13 (2)*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

207

एस सी आर।

अगला सवाल यह उठता है कि प्रोटेक कितनी दूर है।

अनुच्छेद *21* के तहत, जैसा कि यह पाया गया है, निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

द.

विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद *21* निवारक निरोध पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, क्योंकि अनुच्छेद *22* खंड *(4)* से *(7)* निवारक निरोध के संबंध में संवैधानिक राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की एक पूरी संहिता बनाता है।

और, बशर्ते केवल इन प्रावधानों का पालन किया जाए, निवारक निरोध से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। अनुच्छेद *21* की भाषा पूरी तरह से सामान्य है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता या कारावास से वंचित करना शामिल है।

दंडात्मक और निवारक दोनों कारणों से। अगर यह वास्तव में संविधान निर्माताओं का इरादा था आगंतुक निरोध के मामलों में अनुच्छेद *21* के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए, अनुच्छेद *22* के खंड *(3)* में अनुच्छेद *21* के संदर्भ को जोड़ने से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुच्छेद *(1)* और *(2)* के खंड किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है या अलग किया गया है। न ही अनुच्छेद *22* के खंड *(4)* से खंड *(7)* की भाषा में ऐसा कुछ भी है जो अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि

अनुच्छेद *21* निवारक डेंटेंशन पर लागू नहीं होता है।

ये खंड केवल पूर्व के कुछ पहलुओं से संबंधित हैं।

ऐसे निरोध की अवधि के रूप में गंभीर निरोध,

कुछ मामलों में निरोध के आदेश की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन, संचार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने के आधार और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर देने का प्रावधान। यह नहीं कहा जा सकता कि

ये प्रावधान एक विस्तृत संहिता बनाते हैं।

के साथ

निवारक निरोध और सुरक्षा से संबंधित सभी मामले

संरक्षण का पूरा क्षेत्र जो अनुच्छेद *21,* अंतर जिस अर्थ में मैंने संकेत दिया है

ऊपर, होगा

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए। इसलिए मैं

राय है कि अनुच्छेद *21* निवारक पर लागू होता है गिरफ्तारी भी।

अब मैं जाँच करूँगा कि क्या

याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है अनुच्छेद *21* और *22* द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को समाप्त करना।

इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा का उल्लंघन करता है। . द.

या *[1950]*

208

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में ध्यान में रखने योग्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निवारक निरोध दिया गया है

स्थिति. यह भयावह दिखने वाली विशेषता है।

संवैधानिक

एक लोकतांत्रिक संविधान में इतनी अजीब तरह से जगह से बाहर। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निवेश करता है

पवित्रता के साथ

मौलिक अधिकार और इसलिए

के साथ असंगत

इसकी प्रस्तावना के वादे हैं

निस्संदेह इसके लिए डिज़ाइन किया गया है

असामाजिक और उप-सामाजिक द्वारा

स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकें

वैकल्पिक तत्व जो हो सकते हैं

राष्ट्रीय खतरे

शिशु गणराज्य का कल्याण।

इस भावना में

अनुच्छेद *22* के खंड *(3)* से *(7)* का, मेरी राय में, जहां तक संभव हो, अर्थ लगाया जाना चाहिए और सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

के साथ

के वैध अभ्यास के लिए प्रदत्त संरक्षणव्यक्तिगत स्वतंत्रता। सबसे पहले, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है,

हिरासत में लिया गया व्यक्ति

अनुच्छेद *22* का खंड *(3)* खंड *(1)* और *(2)* में दिए गए सुरक्षा उपायों के लाभ से निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी भी कानून के तहत बाहर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसी अनुच्छेद का खंड *(5)* इन सुरक्षा उपायों से वंचित करने के लिए कुछ संशोधन करता है, जिसमें यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस आधार पर सूचित करने का प्रावधान करता है जिसके आधार पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा परामर्श करने और बचाव करने का महत्वपूर्ण अधिकार समाप्त हो गया है। इसी तरह, एक के अधिकार के बिना *24* घंटे की अवधि से अधिक हिरासत में हिरासत के खिलाफ निषेध

मजिस्ट्रेट को भी मामलों में ले जाया गया है

निवारक निरोध।

यह विवादित नहीं था कि,

खंडों के व्यक्त प्रावधान किस हद तक

(4) (7) के निरसन या संक्षिप्तकरण को प्राधिकृत करने के लिए

अन्य अनुच्छेदों या उप-अनुच्छेदों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय

संशोधित रूप में अन्य सुरक्षा उपायों का प्रावधान,

वे व्यक्त करते हैं

प्रावधानों को शासन करना चाहिए। चारों में से

उचित प्रक्रिया की आवश्यक बातें जिस पर श्री नांबियार

जोर देकर, *(*जो सामान्य का भी हिस्सा है और

दंड प्रक्रिया के तहत स्थापित प्रक्रिया

कोड, हालांकि मैं सहमत नहीं हो सकता कि वे अपरिवर्तनीय हैं

और विधायी परिवर्तन से परे*)* आवश्यकताएँ

स्थापित करने का अवसर

नोटिस देना और

उसका

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है,

लेने के लिए

बेगुनाही होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

209

एस सी आर।

अनुच्छेद *22* के खंड *(5)* द्वारा उपबंध किया गया है। जहाँ तक आचरण के एक निश्चित मानक का संबंध है जिसके अनुरूप होना संभव है, अनुच्छेद *22* कोई विशिष्टता नहीं देता है।

और अगर

निवारक निरोध के मामलों में प्रावधान,

में

इस तरह की सुरक्षा को कहा जा सकता है

अंतर्निहित

समझाया।

विधि द्वारा इस अर्थ में स्थापित प्रक्रिया

कोई शक नहीं।

ऊपर निवारक निरोध मामलों में, यह हो सकता है पुकारा जाता है। इस बिंदु पर विचार किया जाएगा।

वर्तमान में

सबसे महत्वपूर्ण, एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण है जो एक निष्पक्ष निर्णय देने में सक्षम है। यह, श्री नाम्बियार प्रस्तुत किया गया, अनुच्छेद *22* द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, खंड *(4) (ए)* में संदर्भित सलाहकार बोर्ड, उसके अनुसार, केवल निरोध की अवधि के प्रश्न से निपटने का इरादा रखता है, अर्थात, हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था या नहीं।

तीन महीने से अधिक समय तक संबंधित व्यक्ति को, और यह निर्णय लेने के लिए नहीं कि क्या व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है

निर्दोष था। एक न्यायाधिकरण जो उस मुद्दे पर एक निष्पक्ष निर्णय दे सकता था, अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा था, जिसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती है, और इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता *(Ch. VIII)*। द इम्पाग्ड

अधिनियम, जिसमें ऐसे न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है

कॉन्ट्रा

यह होगा।

अनुच्छेद *21* को रद्द कर दिया गया था और इसलिए यह अमान्य था। देखा कि यह पूरा तर्क इस पर आधारित है प्रमुख आधार कि सलाहकार बोर्ड में उल्लेख किया गया है

अनुच्छेद *22* का खंड *(4) (क)* निरोध के औचित्य के मुद्दे से निपटने के लिए अभिप्रेत न्यायाधिकरण नहीं है। क्या यह दृष्टिकोण सही है*?*

यह तर्क दिया गया था कि शब्द "पर्याप्त कारण"

खंड *(4)* के उपखंड *(ए)* में ऐसे निरोध के लिए तीन महीने से अधिक के निरोध का संदर्भ था। खंड *(4)* में कहा गया है कि इस दृष्टिकोण का समर्थन खंड *(7)* के उपखंड *(ए)* की भाषा द्वारा किया गया था जिसके द्वारा संसद परिधि निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

स्थिति जिसके तहत और मामलों के वर्ग या वर्ग जिसमें किसी व्यक्ति को सलाह के बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता हैबोर्ड। दूसरे शब्दों में, विद्वान विद्वान परामर्श प्रस्तुत किया, *[1950]*

210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड *(4)* और *(7)* का संयुक्त प्रभाव यह था कि किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता था।

महीनों तक एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना कि लंबी अवधि के लिए हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था, उन मामलों को छोड़कर जहां संसद ने एक सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी ऐसी अवधि के लिए हिरासत को अधिकृत करने वाला कानून पारित किया था।

इस प्रकार ये

अवधि के साथ

केवल दो खंड संबंधित थे निवारक निरोध का, और सलाहकार बोर्ड का भी, जो उन खंडों ने उस उद्देश्य के लिए प्रदान किया था। मैं हूँ।

इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ। मेरा झुकाव है

यह सोचें कि उपखंड *(ए)* में "ऐसी निरोध" शब्द खंड *(4)* में उल्लिखित निवारक निरोध को संदर्भित करते हैं और तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखने के लिए। न्यायाधीशों या वकीलों से बना एक सलाहकार मंडल शायद ही यह तय करने की स्थिति में होगा कि बचाव पक्ष से जुड़े कारणों से निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को कब तक ऐसा करना चाहिए।

यह कार्यपालिका के लिए एक मामला होना चाहिए

हिरासत में लिया जाए। अधिकारियों,

रक्षा विभाग, यह निर्धारित करने के लिए,

क्योंकि वे अकेले ही देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और उनके पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा है। वह सब एक सलाहकार बोर्ड

कर सकते हैं

उचित रूप से ऐसा करने के लिए कहा जाना, शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में, यह निर्णय करना है कि क्या निरोध उचित है और मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। यह तथ्य कि सलाहकार बोर्ड को तीन महीने की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट देनी होती है और इसलिए इसे केवल एक या दो दिन पहले प्रस्तुत कर सकता है, वैध रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि बोर्ड पूरी तरह से इस मुद्दे से संबंधित था कि हिरासत उस अवधि के बाद भी जारी रहना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि ऐसा कोई भी न्यायाधिकरण अपनी रिपोर्ट भेज सके, एक उचित समय समाप्त होना चाहिए, क्योंकि आधार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाना है, उसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को अपना प्रतिनिधित्व करना होगा जिसे उचित विभागीय चैनल के माध्यम से बोर्ड के सामने रखा जाना है। इनमें से प्रत्येक कदम में, आधिकारिक दिनचर्या के दौरान, कुछ समय लग सकता है, और तीन महीने की अवधि को बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता से पहले अनुमति देने के लिए एक उचित अवधि माना जा सकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, यह मानते हुए कि शब्द "इस तरह से रोके गए हैं"

निरोध की अवधि के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड द्वारा जांच को तीन महीने से अधिक की अवधि के एकमात्र मुद्दे तक सीमित रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, इस सवाल के संदर्भ के बिना कि क्या निरोध उचित था या नहीं। वास्तव में, यह कल्पना करना मुश्किल है कि कैसे एक न्यायाधिकरण निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए, यह विचार किए बिना कि क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था। मेरा मानना है कि सलाहकार मंडल ने इसका उल्लेख किया है

खंड *(4)* में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने पर कुछ मामलों में निवारक निरोध के आदेशों की समीक्षा के लिए संविधान द्वारा तैयार किया गया तंत्र है। यह वह दृष्टिकोण है जिस पर संसद ने विवादित अधिनियम को अधिनियमित करने में प्रगति की है जैसा कि इसकी धारा *9* और *10* से देखा जाएगा, और मुझे लगता है कि यह सही दृष्टिकोण है। यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद *21* या अन्यथा के आधार पर किसी अन्य निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा अपने मामले का निर्णय लेने का दावा नहीं कर सकता है।

श्री नाम्बियार ने हालांकि इस बात पर आपत्ति जताई कि इस दृष्टिकोण पर,

एक कानून किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा के लिए प्रावधान किए बिना तीन महीने के लिए निवारक निरोध को अधिकृत कर सकता है, और इससे भी अधिक अवधि के लिए यदि संसद एक अधिनियम पारित करती है जैसा कि खंड *(7)* के उप-खंड *(ए)* में विचार किया गया है। यह ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह का परिणाम व्यक्ति के दृष्टिकोण से कितना भी खेदजनक हो सकता है।

हिरासत में, कोई उपाय नहीं हो सकता है अगर, एक उचित परखंड *(4)* और *(7)* के निर्माण में पाया गया है कि संविधान व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई उच्च सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

विवादित के प्रावधानों के बगल में मुड़ना

जिसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, वह

अधिनियम,

केवल उन प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक होगा जो हमारे समक्ष याचिकाकर्ता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहलेजगह, यह तर्क दिया गया था कि धारा *3*, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सशक्त बनाती है

किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लें यदि वह "संतुष्ट" है कि उसे किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है।

9-3 एस. सी. इंडिया/*58 212*

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

) राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह धारा आचरण के किसी भी उद्देश्यपूर्ण और सुनिश्चित मानक को निर्धारित नहीं करती है जिसके अनुरूप होना संभव होगा, लेकिन हिरासत का आदेश देने के लिए इसे संबंधित सरकार की इच्छा और खुशी पर छोड़ देता है। तर्क इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून की उचित प्रक्रिया के बराबर है। मैंने पहले ही यह दिखाने का प्रयास किया है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा, तर्क इस बात को नजरअंदाज करता है कि निवारक निरोध के उद्देश्यों के लिए यह मुश्किल होगा,

अगर नहीं

आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमों को निर्धारित करना असंभव है जिसका पालन करने में विफलता से इस तरह की नजरबंदी होनी चाहिए। जैसा कि शब्द का तात्पर्य है, ऐसे मामलों में निरोध इस दृष्टि से किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को कुछ उद्देश्यों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार करने से रोका जा सके जो इस तरह के निरोध के लिए प्रावधान करने वाले कानून के विचार में हैं। न ही यह इंगित करना व्यावहारिक होगा या

पहले से गणना करें कि किन कृत्यों या कृत्यों के वर्गों को प्रतिकूल माना जाएगा। जिम्मेदारी

राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के रखरखाव के लिए कार्यकारी सरकार पर यह स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए कि जब भी उन्हें लगता है कि अवसर की आवश्यकता है तो निवारक निरोध की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उस सरकार को छोड़ दिया जाना चाहिए।

धारा *12* की काफी आलोचना हुई।

वह खंड, जो अवधि को नियंत्रित करता है

याचिकाकर्ता की नजरबंदी इस प्रकार हैः --

"कुछ मामलों में निरोध की अवधि। - कोई भी।

निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग के मामलों में या निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी नजरबंदी की तारीख से एक साल से अधिक नहीं, अर्थात्, जहां ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने की दृष्टि से हिरासत में लिया गया है।

(क*)* भारत की रक्षा, भारत के साथ संबंध

विदेशी शक्तियाँ या भारत की सुरक्षा*;* या

*((*ख*)* किसी राज्य की सुरक्षा या रखरखाव

सार्वजनिक व्यवस्था।

एस सी आर।

(2) ए के तहत हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला

निरोध आदेश जिसके लिए उप-धारा *(1)* के प्रावधान लागू होते हैं, उसकी निरोध की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, ऐसी सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया था, और जहां आदेश धारा *3* की उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जिसके लिए ऐसा अधिकारी अधीनस्थ है, किसी व्यक्ति के परामर्श से

या के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है या है

जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा उस ओर से नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है।

यह आग्रह किया गया था कि यह अनुपालन नहीं करता है

अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* की आवश्यकताएँ क्योंकि यह केवल सूची *I* की प्रविष्टि *9* और सूची *III* की प्रविष्टि *3* में उल्लिखित "मामलों" या विधायी विषयों को दोहराता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची। अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* के तहत संसद को उन परिस्थितियों को निर्धारित करना है जिनके तहत और

मामलों के वर्ग जिनमें "

या

किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

लंबा

बिना प्राप्त किए तीन महीने से अधिक

राय

एक सलाहकार मंडल। यह कहा गया था कि खंड

निवारक का

(4) (ए*)* साधारण सुगमताओं के लिए प्रदान किया गया

नज़रबंदी जहाँ ऐसी नज़रबंदी हो सकती है

जारी नहीं है

बिना प्राप्त किए तीन महीने से अधिक

की राय

एक सलाहकार बोर्ड, जबकि खंड *(7) (*ए*)* ने अधिक के लिए निरोध के विशेष मामलों के लिए प्रावधान किया

प्रतिकूल आचरण के बढ़े हुए रूपों के लिए सलाहकार मंडल की राय की सुरक्षा के बिना तीन महीने। दूसरे शब्दों में, खंड *(4) (ए)* ने नियम निर्धारित किया और खंड *(7) (ए)* ने एक अपवाद अधिनियमित किया।

यह था।

अतः संसद द्वारा इंगित करना आवश्यक है

के लिए

प्राधिकार को उसके मार्गदर्शन के लिए हिरासत में रखना, प्रतिकूल गतिविधि के अधिक आक्रामक रूप, और केवल उन विषयों का उल्लेख करना जिनके संबंध में संसद निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने के लिए विधायी सूचियों के तहत अधिकृत है, शायद ही ऐसे प्राधिकरण को कोई मार्गदर्शन दे सकता है और इसे खंड *(7)* की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जाना चाहिए। *214* में दो गुना भ्रांति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

यह तर्क। सबसे पहले, खंड *(4) (ए)* और खंड *(7) (ए)* के बीच एक नियम और एक अपवाद को अधिनियमित करने के रूप में सुझाए गए सहसंबंध,बिना नींव के निर्माण। खंड *(4)* और *(7)* को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि निवारक निरोध दो मामलों में लंबे समय तक चल सकता है: *(1)* जहाँ सलाहकार मंडल की राय प्राप्त की जाती है,

विषय

(ए) का

लेकिन एक निर्धारित अवधि *[*उपखंड खंड *(4)]* और *(2)* जहां एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है

ए के तहत

उपखंड *(क)* के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि

और *(बी)*

खंड *(7) [*खंड *(4)* का उपखंड *(ख)]*।

ये हैं।

दो अलग

और स्वतंत्र प्रावधान। यह है।

यह महत्वपूर्ण है कि खंड *(4)* के उपखंड *(ख)* को उसी खंड के उपखंड *(क)* के परंतुक या अपवाद के रूप में नहीं कहा गया है जैसा कि होता यदि वह

संचालन करने का इरादा। जैसे कि। खंड *(4) (*क*)* और खंड *(7) (*क*)* को एक नियम के रूप में सहसंबंधित करने का प्रयास और

अ.

अपवाद क्रमशः उन खंडों की भाषा और संरचना दोनों के खिलाफ है।

दूसरा, तर्क तथ्य की दृष्टि खो देता है।

वह खंड *(7)* निवारक निरोध से संबंधित है जो एक विशुद्ध रूप से एहतियाती उपाय है जिसे "सभी मामलों में, कुछ हद तक, सबूत से अलग संदेह या प्रत्याशा पर जानबूझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है" *[*प्रभु के अनुसार

आक्षेपित अधिनियम की धारा *3* में आचरण के वस्तुनिष्ठ नियम धारा *12* की इस आलोचना पर भी लागू होते हैं। यह होगा। विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख करना, या विभिन्न वर्गों की गणना करना, यदि अव्यावहारिक नहीं है, तो कठिन होगा।

ऐसे संपूर्ण मामले जिनमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाना चाहिए

व्यापक रूपरेखा को छोड़कर, निवारक उद्देश्यों के लिए तीन महीने से अधिक के लिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिंसक और विध्वंसक संगठन से संबंधित है।अपनी नीति के रूप में गतिविधि। पार्टी की अपनी सदस्यता के अलावा उस व्यक्ति ने तब तक कुछ नहीं किया होगा जब तक कि वह

गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। लेकिन अगर वह रिहा हो गया तो हो सकता है प्रीजुडी के सबसे हल्के रूप से कुछ भी करें

सियाल गतिविधि, जैसे कि एक आपत्तिजनक हैंडबिल चिपकाना

एक जमाखोरी, तोड़फोड़ के सबसे अपमानजनक कृत्यों के लिए।

(1) एल. आर. *1917* ए. सी. *260,275*।

215

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

प्रतिकूल गतिविधियों के बढ़े हुए रूपों की श्रेणियों की एक लंबी श्रृंखला की धारा *12* में सम्मिलन, या विभिन्न परिस्थितियों की गणना जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है, यह निर्धारित करने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को कोई सहायता कैसे हो सकती है कि क्या संबंधित व्यक्ति को तीन महीने के लिए या लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखा जाना चाहिए*?* इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक और पर्याप्त होगा वह यह है कि वह व्यक्ति है

ऐसे संगठन का एक सदस्य और शायद

सेक्यू के लिए प्रतिकूल विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न हों

राज्य का अधिकार या सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव

दूसरे शब्दों में, वह अनुभाग में वर्ग *(बी)* से संबंधित है

या,

जबकि गणना और वर्गीकरण विस्तार से

12 .

होगा।

निःसंदिग्ध रूप से सजा के वर्गीकरण में मदद करता है

किए गए अपराधों में, वे बहुत उपयोगी नहीं होंगेनिवारक निरोध की अवधि तय करना। पर्याप्त है।

ऐसे मामलों में मार्गदर्शन मोटे तौर पर भारतीय द्वारा दिया जा सकता है।

पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि की सामान्य प्रकृति का उल्लेख करना

जिसमें किसी व्यक्ति के शामिल होने की संभावना है, और वास्तव में वहसंसद ने धारा *12* में यही किया है। संदर्भ

इस संबंध में रक्षा के नियम *34* में बनाया गया था।

भारत रक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए भारत के नियम,

ब्रिटिश भारत की बाड़ या सार्वजनिक सुरक्षा या हित। सातवीं अनुसूची की सूची *I* और *III* में

संविधान में छह विषयों का उल्लेख किया गया है - संसद किन कानूनों के लिए प्रावधान कर सकती है

निवारक निरोध, और अभियुक्त की धारा *12*

या वे परिस्थितियाँ जिनमें लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है अधिकृत। मैं असफल हूँ।

यह देखने के लिए कि यह क्यों नहीं हो सकता है

मामलों के व्यापक वर्गीकरण के रूप में माना जाता है या

उन परिस्थितियों का विवरण जहाँ संसद विचार करती है

लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित होगा। एक वर्ग अच्छी तरह से हो सकता है

उस लक्ष्य के संदर्भ में निर्दिष्ट किया गया है जो कोई चाहता है

सुरक्षित करने के लिए, और वर्ग *(ए)* के रूप में संदर्भित मामले

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और *(बी)* धारा *12* की उप-धारा *(1)* का स्पष्ट रूप से

जिन उद्देश्यों को संसद सुरक्षित करना चाहती थी

धारा को लागू करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्गीकरण इस तरह के सामान्य उद्देश्यों के संदर्भ में कैशन नहीं है

अनुच्छेद *22 (7)* का उल्लंघन करें।

यह तर्क दिया गया था कि संसद ने अधिनियम में ऐसा नहीं किया

धारा *12* में, दोनों को निर्धारित करने का अपना कर्तव्य निभाएँ।

परिस्थितियाँ और वर्ग या वर्ग

मामलों की

प्राप्त करना

सलाह देना

जहाँ हिरासत में लिया गया है

बिना

बोर्ड की राय तीन से अधिक अवधि के लिए हो सकती है। महीनों तक। के बीच विभेदक "या" का उपयोग

शब्द "परिस्थितियाँ" और शब्द "वर्ग या वर्ग" यह कहा गया था कि मामलों से पता चलता है कि संसद

इस विचार पर आगे बढ़े कि इसे दोनों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

यह अनुच्छेद *22 (7)* का उल्लंघन था।

उन शब्दों के बीच संयुग्म "और" का उपयोग किया।

इस आपत्ति में कोई सार नहीं है। के रूप में

मैं अनुच्छेद *22 (7)* पढ़ता हूं जिसका अर्थ है कि संसद

या तो

कक्षाएँ

परिस्थितियाँ या

निर्धारित करें।

या दोनों, और अधिनियमन धारा में

में से

12

मामले

संसद ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित मामलों पर विचार किया

उप-धारा *(1)* के खंड *(ए)* और *(बी)* में पर्याप्त रूप से

दोनों परिस्थितियों का संकेत देते हुए जिसके तहत

और वे वर्ग जिनमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है

लंबी अवधि के लिए।

कहने के लिए,

उदाहरण के लिए,

कि

जिन व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार करने की संभावना हैभारत के बचाव को तीन से अधिक हिरासत में लिया जा सकता है

महीनों को तुरंत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अन्य में

शब्दों में, वर्गीकरण वर्गीकरण स्वयं इस तरह का हो सकता है कि परिस्थितियों का पर्याप्त विवरण हो।

खंड *(7)* के प्रयोजनों के लिए। परिस्थितियाँ जो तीन से अधिक एहतियाती हिरासत को उचित ठहराएंगी

सलाहकार बोर्ड का सहारा लिए बिना महीनों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, और यह मेरे निर्णय में धारा *12* की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि निर्दिष्ट मामलों के अलावा किसी भी परिधि का उल्लेख नहीं किया गया है। उप-धारा *(1)* के खंड *(ए)* और *(बी)* में। यह वास्तव में एकल होगा कि न्यायालय एक को खारिज कर दे

संसदीय अधिनियम क्योंकि इसकी राय में *217*

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसमें कुछ वर्गीकरण किए गए हैं।

अपूर्ण है या

कुछ परिस्थितियों का उल्लेख

अनिर्दिष्ट या में है

पर्याप्त है।

अंत में, श्री नांबियार ने अनुभाग पर अपना हमला पलट दिया

14 जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संप्रेषित हिरासत के आधारों और हिरासत के आदेश के खिलाफ उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है, और अदालत को उप-धारा *(2)* के तहत दंडनीय अभियोजन के उद्देश्यों को छोड़कर इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति देने से रोकता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा खुलासा या प्रकाशित करना अपराध बनाता है।

प्रतिनिधित्व

पहले के बिना

आधार या प्राधिकरण

केंद्र का

सरकार या राज्य

सरकार, जैसा भी मामला हो। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद *22* के खंड *(5)* के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकारों को प्रभावी रूप से रद्द कर देता है जो उसे अपनी नजरबंदी के आधारों से अवगत कराने और एक अभ्यावेदन करने का अधिकार देता है।

आदेश के खिलाफ। यदि आधार बहुत अस्पष्ट हैं जो उन्हें ऐसा कोई अभ्यावेदन देने में सक्षम नहीं बनाते हैं, या यदि वे उनकी नजरबंदी के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, या ऐसे हैं जो यह दर्शाते हैं कि उनकी नजरबंदी प्रामाणिक नहीं है, तो उन्हें इस न्यायालय में जाने का अधिकार है और इस उपाय की गारंटी भी उन्हें अनुच्छेद *32* के तहत दी गई है। ये। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि अधिकारों और उपचारों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है, यदि उसे अभियोजन की पीड़ा पर अदालत को आधारों का खुलासा करने से रोका जाता है। इस विवाद में बहुत ताकत है। महान्यायवादी इसके उत्तर में केवल इतना ही कह सकता था कि यदि अधिनियम के अन्य प्रावधानों को वैध ठहराया जाता है, तो न्यायालय के लिए उन आधारों की पर्याप्तता की जांच करने का अधिकार नहीं होगा जिन पर कार्यपालिका

प्राधिकरण इस बात से "संतुष्ट" था कि नजरबंदी की आवश्यकता थी, जैसा कि मछिंदर शिवाजी महार बनाम में निर्धारित किया गया था। द. राजा *(1)*, और इसलिए याचिकाकर्ता धारा *14* के कारण अपने अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता था, जिसने केवल साक्ष्य का नियम लागू किया था। तर्क इस बात को नजरअंदाज करता है कि ऊपर उल्लिखित निर्णय में यह मान्यता दी गई थी कि यह देखने के लिए कि क्या वे उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे जो विधायिका के पास था, हिरासत के आधारों की जांच करने के लिए न्यायालय के लिए खुला होगा।

(1) [1949] एफ. सी. आर. *827*।

[1950]

218

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदाहरण के लिए, कृत्यों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए

धारा *14* द्वारा असंभव बना दिया गया, और संरक्षणइस प्रकार अनुच्छेद *22 (5)* और अनुच्छेद *32* द्वारा प्रदत्त है -

नासमझ।

यह धारा *14* के विपरीत है।

प्रस्तुत किया गया

में अनुच्छेद *22 (5)* और अनुच्छेद *32*

प्रावधानों को स्पष्ट करता हैजहाँ तक यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को खुलासा करने से रोकता है

अदालत को उनकी नजरबंदी की विज्ञप्ति के आधार हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी या प्रतिनिधि द्वारा उसे सौंपा गया

निरोध के आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा भेजा गया,

उपरोक्त उद्देश्य, और उस हद तक यह आयोजित किया जाना चाहिए अनुच्छेद *13 (2)* के तहत शून्य होना। लेकिन यह करता है

अधिनियम के शेष भाग को प्रभावित नहीं करता है जो अलग करने योग्य है। के रूप में

याचिकाकर्ता ने अपने बयान के आधार का खुलासा नहीं किया

इस बिंदु पर हमारे निर्णय के लंबित रहने पर, वह अब उन आधारों के आधार पर अपना उपचार लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

परिणामस्वरूप, आवेदन विफल हो जाता है और खारिज कर दिया जाता है। जे. महाजन-भारत के लोग गंभीरता से

भारत को एक संप्रभु लोकतंत्र बनाने का संकल्प लिया

26 नवंबर *1949* को टिक गणराज्य ने खुद को एक संविधान दिया जो *26* जनवरी *1950* को लागू हुआ। यह पहला मामला है जिसमें इस न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि संविधान ने इस देश के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित की है।

पहले से ही था

ए. के. गोपालन, याचिकाकर्ता, जो

अधीक्षक की अभिरक्षा में,

केंद्रीय जेल,

कुड्डालोर को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था

27 फरवरी *1950* को निवारक निरोध अधिनियम, *1950 (1950* का अधिनियम *IV)* की धारा *3 (1)* के तहत। आदेश में कहा गया था कि मद्रास के राज्यपाल

इस बात से संतुष्ट था कि उसे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए आदेश देना आवश्यक था। *20* मार्च *1950* को इस न्यायालय में अनुच्छेद *32* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत एक याचिका प्रस्तुत की गई थी।

219

एस सी आर।

एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करने वाले संविधान का

बंदी प्रत्यक्षीकरण मद्रास राज्य को निर्देश देता है कि

उसे अदालत के सामने पेश करें और उसे स्थापित करेंस्वतंत्रता। तदनुसार एक रिट जारी की गई थी। वापसी

रिट में कहा गया है कि अधिनियम के तहत हिरासत कानूनी है

1950 का चौथा, संसद द्वारा अधिनियमित। याचिकाकर्ता ने

यह तर्क देता है कि अधिनियम कुछ शर्तों का उल्लंघन करता है

संविधान के भाग *III* के प्रावधान और इस प्रकार हैविधायिका की संवैधानिक सीमाओं के बाहर

और इसलिए शून्य और अप्रवर्तनीय।

यह मामला दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

स्पष्ट रूप से प्रदत्त विधायी शक्ति का कारण बनता है

7 वीं अनुसूची को आक्षेपित किया गया है और क्योंकि

नागरिकों की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। द.

इस प्रश्न का निर्णय कि क्या *1950* का अधिनियम *IV* है।

भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन लेता है या कम कर देता हैसंविधान का *III* इस पर विचार करने पर निर्भर करता है -

दो बिंदुः

(1) संविधान ने किस हद तक सुरक्षा प्रदान की है*?*

भारत के नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और

(2) क्या विवादित कानून किसी भी तरह से लिया गया है

इस तरह से सुरक्षित अधिकारों को हटा दिया या संक्षिप्त कर दिया और यदि ऐसा है, तो

किस हद तक*?*

1950 के अधिनियम *IV* में निवारक निरोध का प्रावधान है।

कुछ मामलों में यह अधिनियमित किया गया है किअस्थायी उपाय। इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा

1 सेंट अप्रैल *1951*। यह.

सशक्त करता है।

केंद्रीय सरकार

मन और राज्य

सरकारें

एक आदेश बनाने के लिए

हिरासत में लिया जाए ताकि

एक व्यक्ति को निर्देशित करना उसे किसी भी तरह से काम करने से रोकना

भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण, भारत के संबंध

विदेशी शक्तियों या भारत की सुरक्षा के साथ। यह भी।

किसी भी तरह से कार्य करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है

राज्य या मुख्य राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक

सार्वजनिक व्यवस्था का अधिभोग या आपूर्ति का रखरखाव

और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं। वह आ गया।

26 फरवरी *1950* को लागू किया गया और अधिनियमित किया गया था

द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

संविधान के भाग *III* के अनुच्छेद *22* खंड *(7)* को *7* वीं अनुसूची की प्रविष्टियों के साथ पढ़ा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधायिका यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में व्यक्त करेगी।

[1950]

220

यह तब तक लागू किया जा सकता है जब तक कि विधायिका अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखने में विफल न हो। यह काफी है यह स्पष्ट है कि न्यायालय केवल अन्यायपूर्ण आधार पर किसी क़ानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकता है।

प्रावधान या क्योंकि यह ऊपर दिया गया है

और नागरिकों के प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दमनकारी, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि

अन्याय निषिद्ध है या ऐसे अधिकारों की गारंटी या संरक्षण संविधान द्वारा दिया गया है। यह भी हो सकता है

ved कि किसी अधिनियम को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय की राय यह स्पिरिट सप के खिलाफ है

संविधान में व्याप्त होने के लिए प्रस्तुत किया गया लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया। किसी भी सामान्य सिद्धांत पर यह मुश्किल है कि न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा संप्रभु विधायी शक्ति की सर्वशक्तिमानता को सीमित करना, सिवाय इसके कि लिखित संविधान के व्यक्त शब्द उस अधिकार को देते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद *13 (2)* ऐसा देता है

इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई भी विधि -उल्लंघन की सीमा शून्य होगी।

निवारक निरोध कानून लोकतंत्र के खिलाफ हैं

रैटिक संविधान और वे मौजूद नहीं पाए जा सकते हैं

दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में। यह. बार में कहा गया था कि ऐसा कोई कानून नहीं था

संयुक्त राज्य अमेरिका में बल। इंग्लैंड में

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार निश्चितराज्य की रक्षा के तहत बनाए गए नियम

सती में निवारक निरोध के लिए अधिनियम का प्रावधान युद्ध के उपाय के रूप में गृह सचिव का गुट

द्वितीय विश्व युद्ध। इसी तरह के नियम परिचय थेभारत में युद्ध की अवधि के दौरान

भारत रक्षा अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम,

1935 , केंद्रीय और प्रांतीय को अधिकार प्रदान किया गया

इस विषय पर पहले कानून बनाने के लिए विधानमंडल

इस विषय पर समय और तब से कानून बनाए गए हैं।यहाँ दृढ़ जड़ और एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं

इस कानून की पुस्तक

दिलचस्प रूप से पर्याप्त

देश।

इस विषय को संविधान में एस. सी. आर. में स्थान मिला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

221

मौलिक अधिकारों पर अध्याय। संघ सूची की प्रविष्टि *9* और *7* वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि *3* में इस विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति के दायरे का उल्लेख है। हालाँकि, इन कानूनों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद *22* के भाग *III* के प्रावधानों के अधीन है।

इस भाग में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" (1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

अभिरक्षा में-जितनी जल्दी हो सके, ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए बिना और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

(2) गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया प्रत्येक व्यक्ति

हिरासत में निकटतम से पहले पेश किया जाएगा

ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

मजिस्ट्रेट।

(3) खंड *(1)* और *(2)* में कुछ भी लागू नहीं होगा।

(क) किसी भी व्यक्ति के लिए जो अभी के लिए है

एक दुश्मन विदेशी; या

(ख) गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत।

(4) निवारक निरोध के लिए कोई कानून नहीं

किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करेगा।

तीन महीने से अधिक की अवधि जब तक कि

(क*)* व्यक्तियों से बना एक सलाहकार मंडल

जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं या रहे हैं या हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष रिपोर्ट दी है -

तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति कि उसकी राय में इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण हैयह बातः

बशर्ते कि इस उपखंड में कुछ भी नहीं होगा

इससे परे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करें

द्वारा बनाई गई किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि खंड *(7)* के उपखंड *(*बी*)* के तहत संसद*;* या

(ख*)* ऐसे व्यक्ति को तदनुसार हिरासत में लिया जाता है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के साथ खंड *(7)* के उपखंड *(*ए*)* और *(*बी*)* के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

222

[1950]

(5) जब किसी व्यक्ति को अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है

पूर्वनिर्धारित निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत किए गए आदेश के बारे में, आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उन्हें सूचित करेगा।

व्यक्ति को

जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और वह उसे प्रतिनिधि बनाने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा

आदेश के खिलाफ प्रेषण।

(6) खंड *(5)* की किसी भी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि -

ऐसा कोई आदेश देने वाला प्राधिकारी जिसे उस खंड में उन तथ्यों को प्रकट करने के लिए संदर्भित किया गया है जिन्हें ऐसा प्राधिकारी सार्वजनिक हित में प्रकट करने के खिलाफ मानता है।

(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क) जिन परिस्थितियों में, और वर्ग

या ऐसे मामलों के वर्ग जिनमें किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। खंड *(4)* के उपखंड *(क)* के प्रावधानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली कानून*;*

(ख) अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी वर्ग या मामलों के वर्गों में हिरासत में लिया जा सकता है*;* और

(ग) एक सलाहकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

खंड *(4)* के उपखंड *(ए)* के तहत एक जांच में बोर्ड।

की संवैधानिक वैधता का प्रश्न

संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विवादित क़ानून से बहुत सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए और इस पर धैर्यपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उचित संदेह के लाभ को विधायी कार्रवाई के पक्ष में हल किया जाना चाहिए, हालांकि ऐसी धारणा निर्णायक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक निरोध का विषय संविधान की विशेष चिंता बन गया क्योंकि सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था, जिसके बारे में अध्याय में कुछ प्रावधान पेश किए गए थे।

मौलिक अधिकार और शर्तों के कारण

नवजात गणराज्य में प्रचलित। निवारक

निरोध का अर्थ है स्वतंत्रता का पूर्ण निषेध।

आंदोलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

और

है।

उन दोनों विषयों के साथ असंगत

और फिर भी यह है

उन्हें भाग *III* में

एक ही डिब्बे में रखा गया

संविधान से।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

223

यद्यपि संविधान ने मान्यता दी है कि

निवारक निरोध के रूप में कानूनों की आवश्यकता ने उनकी कठोरता को कम करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए हैं। इस विषय पर प्रदत्त विधायी शक्ति पर बंधन लगाकर। ये हैं।

(1) कि कोई भी कानून नजरबंदी का प्रावधान नहीं कर सकता है

तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए जब तक कि हिरासत के कारण की पर्याप्तता की जांच तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर एक सलाहकार बोर्ड द्वारा नहीं की जाती है। यह प्रावधान निरोध की अवधि के मामले में विधायी शक्ति को सीमित करता है। निवारक निरोध का एक कानून अमान्य होगा यदि यह एक सलाहकार बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना तीन महीने से अधिक समय तक निरोध की अनुमति देता है।

(2) कि राज्य का कानून हिरासत को अधिकृत नहीं कर सकता है

खंड *(7)* में दी गई शक्तियों के तहत संसद द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से परे। यह विधायी शक्ति पर एक सीमा है

राज्य

विधायिका। वे संसद द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक निवारक निरोध को अधिकृत करने वाला कानून नहीं बना सकते हैं।

(3) कि संसद भी कानून नहीं बना सकती

सलाहकार बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध को अधिकृत करना जब तक कि कानून अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* में निर्धारित शर्तों के अनुरूप न हो। सलाहकार बोर्डों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाने का भी प्रावधान किया गया है। यह एक सुरक्षा है

प्रक्रिया के किसी भी मनमाने रूप के खिलाफ जो हो सकता है अन्यथा राज्य के कानूनों में जगह मिलती है।

इनके अलावा सक्षम और अक्षम करने वाले प्रावधान

अनुच्छेद *22* के खंड *(5)* द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति

निवारक निरोध के कानून के तहत उसे हिरासत के आधार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और उसे प्रतिनिधित्व विरोध करने का भी अधिकार है। निवारक निवारक निरोध के आदेश के खिलाफ। इस अधिकार की गारंटी ड्यूरा से स्वतंत्र रूप से दी गई है।

निरोध की अवधि और सलाहकार मंडल के अस्तित्व या अस्तित्व के अभाव की परवाह किए बिना।

नहीं।

मशीनरी, हालांकि, प्रदान की गई है या स्पष्ट रूप से *224*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

इस प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए उल्लेख किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक संवैधानिक अधिकार को एक आवश्यक परिणाम के रूप में प्रदान किया गया है, तो अधिकार के उल्लंघन के मामले में निवारण प्राप्त करने के लिए एक संवैधानिक उपाय पर विचार किया जाना चाहिए और यह इरादा नहीं किया जा सकता था कि अधिकार केवल भ्रामक था और यह कि एक प्रतिनिधित्व को ठंडे बस्ते में जगह मिल सकती है। खंड *(5)* के आधार पर किसी निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करना, मेरी राय में, इसमें निहित गारंटीकृत अधिकार का एक आवश्यक परिणाम है। यह अधिकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी बेगुनाही स्थापित करने और न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया गया है, और किसी भी न्याय को तब तक सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है जब तक कि किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाता है। यह व्याख्या जो मैं अनुच्छेद *22* के खंड *(5)* पर करने के लिए इच्छुक हूं, संविधान की प्रस्तावना में निहित घोषणा के गंभीर शब्दों द्वारा उचित है। यह घोषणा ही है जो हमारे संविधान को उदात्त बनाती है और यह गारंटी है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है।

मौलिक अधिकारों पर अध्याय जो इसे स्वतंत्रता के सबसे बड़े चार्टरों में से एक बनाता है और जिसके लोग

गर्व हो सकता है। यह चार्टर

इस देश में

अनिच्छुक हाथों से मजबूर नहीं किया गया है मैग्ना कार्टा की तरह एक संप्रभु लेकिन यह देश के लोगों द्वारा अपनी संविधान सभा के माध्यम से खुद को दिया गया है। इस गंभीर घोषणा के संदर्भ के बिना संविधान के भाग *III* के प्रावधानों की कोई भी व्याख्या किसी को गलती की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है। यदि अनुच्छेद *22* के खंड *(5)* द्वारा किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अधिकार एक गारंटीकृत अधिकार है और न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया है, तो यह इस प्रकार है कि उसे तब तक कोई न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिनिधित्व के गुण-दोष पर विचार नहीं करता है और देता है।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अपराध या निर्दोषता पर उनकी राय। मेरे विचार में अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है।

यह मानते हुए मायावी बना दिया कि नजरबंदी

या

प्राधिकरण स्वयं प्रतिनिधित्व पर निष्पक्ष दिमाग से विचार करेगा और न्याय प्रदान करेगा। कि

एक तरह से अभियोजक को एक न्यायाधीश बना देगा

और ऐसी प्रक्रिया सभी धारणाओं *225* के प्रतिकूल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

न्याय की। संविधान ने खंड *(6)* में तथ्यों को छिपाने के निरोध प्राधिकारी पर विशेषाधिकार प्रदान करके खंड *(5)* में दिए गए अधिकारों को और कम कर दिया है।

प्राधिकरण सार्वजनिक रूप से नहीं माना जाता है

जिसे उन्होंने कहा

यह विशेषाधिकार दिया गया है।

हितों का खुलासा करना।राज्य की सुरक्षा के लिए और संभवतः

सख्त प्रावधान कोई अतिरिक्त अवरोध नहीं लगाया जा सकता है के प्रतिनिधित्व पर उचित विचार

यह मानते हुए हिरासत में लिया गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति

प्राधिकरण स्वयं प्रतिनिधि पर उचित रूप से विचार करेगा।

यह। इसे इस संदर्भ में भी याद रखना होगा।कि निवारक निरोध के कानून के अधीन एक व्यक्ति

प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया गया है

वे व्यक्ति जो दंडात्मक कानून के अधीन हो जाते हैं

निरोध *[*अनुच्छेद *22* के खंड *(1)* और *(2)* के अनुसार*]*। वह. किसी वकील से परामर्श करने या होने के अधिकार से वंचित किया गया है

उसके द्वारा बचाव किया गया और उसे हिरासत में रखा जा सकता है

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।

अनुच्छेद *22* के प्रावधानों की जांच करने के बाद*, I*

अब पहले प्रश्न पर विचार करें जो था

विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमारे समक्ष प्रचार किया गया*;*

अर्थात्, संविधान का वह अनुच्छेद *22* जिसके साथ पढ़ा जाता है -

7 वीं अनुसूची में प्रविष्टियाँ पर एक पूर्ण कोड था

निवारक निरोध का विषय, और ऐसा होने पर,

भाग *III* के अन्य अनुच्छेदों को लागू नहीं किया जा सका

अभियुक्त की वैधता पर विचार करना

कानून। यह विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था

याचिकाकर्ता कि उस हद तक जो प्रावधानों को व्यक्त करता है

वे प्रावधान प्रबल होंगे और प्रभावी नहीं हो सकते थे भाग *III* के अन्य प्रावधानों द्वारा अपमानित किया गया। यह था,

हालाँकि, आग्रह किया कि जिन मामलों पर यह लेख है

इस विषय पर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया था

संविधान के भाग *III* के प्रावधान लागू थे अनुच्छेद *19* और *21* और उस सीमा तक

इस विषय पर बनाए गए कानून न्यायोचित थे। क्रम में

यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि संविधान के निर्माता

निवारक के संबंध में प्रावधानों का उद्देश्य

अनुच्छेद *22* में निरोध स्व-निहित होने के लिए स्पष्ट

इस तरह के इरादे का संकेत एकत्र किया जाना चाहिए।यदि इस अनुच्छेद में सन्निहित प्रावधानों पर विचार किया गया है *[1950]*

226

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन सभी प्रमुख प्रश्नों के साथ जो उत्पन्न होने की संभावना हैप्रक्रिया के मामलों में या कारण के प्रश्नों पर

निरोध की अवधि की क्षमता, का अनुमान इस तरह का संकेत अप्रतिरोध्य होगा। आम तौर पर

जब किसी विषय पर संविधान में स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है।कुछ विस्तार से, यह मान लेना होगा कि

इरादा जनरल के आवेदन को बाहर करने का था

एक्सप्रेस

कहीं और।

उसमें निहित

प्रावधान

दूसरे का बहिष्कार।

एक बात का उल्लेख एक है

अल्टेरियस अल्टेरियस। . मैं संतुष्ट हूँ।

संविधान की पूरी योजना की समीक्षा परकि इरादा अनुच्छेद *22* को स्व-निहित बनाना था

निवारक निरोध के विषय पर कानूनों के संबंध में। यह तर्क दिया गया कि सभी लेखों में

संविधान को सौहार्दपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए

तरीका और एक लेख को स्थायी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए अपने आप से और दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होने के रूप में

एक ही भाग में लेख। यह कहा जाता था कि वे सभी एक दूसरे के पूरक थे। इस संबंध में यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद *22* के तहत बनाया गया कानून

यह तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह संविधान के अनुच्छेद *21* के प्रावधानों के अनुरूप न हो। यह लेख प्रदान करता है

व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।

कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं। यह तर्क दिया गया था कि सार में अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई या निष्पक्ष सुनवाई दिए बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और जब तक कि निवारक निरोध का कोई कानून ऐसी सुनवाई का प्रावधान नहीं करता है, तब तक कानून इस अनुच्छेद का उल्लंघन करेगा और इस प्रकार शून्य होगा। के लिए स्वीकार करना

तर्क *(*लेकिन बिना किसी अभिव्यक्ति के*)*

राय

यह*)*

कि

द.

सीखा है

यह

में से

विवाद

पर

सलाह सही है,

क्या

सवाल उठ रहा है

अनुच्छेद *22* में कुछ भी है जो निवारक निरोध पर कानून के लिए उपरोक्त अनुच्छेद *21* के अनुप्रयोग को नकारता है। मेरी राय में, खंड *(1)* और *(2)* के साथ पठित अनुच्छेद *22* का उपखंड *(5)* इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि विद्वानों द्वारा उठाया गया विवाद

सलाह ठीक नहीं है। खंड *(5)*, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह प्रावधान करता है कि किसी बंदी को उसकी नजरबंदी के आधार पर नोटिस दिया जाना चाहिए। यह एक सीमित सुनवाई भी प्रदान करता है क्योंकि यह उसे एस. सी. आर. को एक अवसर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

227

उसकी निर्दोषता स्थापित करें। जैसा कि, मेरी राय में, प्रति हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन का विचार

खंड *(5)* में निहित है, यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वह सब कुछ देता है जिसका वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत हकदार है। संविधान द्वारा अपनी पसंद के वकील द्वारा परामर्श करने और प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को व्यक्त शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के अवसर से भी वंचित कर दिया जाता है। जब संविधान ने कुछ अधिकारों को छीन लिया है जो किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास होंगे और उसके उपबंध में प्रक्रिया के मामले में भी उसे कुछ अन्य अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो निष्कर्ष स्पष्ट है कि इरादा ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर न्यायिक कार्यवाही में प्रदान की गई विस्तृत प्रक्रिया के अधिकार से वंचित करना था। अनुच्छेद *22* का खंड *(6)* इस निष्कर्ष का बहुत दृढ़ता से समर्थन करता है। निवारक निरोध के कानून के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे विस्तृत नियमों को निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं होता यदि इरादा यह होता कि ऐसा कानून संविधान के अनुच्छेद *21* के प्रावधानों के अधीन होता। अपने अंतिम विश्लेषण में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान पक्ष का तर्क इस बात का समाधान करता है कि विवादित क़ानून हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक निष्पक्ष त्रिकोणीय का प्रावधान नहीं करता है और इस हद तक यह उल्लंघन करता है।

संविधान का अनुच्छेद *21*। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेरी राय में, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद *22* के भीतर ही निहित है और ऐसा होने पर, अनुच्छेद *22* के तहत बनाई गई कानून पर अनुच्छेद *21* का अनुप्रयोग बहिष्कृत है।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि निवारक का एक कानून

निरोध अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत एक नागरिक को गारंटीकृत भारत के क्षेत्र के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करता है और ऐसा होने पर,

अनुच्छेद *19* के उपखंड *(5)* के प्रावधानों का कारण

यह तर्कसंगतता के आधार पर न्यायोचित था। यह सच है, जैसा कि पहले ही बताया गया है, कि निवारक निरोध का कानून एक नागरिक के मुक्त आवाजाही के अधिकार के साथ पूरी तरह से असंगत है। पदार्थ में निवारक निरोध अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत गारंटीकृत आवाजाही की स्वतंत्रता का निषेध है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल इसे प्रतिबंधित करता है। जो भी हो,

10-3 एस. सी. इंडिया*/58 228*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या यह अभिप्रेत था कि अनुच्छेद *19* अनुच्छेद *22* के प्रावधानों के तहत बनाई गई विधि को नियंत्रित करेगा। अनुच्छेद *19 (5)* एक बचत और सक्षम प्रावधान है। यह संसद को अधिकार देता है कि

आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध प्रतिबंध लगाने वाली कानून बनाएँ जबकि अनुच्छेद *22 (7)* है

संसद को सशक्त बनाने वाला एक और सक्षम प्रावधान

कुछ परिस्थितियों में निवारक निरोध के विषय पर कानून बनाएँ। यदि कोई कानून कॉन के अनुरूप है

अनुच्छेद *19 (5)*। एक सक्षम प्रावधान को दूसरे सक्षम प्रावधान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद *13 (2)* बिल्कुल लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में। यदि संविधान का इरादा यह था कि निवारक विषय पर एक कानून बनाया गया था

नजरबंदी का परीक्षण कारण की कसौटी पर किया जाना था

सामर्थ्य, तब यह उस सीमा के सटीक दायरे के बारे में अनुच्छेद *22* में पूर्व प्रेस से प्रावधान करके खुद को परेशान नहीं करता, जिसके अधीन ऐसी कानून है।

उस प्रक्रिया का उल्लेख करके बनाया जा सकता था जो उस विषय से संबंधित कानून को प्रदान करनी थी। तब अनुच्छेद *22* के कुछ प्रावधान अनावश्यक होते, उदाहरण के लिए, यह प्रावधान कि कोई भी निरोध तीन महीने से अधिक समय तक नहीं रह सकता है।एक सलाहकार बोर्ड द्वारा इस तरह के निरोध की जांच की आवश्यकता। यह प्रावधान नकारात्मक है

यह विचार

कि सलाहकार मंडल के परामर्श के बिना तीन महीने की अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना।

तर्कसंगतता के आधार पर न्यायसंगत होगा। फिर से अनुच्छेद *22* ने एक सुरक्षा प्रदान की है कि यदि एक सलाहकार बोर्ड को समाप्त करना है, तो इसे केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही समाप्त किया जा

सकता है और संसद को भी इस तरह के कानून को लागू करने में कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यदि इस विषय पर कोई कानून न्यायसंगत होता तो अनुच्छेद *22* में यह प्रावधान अनावश्यक होता। खंड *(7)* के उप-उपखंड खंड *(ख)* में

बनाया गया।

हो चुका है

अनुच्छेद *22* का प्रावधान है -

एना

अधिकतम

अवधि

संसद

ब्लिंग

ठीक करें

को

हिरासत में लिया जा सकता है

के तहत

जिसके लिए एक व्यक्ति

के तहत

निवारक निरोध के विषय पर एक कानून।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

229

यह स्पष्ट प्रावधान संसद के लिए किसी भी अवधि को तय करने के लिए खुला है, मान लीजिए, किसी व्यक्ति की हिरासत की अधिकतम अवधि के रूप में पांच से दस साल की अवधि भी। हो सकता है*?*

यह कहा जा सकता है कि संविधान के इस स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए ऐसी कानून का उद्देश्य अनुच्छेद *19 (5)* के कारण न्यायसंगत होना था*?* निवारक निरोध कानूनों में निरोध की अवधि प्रमुख मामला है जो

संभवतः अनुच्छेद *19 (5)* के तहत वास्तविकता की कसौटी पर जांच की जा सकती है, लेकिन यह पूर्व में किया गया है।

अनुच्छेद *22* में स्पष्ट प्रावधानों द्वारा बाहर रखा गया। इसलिए, मेरे निर्णय में, अनुच्छेद *22* के अनुकूल दृष्टिकोण की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निवारक निरोध के कानून के संबंध में इसे स्व-निहित बनाने का इरादा था और निवारक निरोध के विषय पर किसी कानून की वैधता की जांच या नियंत्रण अनुच्छेद *21* के प्रावधानों या अनुच्छेद *19 (5)* के प्रावधानों द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद *13 (2)* का ऐसी स्थिति पर कोई अनुप्रयोग नहीं है और अनुच्छेद *22* हैइन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन नहीं। अनुच्छेद *22* में संविधान ने इस हद तक प्रावधान किया है कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। निवारक निरोध के विषय के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुच्छेद *22* में प्रावधान किया गया है और ऐसा होने पर निवारक निरोध के विषय पर किसी कानून की वैधता की जांच करने का एकमात्र सही तरीका यह विचार करना है कि क्या बनाई गई कानून अनुच्छेद *22* की आवश्यकताओं को पूरा करती है या किसी भी तरह से उन्हें कम करती है या उनका उल्लंघन करती है और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो कानून वैध होगा, लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है, तो कानून शून्य होगा।

इस विचार को व्यक्त करते हुए कि अनुच्छेद *22* एक अर्थ में है

तथापि, निवारक निरोध के कानून में निहित मुझे यह निर्धारित करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि लेख के निर्माता किसी भी मामले में

जिस तरह से अनदेखी की गई

अनुच्छेद *21* में उल्लिखित सुरक्षा उपाय। .

अनुच्छेद *21* में

राय, मूल कानून निर्धारित करता है

संरक्षण देने के रूप में

जीवन और स्वतंत्रता के लिए क्योंकि यह कहता है कि उन्हें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

पूर्ववर्ती कुछ मौजूद होना चाहिए

एक शर्त के रूप में ऐसा करने के लिए अधिकार प्रदान करने वाली मूल विधि और

कानून को आगे प्रक्रिया के एक तरीके का प्रावधान करना चाहिए

इस तरह के अभाव के लिए। यह लेख निरंकुश शक्ति के प्रयोग के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है

कार्यकारी। यह आगे इसके खिलाफ प्रतिरक्षा देता है। अवैध कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। यह.

यह भी गारंटी देता है कि इसकी वास्तविक अवधारणा में

या उसकी स्वतंत्रता। यह शानदार के विचार को नकारता है, कार्यवाही के मनमाने और दमनकारी रूप। द.

इसलिए अनुच्छेद *21* में अंतर्निहित सिद्धांत हैं - अनुच्छेद *22* के प्रारूपण में ध्यान में रखा गया है। एक कानून ठीक से

अनुच्छेद *22* के तहत बनाया गया और जो सभी मामलों में मान्य है

उस लेख के तहत और मूल रूप से भी निर्धारित किया गया है

इस विषय पर विशेषण कानून के रूप में पूरी तरह से संतुष्ट होगा अनुच्छेद *21* की आवश्यकताएँ, और ऐसा होने पर, हैं।

इन दोनों अनुच्छेदों के बीच कोई टकराव नहीं है।

निर्णय के लिए अगला सवाल यह है कि

क्या *1950* के अधिनियम *IV* में कुछ ऐसा है जो भाग *III* के अनुच्छेद *22* के प्रावधानों के खिलाफ है

संविधान से। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा *3* खराब थी

क्योंकि यह किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए मानदंड के रूप में "सरकार की संतुष्टि" बनाता है। कहा गया है।

कि जैसा कि धारा *3* ने किसी व्यक्ति के लिए आचरण का कोई वस्तुनिष्ठ नियम निर्धारित नहीं किया था और क्योंकि लोगों को यह नहीं बताया गया था कि उनसे किस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, इसका परिणाम यह था कि यह ज्ञात नहीं किया जा सकता था कि किसी व्यक्ति से किन कार्यों से बचने की अपेक्षा की जाती है और उसकी ओर से कौन सा आचरण प्रतिकूल था।

राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए; दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया था कि धारा *3* ने किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य के निर्धारण को सरकार के मनमाने निर्णय पर छोड़ दिया था और यह कि इस कानून को प्रशासित करने वाले अधिकारी को भी अपनी संतुष्टि पर पहुंचने के लिए कोई मार्गदर्शन और आचरण का कोई मानक नहीं दिया गया था कि क्या आचरण राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल था।

राज्य आदि। विद्वान वकील की यह आलोचना,मेरी राय में, वैध नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिरासत का आदेश सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की संतुष्टि पर निर्भर करता है

सरकार लेकिन यह प्रावधान इसके अनुसार है।

संविधान के अनुच्छेद *22* के साथ, जो मेरे विचार से, की संतुष्टि पर निरोध का विचार करता है

अपनी प्रकृति से उप

कार्यकारी प्राधिकरण। अधिनियम ऐसा है कि इसका तात्पर्य आदेश देने के लिए सौंपे गए प्राधिकारी के निर्णय पर निरोध है। निवारक निरोध के कानून का पूरा इरादा और उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि इस तरह के प्रावधान के अधीन थी।

वस्तुनिष्ठ मानक और शर्तों के अधीन भी था

कानूनी प्रमाण और प्रक्रिया के बारे में। *7* वीं अनुसूची में इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र रक्षा आदि और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए दिया गया है। ये ऐसे विषय हैं जो राज्य के जीवन और अस्तित्व से संबंधित हैं।

यह माना जाता है कि प्रत्येक नागरिक को पता है कि व्यवहार क्या है

राज्य के जीवन या एक व्यवस्थित राज्य के रूप में इसके अस्तित्व के लिए हानिकारक। यह देखते हुए कि राज्य

ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी सरकार है जो खुद को संचालित करती है

एक उचित तरीका और यह भी मानते हुए कि इसके अधिकारी

आम तौर पर समझदार पुरुष होंगे, यह नहीं कहा जा सकता है कि

संतुष्टि के लिए

सरकार के रूप में

उन व्यक्तियों के पूर्वाग्रहपूर्ण कृत्यों का न्याय करने के लिए मानक जो निवारक निरोध के कानून की धारा *3* के अधीन हैं

किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद *22* का उल्लंघन करता है।

में

ट्यूशन।

विवादित अधिनियम की धारा *7* पूरी तरह से प्रभावी है

अनुच्छेद *22* उपखंड *(5)* के प्रावधानों के लिए और अधिनियम

वह प्रतिनिधित्व केंद्र को दिया जाना चाहिए या

राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो। यह मैं था।

इस आधार पर पीच किया गया कि कोई मशीनरी नहीं है इस पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए यहाँ प्रदान किया गया है

प्रतिनिधित्व के गुण। इस हद तक, पहले से ही

इंगित किया गया है कि कानून दोषपूर्ण है। . एक के अभाव में

प्रतिनिधित्व में उठाया गया यह डी के लिए खुला हो सकता हैएक उचित अधिकार के लिए अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय का रुख करने के लिए

राहत मिलती है। हालाँकि, इसे व्यक्त करना अनावश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए खुले सटीक उपाय के बारे में राय

इस संबंध में व्यक्ति। प्रावधान का अभाव

हालाँकि क़ानून में इस प्रकृति से ऐसा नहीं होगा कि

पूरी तरह से कानून। शून्य। अधिनियम की धारा *9* में संदर्भ *232* दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अधीन आने वाले मामलों में अनिवार्य सलाहकार बोर्ड को आदेश के छह सप्ताह के भीतर खंड *(ए)* का उपखंड *(iii)* या धारा *3* की उप-धारा *(1)* का खंड *(*बी*)*। द.

सलाहकार मंडल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा *10* में निर्धारित की गई है। संसद को खंड *(7)* के उपखंड *(*सी*)* में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि कानून ने एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की थी, न ही उसे साक्ष्य देने का अधिकार दिया था

निर्दोषता। मेरी राय में, यह

उसे स्थापित करें

को

और किसी भी तरह से नहीं

आलोचना यह है कि

ध्वनि

नहीं।

कानून को अमान्य करें। सलाहकार मंडल को हिरासत में लिए गए व्यक्ति से भी ऐसी जानकारी मांगने की शक्ति दी गई है जिसकी उसे आवश्यकता है। इसे अभ्यावेदन में निहित तथ्यों और तर्कों के आलोक में आईआर के समक्ष रखी गई सामग्री की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। अवसर उतना पूर्ण नहीं है जितना किसी व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिलता है, लेकिन जब संविधान स्वयं पूर्व निरोध मामलों के

लिए निर्धारित की जा रही एक विशेष प्रक्रिया को लागू करता है, तो उस विषय पर कानून की वैधता को इस आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता है। के लिए विरोध किया।

अधिनियम की धारा *11* पर भी आक्षेप लगाया गया था

इस आधार पर कि यह आहत करता है

द.

संविधान

खिलाफ

जैसा कि प्रदान किया गया है

के लिए

नजरबंदी

निवारक

अनिश्चित काल के लिए। अवधि।

मेरी राय में यह खंड

अधिनियम की धारा *1* के उपखंड *(3)* के प्रावधान की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि अधिनियम *1* अप्रैल, *1951* से प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा, "ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझता है" शब्द किसी भी तरह से अनुच्छेद *22* के प्रावधानों के खिलाफ नहीं हैं, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है -

निवारक निरोध के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित करने वाला कानून बनाने की शक्ति। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट ने हिरासत की अवधि के लिए अधिकतम अवधि के रूप में एक वर्ष की अवधि निर्धारित की है जहां हिरासत एक सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के बिना होनी चाहिए। मेरी राय में, धारा *11* में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वोच्च विधानमंडल की शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं के बाहर हो।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

233

यह अधिनियम की धारा *12* है जिस पर हमला किया गया था

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील

बल्कि वाह।

धीरे-धीरे। यह खंड एक बहुत ही विवादास्पद चरित्र का है। यह अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* के अधिकार पर अधिनियमित किया गया है और इस प्रकार चलता हैः

" (1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति

मामलों के वर्ग या निम्नलिखित में से किसी भी परिधि के तहत

प्राप्त किए बिना हिरासत में लिया जाए

मुद्राएँ हो सकती हैं

से अधिक समय तक

तीन महीने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की राय, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं

उसकी नजरबंदी की तारीख, अर्थात्, जहां ऐसे व्यक्ति ने

उसे रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था

किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना

(क) भारत की रक्षा, भारत के साथ संबंध

विदेशी शक्तियाँ या भारत की सुरक्षा; या

((ख) किसी राज्य की सुरक्षा या रखरखाव

सार्वजनिक व्यवस्था।

(2) ए के तहत हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला

निरोध आदेश जिसके लिए उप-धारा के प्रावधान

(1) छह महीने की अवधि के भीतर लागू होगा

उसकी नजरबंदी की तारीख, जहां आदेश था, उसकी समीक्षा की जाए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया

ऐसी सरकार द्वारा, और जहां आदेश थाकी उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया

धारा *3*, राज्य सरकार द्वारा जिसके लिए

अधिकारी अधीनस्थ होता है, किसी व्यक्ति के परामर्श से

द्वारा उस ओर से नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के रूप में

मामला हो सकता है "।

अनुभाग का उद्देश्य शर्त का पालन करना है

अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* में निर्धारित। यह कैसे था

कभी, तर्क दिया कि सार और वास्तविकता में यह विफल रहा है

वहाँ निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने के लिए

में; कि यह न तो परिस्थितियों का उल्लेख करता हैकौन से और न ही ऐसे मामलों के वर्ग जिनमें निवारक

सलाहकार मंडल को अनुमति दी जा सकती है। अहम सवाल विचार के लिए यह है कि क्या धारा *12* का उल्लेख है

कोई भी परिस्थिति जिसके तहत या वर्गों को परिभाषित किया गया हो

जिन मामलों में अधिकार खंड *(7)* द्वारा प्रदत्त किया गया था

234

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सलाहकार मंडल को समाप्त करना। जहाँ तक मैं वर्गीकरण के विषय पर पाठ्य-पुस्तक लेखकों की राय से प्राप्त करने में सक्षम रहा हूँ, नियम स्पष्ट प्रतीत होता है कि

मामलों का वर्गीकरण करने में मांगी गई वस्तुओं के वर्गीकरण के साथ कुछ संबंध होना चाहिए।

पूरा करने के लिए। इसलिए विचार के लिए प्रश्न यह है कि जब संविधान ने अनुच्छेद *22* में खंड *(7)* को शामिल किया था तो किस उद्देश्य को पूरा करने की मांग की गई थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खंड *(7)* का वास्तविक उद्देश्य एक आकस्मिकता का प्रावधान करना था जहां एक सलाहकार बोर्ड की अनिवार्य आवश्यकता को विफल कर सकता है

निवारक कानून का उद्देश्य

नजरबंदी।

मुझमें

राय में, इसे असामान्य और असाधारण मामलों से निपटने के लिए संविधान में शामिल किया गया था, ऐसे मामले ऐसे थे जहां एक सलाहकार बोर्ड को विश्वास में नहीं लिया जा सकता था। इस तरह के द्रासुक कानून बनाने का अधिकार सर्वोच्च विधानमंडल को सौंपा गया था, लेकिन आगे इस सुरक्षा के साथ कि यह केवल इस तरह की कठोर प्रकृति का कानून बना सकता है, बशर्ते कि यह उन परिस्थितियों को निर्धारित करे जिनके तहत ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाना था या वैकल्पिक रूप से यह मामलों के वर्गों को निर्धारित करता है या मामलों का एक निर्धारित समूह बताता है जिसमें ऐसा किया जा सकता है। इरादा हिरासत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ मानक निर्धारित करना था, जिसके आधार पर सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बिना तीन महीने की अवधि से आगे हिरासत का आदेश दिया जा सकता था। इस संबंध में यह याद रखना होगा कि संविधान ने वास्तव में कुछ असामान्य स्थिति और व्यक्तियों के कुछ खतरनाक समूहों के बारे में सोचा होगा जब उसे एक सलाहकार बोर्ड जैसे न्यायाधिकरण को समाप्त करना आवश्यक लगा जो कैमरे में काम करता है और जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई देने के लिए भी बाध्य नहीं है और जिसकी

कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसी हानिरहित संस्था से बचने के लिए निवारक निरोध के विषय पर कानून को केवल विशिष्ट परिस्थितियों और विशिष्ट स्थितियों के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता था, जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किया जाना था और मेरी राय में खंड *(7)* का यही उद्देश्य था। यदि विशिष्टता किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के नियंत्रण या दृष्टिकोण से बाहर की स्थिति में निहित है, तो यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति का वर्णन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट होगी।

235

एस सी आर।

परिस्थितियों के प्रिस्क्रिप्शन के लिए राशि

न्यायसंगत ठहराएँ

तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखना

एक सलाहकार बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना एक कानून द्वारा। यदि, हालांकि, असामान्यता व्यक्तियों के एक निश्चित निर्धारित सक्षम समूह की गतिविधियों के आचरण और चरित्र से संबंधित है, तो यह एक

ऐसे मामलों का वर्ग जिन पर विचार किया जाना था

खंड *(7)* के अधीन। ऐसे मामलों में ही मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है।की अवधि से परे कानून द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सकता है

तीन महीने।

यह दलील पेटी के विद्वान वकील ने दी थी

कि वाक्यांश "परिस्थितियाँ जिनके तहत, और उन मामलों के वर्ग जिनमें खंड *(7)* में उपयोग किया गया था

एक संचयी अर्थ में समझा जाना; दूसरी ओरहाथ, विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने तर्क दिया कि

"और" शब्द का प्रयोग इसी खंड में किया गया था। "या" के रूप में अर्थ। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही शब्द

" और यह नहीं दिया गया है कि वाक्यांश का सही अर्थ यह था कि संसद निर्धारित कर सकती थी

या तो परिस्थितियों या मामलों के वर्गों के लिए

निवारक निरोध के विषय पर कानून बनाना

एक सलाहकार बोर्ड की मशीनरी के बिना तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत को अधिकृत करना।

1950 की पूर्ण पीठ संदर्भ संख्या *1* में, जे. दास गुप्ता।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खंड को अधिनियमित करने में विधायिका का इरादा यह था कि एक सलाहकार बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध को अधिकृत करने वाले निवारक निरोध के कानून को खंड *(7)* में निर्धारित दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना था, न कि केवल वैकल्पिक में से एक आवश्यकता को पूरा करना था। यही विचार मेरे भाई सर फजल अली ने भी व्यक्त किया है। मैं उनके साथ इस विचार को साझा करता हूं। हालाँकि, मैं इस मामले पर एक अलग पहलू से इस धारणा पर विचार करना चाहूंगा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा उठाया गया तर्क सही है।

पहले इस सवाल से निपटना कि क्या अनुभाग

12 जहाँ तक मैं देख सका हूँ, किसी भी परिस्थिति का उल्लेख करते हुए, यह किसी भी परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव आदि से जुड़े पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य परिस्थितियों के साथ-साथ *236* भी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मामलों के वर्ग। मेरी राय में, यह रेखाअनुच्छेद *22* के खंड *(7)* के अर्थ में दृष्टिकोण को सही नहीं माना जा सकता है। मैं विद्वान महान्यायवादी से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं कि वाक्यांश "परिस्थितियाँ जिसके तहत कुछ स्थिति का अर्थ है"

दूसरे शब्दों में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अपने कृत्यों के विपरीत, इसका अर्थ है उस देश में कुछ ऐसा होना जिससे हिरासत में लिए गए व्यक्ति का संबंध नहीं है, जैसे कि तनावपूर्ण सांप्रदायिक भावनाओं की स्थिति, एक अनुमानित आंतरिक विद्रोह या पी. आर. अव्यवस्था, एक आसन्न युद्ध या अनुमानित युद्ध का संकट, आदि। ऐसी स्थिति में माची

खंड स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है। यदि अनुमान लगाना अनुज्ञेय था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि धारा *12* के प्रारूपक ने अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* के शब्दों को बिना किसी उपबंध के दोहराया। उन शब्दों के अर्थ के लिए अपने मन का अनुप्रयोगऔर चूंकि कानून को एक आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जल्दबाजी में पारित किया गया था, इसलिए यह उन दोषों से ग्रस्त है जिनसे सभी जल्दबाजी में कानून पीड़ित हैं।

अब मैं इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि क्या धारा *12* है

उन मामलों को वर्गीकृत किया जाता है जिनमें एक नागरिक को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, बिना एक सलाहकार बोर्ड के तंत्र के लाभ के। इस धारा ने पाँच विषयों को विधायी सूची से बाहर कर दिया है और इन्हें मामलों के वर्गों के रूप में वर्णित किया गया है। सवाल यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि *7* वीं अनुसूची के तहत निवारक निरोध का कानून बनाए जाने से जुड़े कारणों के लिए विषयों की सभी या किसी भी श्रेणी का केवल चयन एक वर्गीकरण के बराबर है।

अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* में यथा अनुध्यात मामलों की संस्तुति। संघ सूची की प्रविष्टि *9* और समवर्ती की प्रविष्टि *3*

7 वीं अनुसूची की किराया सूची निम्नलिखित छह विषयों पर पूर्व-वायु निरोध के विषय पर संसद की विधायी शक्ति का दायरा निर्धारित करती है:

(1) भारत की रक्षा, *(2)* विदेश मामले, *(3)* से

भारत की सुरक्षा, *(4)* राज्य की सुरक्षा, *(5)* रखरखाव *237*

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक व्यवस्था, *(6)* समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव।

अनुच्छेद *22* का खंड *(4)* सभी के संबंध में आदेश देता है -

छह विषय जो कोई भी कानून एक सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के बिना तीन महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध के लिए प्रदान नहीं कर सकता है। खंड *(7)* परिस्थितियों के प्रिस्क्रिप्शन और उन मामलों के वर्गों के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा एक विज्ञापन दृश्य बोर्ड के साथ वितरण के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है जिसमें ऐसा वितरण किया जा सकता है। विधायी मेरी राय में खंड *(4)* और *(7)* के तहत अधिकार इन सभी छह विषयों तक फैला हुआ है। जब हिरासत का इरादा होता है तो सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए

होना।

उपखंड *(4)* में विषयों का उल्लेख किया गया है। असाधारण। नेरी और असामान्य प्रक्रिया को अपनाने का इरादा था

कुछ असामान्य मामलों में जिसके लिए प्रावधान किया जा सकता है

खंड *(7)* के अधीन संसदीय कानून द्वारा बनाया जाए।

तथापि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम *4* की धारा *121950* इस प्रक्रिया को काफी विपरीत कर दिया है

संविधान का उद्देश्य। इस धारा द्वारा अधिनियम *IV*

1950 ने पांच में सलाहकार बोर्ड को हटा दिया है।

उपर्युक्त छह विषयों में से और कॉम

में निर्धारित एक सलाहकार बोर्ड की स्पंदन प्रक्रिया

अनुच्छेद *22* के खंड *(4)* को निम्न में से एक में परिवर्तित कर दिया गया है -

ये छह विषय। यह देने से प्राप्त हुआ है

"परिस्थितियों के तहत" वाक्यांश का एक निर्माण

कौन से और उन मामलों के वर्ग जिनमें

यह विषयों के साथ सह-व्यापक और समरूप है।

कानून।

राय, इस निर्माण की

मुझमें

अनुच्छेद *22*, और सभी के लिए अनुच्छेद *22* का खंड *(4)* बनाता हैतंबू और उद्देश्य नगेटरी। इस तरह का निर्माण

खंड संविधान के बराबर होगा जिसमें कहा गया है

एक सांस जो निवारक निरोध का कानून नहीं ले सकता है

तीन से अधिक अवधि के लिए निरोध का प्रावधान

एक सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के बिना महीने और

वही सांस और पल यह कहते हुए कि संसद,

यदि वह ऐसा चाहे तो सभी या किसी के संबंध में ऐसा कर सकता है।

विधायी क्षेत्र में उल्लिखित विषय। अगर ऐसा है।

अगर ऐसा होता, तो यह पूरी तरह से अनावश्यक होतासर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[1950]* के एक मामले पर संविधान में इस तरह के संरक्षण के माध्यम से

238

जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से प्रभावित करता है। दूसरी ओर, यह अभिनिर्धारित करना खंड का एक उचित निर्माण होगा कि संविधान अधिकृत करता है।

संसद ने कहा कि गंभीर वर्गों के मामलों में या उन व्यक्तियों के समूहों के मामलों में जो अपरिवर्तनीय हैं या जिनकी गतिविधियाँ गुप्त हैं, एक सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समाप्त किया जा सकता है, जो राज्य के हित में आवश्यक है। धारा *12* के निर्माताओं द्वारा अपनाए गए अन्य निर्माण पर, संविधान को ऐसा कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करके खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, अगर यह इरादा था, तो यह बहुत स्पष्ट शब्दों में लेख का मसौदा तैयार करके इसका संकेत देता।

22 खंड *(4)* इस प्रकार हैः

" जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध को अधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड ने इस तरह के निरोध के कारण की पर्याप्तता की जांच नहीं की है।

*"*जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता*"* शब्द उस निर्देश के अनुरूप होते जो धारा *12* के निर्माताओं ने अनुच्छेद *22* खंड *(7)* पर रखा है।

मेरा यह भी मानना है कि निर्माण

विद्वान महान्यायवादी द्वारा अनुच्छेद *22* के उपसंहार *(7)* पर रखा गया और अधिनियम *IV* के निर्माताओं द्वारा अपनाया गया*1950* एक बहुत ही विसंगत स्थिति पैदा करता है। समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध के कानून के दृष्टिकोण से मामले की जांच की जा सकती है। इस विषय को *1950* के अधिनियम *IV* की धारा *9* के तहत रखा गया है। मान लीजिए कि एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है और

रेलवे प्रणाली में तोड़फोड़ होने का खतरा है और हिरासत के आदेश पारित करना आवश्यक हो जाता है

कुछ लोगों के खिलाफ। *1950* के अधिनियम *IV* के अनुसार ऐसी गंभीर स्थिति में एक सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया अनिवार्य है, जबकि दूसरी ओर, यदि किसी क्रिकेट मैच में अंपायर के गलत निर्णय के कारण या होली का त्योहार मनाने वाले व्यक्तियों के आचरण के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका है, तो तीन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों से परे हिरासत

एस सी आर।

239

सलाहकार मंडल के संदर्भ के बिना महीनों का आदेश दिया जा सकता है। क्या इस तरह का विसंगतिपूर्ण परिणाम संविधान निर्माताओं की परिकल्पना में हो सकता है*?* इस धारा पर मैं जो निर्माण करना चाहता हूं, वह दंडात्मक निरोध के कानून की योजना के अनुसार है। चोट भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है और यह दंडात्मक निरोध के उपखंडों में से एक है। विषय पर मामलों को वर्गीकृत किया गया है

विभिन्न समूहों, अर्थात्, साधारण चोट, गंभीर चोट, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट, स्वीकारोक्ति लेने के लिए गंभीर चोट, एक लोक अधिकारी को अपना कर्तव्य करने से रोकने के लिए गंभीर चोट, जल्दबाजी में कार्य से गंभीर चोट, और उकसाने पर गंभीर चोट। यहाँ तक कि सिम प्ले हर्ट को भी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमले के विषय से भी इसी तरह निपटा गया है। धारा *352* से *356* अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत मामलों से संबंधित है, यानी साधारण हमला, लोक सेवक पर हमला, महिलाओं पर हमला, चोरी करने के प्रयास में हमला, गलत के लिए हमला, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से सीमित करना और गंभीर उकसावे पर हमला को अलग से वर्गीकृत किया गया है। एक अन्य दृष्टांत दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा पूर्व-वायु धारा *107* से *110* में प्रस्तुत किया गया है। ये व्यक्तियों के विभिन्न समूहों से संबंधित हैं-एक वर्ग में आवारा, दूसरे में आदतन अपराधी, तीसरे में बुरे चरित्र और चौथे में शांति भंग करने वाले। ऐसा लगता है कि यह इनके समान ही है कि संविधान द्वारा यह निर्धारित किया गया होगा कि मामलों के वर्गों को संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। संविधान ने हिरासत की अवधि के अलग-अलग पैमाने को इस

विचार के साथ मान्यता दी है कि यह पकड़े गए कार्य की प्रकृति, सामान्य मामलों में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत, अधिक गंभीर मामलों में एक सलाहकार बोर्ड के हस्तक्षेप से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत, जबकि अधिक खतरनाक वर्ग के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मध्यस्थता के बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत और किए गए कार्यों के लिए अलग-अलग होगा।

परिस्थितियाँ। यह शायद ही कहा जा सकता है कि सभी

कब्र में निवारक निरोध के मामले

जुड़े कारणों के लिए

जनता के रखरखाव के साथ

ऑर्डर उसी पर खड़ा है

गुरुत्वाकर्षण की डिग्री में पैर रखना और उसी *240* के लायक है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

निरोध की अवधि और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से जुड़े सभी मामले उनकी गंभीरता के मामले में इस तरह के आधार पर खड़े हैं कि एक उदार उपचार की आवश्यकता है। यह सच है कि एक अर्थ में सभी व्यक्ति जो

भारत की रक्षा के लिए प्रतिकूल रूप से हो सकता है

कार्य करें

व्यापक रूप से एक समूह बनाने के लिए कहा जाता है और इसी तरह ऐसे व्यक्ति जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से कार्य करते हैं, वे एक और वर्ग बना सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इस व्यापक अर्थ में था कि वर्गीकरण

संविधान द्वारा अभिप्रेत था

खंड *(7)* या यह एक संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थ में अभिप्रेत था? यह याद रखना होगा कि कानून के तहत

खंड *(7)* का उद्देश्य लंबी अवधि के लिए निरोध प्रदान करना था और ऐसा कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से कम करता है और इस स्थिति में एक संकीर्ण प्रावधान देता है।

और इस अभिव्यक्ति का सीमित अर्थ कानूनों के निर्माण के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार होगा।

अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* का व्यापक निर्माण

विधायी सूची के सभी विषयों को खंड के दायरे में लाता है और एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से कम करता है। संविधान निर्माताओं की यह मंशा कभी नहीं हो सकती थी। संकीर्ण और प्रतिबंधित व्याख्या लेख की योजना के अनुरूप है और यह विधायी सूची के पूरे क्षेत्र पर भी काम करती है और उस क्षेत्र के भीतर यह प्रत्येक विषय के कुछ हिस्सों का सीमांकन करके काम करती है जिसके लिए गंभीर उपचार की आवश्यकता होती है। अगर मैं निष्कर्ष में ऐसा कह सकता हूं, तो धारा *12* भेड़ के बच्चे के बारे में है।

और एक ही वर्ग में तेंदुआ क्योंकि वे होते हैं

चौगुना। इस तरह का वर्गीकरण नहीं हो सका

संविधान निर्माताओं के विचारों में रहने के लिए

जब अनुच्छेद *22* में खंड *(7)* प्रस्तुत किया गया था। ऊपर दिए गए कारणों से, मेरी राय है कि खंड

12 1950 के अधिनियम *IV* की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं।

संविधान के अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* के अंतर्गत आता है और यह ऐसी विधि नहीं है जो उस खंड के दायरे में आती हो।

ऐसा होने पर, *1950* के अधिनियम *IV* की यह धारा अमान्य है। और इसके कारण याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया

उचित नहीं ठहराया जा सकता। एस. सी. आर. में कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

241

यह कानून जिसके तहत उसे किसी भी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है

जो भी हो।

यह तर्क दिया गया था कि यह न तो व्यावहारिक था और न ही

उन व्यक्तियों के पकड़े गए कृत्यों के मामले में किसी भी निश्चित आधार पर वर्गीकरण करना संभव है जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या राज्य की सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए प्रतिकूल प्रकृति की हैं। मेरे विचार से यह तर्क उचित नहीं है। इस तरह का वर्गीकरण भारत रक्षा अधिनियम के तहत नियमों में विनियमन *34* में "एक पूर्वाग्रहपूर्ण अधिनियम" को परिभाषित करके किया गया था। समूहों को सटीक रूप से निर्धारित करने या ऐसे समूहों के आचरण को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने में कठिनाई कानून के स्पष्ट प्रावधानों का पालन नहीं करने या इसकी अवज्ञा करने का कोई आधार नहीं है। अगर प्रावधानों का पालन करने के लिए गंभीर प्रयास किया गया तो मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।

खंड *(7)* का। मैं नहीं देख सकता कि अनिवार्य आवश्यकता

एक सलाहकार बोर्ड के गठन से ऐसा होने की संभावना है विनाशकारी या विनाशकारी परिणाम जो सभी मामलों में या

छह में से कम से कम पाँच में, कानून के विषय

इस आवश्यकता को समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। एक सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता है

संविधान की प्रस्तावना के साथ नृत्य करें और

सबसे कम न्यूनतम जो निवारक कानून बना सकता है

कुछ हद तक हिरासत एक डेमो के लिए सहनीय है

क्रेटिक संविधान। इस तरह के कानून के बिना भी कुछ औचित्य हो सकता है

एक की आवश्यकता

सलाहकार मंडल की होगी बैठक

खतरनाक परिभाषित किया गया

स्थितियाँ या

एक वर्ग से निपटें

जो लोग एक

राज्य लेकिन बिना

ऐसी सीमा

के लिए खतरा कानून होगा

सभी का विनाशकारी

व्यक्तिगत धारणाएँ

स्वतंत्रता। यह माना जाना चाहिए कि संविधान ने अपने नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की थी जब उसने खंड *(7)* में कुछ शर्तें निर्धारित की थीं और यह नहीं माना जा सकता था कि उसने उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी और खंड *(7)* में उपयोग किए गए शब्द केवल भ्रामक थे और उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं था।

1950 के अधिनियम *IV* की धारा *14* का विरोध किया गया है।

इस आधार पर कि यह उल्लंघन करता है और कम करता है

संविधान के अनुच्छेद *22 (5)* और *32* के प्रावधान। यह खंड इन शब्दों में है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

" (1) कोई भी न्यायालय इन उद्देश्यों के अलावा नहीं होगाः

उप-धारा *(2)* के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पक्ष, उसके समक्ष धारा *7* के तहत किए गए किसी संचार के सार के बारे में कोई बयान या कोई सबूत देने की अनुमति देता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ निरोध आदेश दिया गया है या उसके खिलाफ उसके द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन की अनुमति देता है।

इस तरह

आदेश,

और

कुछ भी होने के बावजूद

किसी अन्य कानून में निहित, कोई भी न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी से अपने समक्ष पेश करने, या किए गए किसी ऐसे संचार या अभ्यावेदन के सार का खुलासा करने, या किसी सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के उस हिस्से का खुलासा करने का हकदार नहीं होगा जो गोपनीय है।

(2) यह आई. एम. से दंडनीय अपराध होगा।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के पूर्व प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसे संचार या अभ्यावेदन की सामग्री होने का तात्पर्य रखने वाली कोई सामग्री या विषय का खुलासा करने या प्रकाशित करने के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, जैसा कि उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट किया गया हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी नहीं होगा

एक व्यक्ति द्वारा अपने कानूनी सलाहकार को किए गए प्रकटीकरण पर आवेदन करें जो निरोध आदेश का विषय है।

यह खंड लोहे के पर्दे की प्रकृति का है।

निवारक निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकरण के कार्यों के आसपास। संविधान ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार बताए जाने के अधिकार की गारंटी दी है। उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है *[*लेख के अनुसार। *22 (5)] ,* फिर भी धारा *14* उसे प्रस्तुत किए गए आधारों या न्यायालय में उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन की सामग्री के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है और इस निषेधाज्ञा के उल्लंघन को कारावास से दंडनीय बनाती है।

संविधान का अनुच्छेद *32 (1)*

संविधान इनमें है

शर्तेंः

"स्थानांतरित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल्यवान कार्यवाहियों की गारंटी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

उप-धारा *(4)* कहती हैः ---

"इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार नहीं होगा

इस संविधान द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा निलंबित।

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई प्राधिकरण एक पारित करता है

7 में उल्लिखित छह विषयों में से किसी से भी संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध का आदेश

अनुसूची, यह न्यायालय हमेशा निरोध को अवैध घोषित कर सकता है और बंदी को रिहा कर सकता है, लेकिन इस न्यायालय के लिए काम करना संभव नहीं है यदि उस पर दिए गए आधारों का खुलासा करने के खिलाफ निषेध है। आधारों की जांच करके ही यह कहा जा सकता है कि क्या आधार संविधान में निहित विधायी शक्ति के दायरे में आते हैं या इसके दायरे से बाहर हैं। पुनः बंदी पर आधार के रूप में कुछ दिया जा सकता है जो बिल्कुल भी आधार नहीं हैं। इस आकस्मिकता में अनुच्छेद *32* के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद *22 (5)* के तहत अधिकार को लागू करने के लिए इस अदालत का रुख करे कि उसे वे वास्तविक आधार दिए जाएं जिन पर निरोध आदेश आधारित है। यह न्यायालय अनुच्छेद *32* के तहत अपने कार्यों का प्रयोग करने और इस बिंदु पर न्याय करने से अक्षम हो जाएगा कि दिए गए आधार उपखंड की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं यदि वह उन आधारों को देखने के लिए खुला नहीं है जो प्रस्तुत किए गए हैं। यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति का एक गारंटीकृत अधिकार है कि उसके पास वही आधार हैं जो हिरासत के आदेश का आधार हैं।

यह। इस न्यायालय को मामले की जांच करने और यह देखने का अधिकार होगा कि क्या प्रस्तुत किए गए आधार वे आधार हैं जिनके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया है या उनमें कुछ अन्य अस्पष्ट या अप्रासंगिक सामग्री है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करने का पूरा उद्देश्य उसे इन आधारों का खंडन करने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सक्षम बनाना है। ताकि यह न्यायालय इस मौलिक अधिकार की रक्षा करने और उसे राहत देने में सक्षम हो सके, यह नितांत आवश्यक है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय को आधारों का खुलासा करने के लिए दंड के दंड के तहत निषिद्ध नहीं किया गया है और इस न्यायालय को आधारों पर गौर करने से अक्षम करने के लिए कानून द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। धारा *14* एक ठोस अपराध पैदा करती है यदि आधारों का खुलासा किया जाता है और यह न्यायालय पर एक कर्तव्य भी निर्धारित करता है

11-3 एस. सी. इंडिया/*58 244*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1930]

ऐसे आधारों के प्रकटीकरण की अनुमति देना। यह वस्तुतः संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत अधिकार के निलंबन के बराबर है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से

कठोर प्रावधान इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रशासन को असंभव बनाता है और साथ ही यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस न्यायालय से न्याय प्राप्त करने से रोकता है। इसलिए, मेरी राय में, यह धारा जब आधारों के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है, तो यह नागरिक को भाग *III* द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन या हनन करती है।

और क्या यह संसद की शक्तियों से परे है

हद तक।

उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि, मेरे

इंगित शून्य हैं और बंदी का निर्णय इन दोनों को नजरों से दूर रखते हुए मामला बनाया जाना चाहिए।

अधिनियम में प्रावधान। यदि धारा *12* और *14* को हटा दिया जाता है

विवादित विधान से, तब परिणाम यह होता है कि याचिकाकर्ता की नजरबंदी कानूनी नहीं है। क़ानून

ऐसे मामलों में महीने या उससे कम जो वह कर सकता थासंविधान के अनुच्छेद *22 (4)* के तहत और

इसलिए याचिकाकर्ता को न्यायोचित रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है तीन महीने की अवधि के लिए भी। मैं उसी के अनुसार

उसकी रिहाई का आदेश दें।

उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा नहीं करता।

इस पर कोई भी राय व्यक्त करना आवश्यक समझते हैं

अन्य बिंदु जिन पर पहले बहुत विस्तार से बहस की गई थी हम, अर्थात्, *(1)* क्या दायरा और सही अर्थ है

अभिव्यक्ति "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" में

संविधान का अनुच्छेद *21,* और *(2)* क्या है

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* और *19 (5)* का सटीक दायरासंविधान।

मुखर्जी जे.-यह एक आवेदन है जिसके तहत

संविधान का अनुच्छेद *32* एक रिट के लिए प्रार्थना करता है

उत्तरदाताओं पर बंदी प्रत्यक्षीकरण

याचिकाकर्ता को रिहा करें, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है

मद्रास राज्य के भीतर केंद्रीय जेल, कुड्डालोर में गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया।

याचिकाकर्ता, यह कहा जाता है, शुरू में गिरफ्तार किया गया था

17 दिसंबर, *1947* को मालाबार और अभियोजन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट रखने के लिए उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में मुकदमा शुरू किया गया था

245

एस सी आर।

कुछ हिंसक भाषण दिए। जबकि ये अपराधी मामले चल रहे थे, उन्हें एक आदेश दिया गया था

मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक के तहत हिरासत

22 अप्रैल, *1948* को आदेश अधिनियम। नजरबंदी का यह आदेश मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध माना गया था।

लेकिन उसी दिन जब फैसला सुनाया गया था,

उन पर नजरबंदी का दूसरा आदेश जारी किया गया। उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए उन्होंने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया

बाद के आदेश के संबंध में कोष, उसका आवेदन

केशन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि क्योंकि वह नहीं था

तीन आपराधिक मामलों में से एक में जमानत दी गई कि

उसके खिलाफ लंबित थे, हिरासत नहीं हो सकी

गैरकानूनी कहा जाए। हालाँकि, स्वतंत्रता दी गई थी

यदि और जब उसे हिरासत में लिया जाता है तो उसे अपने आवेदन को नवीनीकृत करने के लिए

आपराधिक कार्यवाही के तहत कार्रवाई बंद हो गई। दो में तीन आपराधिक मामलों में से मुकदमे से पहले

मजिस्ट्रेट का कार्यकाल *23* फरवरी, *1949* को समाप्त हो गया और याचिकाटियोनर को *6* के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी

26 सितंबर, *1949* को अपील में खारिज कर दिया गया था। के रूप मेंतीसरे मामले के संबंध में उनका मुकदमा सत्रों द्वारा चलाया गया था।

उत्तरी मालाबार के न्यायाधीश को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

अपील करें। याचिकाकर्ता ने एक नया आवेदन किया उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए प्रार्थना की

मद्रास रखरखाव के तहत उनकी नजरबंदी का सम्मान

लोक व्यवस्था अधिनियम और यह आवेदन, जो था

उसने अपनी कैद की सजा पूरी करने के बाद सुना

ऊपर उल्लिखित, जनवरी, *1950* में खारिज कर दिया गया था।

25 फरवरी, *1950* को निवारक निरोध अधिनियम

संसद द्वारा पारित किया गया था और *1* मार्च कोइसके बाद, के तहत आवेदक की नजरबंदी

मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट रद्द कर दिया गया था

एड और उन्हें हिरासत का एक नया आदेश दिया गया था

निवारक निरोध अधिनियम की धारा *3 (1)* के तहत

1950. उत्तरदाताओं की ओर से हिरासत

याचिकाकर्ता को शक्ति के आधार पर न्यायोचित ठहराने की मांग की जाती है

1950 का निवारक निरोध अधिनियम। पद की स्थितिदूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से लिया गया

यह है कि उक्त अधिनियम अमान्य है और अधिकार के बाहर है

कुछ *246* के साथ संघर्ष में होने के कारण स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि निरोध

याचिकाकर्ता का अमान्य है और उसे होना चाहिए

आज़ादी में।

जिन विवादों को बील द्वारा आगे रखा गया है

श्री नाम्बियार जो याचिका के समर्थन में पेश हुए,

इन्हें चार शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी पहली रचनायह है कि निवारक निरोध के रूप में, सार में, एक

के माध्यम से एक व्यक्ति की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध

भारतीय क्षेत्र से बाहर, यह दायरे में आता हैसंविधान के भाग *III* के अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)*

जो मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद के खंड *(5)* के तहत, इस पर लगाया गया कोई प्रतिबंध

मुक्त आवाजाही का अधिकार उचित होना चाहिए और होना चाहिए

आम जनता के हित में निर्धारित किया जाए। सवाल यह है कि क्या यह उचित है या नहीं

न्यायसंगत मामला जिसका निर्धारण किया जाना है

अदालत। यह कानूनी स्थिति होने के कारण विद्वान वकील

धारा *3,7,10,11,12,13* और *14* में पूरी तरह से एक है उचित है और उस आधार पर अमान्य किया जाना चाहिए।

विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा विवाद

वकील का कहना है कि विवादित कानून विवाद में है

संविधान के अनुच्छेद *21* के प्रावधान के साथ खिलवाड़ क्योंकि यह प्रति के अभाव के लिए प्रावधान करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने वाले व्यक्ति की सोनल स्वतंत्रता। यह तर्क दिया जाता है कि शब्द

' यहाँ *'*विधि*'* का अर्थ किसी विशेष विधायी अधिनियमन से नहीं है या उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है देश का सामान्य कानून, जो प्रक्रिया के संबंध में प्राकृतिक न्याय के उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है जिन्हें सभ्य न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों में मौलिक मानसिक माना जाता है।

विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि

निवारक निरोध के संबंध में प्रक्रिया, यदि कोई हो, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद *22* द्वारा निर्धारित किया गया है, जो स्वयं फंडा पर अध्याय में जगह पाता है। मानसिक अधिकारों को प्रक्रिया के उन सामान्य नियमों पर हावी होना चाहिए जिन पर अनुच्छेद *21* द्वारा विचार किया गया है लेकिन

जिन मामलों के लिए अनुच्छेद *22* में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में अनुच्छेद *21* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में सामान्य प्रावधान किया गया है।

247

एस सी आर।

आवेदन करना चाहिए। उन्होंने अपने तर्क के दौरान संकेत दिया हैइस तरह की प्रक्रिया की आवश्यकताएँ क्या हैं और

कि निवारक की धारा *12* का प्रावधान निरोध अधिनियम के अनुच्छेद *22 (7)* के साथ टकराव है

संविधान।

इस आवेदन के समर्थन में अंतिम तर्क है

कि पूर्ववत की धारा *3* और *14* के प्रावधान

विचाराधीन निरोध अधिनियम अमान्य हैं क्योंकि वे ले जाते हैं और मौलिक अधिकार को पूरी तरह से निरर्थक बनाना

जैसा कि अनुच्छेद *32* में प्रावधान किया गया है, संवैधानिक उपचार

संविधान से।

इन बिंदुओं पर चर्चा करते समय यह अच्छा होना चाहिए कि

भारतीय संविधान की सामान्य योजना को ध्यान में रखें

मौलिक के संरक्षण से संबंधित शिक्षा

नागरिकों के अधिकार और लागू की गई सीमाएँ शासन की विधायी शक्तियों पर यह सम्मान

मन में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है।

ट्यूशन और हालांकि इसने कई को अपनाया है

अंग्रेजी संसदीय प्रणाली के सिद्धांत

है।

निरपेक्ष के अंग्रेजी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया

विधान के मामलों में संसद की सर्वोच्चता।

इस संबंध में इसने अमेरिकी संविधान का पालन किया है।

राज्य और अन्य प्रणालियाँ

उस पर मॉडल। ध्यान देने योग्य

उनके राजनीतिक चरित्र का प्रतिनिधित्व करना

संस्थान, अमेरिकी सीमाओं का सम्मान करते हैं

के कार्य पर उनके संविधान द्वारा अधिरोपित सरकार, विधायी और कार्यपालिका दोनों, अनिवार्य रूप से

सार्वजनिक और निजी अधिकारों का संरक्षण करना। वे.

जिसे वर्णित किया गया है उस पर एक जाँच के रूप में कार्य करें

बहुमत की निरंकुशता; और जैसा कि में देखा गया थाहुर्टाडो बनाम का मामला। कैलिफोर्निया के लोग *(1)*

" एक ऐसी सरकार जो जीवन, स्वतंत्रता और

अपने नागरिकों की संपत्ति, हर समय के अधीन

पूर्ण स्वभाव और सम का असीमित नियंत्रण

सत्ता का सबसे लोकतांत्रिक भंडार, आखिरकार है

लेकिन एक निरंकुशता "। भारत में यह संविधान है कि

सर्वोच्च है और संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल भी

लेचरों को केवल उनकी सीमाओं के भीतर कार्य नहीं करना चाहिए तीनों में सीमांकित संबंधित विधायी क्षेत्र

(1) 110 यू. एस. *516*

248

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान की सातवीं अनुसूची में आने वाली सूचियाँ

यह, लेकिन संविधान का भाग *III* गारंटी देता है कि

नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार जो कानूनस्वायत्त प्राधिकारी किसी भी कारण से उल्लंघन नहीं कर सकते। एक कानून

कानून के वैध होने के लिए, सभी मामलों में, अनुरूप होना चाहिए।

संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ और यह के लिए है न्यायपालिका यह तय करेगी कि क्या कोई

अधिनियम है

असंयमित

ट्यूशनल या नहीं।

अनुच्छेद *13 (2)*

इस पर अनिवार्य है

इंगित करें और स्पष्ट रूप से प्रदान करें कि राज्य नहीं करेगा

कोई भी कानून बनाएँ जो अधिकार को छीन ले या कम कर दे

इस भाग द्वारा प्रदत्त और उल्लंघन में बनाई गई कोई विधि

इस खंड का उल्लंघन उल्लंघन की सीमा तक होगा।

उन सभी मौजूदा कानूनों को मान्य करता है जो इसके साथ असंगत हैं संविधान के इस भाग के प्रावधान।

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार

ट्यूशन को सात शीर्षों या केट के तहत वर्गीकृत किया गया है।

गोरियों। वे इस प्रकार हैं:

(1) समानता का अधिकार*;*

(2) स्वतंत्रता का अधिकार*;*

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार*; (5)* सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार*;*

(6) संपत्ति का अधिकार*;* और

(7) संवैधानिक उपचार का अधिकार।

व्यवस्था कई मायनों में भिन्न है

जिसे अमेरिका में अपनाया गया था

संविधान और भालू

कुछ बिंदुओं पर एक समानता

में समान घोषणाएँ

अन्य देशों के संविधान।

मौलिक अधिकारों के विभिन्न वर्गों में से

ऊपर के बारे में बात करते हुए, हम यहाँ मुख्य रूप से चिंतित हैं

स्वतंत्रता का अधिकार जो चार अनुच्छेदों में वर्णित है

अनुच्छेद *19* से शुरू होकर और अधिकार के साथ भीसंवैधानिक उपचार जो सन्निहित है

में

अनुच्छेद *32.*

अनुच्छेद *10* स्वतंत्रता के कुछ रूपों की गणना करता है।

या

स्वतंत्रता,

जिसके निष्कर्षण की गारंटी है

अनुच्छेद *20* में कुछ संरक्षण हैं -

संविधान।आपराधिक अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों के मामलों में दिया जाता है।

अनुच्छेद *21* सामान्य शब्दों में बताता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को छोड़कर, उसे अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।

249

एस सी आर।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। लेख *22* इस संबंध में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है

गिरफ्तारी और निरोध और अपवाद के रूप में इस प्रकार बनाए गए नियम, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं

निरोध का विशेष रूप जिसे निवारक के रूप में जाना जाता है

नजरबंदी।

श्री नाम्बियार द्वारा पहला तर्क दिया गया

इस प्रश्न पर विचार करना शामिल है कि क्या

निवारक निरोध, जो विषय वस्तु है विवादित विधायी अधिनियम, के भीतर आता है

संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* की परिधि, समझौता

जिसे पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है

भारत का क्षेत्र मौलिक अधिकारों में से एक है

सभी नागरिकों को गारंटी। अगर यह इसके भीतर आता है

उपखंड, यह विवादित नहीं है कि अनुच्छेद *19* का खंड *(5)*

इसकी ओर आकर्षित किया जाएगा और यह अदालतों के लिए होगायह तय करने के लिए कि क्या इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं

संसद द्वारा अधिकार उचित प्रतिबंध हैं और

खंड द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं

(5) लेख से।

इस शब्द की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।

' भारतीय कानून में 'निवारक निरोध', हालांकि विधान के किसी विषय का वर्णन जिसमें यह हुआ

भारत सरकार अधिनियम, *1935* की विधायी सूचियाँ, और सूची *I* और वस्तु की वस्तु *9* में उपयोग किया गया है

3 संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची *III*

ट्यूशन। अभिव्यक्ति की उत्पत्ति भाषा में हुई है।

इंग्लैंड में न्यायाधीशों या लॉ लॉर्ड्स द्वारा उपयोग किया जाता है जबकि

विनियमन के तहत निरोध की प्रकृति की व्याख्या करना

*14 ((*ख*)* राज्य समेकन रक्षा अधिनियम, *1914,*

प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप पर पारित; औरउसी भाषा को दोहराया गया था जिसके संबंध में

पिछली दुनिया के दौरान बनाए गए आपातकालीन नियमयुद्ध। 'निवारक' शब्द का उपयोग विरोधाभास में किया जाता है।

'दंडात्मक' शब्द। शब्दों को उद्धृत करने के लिए

रेक्स बनाम में लॉर्ड फिनले। होलीडे *(1),* यह एक नहीं है दंडात्मक लेकिन एक एहतियाती उपाय "। उद्देश्य यह है कि

किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दंडित करने के लिए नहीं बल्कि

ऐसा करने से पहले उसे रोकें और उसे ऐसा करने से रोकें

करते हैं। न कोई अपराध साबित होता है और न ही कोई आरोप सूत्र।

टेड; और इस तरह की नजरबंदी का औचित्य संदेह है

(1) [1917] ए. सी. *260* पी. *269 .*

जिसे केवल कानूनी साक्ष्य *(1)* द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।अमेरिका में इस तरह की नजरबंदी अज्ञात है। यह था।

केवल युद्ध के दौरान इंग्लैंड का सहारा लिया। समय लेकिन नहीं

दुनिया में जिस देश के बारे में मुझे पता है, उसने यह बनाया है उनके संविधान का एक अभिन्न अंग जैसा कि किया गया है

भारत में। यह निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह

नीति के प्रश्नों पर अटकलें लगाना हमारा काम नहीं है या

उन कारणों का पता लगाने का प्रयास करने के लिए जिन्होंने प्रतिनिधि का नेतृत्व किया

इस तरह के कठोर प्रावधान करने के लिए हमारे लोगों के संवेदनशील

स्वयं संविधान में, जिसे माना नहीं जा सकता है स्वतंत्रता पर सबसे हानिकारक अतिक्रमण के रूप में

लोगों के संबंध।

एहतियात के तौर पर भी एक आदमी को हिरासत में लेना

नागरिक या विदेशी, जिससे वह वंचित नहीं रहेगा उसका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सिवाय इसके कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, की आवश्यकताएँ

लेख। *21* निश्चित रूप से इसका पालन करना होगा,

निवारक निरोध को कानून में वैध बनाना। ये क्या हैं*?*

यह अनुच्छेद *21* के तुरंत बाद आता है। यह सभी के लिए सुरक्षित है। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ मौलिक अधिकार

और हिरासत, और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अपवाद के रूप में इस प्रकार घोषित अधिकारों के लिए, कुछ विशिष्ट बनाता है

निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान। विषय-वस्तु।निवारक निरोध में निर्दिष्ट किया गया है और इसका गठन किया गया है

संघ विधायी सूची में मद संख्या *9* और यह भी

फॉर्म आइटम

नंबर *3*

समवर्ती सूची में। के तहत

संविधान का अनुच्छेद *246*, संसद और

राज्य विधानमंडलों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। अपने संबंधित अधिकारियों के दायरे में विषय।

अनुच्छेद *22* का खंड *(3)* स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि -

किसी के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कानून। एकमात्र

मौलिक अधिकार जो गारंटीकृत हैं

निवारक निरोध के मामले में संविधान

और जो उस हद तक प्रतिबंध लगाता है

इस संबंध में विधायी विधायी शक्तियों का प्रयोग

(1) लार्ड मैकमिलन द्वारा लिवर्साइन वी. में। एंडरसन *[1912]* ए. सी. *206* पी. *254 .*

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

251

अनुच्छेद *22* के खंड *(4)* से खंड *(7)* में निहित है। खंड

(4) यह निर्धारित करता है कि निवारक निरोध का कोई कानून नहीं है किसी व्यक्ति को एक अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करेगा।

तीन महीने से अधिक समय तक, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड न हो

उपखंड *(क)* में निर्धारित तरीके से गठित

खंड की समाप्ति से पहले रिपोर्ट की गई है

अवधि कि इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है।

निरोध की अवधि, किसी भी स्थिति में, अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम जिसकी अध्यक्षता करने का संसद को अधिकार है

खंड *(7) (ख)* के अधीन अभिकथन। संसद को भी दिया जाता है

परिस्थितियों को निर्धारित करने का अधिकार और

मामलों का वह वर्ग जिसके तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए

की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध

सलाहकार मंडल। एक सुरक्षा प्रदान की गई है खंड *(5)* में निहित सभी मामलों के लिए और जो

यह निर्धारित करता है कि आदेश देने वाला प्राधिकारी

ऐसा व्यक्ति जिसके आधार पर आदेश दिया गया है बनाया और उसे जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा

यहाँ, प्राधिकरण हिरासत के आधार देते हुए ऐसे तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह विचार करता है।

सार्वजनिक हित का खुलासा करने के खिलाफ।

जिस सवाल पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या

निवारक निरोध से संबंधित एक कानून न्यायसंगत है

संविधान का अनुच्छेद *19 (5)* इस प्रकार है कि में मुक्त आवाजाही के अधिकार को दूर या कम करता है

खंड *(1) (*घ*)* द्वारा प्रत्याभूत भारत का राज्यक्षेत्र

लेख। ऊपर जो कहा गया है, उससे यह देखा जाएगा।

वह अनुच्छेद *22* विशेष रूप से विषय से संबंधित है

और स्पष्ट रूप से दूर ले जाता है

निवारक हिरासत

द.

नजरबंदी

गिरफ्तारी से संबंधित मौलिक अधिकार और

अनुच्छेद के खंड *(1)* और खंड *(2)* में उल्लिखित

ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है जो संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित

संविधान के अनुच्छेद *246* के तहत

विधायी सूचियों में प्रासंगिक आइटम। मैं चला जाऊँगा।इस पल के लिए सवाल यह है कि कितनी दूर है

न्यायालय की तर्कसंगतता या अन्यथा की जांच कर सकता है

252 से संबंधित किसी भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

[1950]

लेख के सटीक दायरे और अर्थ पर विचार करना।*21 ;* लेकिन यह बहुत विवाद से परे है कि अब तक

मूल कानून का संबंध है, संविधान का अनुच्छेद *22*

यह विधायिका को लेने का स्पष्ट अधिकार देता है

गिरफ्तारी से संबंधित मौलिक अधिकारों को दूर करना और

उल्लेख, जो पहले दो खंडों द्वारा सुरक्षित हैं

लेख। इस विषय पर कोई भी कानून केवल

खंड *(4)* से *(7)* की आवश्यकताओं के अनुरूप होना और

बशर्ते कि किया जाता है, भाषा में कुछ भी नहीं है

नियोजित और न ही उस संदर्भ में जिसमें यह दिखाई देता है सुझाव के लिए कोई भी आधार प्रदान करता है कि इस तरह के कानून को

अपने चरित्र में उचित हो और यह होगा कि

उस आधार पर न्यायालय द्वारा समीक्षित। दोनों लेख

19 और *22* संविधान के एक ही भाग में होते हैं।

और वे दोनों मौलिक निर्धारित करने का इरादा रखते हैं

जिन अधिकारों की संविधान गारंटी देता है। यह ठीक है। यह तय किया कि संविधान की व्याख्या एक में की जानी चाहिए

और यह धारणा होनी चाहिए कि कोई संघर्ष याइसके निर्माताओं द्वारा तिरस्कार का इरादा किया गया था। आपस में

संविधान के शब्दों से पहले, वही सिद्धांतनिस्संदेह लागू होते हैं जो निर्माण में लागू होते हैं

एक क़ानून, लेकिन जैसा कि लॉर्ड राइट द्वारा देखा गया था

जेम्स वी. ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल *(1),* "अंतिम

उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों पर परिणाम निर्धारित किया जाना चाहिए।

वैक्यू में नहीं बल्कि एक एकल परिसर में होने के रूप मेंउपकरण जिसमें एक भाग प्रकाश डाल सकता है

अन्य "। " "उनके प्रभु ने आगे कहा", संविधान को संघीय समझौते के रूप में वर्णित किया गया है।

और निर्माण को अपने सभी भागों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।

. मुझे ऐसा लगता है कि कोई संघर्ष या विरोध नहीं है

संविधान के दो प्रावधानों और स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की योजना और भाषा की जांच के बीच अंतर यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि कौन सा खंड

(1) ((घ) अनुच्छेद *19* का विचार निरोध से स्वतंत्रता नहीं है, या तो दंडात्मक या निवारक है; यह नागरिक अधिकार के एक अलग पहलू या चरण से संबंधित है और बात करता है।

स्वतंत्रता।

(क) पी. पर ए. सी. *578*। *613 .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

253

एस सी आर।

अनुच्छेद *19,* जो इस श्रृंखला का पहला है

लेख, स्वतंत्रता की सात किस्मों या रूपों की गणना करता है

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ शुरुआत और

किसी भी व्यापार, पेशे का अभ्यास करने के स्वतंत्र अधिकार के साथ समाप्त

या व्यापार। अनुच्छेद *19* से *22* में घोषित अधिकार

स्वतंत्रता की पूरी सूची को निश्चित रूप से समाप्त न करें।जो कानून के तहत लोगों के पास है। का उद्देश्य

संविधान के निर्माताओं को स्पष्ट रूप से गणना करनी है

और स्वतंत्रता के उन रूपों की गारंटी देते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं।

संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध श्रेणियाँ

लेखकों को मौलिक माना जाता है औरसमुदाय के लिए महत्वपूर्ण।

निरपेक्ष या निरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं हो सकती।

अनियंत्रित स्वतंत्रता जो पूरी तरह से संयम से मुक्त है, उसके लिए

और अव्यवस्था। कब्ज़ा

अराजकता की ओर ले जाएगा

और सभी अधिकारों का आनंद, जैसा कि द्वारा देखा गया था। द. जैकबसन बनाम में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। मैसाचुसेट्स

(1), ऐसी उचित शर्तों के अधीन हैं जो हो सकती हैं

समुदाय की नैतिकता। इसलिए यह सवाल परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करने के प्रत्येक मामले में उत्पन्न होता है

व्यक्ति और समाज का। कुछ मामलों में,मुक्त व्यायाम पर प्रतिबंध लगाना होगा

के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत अधिकार

समाज; दूसरी ओर, सामाजिक नियंत्रण जो मौजूद है

सार्वजनिक भलाई के लिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि

व्यक्तिगत अधिकारों के नुकसान के लिए दुरुपयोग किया जाए और

उसे अपने जीवन का आदेश दें जैसा वह चाहता है, कहने के लिए जो वह चाहता है, जाने के लिएजहाँ वह किसी भी व्यापार, व्यवसाय या आह्वान का पालन करेगा।

अपनी खुशी से और कोई और काम करना जो वह कर सकता है कानूनी रूप से किसी अन्य द्वारा अनुमति या बाधा के बिना करें

व्यक्ति। दूसरी ओर बहुत सुरक्षा के लिए "

इन स्वतंत्रताओं से समाज को कुछ निश्चित रूप से खुद को लैस करना चाहिए।

इसका

शक्तियाँ। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता मूल्यवान नहीं होगी।

नाम

यदि इसका किसी के द्वारा दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन किया जा सकता है

गलत-कर्ता

और अगर उसकी संपत्ति या संपत्ति का शिकार किया जा सकता है

एक चोर या एक लुटेरे द्वारा। इसलिए समाज,सुरक्षा के लिए कुछ शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है

इन स्वतंत्रताओं में से और गिरफ्तार करने, जेल की खोज करने और

(1) 197 यू. एस. *11.*

उचित रूप से प्रयोग किया जाता है, वे स्वयं सुरक्षा उपाय हैंस्वतंत्रता, लेकिन उनका निश्चित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है। द.

पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है। बिना कोई कारण बताए; वे उसकी खोज कर सकते हैं

थोड़े से बहाने पर संपत्ति; वह उप हो सकता है एक नकली मुकदमे में शामिल किया गया और यहां तक कि अपराधों के लिए दंडित किया गया

कानून के प्रति असंवेदनशील। अतः संविधान क्या है,

लोगों के अधिकारों की घोषणा करने का प्रयास है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना और

सामाजिक नियंत्रण।

मुझे ऐसा लगता है कि संविधान का अनुच्छेद *19*

लोक कल्याण या सामान्य नैतिकता। दूसरी ओर, अनुच्छेद *20,21* और *22* मुख्य रूप से संबंधित हैं -

समाज के हित और वे सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिसके भीतर राज्य नियंत्रण का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद *19* "स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और उल्लेख करता है

इसके कई रूप और पहलू जो सुरक्षित हैं

"स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति का उपयोग न करें और वे उन प्रतिबंधों को निर्धारित करें जिन पर प्रतिबंध लगाए जाने हैं

राज्य नियंत्रण जहाँ एक व्यक्ति की मांग की जाती है

अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मूल्यवान। का अधिकार अपने जीवन और अंगों की सुरक्षा और प्रति व्यक्ति का आनंद लेने के लिए

भौतिक रूप से स्वतंत्रता के अर्थ में सोनल स्वतंत्रता

किसी भी प्रकार का तनाव और जबरदस्ती, अंतर्निहित जन्म है।

दूसरों को उनके साथ हस्तक्षेप करने से रोकना और इसलिए उन्हें "स्वतंत्रता" के संदर्भ में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

विशेष कार्य करना। इम का भी कोई सवाल नहीं है।

व्यक्तियों की गतिविधियों पर सीमाएँ लगाना जहाँ तक इन अधिकारों के प्रयोग का संबंध है। इनके लिए

कारण, मुझे लगता है, इन अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है

संविधान के अनुच्छेद *19* में। एक व्यक्ति हो सकता है

केवल कार्रवाई द्वारा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

255

एस सी आर।

राज्य का, या तो किसी दंड के प्रावधानों के तहतअधिनियमन या किसी अन्य जबरदस्ती के अभ्यास में

कानून के तहत इसमें निहित प्रक्रिया। क्या है संविधान इसलिए क्या शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना है

आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का

युगल। राज्य प्राधिकरण पर प्रतिबंध इस प्रकार काम करते हैं -

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी

के लिए

लोगों को जीवन का आनंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जोइस प्रकार विधियों को छोड़कर अनुल्लंघनीय घोषित किए जाते हैं

इन लेखों में बताया गया है। मेरी राय में, समूहअनुच्छेद *20* से *22* में संपूर्ण को शामिल किया गया है

सुरक्षा

वंचितता के संबंध में संविधान द्वारा गारंटीकृत

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के संबंध में

मूल के साथ-साथ प्रक्रियात्मक कानून के लिए। यह है कि

नहीं।

यह कहना सही है, जैसा कि मैं बाद में पूरी तरह से दिखाऊंगा, कि

अनुच्छेद *21* केवल प्रक्रिया के मामलों तक ही सीमित है।

एक ठोस कानून होना चाहिए, जिसके तहत

राज्य को एक व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने का अधिकार है और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऐसा कानून एक वैध कानून होना चाहिए।

जिसे विधायिका इसके भीतर अधिनियमित करने के लिए सक्षम है इसे सौंपी गई शक्तियों की सीमाएँ और जो नहीं

किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना जो

संविधान निर्धारित करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति नहीं हो सकता है पूर्व कार्योत्तर कानून के तहत दोषी ठहराया गया या दंडित किया गया, या

कानून जो अभियुक्त को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर करता है

आपराधिक मुकदमे में या उसी अपराध के लिए उसे दंडित करता है

एक बार से अधिक। . ये हैं सुरक्षा के प्रावधान

अनुच्छेद *20* के अनुसार। पुनः गिरफ्तारी का प्रावधान करने वाला कानून और

निरोध को निर्धारित सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए।

खंड *(1)* और *(2)* या अनुच्छेद *22* द्वारा। ये प्रावधान

वास्तव में मामले में स्पष्ट रूप से वापस ले लिया गया है

निवारक हिरासत

और बहुत कुछ की सुरक्षा

कमजोर और क्षीण चरित्र को प्रतिस्थापित किया गया है

उनके स्थान पर; लेकिन यह नीति का सवाल है।संविधान द्वारा अपनाया गया जो हमसे संबंधित नहीं है

बिल्कुल भी। अतः स्थिति यह है कि

संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

इस हद तक संरक्षण कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है

एक द्वारा पारित एक वैध वैध कानून के तहत छोड़कर इन अधिकारों का

उल्लिखित सीमाओं के भीतर सक्षम विधानमंडल

ऊपर और प्रक्रिया के अनुसार जो

इस तरह का कानून निर्धारित करता है। अनुच्छेद *19,* दूसरी ओर*, 256*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

नागरिक स्वतंत्रता के कुछ विशेष रूपों का वर्णन करता है

अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकारों से स्वतंत्र रूप से

21. उनमें से अधिकांश संबंधित या आश्रित हो सकते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लेकिन इसके साथ समान नहीं हैं; और अनुच्छेद *19* का उद्देश्य सीमाओं को इंगित करना है।

जिसके भीतर राज्य, कानून द्वारा, लागू कर सकता है

व्यक्तियों। तर्कसंगतता या अन्यथा या ऐसा कानून वास्तव में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

कई खंडों या अनुच्छेद में निर्धारित सीमा

स्वतंत्रता। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

वे अधिकार जो लोग किसी भी राज्य के तहत प्राप्त करते हैं और

और निश्चित निश्चित अभिव्यक्ति

ऐसे मामले सटीक हैं इरादे का

विधायिका का है

हो चुका है

संविधान द्वारा परिवर्तनीय मानकों को प्राथमिकता दी गई

न्यायपालिका स्थापित हो सकती है। हम पाते हैं।

जो कि

दे।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित

अधिकारमें लगभग एक ही शब्दों में क्लैर्ड

द.

आयरिश

संविधान का अनुच्छेद *40 (1) (4) (1)* जिसमें से

लेट जाता है

कि "कोई भी नागरिक वंचित नहीं रहेगा"

उसका

व्यक्तिगत

कानून के अनुसार स्वतंत्रता "। संविधान में

व्यक्ति को अलंघनीय घोषित किया गया है और कोई सीमा नहीं है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लागू या वंचित किया जा सकता है

अनुच्छेद *74)*। जापानी संविधान का अनुच्छेद *31* भारतीय संविधान के अनुच्छेद *21* का निकटतम समानांतर है।

ट्यूशन और भाषा लगभग समान हैं। यह है। संविधान द्वारा व्यवहार में अपनाई गई योजना

पर अध्याय में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ

मौलिक अधिकार और इसलिए मेरी राय में,

किसी अधिनियम की वैधता निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण

जिसके तहत किसी व्यक्ति को वंचित करने की कोशिश की जाती है

उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नहीं पाया जाना चाहिए

अनुच्छेद *19,* लेकिन निम्नलिखित तीन अनुच्छेदों में संविधान। अनुच्छेद *20* का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

जहाँ तक निवारक निरोध से संबंधित कानून है

चिंतित हैं।

श्री नांबियार का पूरा प्रयास अदालत की रिपोर्टों को शीर्ष पर रखने का रहा है

एस सी आर।

257

यह स्थापित करें कि संविधान का अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* पढ़ा गया है

अनुच्छेद *19 (5)* मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है।

व्यक्तिगत के मूल कानून के संबंध में नागरिकों का

स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद *21* पुनः संरक्षण का प्रतीक है।

इन प्रावधानों को गलत कोण से देखना यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद *19* उपखंड से संबंधित है

केवल विरोधी कानून, और न ही अनुच्छेद *21* केवल मामलों के साथप्रक्रिया। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान

खंड *(5)* और अनुच्छेद *21* के साथ पठित अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* एक-दूसरे के पूरक हैं।

सामग्री और

असंवेदनशील नहीं

दोनों प्रावधानों की विषय वस्तु

हैं।

और वे पूरी तरह से अलग सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं।

अनुच्छेद *19* में "जीवन के अधिकार" का कोई उल्लेख नहीं है।

हालाँकि यह प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण है।

जिसके लिए अनुच्छेद *21* में प्रावधान किया गया है। अगर

विद्वान वकील का तर्क सही है, हम यह मानना होगा कि किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है

जहाँ तक जीवन के अधिकार के संबंध में संविधान द्वारामूल कानून का संबंध है। दूसरे स्थान पर; यहाँ तक कि

यदि आंदोलन की स्वतंत्रता को एक माना जा सकता है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तत्व, निश्चित रूप से हैं

अवधारणा में शामिल अन्य तत्व और स्वीकार्य रूप से

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अन्य रूपों के लिए कोई प्रावधान नहीं है

संविधान के अनुच्छेद *19 (5)* में पाया जा सकता है। इसके अलावा

अधिक अनुच्छेद *19* केवल नागरिकों पर लागू होता है, जबकि

नागरिकों के साथ-साथ विदेशी भी। एकमात्र सही तरीका इन विसंगतियों से बचना दो प्रावधानों की व्याख्या करना है।

विभिन्न विषयों पर लागू होने के रूप में और यह होगा

अगर हम योजना को ध्यान में रखते हैं तो सही निष्कर्ष निकलें

जो लेखों के इस समूह का आधार है।

अब मैं अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* की भाषा की ओर मुड़ूंगा।

और देखें कि क्या वास्तव में निवारक हिरासत आती है

अपने दायरे में। अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में प्रावधान है कि सभी

नागरिकों को स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा।

भारत का क्षेत्र। दो उपखंड जो

उपखंड *(घ)* के तुरंत बाद आते हैं और अंतरंग होते हैं

इसके साथ जुड़े हुए, इन शब्दों में हैं:

" (ई) देश के किसी भी हिस्से में रहना और बसना।

भारत का क्षेत्र; *258*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

(च*)* संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करना।

खंड *(5)* इन तीनों उपखंडों से संबंधित है और यह बताता है कि उनमें कुछ भी ओपेरा को प्रभावित नहीं करेगा

जहाँ तक वह अधिरोपित करता है, किसी विद्यमान विधि की, याराज्य को कोई कानून बनाने से रोकें,

किसी भी अभ्यास पर उचित प्रतिबंध

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार या तो

आम जनता के हितों या उनकी सुरक्षा के लिए

किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित।

मैं विद्वान महान्यायवादी से सहमत हूँ कि

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* का अर्थ लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अभिव्यक्ति "भारत के पूरे क्षेत्र में",

और यह एक विशेष और विशेष प्रकार का अधिकार है। ,

पूरे भारतीय क्षेत्र में मुक्त आवाजाही,

यही संविधान का उद्देश्य और उद्देश्य है -

सुरक्षित। अगले उप-उपखंड खंड में, रहने का अधिकार और

"भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में" बसने की अनुमति दी गई है। और यहाँ फिर से भौतिक चीज़ का अधिकार नहीं है

निवास या बस्ती लेकिन रहने या बसने का अधिकार

भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में। एक अनुरूप के लिए प्रावधान, हम अनुच्छेद *301* का उल्लेख कर सकते हैं जो कहता है कि

इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वाणिज्य

और भारत के पूरे क्षेत्र में संभोग

मुक्त हो जाओ। अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंड *(घ)* का अर्थ

यह स्पष्ट होगा कि क्या हम इसे उपखंड *(ई)* के साथ लेते हैं और

(च*),* जिन सभी को खंड में एक साथ जोड़ा गया है*(5)* और जिनमें से सभी के लिए समान प्रतिबंध शामिल हैं

याद रखें कि ये अधिकार केवल उपलब्ध हैं नागरिक। किसी विदेशी या विदेशी के लिए, कोई गारंटी नहीं

नागरिकों

ऐसे अधिकार दिए गए हैं। आम तौर पर सभी

एक भाग से स्थानांतरित करने का स्वतंत्र अधिकार होगा

में से

भारतीय क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। वे स्थानांतरित कर सकते हैं।

उनके

उनके एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर निवास

चुनें और जहाँ चाहें वहाँ बस जाएं। आज़ादी का अधिकार

इन अधिकारों की गारंटी देने पर जोर दिया जाता है कि पूरा भारतीय संघ अपने होने के बावजूद

कई राज्यों में विभाजित वास्तव में एक इकाई है

जहाँ तक संघ के नागरिकों का संबंध है। सभी *259*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

नागरिकों को क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाने के लिए समान विशेषाधिकार और समान सुविधाएं होंगी और वे रह सकते हैं।

जहाँ भी वे

या व्यापार जारी रखें

अंतर-राज्य या अन्यथा

जैसे; और कोई प्रतिबंध भी नहीं

स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

इन सम्मानों के बीच

एक भारत का हिस्सा और दूसरा।

जहाँ तक पूरे क्षेत्र में मुक्त आवाजाही की बात है

संबंधित है, अधिकार खंड *(5)* के प्रावधान के अधीन है, जिसके तहत आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में इन स्वतंत्रताओं पर उचित सीमा लगाई जा सकती है। के हितों

सार्वजनिक जो इस तरह की आवश्यकता है

प्रतिबंध

विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वे हो सकते हैं

महामारी से बचाव से जुड़ा हुआ

या फैलाएँ

हो सकता है

संक्रामक रोगों का संक्रमण; कुछ स्थानों पर फिर से सैन्य उद्देश्यों के लिए बंद रखा गया और हो सकता है

उन क्षेत्रों में प्रवेश का निषेध जो वास्तविक हैं या

कुछ में से

संभावित युद्ध क्षेत्र या जहाँ गड़बड़ी हो

हो सकता है,

प्रकार या अन्य प्रबल। चाहे जो भी कारण हों।

यह आवश्यक है कि इन प्रतिबंधों को

कारण होना

सक्षम, अर्थात, उद्देश्य के अनुरूप

रखा गया। इसके अलावा सामान्य

जिनके लिए वे

ब्याज, संविधान ने संरक्षण को निर्दिष्ट किया है।

अनुसूचित जनजातियों के हितों में से एक

जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

केटेड वर्ग के लोग जिन पर थोपा जा सकता है चतुर बनें और लोगों को डिजाइन करें। अतः वे हैं -

विभिन्न प्रावधान जो उन्हें अलग-थलग करने से भी अक्षम करते हैंविशेष परिस्थितियों को छोड़कर उनकी अपनी संपत्तियाँ।

और उनके लाभ के लिए, कानून हो सकते हैं

उनके हित मेंनागरिकों के जाने के सामान्य अधिकार को सीमित कर दिया या

विशेष क्षेत्रों में बसें या उनमें संपत्ति अर्जित करें।

अनुसूचित जनजाति के हित का संदर्भ देता है

यह बिल्कुल स्पष्ट है-कि स्वतंत्र आंदोलन की बात की गई है

खंड लोकोमोशन के सामान्य अधिकारों से संबंधित नहीं है लेकिन

एक से स्थानांतरित या स्थानांतरित करने के विशेष अधिकार के लिए

भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा दूसरे में, बिना किसी के

भेदभावपूर्ण बाधाएँ।

अगर हम देखें तो इस दृश्य को और समर्थन मिलेगा।

के संविधान में कुछ समान प्रावधानों के लिए

12—3 एस. सी. इंडियाफ *8 [1950]*

260

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य देश। यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंड *(*डी*), (*सी*)* और *(*एफ*)* एक ही लेख में लगभग समान भाषा में सन्निहित हैं। , डैनजिग के मुक्त शहर के संविधान का अनुच्छेद *75*। लेख इस प्रकार है:

"सभी नागरिकों को आवाजाही की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा।

मुक्त शहर के भीतर और अधिकार होगा

रहने के लिए

और किसी भी स्थान पर बसने के लिए जो वे चुन सकते हैं, वास्तविक संपत्ति हासिल करने और किसी भी वैव में अपना जीवन यापन करने के लिए।

बिना कानूनी रूप से इस अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी।प्रतिबंध "।

इस प्रकार कई अधिकारों का एक साथ उल्लेख किया गया है

एक ही श्रेणी में शामिल किया जा रहा है, जबकि उन्हें "व्यक्ति की स्वतंत्रता" से अलग किया गया है जिसे अनुच्छेद *74* में "कानून के आधार पर छोड़कर अलंघनीय बताया गया है" जो इस अनुच्छेद से ठीक पहले दिखाई देता है। थोड़ा बदला हुआ एक समान प्रावधान

भाषा संविधान के अनुच्छेद *111* में आती है जर्मन रीच जो निम्नलिखित में लिखा गया है

तरीका -

"सभी जर्मनों को परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है। अधिवास

पूरे रीच के भीतर। हर किसी को अधिकार है कि

राज्य के किसी भी हिस्से में रहें जिसे वह चुनता है, बसने के लिए

वहाँ, भूमि संपत्ति का अधिग्रहण करें और किसी भी साधन का पीछा करेंआजीविका "। यहाँ फिर से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद *114* में अलग से चर्चा की गई है। ए.

हमारी चर्चाओं के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि

अभिव्यक्ति "भारत के पूरे क्षेत्र में"

ओसी

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में करींग का उपयोग इसके साथ किया जा सकता है

पासपोर्ट विनियमों को सहेजने या जोर देने के लिए एक दृष्टिकोणकि मुक्त प्रवास के किसी भी अधिकार की गारंटी नहीं है

संविधान। यह सुझाव मुझे नहीं लगता

उचित रहें। कोई भी राज्य अपने नागरिकों को गारंटी नहीं दे सकता है कि

अपने क्षेत्र के बाहर कुछ भी करने का स्वतंत्र अधिकार।

उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों में से

यह सच है। अनुच्छेद *19* में और न कि केवल स्वतंत्र रूप से चलने के अधिकार का

मन में। आगे मुझे ऐसा लगता है कि शब्द "के माध्यम से"

भारत के क्षेत्र से बाहर "का कोई लेना-देना नहीं है

प्रवास के अधिकार। हम पाते हैं कि दोनों में

डांसिंग के साथ-साथ जर्मन संविधान में, जहाँ

exer के संबंध में इसी तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है *261* के दौरान मुक्त आवाजाही के अधिकार का अधिकार

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्र में, ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं जो सभी नागरिकों को अन्य देशों में प्रवास के स्वतंत्र अधिकार की गारंटी देते हैं *(*डैनजिंग संविधान के अनुच्छेद *76* और जर्मन रीच के संविधान के अनुच्छेद *112* के अनुसार*)*। इसलिए, मेरी राय में, निवारक निरोध स्पष्ट भाषा के भीतर नहीं आता है।

`01

के खंड *(1) (*घ*)* की भावना और इरादे के भीतर

ए के साथ

संविधान का अनुच्छेद *19* नागरिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से अलग पहलू या रूप।

निवारक निवारक निरोध,

यह सच है कि इसकी वजह से

से रोका जा सकता है

के अधिकार का प्रयोग करना

अनुच्छेद *19 (1)* के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर एक व्यक्ति मुक्त आवाजाही। *(* घ*)* संविधान का, लेकिन यह केवल निरोध के आदेश के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के नुकसान के लिए आकस्मिक या परिणामी है। नहीं।

खंड *(1) (*घ*)* के तहत केवल अधिकार, लेकिन कई

अनुच्छेद *19 (1)* के अन्य उपखंडों के तहत गिने गए अन्य अधिकार खो सकते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं।

जब तक निवारक निरोध जारी रहता है।

इस प्रकार ए

सो।

जब तक वह हिरासत में है तब तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है किसी भी पेशे का अभ्यास करने में सक्षम,

या कोई भी व्यापार करें

या व्यवसाय जो वह करना चाहेगा; लेकिन इससे निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कानून नहीं बन जाएगा

के तहत अधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने वाला कानून

संविधान का अनुच्छेद *19 (1) (छ)* और यह होगा -

यह सुझाव देना बेतुका है कि ऐसे मामलों में

कानून का परीक्षण इसके अनुसार किया जाना चाहिए अनुच्छेद *19* के खंड *(6)* की अनिवार्यता और केवल

प्रतिबंध जो व्यक्ति के स्वतंत्र होने पर लगाए जा सकते हैं

व्यापार और पेशे का अभ्यास वे हैं जो निर्दिष्ट हैं -

वह खंड। श्री नाम्बियार स्वीकार करते हैं कि ऐसे मामलों में हम

विशेष के पदार्थ को देखना चाहिए

कानून

और केवल तथ्य यह है कि यह संयोग से

खाइयाँ

किसी अन्य अधिकार पर जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता है

हालांकि उनका कहना है कि

संबंध भौतिक नहीं है।सार या पदार्थ

एक कानून जो प्रदान करता है

निवारक निरोध के लिए ले जाना या कम करना है

स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार और वास्तव में, "व्यक्तिगत

उनके अनुसार "स्वतंत्रता" का अर्थ कुछ और नहीं है

गति का अप्रतिबंधित अधिकार। विद्वान सलाहकार

काले रंग में परिच्छेद

इस संबंध में कुछ को संदर्भित करता है

कानूनों पर पत्थर की टिप्पणियां

इंग्लैंड का, जहाँ *[1950]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

262

लेखक चर्चा करता है कि वह प्रत्येक में निहित तीन पूर्ण अधिकारों को क्या कहते हैं

अंग्रेज, अर्थात्, अधिकार

व्यक्तिगत रूप से

सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और

संपत्ति।

ब्लैकस्टोन के अनुसार, सुरक्षा में शामिल हैं

एक व्यक्ति के कानूनी और निर्बाध आनंद मेंजीवन, उसका अंग, उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य और उसकी प्रतिष्ठा; जबकि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता"

की शक्ति में

इसमें शामिल हैंस्थिति

या किसी को स्थानांतरित करना

व्यक्ति को किसी भी स्थान पर बदलने का चलन, किसी का अपना झुकाव बिना कारावास या संयम के निर्देशित हो सकता है जब तक कि उचित न हो। कानून का पाठ्यक्रम *(1)*। यह देखा जाएगा कि ब्लैकस्टोन "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति का उपयोग कुछ संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थों में करता है। संविधान पर बाद के लेखकों द्वारा इसका एक बहुत व्यापक और बड़ा अर्थ दिया गया है।

राष्ट्रीय दस्तावेज, विशेष रूप से अमेरिका में। सामान्य भाषा में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का अर्थ है व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित या उससे संबंधित स्वतंत्रता; और इस अर्थ में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" शारीरिक संयम या जबरदस्ती का विरोधी है। डाइसी के अनुसार, जो "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" विषय पर एक मान्यता प्राप्त अधिकारी है, उसका अर्थ है व्यक्तिगत अधिकार जिसके अधीन नहीं किया जाना है।

कारावास, गिरफ्तारी या किसी भी तरह से अन्य शारीरिक जबरदस्ती जो कानूनी औचित्य को स्वीकार नहीं करती है *(*

यह, मेरी राय में, नहीं का यह नकारात्मक अधिकार है

होने के नाते

किसी भी प्रकार के शारीरिक संयम या जबरदस्ती के अधीन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार है और न कि केवल भारत के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है।

क्षेत्र।

इस संबंध में, यह नहीं हो सकता है

के लिए अप्रासंगिक

इंगित करें कि यह अनुसार था

रिकॉम के साथ

प्रारूपण समिति का संशोधन

वह शब्द

अनुच्छेद *15* में

" आज़ादी "

" व्यक्तिगत "पहले डाला गया था

अनुच्छेद *21* के अनुसार।

संविधान जो अब

खड़े हैं।

समिति ने यह कहा है कि

प्रारूपण की रिपोर्ट में

कि "स्वतंत्रता" शब्द होना चाहिए

इन द्वारा योग्य

इससे पहले "व्यक्तिगत" शब्द का उच्चारण;

अन्यथा,

इसका बहुत व्यापक रूप से अर्थ लगाया जा सकता है ताकि अनुच्छेद *13* में पहले से ही वर्णित स्वतंत्रताओं को भी शामिल किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद *13* वर्तमान अनुच्छेद *19* है। यदि प्रारूपण समिति के विचारों को स्वीकार किया जाता है

(1) वीडियो चेज़ का ब्लैकस्टोन, चौथा एडन. पीपी। *68 , 73 .*

(2) संवैधानिक कानून पर डाइस के माध्यम से, *9* वीं संस्करण। पीपी। *207 208. .*

263

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

संविधान सभा, स्पष्ट रूप से इरादा था कि

की अवधारणा से अनुच्छेद *19* की सामग्री

अनुच्छेद *21* में उपयोग की गई "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" को बाहर करें। संविधान में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ का पता ड्राफ्टिंग कॉम की रिपोर्टों से किस हद तक लगाया जा सकता है

सदन में मिट्टी या बहस एक ऐसा मामला है जो संदेह से मुक्त नहीं है और मुझे इस मामले के अर्थ पर चर्चा करते समय इस मामले को बाद में उठाना पड़ सकता है।

संविधान के अनुच्छेद *21* में सामग्री खंड।

यह.

इस स्तर पर यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि प्रारूपण की रिपोर्ट

समिति एक उपयुक्त सामग्री है

जिसे संविधान के शब्दों की व्याख्या आधारित हो सकती है, यह निश्चित रूप से विवाद के खिलाफ है

आवेदक का कथन और यह दर्शाता है कि उपयोग किए गए शब्द

संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* का अर्थ यह नहीं है कि

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति के रूप में चीज़

वैसा ही अनुच्छेद *21* में है। यह सर्वविदित है कि

वह शब्द

"स्वतंत्रता की स्थिति को अपने आप में बहुत कुछ दिया गया है

संयुक्त

का सर्वोच्च न्यायालय

व्यापक अर्थ

इसमें न केवल व्यक्तिगत मुफ्त शामिल है।

अमेरिका के राज्य।

शारीरिक संयम से लेकिन स्वतंत्र होने का अधिकार

अपनी संपत्ति का उपयोग करना और मुक्त पारस्परिक संबंधों में प्रवेश करना। भारतीय संविधान में,

जानबूझकर इसे शरीर से मुक्ति तक सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है कारावास या अन्यथा द्वारा व्यक्ति का संयम।

प्रारूप समिति की रिपोर्ट के अलावा, किक्या अभिव्यक्ति का सादा व्याकरणिक अर्थ है

मैं पहले ही समझा चुका हूँ।

काफी हो।

शायद नहीं, मुझे लगता है,

कहने के लिए सटीक

कि संविधान के अनुच्छेद *19* का संचालन है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है या में वर्णित कई अधिकारों का संक्षिप्तकरण

अनुच्छेद *19,* लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अधिकारों की प्रकृति

ऐसा है कि उनमें मुक्त व्यायाम संभव नहीं हैव्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। दूसरी ओर,

संपत्ति रखने और उसका निपटान करने का अधिकार जो उप में है

अनुच्छेद *19 (1)* का खंड *(च)* और जो आश्रित नहीं है। मालिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार पर *264* मई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

यदि मालिक को कैद या हिरासत में लिया गया है तो यह प्रभावित नहीं होगा।

वैसे भी, मुद्दा पुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

वर्तमान चर्चा के पोज़। परिणाम यह है कि

मेरी राय, पहला विवाद

श्री नाम्बियार द्वारा उठाया गया

सफल नहीं हो सकते और यह माना जाना चाहिए कि हम नहीं हैं

निवारक निरोध अधिनियम और देखें कि क्या यह है खंड *(5)* में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर

अनुच्छेद *19* का।

श्री द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु पर आते हैं।

मैं अब

नाम्बियार आवेदन के समर्थन में; और इस पर हमारे पास सबसे विस्तृत प्रकृति के तर्क थे

दोनों पक्षों के विद्वान वकील ने हमें संबोधित किया, काफी मात्रा में सीखने और पुनः प्राप्त करने का प्रदर्शन करना

खोज करते हैं। हालाँकि, मुद्दा छोटा है और संविधान के अनुच्छेद *21* पर रखी जाने वाली व्याख्या पर निर्भर करता है, जो यह बताता है कि "कोई व्यक्ति नहीं"।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सिवाय इसके

उससे वंचित किया जाएगा।

कानून द्वारा स्थापित "।

प्रक्रिया के अनुसार

ए. पर

लेख का सादा अर्थ पढ़ना

लगता है कि

कि आप नहीं कर सकते

एक आदमी को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना,

जब तक आप उस कानून का पालन नहीं करते हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं जो ऐसी स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रावधान करता है। अभिव्यक्ति "प्रक्रिया" का अर्थ है तरीका और रूप

लागू करें

कानून का पालन करें। मेरी राय में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया होने के लिए, जो कानून इसे स्थापित करता है, वह एक वैध और वैध कानून होना चाहिए जिसे विधायिका संविधान के अनुच्छेद *245* और विधायी सूचियों में विशेष वस्तुओं के अनुसार अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, जिनसे वह संबंधित है। यह भी विवादित नहीं है कि इस तरह के कानून से संविधान के भाग *III* में घोषित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा लिया गया रुख यह है कि वर्तमान मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है

के बारे में

निवारक निरोध से संबंधित कानून को अधिनियमित करने के लिए उस संसद की क्षमता जो पूरी तरह से सूची *I* की मद *9* और सूची *III* की मद *3* द्वारा कवर की गई है, और क्योंकि इस तथ्य के कारण कि विधि के उचित या अन्यथा विचार के लिए कोई सवाल नहीं उठता है कि अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* इस मामले की ओर आकर्षित नहीं है, कानून को कानून का एक वैध टुकड़ा माना जाना चाहिए और यदि प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

265

एस सी आर।

इसके द्वारा निर्धारित वैधता का पालन किया गया है

नजरबंदी को संभवतः चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिनि।आगे तर्क यह है कि अनुच्छेद *22* विशेष रूप से समर्थक है

और पूरी तरह से लेट जाता है

नजरबंदी

निवारक उपायों पर जोर

इस विषय पर कानून की क्या आवश्यकताएँ हैं

होना चाहिए। जैसा कि विवादित अधिनियम के अनुरूप है

अनुच्छेद *22* की अपेक्षाएँ, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं

संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत वैधता बिल्कुल भी उत्पन्न होती है।

उनके तर्कों के बाद के पहलू पर, मैं ध्यान दूंगा

जहाँ तक मुख्य तर्क का संबंध है,

बाद में। श्री नाम्बियार द्वारा लिया गया रुख यह है कि अनुच्छेद *21*

केवल प्रक्रिया को संदर्भित करता है और मूल को नहीं

जो एक है

कानून; प्रक्रिया, हालांकि, होनी चाहिए

कानून द्वारा स्थापित। अभिव्यक्ति "कानून" में

इस संदर्भ का अर्थ या तात्पर्य नहीं है,

के अनुसार

विद्वान सलाहकार, कोई विशेष

अधिनियमित कानून

के साथ

अनुरूपता में विधायिका द्वारा

पुनः

संविधान की आवश्यकताएँ या

अन्यथा

एक बाध्यकारी प्राधिकरण रखने वाला। यह कानून में संदर्भित करता है

अमूर्त या सामान्य अर्थ में-न्याय के अर्थ में और नहीं

लेक्स-और इसका अर्थ है कानूनी सिद्धांत

या

मौलिक नियम जो प्रत्येक प्रणाली के मूल में निहित हैं

हमारे अपने और प्राधिकरण सहित सकारात्मक कानून काजिनका सभी के न्यायशास्त्र में स्वीकार किया गया है

यह तर्क दिया जाता है कि यदि शब्द

सभ्य

देशों।

"कानून की व्याख्या किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए अर्थ में की जाती है।

कानून, अनुच्छेद *21* को मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता था

विधायी

चेक लगाना या

पर सीमा

सरकार का अधिकार। यह हमेशा काम करेगा

विधायिका को एक कानून पारित करने के लिए अनुरोध

एक पूरी तरह से मनमाना और तर्कहीन प्रक्रिया के सभी प्राथमिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया

न्याय और निष्पक्षता

नेस और लोगों के पास नहीं होगा

किस चीज की रक्षा करें

कभी भी, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की गई होकरने के लिए। समर्थन में

इस तर्क के विद्वान

वकील ने बड़ी संख्या में अमेरिकियों पर भरोसा किया हैऐसे मामले, जहाँ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन किया था

"कानून की उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत जैसा कि इसमें दिखाई देता है

अमान्य होने के उद्देश्य से अमेरिकी संविधान

विभिन्न विधायी अधिनियमों को लागू करना जो

कि न्यायालय मनमौजी और मनमाना और विरोध करने वाला हो

कानून के मूल सिद्धांतों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

266

[1950]

का मसौदा

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूल में

भारतीय संविधान के अनुच्छेद *15 (*जो अब अनुच्छेद *21* के रूप में खड़ा है*)* में उपयोग किए गए शब्द "कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार" थे। प्रारूपण समिति

के स्थान पर

"उचित प्रक्रिया"

सिफारिश की गई है कि

अभिव्यक्ति "प्रक्रिया के अनुसार स्थापित

खंड,

कानून द्वारा "प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान में

प्रस्फुटित। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद *21* को जापानी संविधान के अनुच्छेद *31* के अनुरूप बनाया गया है, जहां "किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और न ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई अन्य आपराधिक दंड लगाया जाएगा"।

तर्क है कि अभिव्यक्ति "प्रक्रिया"

नाम्बियार

स्थापित किया गया

संविधान के अनुच्छेद *21* में कानून द्वारा

इसका वही अर्थ है जो अमेरिका में "नियत प्रक्रिया" खंड का है, जो केवल इस हद तक प्रतिबंधित है। , कि यह प्रक्रिया के मामलों तक सीमित है और मूल विधि कानून के प्रश्नों तक विस्तारित नहीं है। . उन तर्कों को स्पष्ट करने के लिए जिन्हें और के लिए आगे बढ़ाया गया है

इस दृष्टिकोण के विरुद्ध और अनुच्छेद *21* में इस खंड को दिए जाने वाले सटीक अर्थ को निर्धारित करने के लिए, इस अवधारणा पर संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक होगा -

"कानून की उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत जैसा कि अमेरिकी संविधान में दिखाई देता है और जिस तरह से यह है

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित और लागू किया गया।

एंग्लो-अमेरिकी के इतिहास में

कानून, द

माना जाता है

"कानून की उचित प्रक्रिया" की अवधारणा या क्या है

इसके समकक्ष "भूमि के कानून" के निशान होने के लिए

इसकी वंशावली

13 वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में मैग्ना चार्टा का प्रसिद्ध *39* वां अध्याय प्रदान करता है

कि "किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा या कैद नहीं किया जाएगा।

या

विच्छेदित, या गैरकानूनी या निर्वासित या किसी भी तरह से विच्छेदित; न ही हम उस पर जाएँगे और न ही उस पर जाएँगे।

लेकिन अपने साथियों के वैध निर्णय और देश के कानून द्वारा। मैग्ना चार्टा को अंग्रेजी स्वतंत्रता के चार्टर के रूप में क्रमिक अंग्रेजी सम्राटों द्वारा पुष्टि की गई थी और यह इन पुष्टिओं में से एक में है *(28* एड। *III,* अध्याय। *3)* "लंदन की स्वतंत्रता के वेस्टमिंस्टर के क़ानून" के रूप में जाना जाता है, कि अभिव्यक्ति "देय"

प्रक्रिया

कानून का "पहली बार प्रकट होता है। इनमें से किसी भी वाक्यांश को *267* में से किसी में भी स्पष्ट या परिभाषित नहीं किया गया था।

एस सी आर।

दस्तावेज़, लेकिन सर एडवर्ड कोक के अधिकार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ है। वास्तव में, उन्होंने गारंटी दी कि व्यक्तियों को बिना कैद किए कैद नहीं किया जाना चाहिए

उचित अभियोग

और उस संपत्ति को जब्त नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उचित रूप में संचालित कार्यवाही के जिसमें मालिक या कब्जे वाले व्यक्तियों को यह दिखाने का अवसर होना चाहिए कि जब्ती क्यों नहीं की जानी चाहिए *(1)*। ये अवधारणाएँ अमेरिका में आई थीं।

उपनिवेशवादियों द्वारा दावा किए गए अंग्रेजों के अधिकारों के हिस्से के रूप में। यह अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में पहले के कुछ राज्य संविधानों में संपादित की गई है और

सटीक वाक्यांश "कानून की उचित प्रक्रिया" पांचवें संशोधन द्वारा संघीय संविधान का एक हिस्सा बन गया जिसे *1791* में अपनाया गया था और जो प्रदान करता है

कि "किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

कानून "। यह लागू किया गया था

उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति

राज्य के बारे में

लगभग समान भाषा में संविधान

की ओर से

1868 में चौदहवाँ संशोधन।

"कानून की उचित प्रक्रिया" का वास्तव में क्या अर्थ है

वर्तमान समय में भी इसे परिभाषित करना मुश्किल है। द कॉनकथन में इस बात का कोई विवरण नहीं है कि "क्या देय है"

कानून की प्रक्रिया "और न ही यह सिद्धांतों की घोषणा करता है

जिसके अनुप्रयोग का पता लगाया जा सकता है। में।

ट्विनिंग वी। न्यू जर्सी *(2)* न्यायालय ने कहाः

" कानून में कुछ वाक्यांश सटीक के इतने मायावी हैं

इस तरह की आशंका। इस अदालत ने हमेशा इनकार किया है

एक व्यापक

देने के लिए

इसकी परिभाषा और है

पसंद है कि यह भरा हुआ है

अर्थ धीरे-धीरे होना चाहिए

समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित

मामलों के निर्णयों के क्रम में जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं।

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि "देय" की आवश्यकता

संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून

संविधान

प्रक्रियाएक सीमा लगाता है

सभी शक्तियों पर

शासन का

विधायी के रूप में

वैसे भी

कार्यपालक

और न्यायिक।

इंग्लैंड में केवल निष्पादन के खिलाफ सुरक्षा के रूप में लागू किया गया

जबरदस्त हड़प और शाही

अत्याचार, अमेरिका में यह

(8)

एक गढ़ बन गया

मनमानी कानून के खिलाफ

(1) संयुक्त राज्य के संविधान पर विलोबी के माध्यम से, *Vol.II*[1],

P.1087

(2) 211 यू. एस. *79.*

(3) वीडियो हुर्टाडो वी। कैलिफोर्निया के लोग, *110* यू. एस. *516* पी. *532 .*

चूँकि यह विधायी शक्ति पर प्रतिबंध है और

मनमाना

उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है

और

मज़बूत कानून, यह इसके भीतर नहीं है

योग्यता

किसी भी प्रक्रिया को उचित प्रक्रिया बनाना।

कांग्रेस से

में से

कानून द्वारा

इसकी केवल इच्छा है; इसके लिए

सीमा काफी निरर्थक है।

जैसा कि निर्धारित किया गया है

में

मामला

विधायी रूप में कार्य करें

ऊपर उद्धृत, "यह कोई नहीं है

कि

कानून है; कानून कुछ और है।

केवल प्रयोग किया जाएगा

इसका अर्थ और अर्थ है

शक्ति "।

एक कार्य के रूप में

का सामान्य कानून

भूमि, बसे हुए और स्थायी

सिद्धांत जो इसमें शामिल हैं

संविधान में और झूठ बोलते हैं

सभी की जड़

कानूनी

प्रणाली। उद्धृत करने के लिए

पहले का तर्क

डैनियल वेबस्टर के शब्द

एक प्रसिद्ध में

सर्वोच्च न्यायालय *(1):*

"कानून के अनुसार

भूमि का सबसे स्पष्ट रूप से इरादा है

सामान्य कानून-एक ऐसा कानून जो इसके समक्ष सुनता है और इसकी निंदा करता है, जो जांच पर आगे बढ़ता है और निर्णय देता है।

मुकदमे के बाद ही। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और उन्मुक्ति को समाज को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों के संरक्षण के तहत रखेगा।

सामान्य कानून के ये कौन से सिद्धांत नहीं हैं

कभी गणना करने का प्रयास किया है। काफी हद तक

और

ये अंग्रेजी सामान्य कानून के सिद्धांत हैं।

न्यायिक कार्यवाही प्राप्त करने के तरीके

इंग्लैंड, द

बसने वालों में

जिन परंपराओं के साथ आया था अमेरिका। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न्यायाधीशों ने इन सिद्धांतों की ओर संकेत किया है

प्राकृतिक न्याय की व्याख्या में क्या है

मतलब

कानून या "देश का कानून",

हालांकि

सामान्य रूप से

सिद्धांत

प्रकृति के एक नियम ने एक ठोस आधार प्राप्त नहीं किया

किसी भी समय। विनेहेमर बनाम। न्यूयॉर्क। *(*)* , न्याय

में

हबर्ड ने खुद को न्यायपालिका द्वारा विधायी प्राधिकरण की सीमा निर्धारित करने या उच्च कानून के किसी भी काल्पनिक सिद्धांत या संविधान के बाहर प्राकृतिक अधिकार के पहले सिद्धांतों पर एक क़ानून को अमान्य घोषित करने का विरोध करने की घोषणा की। कोक की एक सर्वोच्च मौलिक कानून की उक्ति जो स्पष्ट रूप से अंग्रेजी सामान्य कानून के सिद्धांतों को संदर्भित करती है, निश्चित रूप से विचार करने योग्य थी।

अमेरिकियों के मन

न्यायाधीशों पर प्रभाव डालने में सक्षम *(3)* और कुछ मामलों में टिप्पणियां हैं

(2) 13 एन. वाई. *379.*

(1) डार्मौथ कॉलेज मामला, *4* व्हीटन पी। *518 .*

(3) संवैधानिक कानून पर विलिस, पी। *647 .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

269

एस सी आर।

जो यह सुझाव देते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सामान्य कानून के सिद्धांतों के समान माना जाता था, सिवाय इसके कि जहां सामान्य कानून के नियमों को मौलिक चरित्र का नहीं माना जाता था या थे

की प्रगति के लिए

अनुपयुक्त

के रूप में कार्य किया

नहीं।

या अमेरिकी समाज की शर्तें *(1)*। में।

समय ऋण संघ का मामला *v.* टोपेका *(2),* यह

ओ. बी.

गो का

कि सीमाएँ हैं

शक्तियों पर

सरकार जो आवश्यकता से बाहर निकलती है

प्रकृति की

व्यक्तिगत

मुक्त सरकारें-निहित आरक्षण

अधिकार जिनके बिना सामाजिक समझौता नहीं हो सकता था

जो मौजूद हैं और जिनका सभी सरकारों द्वारा सम्मान किया जाता है

नाम के लिए शीर्षक। जिसका संकेत दिया गया है, वह निस्संदेह है

सामाजिक समझौते का पुराना विचार

जिसके तहत राजनीतिक

अस्तित्व में आना चाहिए; और

संस्थान थे

कि जब अमेरिकियों का गठन हुआ था

सुझाव के एक हिस्से को समर्पण करके खुद को एक राज्य में

जो उस समय उनके पास था

और

उनके अधिकार

जो संभवतः उन्हें उनसे विरासत में मिला था

अंग्रेज़ी

पूर्वजों, एक मौलिक के कुछ अधिकार थे

चरित्र अभी भी उनके द्वारा आरक्षित है जो कोई भी राज्य नहीं कर सकता था

शायद ले जाएँ।

पहले ही कहा जा चुका है, "कानून की उचित प्रक्रिया"

के रूप में

अमेरिका में न्यायाधीशों या न्यायविदों द्वारा कभी भी परिभाषित नहीं किया गया है।

अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा वर्णन यह कहना होगा कि

कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक विशेष मामले में इस तरह का अभ्याससरकार की शक्तियाँ

के रूप में

तय किया गया

के अधिकतम

कानून अनुमति और मंजूरी, और ऐसे सुरक्षा उपायों के तहत

उन अधिकतम के रूप में व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण

उन मामलों के वर्ग के लिए निर्धारित करें जिनमें से एक

प्रश्न संबंधित है *(3)*।

संबंधित खंड के वास्तविक अनुप्रयोग में

विशेष मामलों के निर्णयों के लिए "कानून की उचित प्रक्रिया" अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रस्तुत किया

विशिष्ट और असामान्य विशेषताएँ और पूरी तरह से कमी है

उनमें एकरूपता और निरंतरता। तब सेपाँचवें में खंड की उपस्थिति

संशोधन

और *19* वीं के मध्य तक

शताब्दी, यह था

प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में और विशेष रूप से

व्याख्या की गई

न्यायिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा

सरकार

(1) कूलीज़ कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशंस, वॉल्यूम। *II,* पीपी। *739.40 .(2) 20* वाल, पी। *655. ( )* कूलीज़ कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशंस, वॉल्यूम। *II, p.741*।

270

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। मुख्यतः यह संबंधित है

प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों पर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था

और अभियुक्त व्यक्तियों को अधिकार की गारंटी दी

सुस्थापित अपराधी के अनुपालन में एक निष्पक्ष मुकदमा

वैसा ही।

कार्यवाही।

सिद्धांत लागू किया जाता है

मशीनरी या कार्यवाही

जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार

न्यायनिर्णित किए गए थे और जिनके द्वारा शक्तियाँ

प्रतिष्ठित

कराधान का प्रयोग किया गया। इस दौरान

डोमेन और

जिस अवधि पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना गया था

किसी भी तरह से महत्वपूर्ण कानून।

परिवर्तन, हालांकि, आया और वह अवधि जो

इसके बाद बढ़ती मान्यता देखी गई

कि वह मूल आधार

अधिकार

जीवन, स्वतंत्रता और

सिद्धांत

संपत्ति द्वारा संरक्षित हैं

देय राशि की आवश्यकता

द.

इसके खिलाफ कानून

कोई भी वंचित करने का प्रयास

प्रक्रिया

राजनीतिक और

प्राधिकरण; और

विधायी द्वारा

आर्थिक स्थितियाँ

हिसाब से ए

देश का

दृष्टिकोण।

न्यायपालिका में इस बदलाव के लिए काफी हद तक

द.

युद्ध एक नए दौर में लाया गया

में से

सिविल के करीब

औद्योगिक विकास से संचय होता है

में से

उद्योगपतियों और एम. आर. के हाथों में बड़ी पूंजी

एक निश्चित निश्चित श्रमिक वर्ग का अर्थ।

नया और आयातित

उत्पन्न हुआ जिसका राज्यों ने प्रयास किया

समस्याएं

चींटी

को

कानून और विनियम। इनमें से कुछ

विभिन्न प्रकार से निपटें

ऐसा लगता है कि उन्हें गलत सलाह दी गई थी और मनमाना और

व्यापारियों के बीच विरोध

वहाँ थाजिसे उन्होंने विधायी अतिक्रमण के रूप में वर्णित किया

उनके निहित निजी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अब

एक प्रत्यक्ष के रूप में कानून की उचित प्रक्रिया के नियम का उपयोग करना शुरू किया

ठोस विधान और किसी भी कानून पर प्रतिबंध

या प्रशासनिक अधिनियम, जो एक लागू किया

सीमा

निजी संपत्ति या मुक्त संपत्ति के अधिकारों पर

अनुबंधित

नियोक्ता और नियोजित के बीच संबंध थे,

कानून *(1)* के उचित उपकर के अनुसार नहीं होने के रूप में अमान्य किया गया। एक वैध अभ्यास क्या था

कानून की शक्तियों में से अब एक न्यायिक बन गया

कानून वैध था जब तक कि यह नहीं था

और नहीं

सवाल में उचित

न्यायालय की राय। सवाल यह है

तर्कसंगतता स्पष्ट रूप से काफी हद तक निर्भर करती है

द.

विशेष व्यक्तियों और न्यायालयों या बल्कि अधिकांश न्यायाधीशों के विचारों ने इस प्रकार उनके विचारों को संगठित किया

स्वयं के

(1) एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, वॉल्यूम। वी, पीपी। *265-67 .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

271

एस सी आर।

निर्णय लेने में सामाजिक और आर्थिक नीति के विचार

तर्कसंगतता या अन्यथा

क़ानून। में

किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भाषा

लेखक, अदालतें एक बन गईं

राज्य दोनों के लिए नकारात्मक तीसरा कक्षविधायिकाएँ और कांग्रेस *(1)*। किस हद तक

स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया

अदालतेंअनुबंध के मामले में चित्रित किया गया है

लोच्नर वी। नया।

यॉर्क *(2)*। उस मामले में सवाल उठा कि

द.

एक श्रम कानून की वैधता जो निषिद्ध है

कार्यकलाप के कुछ क्षेत्रों में व्यक्तियों का नियोजन

सप्ताह में *60* घंटे से अधिक। लोच्नर के लिए संकेत दिया गया था

अपने बिस्कुट में एक आदमी को काम पर रखकर इस कानून का उल्लंघन करना

सप्ताह में घंटे। *5* से *4* के बहुमत से न्यायालयकानून को इस आधार पर अमान्य ठहराया कि

"श्रम खरीदने या बेचने का अधिकार स्वतंत्रता का हिस्सा है।

संशोधन द्वारा तब तक संरक्षित किया जाता है जब तक कि ऐसी सीमाएं न हों जो अधिकार को बाहर करती हों। उस निर्णय की आलोचना केवल इस आधार पर नहीं की गई है कि यह एक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित था, जिसे जे. होम्स, जो असंतुष्ट न्यायाधीशों में से एक थे, की भाषा को उद्धृत करने के लिए "देश के एक बड़े हिस्से द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था;>>" लेकिन इसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि ऐसा विनियमन आवश्यक था।

के लिए

कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात

कहो,

यह वास्तव में पुलिस शक्तियों का एक प्रयोग था

के साथ

लोक हित के किसी उद्देश्य को पूरा करने का दृष्टिकोण *(3 3)*।

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि जबकि देय

प्रक्रिया सिद्धांत

न्यायिक द्वारा विस्तारित किया जा रहा था

पुलिस शक्ति का सिद्धांत जो

घोषणाएँ,

"देय" पर एक चेक के रूप में

कुछ हद तक काम करता है

साथ ही महत्वपूर्ण हो रहा है

प्रक्रिया खंड था

नृत्य। मोटे तौर पर, पुलिस शक्ति को "सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता और सुविधा के हित में अपने लोगों के आचरण को विनियमित करने के लिए सरकार के अधिकार" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस अधिकार के तहत,

ए

सरकार संबंधित नियम बना सकती है

द.

भवन की सुरक्षा, यातायात का विनियमन, लाइलाज बीमारियों की सूचना, बाजारों का निरीक्षण, कारखानों की सफाई, महिलाओं के लिए काम के घंटे

(1) अमेरिकी संविधान पर केली और हार्बिनसन, पी। *539 .*

(2) 198 यू एस, *45, (3)* वीडियो विलोबी ऑन द कांस्टीट्यूशन ऑफ द यू. एस., वॉल्यूम। *III,* पी। *171 .*

[1950]

272

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और बच्चे, मादक पदार्थों की बिक्री और ऐसे अन्य मामले *"(1)*। यहाँ फिर से, न्यायालय राज्य द्वारा पुलिस शक्तियों के प्रयोग में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, यह न्यायिक घोषणाओं द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आम तौर पर स्वीकार किया गया सिद्धांत यह है कि हालांकि पुलिस शक्तियों के प्रयोग की आड़ में विधायिका द्वारा कोई भी अधिनियम आवश्यक रूप से संवैधानिक नहीं होगा, फिर भी यदि विनियमन में एक है

प्रत्यक्ष

इसके प्रस्तावित उद्देश्य के संबंध में, जो कि किसी वैध सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति है, कानून के विवेक या नीति की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जानी चाहिए। नियम इसके अपवादों के बिना नहीं है लेकिन

उन्हें हमारे लिए विस्तृत करने के लिए

यह आवश्यक नहीं है

उपस्थित

उद्देश्य *(2)*। बाद के निर्णय, हालांकि काफी समान नहीं हैं, पुलिस शक्ति सिद्धांत के बढ़ते प्रभाव को प्रकट करते हैं। यह कहा जा सकता है कि *1936* से न्यायिक पेंडुलम में एक निश्चित बदलाव आया है।

वेस्ट कोस्ट होटल के मामले में

दूसरी दिशा में। कंपनी वी। पारिश *(3)* जो वैधता से संबंधित है

न्यूनतम मजदूरी को विनियमित करने के लिए एक क़ानून का

महिलाओं, मुख्य न्यायाधीश ह्यूजेस, जिन्होंने दिया

न्यायालय की राय निम्नलिखित रूप में देखी गईः

जिनके द्वारा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है

"हर मामले में

न्यूनतम हमला

महिलाओं के लिए मजदूरी विनियमन है

अनुबंध की स्वतंत्रता से वंचित होना। मुक्त क्या है*?*

डोम*?* संविधान स्वतंत्रता की बात नहीं करता है

अनुबंध। यह स्वतंत्रता की बात करता है और निषेध करता है।

द.

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता।

अभाव

में।

संविधान के उस अभाव को प्रतिबंधित करना

नहीं करता है

पूर्ण और अनियंत्रित स्वतंत्रता।

पहचानें

प्रत्येक चरण में स्वतंत्रता का अपना इतिहास और महत्व है। टशन। लेकिन जिस स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है वह स्वतंत्रता है

ए

सामाजिक संगठन जिसके लिए कानून के संरक्षण की आवश्यकता होती है

स्वास्थ्य, सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बुराइयाँ,

के खिलाफनैतिकता और लोगों का कल्याण "।

बाद के वर्षों में निश्चित रूप से संकेत मिले

कि एक उप के रूप में कानून की उचित प्रक्रिया की आवश्यकता है

सरकारी नियंत्रण पर स्थायी प्रतिबंध लग रहा है

अतीत की बात है और नियम को अधिक प्रतिबंधित किया जा रहा है

(1) वीडिय मुनरो-द गवर्नमेंट ऑफ द यू. एस., पी. *522 .*

(2) यू. एस. एस. के संविधान पर विलोबी का वीडियो। , खण्ड. *III,* पीपी। *1709-70 .(3) 300* यू. एस. *379 273*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर। और इसके मूल प्रक्रियात्मक अर्थ के लिए अधिक। भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी इस स्तर *(1)* पर निश्चित रूप से नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि "नियत प्रक्रिया" खंड

अमेरिकी संविधान में उपयोग किया जाने लगा

न्यायपालिका के हाथों में उपकरण

सामाजिक विधान पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम। न्यायिक घोषणाएँ किसी भी समान सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं होती हैं, और

आर्थिक और सामाजिक विचार

न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय में बहुमत बनाते हैं कुछ समय के लिए, किसी की तर्कसंगतता या अन्यथा को मापने के लिए यार्ड-स्टिक का गठन करें।

उस अवधि के दौरान पारित अधिनियम। अमेरिकी संवैधानिक कानून का कोई भी लेखक अब तक सक्षम नहीं हुआ है।

एक निश्चित और सुसंगत समूह की तरह कुछ भी विकसित करने के लिए

जिन मामलों में

"कानून की उचित प्रक्रिया" के बड़े जन सिद्धांत में से सिद्धांतों को लागू या लागू किया गया है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि

हमें समझ लेना चाहिए

भारत में संविधान निर्माताओं ने कैसे व्यवहार किया

एक अनुरूप पर

और प्रावधानों को अंतिम रूप दिया,

ड्राफ्ट कॉन में

भारतीय संविधान का विषय।

अनुच्छेद *15 (*जो अब अनुच्छेद *21* के रूप में खड़ा है*)*

स्पष्ट रूप से *5* वीं और *14* वीं के आधार पर तैयार किया गया था अमेरिकी संविधान में संशोधन। द.

लेख इस प्रकार लिखा गया था। *:*

" किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना।

मसौदा समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की

इस लेख की भाषा में बदलाव किया। द. पहला सुझाव यह था कि "व्यक्तिगत" शब्द

करेंगे।

"स्वतंत्रता" शब्द से पहले डाला जाए और दूसरा

"प्रक्रिया के अनुसार" अभिव्यक्ति

कि कानून द्वारा स्थापित किया गया था "के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा" उचित प्रो कानून का उपकर ", इसका कारण यह दिया गया है कि पूर्व अभिव्यक्ति अधिक विशिष्ट थी।

विद्वान महान्यायवादी ने पहले रखा है

संविधान सभा में बहस

केंद्रित करना

इस सिफारिश को स्वीकार करने का दौर

में से

मसौदा समिति और उन्होंने हमें भेजा है

(1) स्विशर-संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक शक्ति का विकास।

पीपी। *123-25 .*

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

274

विधानसभा के कई सदस्यों के भाषण जो

कॉन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

व्यवस्था। अर्थ का पता लगाने में सहायता के रूप में

संविधान के शब्दों में, ये बहसें संदिग्ध हैं

मूल्य "। उनके लिए रिसॉर्ट हो सकता है ", विलोबी कहते हैं,

" महान के साथ

सावधानी और केवल तभी जब अव्यक्त अस्पष्टताएँ हों

हल किया जाना है। कार्यवाही हो सकती है

कुछ हो जाएँ

मूल्य जब वे स्पष्ट रूप से उद्देश्य को इंगित करते हैं

प्रावधान। लेकिन जब सवाल अमूर्त का होता है

मतलब

अगर, इस स्रोत से प्राप्त करना मुश्किल होगा

व्याख्या में बहुत अधिक भौतिक सहायता *"(1)*।

विद्वान महान्यायवादी स्वीकार करते हैं कि ये

बहस का अर्थ समझाने के लिए स्वीकार्य नहीं हैं

उपयोग किए गए शब्द और वह उनका उपयोग केवल इसके लिए करना चाहते थे यह दिखाने का उद्देश्य कि संविधान

सभा

जब उन्होंने अंततः सिफारिश को अपनाया

में से

मसौदा समिति, निहितार्थ से पूरी तरह से अवगत थी

एक्सप्रेस आयन के पुराने रूप और नए रूप के बीच के अंतर। मेरी राय में, व्याख्या में

सबूत

संविधान, यह बेहतर होगा अगर इस तरह के बाहरी

अलग-अलग

खाते से बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह के मामलों में, सदस्य विभिन्न आवेगों पर कार्य करते हैं और

अलग-अलग

उद्देश्य और यह काफी संभव है कि कुछ सदस्य

कुछ शब्दों को एक विशेष अर्थ में स्वीकार किया, जबकि अन्य ने उन्हें एक अलग प्रकाश में लिया।

यह रिपोर्ट

तथापि, प्रारूपण समिति की,

दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है और ऐसे निश्चित अधिकारी हैं जिनमें सदन में होने वाली बहसों की तुलना में ऐसी रिपोर्टों को अधिक महत्व दिया गया है। कैमिनेटी वी। संयुक्त राज्य अमेरिका *(2)*, यह कहा जाता है कि रिपोर्ट

साथ में

कांग्रेस के लिए

प्रस्तावित उत्पादन

कानून मदद कर सकता है

न्यायालयों में

संदिग्ध व्याख्या के मामले में विधान के सही अर्थ तक पहुँचना। रिपोर्ट बहुत छोटी है। यह बस इतना कहता है कि सुझाए गए परिवर्तन का कारण चीज़ को और अधिक विशिष्ट बनाना है।

मेरे मन में है कि अगर

मुझे कोई संदेह नहीं है।

"देय

खंड जो मूल मसौदे में दिखाई दिया

प्रक्रिया को अंततः संविधान सभा द्वारा बरकरार रखा गया था, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माता

संयुक्त राज्य अमेरिका के पी। *64 .*

(1) संविधान पर विलोबी का वीडियो

(2) 242 यू. एस. *470*

एस सी आर।

275

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान चाहता था कि उस अभिव्यक्ति को धारण किया जाए

एक ही

जैसा कि अमेरिका में होता है। लेकिन जब वह रूप

था।

छोड़ दिया गया और दूसरे को जानबूझकर प्रतिस्थापित किया गया था

इसके स्थान पर, यह कहना संभव नहीं है कि इसके बावजूद

भाषा और अभिव्यक्ति में अंतर, उन्हें होना चाहिए एक ही बात का अर्थ है और एक ही विचार व्यक्त करते हैं।

श्री.

नांबियार का तर्क

की दृष्टि से

कुछ हद तक

जैसा कि प्रचलित है

कानून की स्थिति

अनिश्चित और तरल

अमेरिका विषय पर, प्रारूपण समिति

के उद्देश्य के लिए एक परिवर्तन की सिफारिश की गई

भाषा को और अधिक विशिष्ट बनाना और वह हमारे पास है। मान लीजिए कि इसे विशिष्ट बनाया गया था

इसमें

तरीका, अर्थात्, कि विस्तारित होने के बजाय

ऊपर से

कानून का पूरा क्षेत्र, मूल

साथ ही

विशेषण,

यह सीमित था

प्रक्रियात्मक

कानून

केवल। यही कारण है, वे कहते हैं, इसके बजाय क्यों

"प्रक्रिया" शब्द को "प्रक्रिया" अभिव्यक्ति को अपनाया गया था, लेकिन विश्व "कानून" का अर्थ वही है जो अमेरिका में "उचित प्रक्रिया" खंड में है और यह किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को नहीं बल्कि मूल सिद्धांत को संदर्भित करता है।

कानूनी प्रणाली में निहित

सभी सिद्धांत जो हैं और अपरिवर्तनीय पर आधारित हैं

प्रकृति के सिद्धांत

अल न्याय।

हालांकि यह तर्क आकर्षक है।

सबसे पहले

हो सकता है

यह संभव है

दृष्टि प्रकट होती है, मुझे नहीं लगता कि

सबसे पहले, यह

इसे ध्वनि के रूप में स्वीकार करना।

काफी है

साफ करें कि फ्रेमर्स

भारतीय संविधान का

किया।

हमारी प्रणाली में अनिश्चितता, अस्पष्टता और परिवर्तनशीलता के तत्वों को शामिल करने की इच्छा नहीं है जो अमेरिका में "उचित प्रक्रिया" सिद्धांत के आसपास बढ़े हैं। वे प्रावधान को स्पष्ट, निश्चित और सटीक बनाना चाहते थे और जानबूझकर "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्दों को चुना, क्योंकि उनकी राय में इस अभिव्यक्ति के अर्थ के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। "उचित प्रक्रिया" के अनुप्रयोग में अनिश्चितता

अमेरिका में सिद्धांत का विशिष्टता से कोई लेना-देना नहीं है

द.

कानून।

मूल और प्रक्रियात्मक के बीच का संबंध

स्वयं

अनिश्चितता और लोच सिद्धांत में हैं

जो एक प्रकार की छिपी हुई खान है, जिसकी सामग्री को कोई नहीं जानता है और केवल समय-समय पर न्यायाधीशों के न्यायिक विवेक के सामने प्रकट किया जाता है। इस सिद्धांत को, भारतीय संविधान ने जानबूझकर खारिज कर दिया

13-3 एस. जी. इंडिया*/58,276*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

और यही कारण है कि उन्होंने इसके स्थान पर एक अलग रूप को प्रतिस्थापित किया, जो उनके अनुसार, अधिक विशिष्ट था। दूसरी जगह, यह दिखाई देता है

मेरे लिए कि जब वही

शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह

आम लोगों के खिलाफ होगा

व्याख्या के अनुसार हमारे संविधान में एक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए निर्माण के नियम

लगायें

किसी अन्य देश के संविधान में कुछ हद तक समान प्रावधान पर, जहां न केवल

भाषा है

अलग, लेकिन

संपूर्ण राजनीतिक स्थितियाँ और निरंतरता

ट्यूशनल सेटअप अलग-अलग हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में "देय" शब्द पर समान रूप से जोर दिया गया है जो पहले आता है और योग्य बनाता है

"क्या?

अभिव्यक्ति

"कानून की प्रक्रिया "। देय "का अर्थ है

किसी विशेष मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित है। यह वह शब्द है जो सिद्धांत के अनुप्रयोग में परिवर्तनीय तत्व का परिचय देता है; क्योंकि जो परिस्थितियों के एक समूह में उचित है वह दूसरे और एक अलग समूह में ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में "देय" शब्द पर विचार किया गया है।

बहुत हटा दिया गया है और यह दिखाता है

स्पष्ट रूप से कि संविधान

भारत के राष्ट्र-निर्माता

पेश करने का कोई इरादा नहीं था

अमेरिकी सिद्धांत। वह शब्द।

"स्थापित "

और अगर "कानून"

आम तौर पर इसका अर्थ है "नियत या निर्धारित"। अर्थात्, जैसा कि श्री नाम्बियार तर्क देते हैं,

कोई विशेष नहीं

कानून का टुकड़ा लेकिन प्राकृतिक न्याय के अनिश्चित और अनिश्चित सिद्धांत जो कानून की सकारात्मक प्रणालियों को रेखांकित करते हैं, "स्थापित" अभिव्यक्ति का उपयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक न्याय एक निश्चित प्रक्रिया की तरह कुछ भी स्थापित नहीं कर सकता है।

ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संविधान के किसी भी भाग में

"कानून" शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि

ट्यूशन" सामान्य कानून "

के रूप में वर्णित है

क्या इंगित कर रहा है

क्षेत्र के बाहर

सिद्धांत

प्राकृतिक प्राकृतिक न्याय

में सेमें से

प्रावधान

सकारात्मक कानून।

दूसरी ओर,

संविधान का अनुच्छेद *31,*

द.

जिसमें दिखाई देता है

मौलिक अधिकारों पर अध्याय, यह स्पष्ट करता है कि "कानून" शब्द इसके बराबर है

राज्य-मा। कानून और

किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना,

प्राधिकरण

या

इस तरह के कानून की मंजूरी आवश्यक है।

कहा।

के रूप में

हो चुका है

भारतीय का

पहले से ही, अनुच्छेद *21* संविधान का प्रावधान एक विशेष, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को छोड़कर, पुनः प्रस्तुत करता है।

277

एस सी आर।जापानी संविधान के अनुच्छेद *31* की भाषा और

योजना और इसके प्रावधान

यह काफी स्पष्ट है

जापानी संविधान

कि कानून की बात करते हुए यह संदर्भित करता है

पारित या मान्यता प्राप्त कानून

जैसे राज्य द्वारा। में।

आयरिश संविधान में भी लगभग इसी तरह की भाषा में प्रावधान है जो एक ही विचार को व्यक्त करता है। अनुच्छेद *40 (4) (1)* में प्रावधान है कि "किसी भी नागरिक को कानून के अनुसार छोड़कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा", और कानून द्वारा निश्चित रूप से राज्य का कानून अभिप्रेत है।

संभवतः समर्थन में सबसे मजबूत तर्क

श्री नाम्बियार का तर्क है कि यदि कानून का अर्थ राज्य द्वारा बनाया गया कानून माना जाता है, तो अनुच्छेद *21* विधान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को संक्षिप्त करने वाले किसी भी कानून को पारित करने का कोई सवाल संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है और जहां तक इस प्रावधान का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद *13 (2)* का कोई संचालन नहीं होगा। शब्दों को उद्धृत करना

एक का

अमेरिकी

न्याय करें कि यह बहुत हद तक संविधान द्वारा विधायिका से बात करने जैसा लगेगा कि बाद वाला इन अनुच्छेदों द्वारा बनाए गए अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता जब तक कि वह ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनता *(1)*।

यह एक प्रशंसनीय है

तर्क लेकिन यह

जाहिर है।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम इसके साथ चिंतित नहीं हैं

मौलिक

संविधान की नीति।

अधिकार

न केवल सीमाएँ लागू करें

विधायिका,

लेकिन वे अभ्यास पर जाँच के रूप में काम करते हैं

कार्यपालक

शक्तियाँ भी, और एक से वंचित करने के मामले में

आदमी

उनका व्यक्तिगत

स्वतंत्रता, उच्च हाथ पर जाँच

उन्हें रोकने के रूप में कार्यपालिका का

से

कोई भी कदम उठाना, जो कानून के अनुसार नहीं है, निश्चित रूप से हो सकता है

के रूप में रैंक

मौलिक अधिकार। में

विभिन्न अन्य देशों के प्रावधान

संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित

हैं।

सोफे पर।

बहुत कुछ उसी भाषा में जैसा कि अनुच्छेद *21* में है। यह सब एक सवाल है

नीति की कि क्या विधायिका या

न्यायपालिका

ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय होगा

भारत के संविधान निर्माता-जानबूझकर

औरइन शक्तियों को रखने का निर्णय लिया

कानूनविदों के हाथ

संविधान, पर

प्रौढ़। जापानी का अनुच्छेद *31* हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद *21* भी मॉडल किया गया है

(1) टेलर बनाम में ब्रोंसन जे. के अनुसार। पोर्ट *4* हिल *140*।

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

278

उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं। द.

जापानी

संविधान, यह ध्यान देने योग्य है,

उसी तरह की गारंटी

गिरफ्तारी, हिरासत और

समय के संबंध में अन्य अधिकार

जो कानून पर जाँच के रूप में काम कर सकता है

न्यायालय तक पहुँच अधिकार भी।

इस प्रकार अनुच्छेद *32* प्रदान करता हैः

" किसी भी व्यक्ति को पहुँच के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अदालतों को "।

अनुच्छेद *34* में कहा गया हैः

" इसके बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

उसके खिलाफ आरोपों के बारे में तुरंत सूचित किया जा रहा है या

परामर्श का तत्काल विशेषाधिकार, और न ही

इसके बिना

उसे हिरासत में लिया जाए।

पर्याप्त कारण के बिना; और

कारण तत्काल होना चाहिए

किसी भी व्यक्ति की मांग, जैसे

उसकी उपस्थिति और

खुले न्यायालय में दिखाया गया

उसके वकील की उपस्थिति "।

यह संभवतः अनुच्छेद *34* के सादृश्य पर था।

जापानी संविधान

कि पहले दो खंड

सभी; और "उचित प्रक्रिया" खंड के बाद त्याग दिया गया थासंविधान सभा द्वारा और वर्तमान रूप था

अनुच्छेद *21* में इसके स्थान पर प्रतिस्थापित, अनुच्छेद *22* था

कुछ प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया

एक तरह का

गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में जाँच करें और इससे सुरक्षा मिलती है।

सीमाएँ निर्धारित करें

लेखक

विधायिका की नैतिकता

साथ ही। ये सुरक्षाएँ वास्तव में

हो चुके हैं।

निवारक निरोध के मामलों से इनकार किया गया

लेकिन

जो नहीं होता है

कि फिर से नीति का सवाल है

हम एक अदालत के रूप में। अतः मेरा निष्कर्ष यह है कि

अनुच्छेद *21* "विधि" शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है -राज्य-निर्मित कानून और कानून के समकक्ष के रूप में नहीं

प्रिंसी को मूर्त रूप देने वाली अमूर्त या सामान्य भावना

प्राकृतिक न्याय। लेख में कहा गया है कि कानून प्रावधानों के तहत एक वैध और बाध्यकारी कानून है।

योग्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान का

विधायिका और वह विषय जिससे वह संबंधित है और करता है

किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है जो

संविधान प्रदान करता है।

जिस दृष्टिकोण से मैंने लिया है, सवाल उठाया गया है

श्री नाम्बियार द्वारा कि निवारक निरोध अधिनियम है

अमान्य, इस तथ्य के कारण कि प्रक्रिया *279* निर्धारित करती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

डाउन प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप नहीं है, विचार के लिए नहीं आता है। यह काफी है। मेरी राय में, यदि कानून एक वैध कानून है जिसे पारित करने के लिए विधायिका सक्षम है और जो नहीं करता है

घोषित मौलिक अधिकारों में से कोई भी

अतिक्रमण

संविधान। यह भी अनावश्यक है कि

भाग *III*

द्वारा उठाए गए प्रश्न पर

एक चर्चा में प्रवेश करें कि क्या अनुच्छेद *22* अपने आप में कानून के संबंध में स्व-निहित संहिता है

निवारक निरोध और यह निर्धारित प्रक्रिया पूरी है या नहीं। भले ही प्रक्रिया पूरी न हो, लेकिन इसे पूरक बनाने की अनुमति नहीं है।

प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू करके। श्री नाम्बियार द्वारा उठाए गए तीसरे बिंदु पर, एकमात्र प्रश्न,

संविधान के अनुरूप नहीं होने के कारण अनुच्छेद *22 (7) (*क*)* के प्रावधान के साथ। अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)*

निर्धारित करने के लिए संसद

संविधान सशक्त करता है

जिन परिस्थितियों में, और वर्ग या वर्ग

जिन मामलों में किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है

किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक

के लिए

की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध

प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार बोर्डखंड *(4)* के उपखंड *(*क*)* का। पूर्व की धारा *12*

वेंटिव डिटेन्शन एक्ट जो एक होने का तात्पर्य है

अधिनियम बनाएँ

संविधान के अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)* के अनुसरण में

यह निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

" (1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति

मामलों के वर्ग या निम्नलिखित में से किसी भी परिधि के तहत

राय प्राप्त किए बिना रुख को हिरासत में लिया जा सकता है

एक अवधि के लिए एक सलाहकार मंडल

उससे भी लंबा

में से

तीन महीने, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं

उसकी नजरबंदी की तारीख, अर्थात्, जहाँ ऐसा व्यक्ति

है।

उसे रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था

किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना

(क*)* भारत की रक्षा, भारत के साथ संबंध

विदेशी शक्तियाँ या भारत की सुरक्षा*;* या

*((*ख*)* किसी राज्य की सुरक्षा या रखरखाव

सार्वजनिक व्यवस्था "।

यह देखा जाएगा कि कुल छह *[1950]* हैं।

280

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

में दो वस्तुओं में प्रमुख या विषय

विधायी

नंबर *3* का

सूची, अर्थात्, सूची *I* की वस्तु संख्या *9* और वस्तु

वस्तु

सूची *III* जो निवारक निरोध से संबंधित है।

सूची *I* के सं. *9* में संबंधित कारणों का उल्लेख किया गया है -

रक्षा,

भारत के विदेशी मामले और सुरक्षा, जबकि मद संख्या *3*

सूची *III* सुरक्षा से जुड़े कारणों की बात करती है

किसी राज्य का, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव औरआवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव

समुदाय। अंतिम सिर को छोड़कर, सभी

शेष पाँच को धारा *12* में सूचीबद्ध किया गया हैनिवारक निरोध अधिनियम और वे किए गए हैं

परिस्थितियों और मामलों के वर्गों दोनों के रूप में उल्लिखित

जिसमें तीन महीने से अधिक समय तक नजरबंदी होगी

किसी भी सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अनुमेय।

श्री नाम्बियार का तर्क

का उल्लेख

यह है कि

छह विधानमंडलों में से पाँच

सिर

धारा *12* में

निर्धारित करने के लिए राशि नहीं

द.

परिस्थितियों के तहत

जिसमें, एक व्यक्ति कर सकता है

जो, या मामलों के वर्ग

से अधिक के लिए हिरासत में लिया जाए

संदर्भ के रूप में तीन महीने

यह भी तर्क दिया जाता है कि

अनुच्छेद *22 (7) (*क*)* द्वारा आच्छादित। इस तथ्य को देखते हुए कि

दो वस्तुएँ "परिस्थितियाँ"

" वर्गों को संयोजन द्वारा अलग किया जाता है

और

संविधान ने वास्तव में क्या विचार किया

" और ",

क्या ऐसा था

इन दोनों वस्तुओं को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और

उनमें से किसी एक का कथन या विनिर्देशन खंड के प्रावधानों का उचित अनुपालन नहीं होगा। यह भी बताया गया है कि "परिस्थितियों" या "वर्गों" के रूप में समान मामलों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद *22 (7)* द्वारा आवश्यक नहीं है और यह पूरी तरह से अतार्किक और अनुचित है।

मुझे कहना होगा कि धारा *12* का मसौदा तैयार किया गया है

बल्कि अनाड़ी तरीके से और निश्चित रूप से इसे बेहतर और अधिक उचित तरीके से तैयार किया जा सकता था। अनुच्छेद *22 (7) (*ए*)* के तहत, संसद उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके तहत, और उन मामलों के वर्गों में, जिनमें सलाहकार बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए निरोध के मामलों को रखने की आवश्यकता हो सकती है - के साथ वितरित। "मामलों के वर्गों" से हमारा मतलब है

कुछ निर्धारित समूह, प्रत्येक समूह में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से एक पक्षीय तरीके से संबंधित होते हैं जो उस समूह के निर्धारण कारक का गठन करते हैं। दूसरी ओर परिस्थितियाँ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

281

एस सी आर।

उन स्थितियों या स्थितियों को संदर्भित करता है जो बाहरी हैं

चिंतित हैं। . निवारक हिरासत हो सकती है

व्यक्तियों कोसंबंधित कारणों के लिए कानून द्वारा प्रदान किया गया

छह के साथ

विधायी सूचियों में प्रासंगिक मदों में निर्दिष्ट विभिन्न मामले, और जो भी कारण हो सकते हैं,

अनुच्छेद *22 (4) (*क*)* में निहित एक प्रावधान जो

यह कहा गया है कि सलाहकार मंडल की मंजूरी के अलावा तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक विकल्प है

संसद ने किया है

खंड *(*ख*)* द्वारा उपबंधित और

द्वारा दी गई सुरक्षा

लेने का विकल्प दिया गया

और मामले

खंड *(*क*)* और परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। जब यह नियम लागू नहीं होगा। मुझे बहुत संदेह है कि क्या अधिनियम की धारा *12* में संसद द्वारा किए गए मामलों का वर्गीकरण वास्तव में उद्देश्य को पूरा करता है।

जिसे संविधान ने ध्यान में रखा था।

इसका आधार

में से

वर्गीकरण को पकड़ा गया है

द.

के कार्य

गिरफ्तार किए गए लोग

के संदर्भ में वर्णित

वस्तुओं में उल्लिखित सामान्य प्रमुख

विधायी

सूची जैसा कि ऊपर कहा गया है। छह में से पाँच

उनके सिर हैं

बाहर निकाला गया और उन मामलों के वर्गों के रूप में लेबल किया गया जिनके लिए लेख के खंड *(4) (ए)* का संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। यह सामान्य ज्ञान के खिलाफ है कि सभी

इन पाँच वस्तुओं से जुड़ी गतिविधियों के रूप समान रूप से खतरनाक हैं और एक ही कठोर व्यवहार के योग्य हैं।

तीव्रता की विभिन्न डिग्री के कार्य हो सकते हैं और इनमें से प्रत्येक सिर के नीचे खतरा।

हालाँकि मुझे नहीं लगता कि धारा *12*

उस उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान के साथ तैयार किया गया जो कॉन्स्टी

ट्यूशन दृष्टि में था। * मैं नहीं कह सकता।

कि सेक

अति अधिकार होने के नाते

यह अमान्य है

संविधान।

संविधान

निर्बाध रूप से दिया है

शक्तियाँ

को

वर्गीकरण

बनाने की बात

संसद में

और यह संसद को अपनाने के लिए खुला है

कोई भी विधि

यदि यह सिद्धांत चुनता है

जैसा वह पसंद करता है।

सिद्धांत

या

निहित

संबंधित विषयों की गणना में

और विधायी प्रमुखों, यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्लिया

इमेंट ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है।

मैं यह भी मानने में असमर्थ हूं कि दोनों "परिस्थितियाँ"

साथ ही "वर्गों" को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि

282 तक

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपखंड *(ए)* की आवश्यकता का पालन करना

लेख का

विशुद्ध रूप से प्रावधान और संसद को सक्षम करना, यदि ऐसा है तोचुनें, पास हो सकते हैं

कोई भी कानून

उसी के संदर्भ में।

निश्चित रूप से प्रदान किया गया

एक वैकल्पिक

कहाँ*?*

शक्ति है

करने का अधिकार

दो अलग-अलग कार्य करें, आम तौर पर यह

इन दोनों का पालन करना इसके लिए अनिवार्य नहीं होगा।

अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकता है। यहाँ कक्षाएँ हैं

निर्दिष्ट और स्पष्ट रूप से वर्गों से बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किए गए कुछ अपराधों को करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है

क्रियाएँ। मैं हूँ।

बहुत संदेह है कि क्या

कक्षाएँ

स्वयं

जैसा कि वे कहते हैं

खंड में की गई "परिस्थितियों" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। परिस्थितियाँ "आम तौर पर युद्ध, विद्रोह जैसी स्थितियों को संदर्भित करती हैं।

परेशानियाँ

और इस तरह की चीजें, नीचे

सामुदायिक

आवश्यकता हो सकती है

द.

कौन सी अतिरिक्त सावधानी बरतें

और

अवधि के बाद संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना

से

बिना मंजूरी के तीन महीने

सलाह देना

बोर्ड उचित हो सकता है।

कहा जाता है कि संभावना

निर्दिष्ट किए गए विशेष कार्यों को करने वाले इन व्यक्तियों में से "परिस्थितियाँ" हो सकती हैं।

मुझमें

राय, यह एक स्पष्ट और समझदार व्याख्या नहीं है। लेकिन वह चाहे जो भी हो, जैसा कि मेरा मानना है कि यह संसद पर अनिवार्य नहीं है

दोनों को निर्धारित करना

परिस्थितियों और मामलों के वर्गों, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि धारा *12* संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, मसौदा थोड़ा बेढंगा है और मुझे नहीं पता कि संसद ने "या" जब संविधान में ही "और" शब्द का उपयोग किया है, तो इस शब्द का उपयोग क्यों किया।

श्री नाम्बियार द्वारा उठाए गए चौथे और अंतिम बिंदु में

विचार के लिए प्रमुख प्रश्न निवारक निरोध अधिनियम की धारा *14* की वैधता है। धारा *14* की उप-धारा *(1)* किसी भी न्यायालय को कोई भी बयान देने की अनुमति देने से रोकती है।

या कोई सबूत

धारा *7* के तहत की गई किसी भी विज्ञप्ति के सार के बारे में उसके समक्ष दिया जाना, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ निरोध आदेश दिया गया है।

बनाया गया।

उनके खिलाफ

या कोई प्रतिनिधित्व आदेश दें। यह आगे प्रदान करता है

कि कोई भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं होगी

283

एस सी आर।

इससे पहले

किसी भी लोक अधिकारी को पेश करने का अधिकारकिसी सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियों या ऐसी किसी विज्ञप्ति या प्रतिनिधित्व के सार का खुलासा करना या किसी सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का वह हिस्सा

सलाहकार बोर्ड

जो गोपनीय है। उप-धारा *(2)*

आगे यह प्रदान करता है।

"यह कारावास से दंडनीय अपराध होगा।

वर्ष, या साथ

एक अवधि के लिए जो एक तक बढ़ सकती है

केंद्र के पूर्व प्राधिकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को खुलासा या प्रकाशित करने के लिए जुर्माना, या दोनों के साथ

सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो

हैटर का उद्देश्य

बनो।

हो सकता है,

कोई भी सामग्री या

इस तरह के किसी भी संचार या प्रतिनिधित्व की सामग्री

जैसा कि उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट किया गया हैः

इसमें कुछ भी नहीं। उप-धारा

बशर्ते कि

एक द्वारा अपने कानूनी सलाहकार को किए गए प्रकटीकरण पर आवेदन करें

वह व्यक्ति जो निरोध आदेश का विषय है।

स्पष्ट रूप से एक हैं

इस धारा के प्रावधान

द.

प्रतिबंध लगाता है

यह.

कठोर चरित्र।

अधिकतर

न्यायालय और इसे रोकता है

किसी भी कथन की अनुमति देना

को

इससे पहले निर्मित

इसका

बनाया जाए या कोई सबूत

किसी भी संचार का सार

बंदी को बनाया गया

नजरबंदी

उसे उन आधारों से अवगत कराना जिनके आधार पर

आदेश दिया गया। न्यायालय भी अक्षम है

सलाहकार मंडल के समक्ष कार्यवाही को देखें या

उत्तरार्द्ध की रिपोर्ट जो गोपनीय है। इसके अलावा

ऐसी सामग्रियों का खुलासा किया गया है

एक के लिए कारावास से दंडनीय

आपराधिक अपराध

अवधि जो बढ़ सकती है

एक साल तक। श्री नाम्बियार का

प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होते हैं

तर्क यह है कि ये

संविधान का अनुच्छेद *32*

के प्रावधानों को निष्प्रभावी जो गारंटी देता है

प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार

उचित कार्यवाहियों द्वारा न्यायालय

इसे स्थानांतरित करें प्रवर्तन

भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकारों का

संविधान।

यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता

अधिकार है

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए इस न्यायालय का रुख करने का

. कोष, और

जब तक कि न्यायालय देखने की स्थिति में न हो

जिस पर

में और

आधारों की जाँच करें

आदेश दिया गया है, यह असंभव है

नजरबंदी

यह किसी भी निर्णय पर आता है

बिन्दु पर और एक पास करें

का अधिकार

उचित निर्णय। हालांकि

इस *284* को स्थानांतरित करें

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत को औपचारिक रूप से नहीं लिया जाता है, पूरी कार्यवाही

इसे अप्रभावी और पूरी तरह से भ्रामक बना दिया जाता है।

प्रत्यर्थी की ओर से, यह इंगित किया गया है

कि

केवल संवैधानिक अधिकार की गारंटी देता है

अनुच्छेद *32*

उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो

इलाज

हैं।

घोषित किया गया

संविधान द्वारा। अगर कोई अधिकार नहीं है

इसके तहत

संविधान, एक व्यक्ति को गारंटीकृत

जिसे किसी के अधीन हिरासत में लिया गया है

निवारक कानून

बंदी बनाएँ

इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।

यह,

द्वारा अधिकार

एक दृष्टिकोण

सब उठ जाते हैं। मैं करता हूँ।

इस न्यायालय में

नहीं।

यह तर्क

सोचिए कि

आय

ध्वनि

ए पर

आधार; और मेरी राय में, धारा *14* लेता है यह कुछ मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है और उनमें भौतिक रूप से कटौती करता है जिनकी गारंटी स्वयं संविधान द्वारा दी गई है। संविधान का अनुच्छेद *22,* खंड *(5)* इस प्रकार निर्धारित करता है -

एक मौलिक अधिकार है कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है

निवारक निरोध के लिए, आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा। व्यक्ति वह आधार जिसके आधार पर

आदेश दिया गया है,

और उसे जल्द से जल्द वहन करेगा

बनाने का मौका

एक प्रतिनिधित्व

आदेश के खिलाफ। खंड *(6)* के अधीन,

प्राधिकरण को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यह खुलासा करना लोक हित के खिलाफ है। लेकिन इस तरह जहाँ तक

आधार संबंधित हैं, प्रकटीकरण नहीं है

किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित। यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर भी निर्भर है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करे। कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है, और मेरी राय में यह बिल्कुल सही है कि यदि किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए गए आधार इतने अस्पष्ट और अनिश्चित चरित्र के हैं कि कोई उचित और पर्याप्त नहीं है। उसी के जवाब में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, कि यह स्वयं उस अधिकार का उल्लंघन होगा जो कानून के तहत बंदी को दिया गया है। मेरे विचार में, न्यायालय के लिए यह निर्णय लेना संभव नहीं होगा कि अनुच्छेद *22*, खंड *(5)* के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं।

सही है।

इसके द्वारा गारंटी उपलब्ध कराई गई है

द.

को

जब तक कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत उसे बताए गए आधार वास्तव में अदालत के समक्ष पेश नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए यह तर्क देना भी खुला है कि हिरासत *285*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

आदेश निरोध प्राधिकारी द्वारा शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग रहा है और यह कि जिन आधारों पर यह आधारित है, वे उचित या प्रासंगिक आधार नहीं हैं जो स्वयं कानून के प्रावधानों के तहत निरोध को उचित ठहराते हैं। बंदी के इन अधिकारों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अप्रवर्तनीय बना दिया जाएगा यदि न्यायालय को उन आधारों पर गौर करने से रोक दिया जाता है जो

धारा *7* के तहत उसे आपूर्ति की गई है

निरोध अधिनियम। मेरी राय में, धारा *14*

निवारक निरोध अधिनियम भौतिक रूप से प्रभावित करता हैभाग *III* के तहत घोषित मौलिक अधिकार

संविधान और इस कारण से यह माना जाना चाहिए

अवैध और अति अधिकार। हालाँकि, यह विवादित नहीं है,

कि इस खंड को शेष से अलग किया जा सकता है

अधिनियम के अन्य प्रावधानों को प्रभावित किए बिना अधिनियम

इसलिए पूरा अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है।

किसी भी तरह से।

अल्ट्रा वायर्स होना।

श्री नाम्बियार

उन्होंने आगे तर्क दिया है कि धारा *3*

अनुच्छेद *32* के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

अधिनियम का भी

संविधान का, क्योंकि यह संतुष्ट करता है

अधिकारियों के मामलों में अंतिम

विशेष रूप से

निवारक

और इस प्रकार इस न्यायालय को रोकता है

नजरबंदी निरोध के औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करना

आदेश दें। यह विवाद सफल नहीं हो सकता क्योंकि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। जैसाकि

पहले ही इंगित किया जा चुका है कि यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि शक्ति का प्रयोग किया गया है

अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से या कि

आधार उचित या प्रासंगिक आधार नहीं हैं जो

नजरबंदी को उचित ठहराएँ।

प्रावधान निस्संदेह हैं

कठोर, लेकिन जैसा कि वे दूर नहीं करते हैं

के तहत अधिकार

संविधान के अनुच्छेद *21* और *22,*

वे नहीं हो सकते

अवैध या अधिकार से बाहर माना जाता है।

कि, मेरी राय में,

परिणाम, इसलिए,

निवारक निरोध अधिनियम को इंट्रा घोषित किया जाना चाहिए

धारा *14* के अपवाद के साथ संविधान को अधिकार देता है

जिसे अवैध और अधिकार से बाहर माना जाता है। द.

हालाँकि, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

खुला रहें।

याचिकाकर्ता को एक नया बनाने के लिए

यह हो सकता है

आवेदन यदि वह चुनता है और यदि आधार हैं

अधिनियम की धारा *7* के तहत उसे आपूर्ति की गई थीइस तरह का आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण दें।

286

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

जे. दास-मेरी भी यही राय है कि यह एप्पली

केशन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

में उपस्थित विद्वान वकील का तर्क

इस आवेदन का समर्थन यह है कि निवारक निरोध अधिनियम, *1950 (1950* का अधिनियम *IV)* के प्रावधान,

बेहद कठोर और पूरी तरह से अनुचित हैं

और

किसी भी स्थिति में, इसे हटा दें या काफी कम कर दें।

संविधान के भाग *III* के प्रावधानों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार और इस न्यायालय को अधिनियम को पूरी तरह से अमान्य घोषित करना चाहिए

संविधान का अनुच्छेद *13 (2)* और याचिकाकर्ता को निर्धारित किया

आज़ादी में।

इस दायरे को ध्यान में रखना आवश्यक है और

संविधान के अधीन न्यायालय की शक्तियों का दायरा। न्यायालय की शक्तियाँ इसके तहत समान नहीं हैं

सभी संविधान। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और इसकी विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए, संसद द्वारा विधिवत बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंग्रेजी न्यायालयों को कानून की व्याख्या करनी होती है और उसे लागू करना होता है; उनके पास इस तरह के कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी संविधान के अनुसार संघ की विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित है और एक अर्थ में कांग्रेस सर्वोच्च विधायी शक्ति है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान सरकार के तीनों अंगों से ऊपर है और वहाँ

इससे पहले, कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून, वैध होने के लिए,

के प्रावधानों के अनुरूप होना

संविधान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और घोषणा करेगा कि

कानून असंवैधानिक होगा

और शून्य। जैसा कि देखा जाएगा।

अधिक पूरी तरह से इसके बाद,

नेता के अधीन राज्य

संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय

सत्ता को ग्रहण किया

मुख्य न्यायाधीश मार्शल का जहाज, किसी भी कानून की घोषणा करें

इसके आधार पर असंवैधानिक

"कानून की उचित प्रक्रिया" में नहीं होना, संयुक्त राष्ट्र के पांचवें संशोधन *(1791)* में पाई जाने वाली एक अभिव्यक्ति राज्य का संविधान और चौदहवाँ

संशोधन

(1868) जो राज्य के संविधानों से संबंधित है। यह इस प्रकार है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना की

कार्यपालिका और कांग्रेस पर सर्वोच्चता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति एस. सी. आर. में कहीं है।

287

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के बीच।

जबकि मुख्य रूप से हमारी संसद छोड़ते हुए और

राज्य विधानमंडल अपने-अपने विधानमंडलों में सर्वोच्च हैं।

कुछ क्षेत्रों में, हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेदों के अनुसार,

विधानमंडलों पर कुछ निर्दिष्ट सीमाएँ लगाएँ

जिनमें से कुछ पर आगे चर्चा करनी होगी।

दबा दिया गया है और यदि कोई उल्लंघन हुआ है अदालत साहसपूर्वक कानून को असंवैधानिक घोषित करेगी।

राष्ट्रीय, क्योंकि न्यायालय अपनी शपथ को बनाए रखने के लिए बाध्य है

संविधान। लेकिन लगाई गई सीमाओं के बाहर

विधायी शक्तियाँ हमारी संसद और राज्य

विधायिकाएँ अपने-अपने विधान में सर्वोच्च हैं।

मंजूरी द्वारा बनाई गई कानून की समझदारी या नीतिमूल्यवान विधायिका। अंग्रेजी के विपरीत हमारा संविधान

संविधान, न्यायालय की सर्वोच्चता को मान्यता देता है

विधायी प्राधिकरण, लेकिन इस तरह की सर्वोच्चता एक बहुत है

एक सीमित, क्योंकि यह उस क्षेत्र तक सीमित है जहाँ

विधायी शक्ति द्वारा सीमित है

सीमाएं लगाई गईं

स्वयं संविधान द्वारा। इसके भीतर

प्रतिबंधित क्षेत्र न्यायालय, कानून की जांच पर

संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है। लेकिन हमारा संविधान, अमेरिकी संविधान के विपरीत,

न्यायालय की पूर्ण सर्वोच्चता को मान्यता नहीं देता है

सभी मामलों में विधायी प्राधिकरण के ऊपर, बाहर के लिए हमारी संवैधानिक सीमाओं का सीमित क्षेत्र

संसद और राज्य विधानमंडल सर्वोच्च हैं।

उनके संबंधित विधायी क्षेत्रों और उस व्यापक क्षेत्र में

भारत में न्यायालय के लिए भूमिका निभाने की कोई गुंजाइश नहीं है

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय। यह ठीक है। हम लगातार इस बुनियादी सीमा को याद रखने के लिए

हमारी अपनी शक्तियाँ।

विवादित अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है

संविधान लागू होने के बाद। अनुच्छेद *246*

संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है

सूची *I* में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सातवीं अनुसूची और यह विशेष शक्ति देता है

288

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

राज्य विधानमंडलों के संबंध में कानून बनाने के लिए

उस अनुसूची की सूची *II* में निर्दिष्ट मामलों में से कोई भी।

यह संसद को समवर्ती शक्ति भी देता है और साथ ही

राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में कानून बनाने के लिए

सूची *III* में उल्लिखित मामलों में से कोई भी

सातवीं अनुसूची। विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं -

अनुच्छेद *248* के तहत संसद में निहित।

ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि की प्रविष्टि *9* के तहत

संसद को सूची *I* और सूची *III* में प्रविष्टि *3* के तहत सूचीबद्ध करें।

संसद और राज्य विधानमंडल दोनों उनके अधीन हैं।

निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए सशक्त

में निर्दिष्ट कई मामलों से जुड़े कारण

संबंधित प्रविष्टियाँ। यह कानून लागू नहीं है।

किसी विदेशी के साथ किसी भी युद्ध के अस्तित्व पर टिप्पणी की गई

शक्ति या आपातकाल की घोषणा पर

संविधान का भाग *18*। हमारा संविधान है, इसलिए, निवारक निरोध को विषय के रूप में स्वीकार किया गया

शांति-समय का मामला एमेर से अलग कानून

गेन्सी कानून। यह प्रदान करने के लिए एक नई विशेषता हैसंविधान में निवारक निरोध। वहाँ है।

नहीं।

किसी अन्य देश के संविधान में ऐसा प्रावधान

जिसे मैं जानता हूँ। जो भी हो, अच्छे कारणों से

या बुरा, हमारे संविधान ने जानबूझकर और स्पष्ट रूप से

संसद और राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई

शांति में भी निवारक निरोध कानून बनाने के लिए

समय। हम में से कई लोगों के लिए एक निवारक निरोध कानून है

हर समय घृणित लेकिन जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह हैकि यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह विवेक पर सवाल उठाए और

संविधान की नीति जो लोगों ने दी है स्वयं के लिए। यह एक और बुनियादी तथ्य है कि

अदालत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ध्यान में रखने वाली अगली बात यह है कि, यदि वहाँ

संविधान में और कुछ नहीं था, विधायी

संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ

उनके संबंधित क्षेत्र निरपेक्ष होते। में।

केवल यह जांचने के लिए कि संसद या राज्य विधायिका ने, एक विशेष कानून बनाने में,

अपने विधायी क्षेत्र में कदम रखा और अतिक्रमण किया

अन्य विधायी शक्ति का विधायी क्षेत्र, लेकिन

अन्यथा किसी की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था

संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि।

एस सी आर।

अदालत की रिपोर्ट

सुपर

289

इस प्रकार सूची *I* की प्रविष्टि *9* के तहत संसद और इसके तहत

सूची *III* की प्रविष्टि *3*-संसद और राज्य विधायिका कठोर निवारक नजरबंदी कर सकती है

कानून जैसा चाहे वैसा बनाएँ। इस तरह के कानून के लेखक हो सकते हैं।

एक पुलिसकर्मी है, एक जिला मजिस्ट्रेट की बात करने के लिए नहीं

या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या के आयुक्त

पुलिस, एक आदमी को लेने के लिए, नागरिक या गैर-नागरिक,

उसे हिरासत में रखें और जब तक वहप्रसन्न हुए। हो सकता है कि इस कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो।

बंदी को उसकी नजरबंदी के आधार की आपूर्ति करने के लिए

उसे कोई भी करने का अवसर देना या प्रदान करना

किसी को भी प्रतिनिधित्व या किसी को स्थापित करने के लिए

सलाहकार मंडल बिल्कुल भी। इसी तरह, प्रविष्टि *1* के तहत और

2 सूची *III* में संसद या राज्य विधानमंडल

हो सकता है कि इसमें उतने ही नए और नए अपराध जोड़े गए हों

इसकी कल्पना ने किसी के लिए निर्धारित और प्रदान किया होगा

अंगों के अपंग होने से लेकर क्रूर दंड

तेल में उबलकर मरने के लिए या पूरे को निरस्त कर दिया

दंड प्रक्रिया संहिता और द्वारा परीक्षण के लिए प्रदान किया गया

लड़ाई या अग्निपरीक्षा या एक के फैसले से दोषसिद्धि के लिए

जादूगर या भविष्यवक्ता। इस तरह के कानून ने मना किया होगा

हालाँकि, सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी भाषण को अस्वीकार करें।

हल्के से, या सभी सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया या प्रतिबंधित कर दिया कानून के दंड के तहत सभी संघों का गठन।

सूची *I* की प्रविष्टि *33* के तहत संसद के पास हो सकता है

किसी की संपत्ति अर्जित करने के लिए एक कानून बनाया

बिना किसी मुआवजे के संघ के उद्देश्य और

सूची *III* में प्रविष्टि *36* के तहत राज्य विधानमंडल कर सकता है

प्रविष्टि *42* के प्रावधानों के अधीन भी ऐसा ही करें।

सूची *III* जो कानून बनाने का अधिकार देती है

मुआवजे के भुगतान के लिए सिद्धांत जो

कुछ भी नहीं से ऊपर कुछ भी हो सकता है। प्रविष्टि *81* के अंतर्गत

संसद प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी कानून बना सकती थी या

यहाँ तक कि अंतर-राज्यीय प्रवास को भी प्रतिबंधित करना ताकि एक बंगाली

बिहार में रहने और बसने में सक्षम नहीं होगा या

इसके उदाहरणों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है

इसके विपरीत।

अत्याचारी कानून जो संसद या राज्य विधानमंडल

लैचर के साथ पढ़ा अनुच्छेद *246* के तहत बनाया जा सकता है

अलग-अलग सूचियाँ अगर संविधान में और कुछ नहीं था

यह। हमारे विधानमंडल, की सीमा के अधीन

विधायी शक्तियों का वितरण इस प्रकार होता

-290 के रूप में अपने संबंधित विधायी क्षेत्रों में सर्वोच्च

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अंग्रेजी संसद है और रही है। न्यायालय में

ऐसी स्थिति में भारत को कानून अपनाना पड़ता

विधिवत बनाया गया, इसकी व्याख्या करें और इसे लागू करें। यह नहीं होगा।

औचित्य के बारे में एक शब्द बोलने का अधिकार है

विशेष कानून का, हालांकि यह कांप गया होगा इस तरह के कानून के राक्षसी अत्याचारों पर।

लेकिन हमारे संविधान ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

विधायिका। इस प्रकार अनुच्छेद *245 (1)* द्वारा विधायीके प्रावधानों के अधीन शक्ति निश्चित रूप से बनाई गई है

यह संविधान "। संविधान की ओर मुड़ते हुए, अनुच्छेद *13 (2)* निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त या कम करता है।

और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई कानूनउल्लंघन की सीमा तक, अमान्य होगा।

यह स्पष्ट रूप से व्यापक पर एक निश्चित सीमा रखता है

अनुच्छेद *246* द्वारा दी गई विधायी शक्तियाँ। यह निश्चित रूप से

न्याय करने के लिए न्यायालय की क्षमता के भीतर और

घोषणा करें कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है

अदालत ने

इस सीमा को।

इस संबंध में एक बार फिर

विधानमंडल पर सर्वोच्चता।

अब तक निर्दिष्ट प्रावधानों से, यह स्पष्ट रूप से

इस प्रकार दो प्रमुख सीमाएँ हैं -

संसद की विधायी शक्ति, अर्थात्,

((i) कि कानून विधायिका के भीतर होना चाहिए।

अनुच्छेद द्वारा विहित संसद की क्षमता

246 ; और

((ii) कि ऐसा कानून प्रो के अधीन होना चाहिए।

संविधान के दृष्टिकोण और दूर नहीं ले जाना चाहिए या

भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करें।

कोई सवाल नहीं हो सकता-और, वास्तव में, विद्वान

महान्यायवादी अन्यथा तर्क नहीं देते हैं-कि

ये दोनों मामले न्यायसंगत हैं और यह दोनों के लिए खुला है।

अदालतें तय करेंगी कि संसद ने उल्लंघन किया है या नहीं

इसकी विधायी शक्ति पर सीमाओं में से कोई भी।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह नहीं कहते हैं

कि विवादित अधिनियम विधायी अधिकार के बाहर है

अनुच्छेद *246* द्वारा विहित संसद की शक्तियाँ।

उनका तर्क है कि विवादित अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को अमान्य करता है

291

एस सी आर।

क्योंकि यह मौलिक को दूर ले जाता है या कम कर देता है

संविधान के भाग *II* द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अधिकार

विशेष निधि की सटीक प्रकृति, विस्तार और दायरामानसिक अधिकार पर जोर दिया और फिर देखने के लिए कि क्या

विवादित अधिनियम को हटा दिया गया है या किसी भी तरह से संक्षिप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार सुनिश्चित किया गया मौलिक अधिकार।

में विभाजित

आम तौर पर किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार

दो वर्ग, अर्थात्, संलग्न अधिकार

व्यक्ति के लिए

(जस पर्सनारम*)* और चीजों के अधिकार,

अर्थात प्रो

पेर्टी (जस. रेरम)। से जुड़े अधिकारों में सेव्यक्ति, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता है।

जिसका अर्थ है जीने का अधिकार, अर्थात वह अधिकार जो किसी का है।

अधिकार के बिना जीवन नहीं लिया जाएगा

कानून। जीवन की स्वतंत्रता के बाद आती है स्वतंत्रता

व्यक्ति, जिसका अर्थ है कि किसी का शरीर नहीं होगा किसी को छुआ गया, उल्लंघन किया गया, गिरफ्तार किया गया या कैद किया गया और

अंगों को घायल या अपंग नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि नीचे

कानून का अधिकार। सच तो यह है कि

जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है

व्यक्ति से जुड़े प्राथमिक अधिकार।

अगर एक आदमी

व्यक्ति स्वतंत्र है। यह तब है और केवल तभी वह कर सकता है

विभिन्न प्रकार के अन्य सहायक अधिकारों का प्रयोग करना, अर्थात कहो, वह, कुछ सीमाओं के भीतर, वह बोल सकता है जो उसे पसंद है,

जहाँ चाहे वहाँ इकट्ठा हों, कोई भी संगठन बनाएँ या संघ, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं क्योंकि उनका अपना झुकाव हो सकता है

प्रत्यक्ष, "जहाँ चाहें वहाँ रहें और बसें और अभ्यास करें

पुत्र और परिणामस्वरूप व्यक्ति से जुड़े अधिकार हैं। यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये सभी नहीं हैं।

व्यक्ति से जुड़े अधिकार। इनके अलावा वहाँ

अन्य अधिकारों की किस्में हैं जो विशेषता भी हैं

व्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे जुड़े सभी अधिकार

व्यक्ति को आमतौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है और

वे बहुत अधिक हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इनमें से कुछ

सहायक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और मौलिक हैं

कि उन्हें अलग माना और महत्व दिया जाता है

व्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा आश्रित अधिकार।

व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

कानून के भीतर जैसा कोई चाहता है वैसा करने का अधिकार। आई.

14-3 एस. सी. इंडिया/*58 292*

[1950]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून के भीतर कहें क्योंकि स्वतंत्रता बेलगाम लाइसेंस नहीं है। इसे एडमंड बर्क ने "विनियमित स्वतंत्रता" कहा था। मोंटेस्क्यू ने पुस्तक *III, Ch* में कहा। *3* , उनके नियमों की आत्मा के बारे में:

"सरकारों में, अर्थात, द्वारा निर्देशित समाजों में

कानून, स्वतंत्रता केवल शक्ति में या वह करने में शामिल हो सकती है जो हमें करना चाहिए, और वह करने के लिए विवश नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच के अंतर को निरंतर प्रस्तुत करना चाहिए। स्वतंत्रता वह करने का अधिकार है जो कानून अनुमति देता है, और यदि कोई नागरिक वह कर सकता है जो वे मना करते हैं, तो उसे अब स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि उसके सभी साथी नागरिकों को समान शक्ति प्राप्त होगी।

एक ही प्रभाव के लिए निम्नलिखित हैं:

अवलोकन

वेबस्टर की अपनी कृतियों में खंड। *II,* पी। *393 :*

"स्वतंत्रता कानून कानून का निर्माण है, अनिवार्य रूप से

यह उस अधिकृत अनुज्ञप्ति से अलग है जो दाईं ओर अतिक्रमण करती है। यह एक कानूनी और परिष्कृत विचार है, उच्च सभ्यता की संतान, जिसे बर्बर कभी नहीं समझते, और न ही कभी समझ सकते हैं।

समझें। स्वतंत्रता

स्वस्थ संयम के अनुपात में मौजूद है; दूसरों पर हमसे दूर रहने के लिए जितना अधिक संयम होगा, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता हमारे पास होगी। यह मान लेना एक गलती है कि स्वतंत्रता कानूनों की कमी में निहित है। विधायी पर नियंत्रण और प्रतिबंधों से भरी हमारी जटिल प्रणाली का काम करना,

कार्यपालिका और न्यायिक शक्ति स्वतंत्रता के लिए अनुकूल है।

और न्याय। ये नियंत्रण और प्रतिबंध व्यक्तिगत अधिकारों और हितों के इर्द-गिर्द निर्धारित कई सुरक्षा उपाय हैं। वह आदमी मुक्त है जो चोट से सुरक्षित है।

इसलिए, स्वतंत्रता पर संयम रखना

एक व्यक्ति का ऐसा करना वास्तव में इच्छित पीड़ितों की स्वतंत्रता को सुरक्षित कर रहा है। विध्वंसक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना या रेलवे लाइनों से मछली की प्लेटों को गुप्त रूप से हटाना असंख्य निर्दोष और संदेहहीन यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसलिए, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को न केवल व्यक्तिपरक रूप से आंका जाना चाहिए जैसा कि उनके संचालन के भीतर आने वाले कुछ व्यक्तियों पर लागू होता है, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के रूप में भी माना जाना चाहिए।

लिब्रेट्री

कहीं अधिक बड़ा

व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति में सामाजिक हित *293*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

स्वतंत्रता को अच्छी तरह से अधीन होना पड़ सकता है

अन्य

अधिक सामाजिक हित। यदि कोई कानून सुनिश्चित करता है और सुरक्षा देता है

कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा किके बाकी सदस्यों की अधिक स्वतंत्रता

कार्यपालिका, विधायिका के साथ-साथ न्यायपालिका के खिलाफ संरक्षित शक्तियों और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। विषय के अधीन

व्यक्तियों पर कुछ प्रतिबंध और उचित जाँच

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार हैं। स्वतंत्रताएँ बहुत अधिक हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसा कि होगा।

इसके बाद और अधिक पूरी तरह से देखा जाए तो हमारा संविधान फिर से लागू हो गया है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया। इसमें है।

उनमें से कुछ को अनुच्छेद *19 (1)* के तहत गारंटी दी गई लेकिन रखा गया

खंड *(2)* से खंड *(6)* द्वारा उन पर प्रतिबंध। इसने रखा है। अनुच्छेद *21* द्वारा राज्य की विधायी शक्तियों की जाँच करना

और *22.* इसने निवारक निरोध का प्रावधान किया है,

यह माना जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधीनस्थ हो सकती है व्यापक सामाजिक हितों के लिए।

अब संविधान की ओर मुड़ते हुए मुझे वह भाग मिलता है

III प्रमुख है और "मौलिक अधिकारों" से संबंधित है।

के तहत

प्रमुख, "सामान्य" प्रावधानों के अलावा

सात

(अनुच्छेद *12*

और

13) , अर्थात् "समानता का अधिकार"

(अनुच्छेद *14* से *18), "*स्वतंत्रता का अधिकार" *(*अनुच्छेद *19* से *18)*

" धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार *"(*अनुच्छेद *25* से *28), "* सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार *"(*अनुच्छेद *29* और

30) , " संपत्ति का अधिकार *"(*अनुच्छेद *31),"* संपत्ति का अधिकार "

संवैधानिक उपचार *"(*अनुच्छेद *32* से *35)*। इसके तहत"स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक को चार लेखों में बांटा गया है,

19 22 तक। अनुच्छेद *19 (1)* निम्नलिखित शब्दों में हैः

" *(1)* सभी नागरिकों को होगा अधिकार

(ख*)* शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;*(* ग*)* संघों या संघों का गठन करना;

(घ*)* पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए

भारत;

(ई*)* क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए

भारत का;

टीए

(च*)* संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करना; और

(छ*)* किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या

आगे बढ़ें।

कोई भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय।

यह ध्यान दिया जाएगा कि सात अधिकारों में से सुरक्षा

अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* द्वारा, उनमें से छह, अर्थात्, *(*क*),*

(ख*), (*ग*), (*घ*), (*ङ*)* और *(*छ*)* वे हैं जिन्हें अधिकार कहा जाता है।

व्यक्ति से जुड़ा हुआ *(*जस पर्सनारम*)*। अवशेष हैं। वस्तु, अर्थात्, *(*च*)* संपत्ति का अधिकार है *(*जस रे

रम*)*। यदि अनुच्छेद *19* में और कुछ नहीं था तो ये

उन्हें जो दिया गया वह पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया होगा।एम. ए. सी. से संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल

इनमें से किसी को भी हटाने या संक्षिप्त करने के लिए कोई कानून बनाना अधिकार। लेकिन अनुच्छेद *19* का अवलोकन इसे समृद्ध बनाता है।

राज्य द्वारा कई में उल्लिखित सीमा तक उस अनुच्छेद के खंड *(2)* से खंड *(6)*। वे खंड बचाते हैं

कुछ लागू करने वाले कानून बनाने की राज्य की शक्ति

परिणाम यह है कि द्वारा दी गई असीमित विधायी शक्ति विभिन्न विधायी सूचियों के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद *246*

सातवीं अनुसूची के प्रावधानों में कटौती की गई है -

अनुच्छेद *19* और राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानून

इन अधिकारों का होना आवश्यक है। वैध होने के लिए, इनका पालन करें

सीमाएँ। क्या वास्तव में किसी कानून ने उल्लंघन किया है

इन सीमाओं का न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना है और

यदि उसके विचार में कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं

खंड *(2)* से खंड *(6)* द्वारा अनुमत से अधिक

घोषणा करें

द.

जो भी लागू हो, न्यायालय करेगा।

समान रूप से असंवैधानिक होना और इसलिए, इसके तहत शून्य होना

अनुच्छेद *13.* यहाँ फिर से आवेदन के लिए गुंजाइश है

न्यायालय के *"*बौद्धिक मानदंड*"* का। अगर, कैसे*?*

कभी भी, अदालत ने जांच पर पाया कि कानून ने नहीं किया है

संवैधानिक सीमाओं को पार किया। न्यायालय

कानून को बनाए रखना होगा, चाहे वह कानून को पसंद करे

या नहीं।

तर्क के पहले भाग को व्यापक रूप से रखा गया है,

अर्थात्, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आम तौर पर गारंटी दी जाती है।

संविधान द्वारा अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा और यह कि वेंटिव डिटेन्शन एक्ट, *1950* ने अनुचित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट लागू की है।

एस सी आर।

295

के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उन पर प्रतिबंध उस अनुच्छेद के खंड *(2)* से खंड *(6)*। सबसे पहला सवाल

इसलिए जो उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या स्वतंत्रताव्यक्ति जो मुख्य रूप से और सीधे निलंबित है

या निवारक निरोध द्वारा नष्ट किया जाना बिल्कुल भी शासित है

अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस तरह की है अनुच्छेद *19 (1)* के किसी भी उपखंड द्वारा क्यों

क्या इसे अनुच्छेद *21* द्वारा भी संरक्षित किया गया है*?* इसका जवाब याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाव दिया गया है कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाता है

अनुच्छेद *19 (1)* और अनुच्छेद *21* केवल एक अतिरिक्त प्रावधान देता है।

प्रक्रिया निर्धारित करके सुरक्षाजिसके लिए वह अधिकार छीन लिया जा सकता है। मैं एक हूँ।

इस तर्क को स्वीकार करने में सक्षम। अगर यह तर्क था

उसके जीवन की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार के रूप में, के लिएजीवन का मूल अधिकार इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है।

अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के उपखंड। इसमें पलटवार किया जाता है

जवाब दें कि कोई भी संविधान या मानव कानून गारंटी नहीं दे सकता है

जीवन जो भगवान का उपहार है जो केवल गारंटी दे सकता है

और उसकी रक्षा करें। तर्क की समानता पर कोई संविधान नहीं

बोलने का अधिकार या स्वतंत्र आंदोलन, एक के लिए मारा जा सकता हैबीमारी से मूक हो जाता है या अपने पैरों का उपयोग खो सकता है

अनुच्छेद *21* का प्रक्रियात्मक संरक्षण कहा गया है यह एक अतिवाद का कार्य होगा, क्योंकि जब भगवान इसे स्वीकार करेंगे

किसी के जीवन से दूर, उसे जो भी अवसर मिला हो

भेजने से पहले आदम को अपना आचरण समझाने के लिए दिया गया

उसे नीचे, वह इन पतित दिनों में होने की संभावना नहीं है

इससे पहले नोटिस या निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकताओं का पालन करें

कोई भी मानव न्यायाधिकरण कहा जाता है। अनुच्छेद *21* द्वारा अपेक्षित।

पाँचवाँ संशोधन और चौदहवाँ संशोधन अमेरिकी संविधान विशिष्ट संरक्षण देता है

जीवन को एक मूल अधिकार के रूप में। ऐसा ही अनुच्छेद *31* करता है।

1946 का जापानी संविधान।

कोई कारण नहीं है

हमारा संविधान ऐसा क्यों नहीं करे। द.

सच्चाई यह है कि अनुच्छेद *21* ने जीवन को वह सुरक्षा दी है

एक मूल अधिकार के रूप में और जैसा कि यहाँ देखा जाएगा

इसके बाद, उस लेख को ठीक से समझा नहीं जाता है

किसी भी विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए पोर्ट। *296*

वकील के तर्क का और भी आश्चर्यजनक परिणामक्योंकि याचिकाकर्ता यह होगा कि भारत का नागरिक

उन्हें केवल अनुच्छेद *19* में उल्लिखित अधिकार होंगे।खंड *(1)* और उसके व्यक्ति से जुड़ा कोई अन्य अधिकार नहीं।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कई अधिकारों के अलावा

अनुच्छेद *19 (1)* के कई उपखंडों में उल्लिखित

वहाँ हैं

कई अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ जो

स्वतंत्र व्यक्ति, अर्थात, एक व्यक्ति जिसके पास अपनी स्वतंत्रता हैव्यक्ति, व्यायाम कर सकता है। इनमें से कुछ अन्य अधिकार हैं -

कलकत्ता के हैरिस सी. जे. ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। *1950* के विविध मामले संख्या *166* में रिपोर्ट किया गया निर्णय

हितेंद्र वी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव*)*

निम्नलिखित में एक पूर्ण पीठ को मामले को संदर्भित करते हुए

शब्दों का उच्चारणः --

"यह याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के पास बहुत कुछ है।

अनुच्छेद *19* में बताए गए अधिकारों की तुलना में अधिक और व्यापक अधिकार

(1) संविधान से। उदाहरण के लिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति कर सकता है

राशन कानून के तहत उसे जो पसंद है उसे खाओ, काम करें

या उतना ही बेकार

जितना वह पसंद करता है

उसे पसंद है। वह कर सकता है।

लाइसेंस कानून के अधीन जो कुछ भी उसे पसंद है उसे पीएँ

और धूम्रपान करते हैं और एक काम करते हैं जो अनुच्छेद *19* में शामिल नहीं है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता थी

परिणाम या अनुच्छेद *19,* तब एक स्वतंत्र व्यक्ति केवल

उस लेख में उल्लिखित सात अधिकार हैं। लेकिन

जाहिर है कि भारत में स्वतंत्र व्यक्ति के पास कहीं अधिक अधिकार हैं।

मैं विद्वानों से पूरी तरह सहमत हूँ।

इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश। अगर यह अन्यथा था,

नागरिक को जो पसंद है उसे खाने का अधिकार किसी भी राशन कानून की आवश्यकता के बिना नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यकारी आदेश द्वारा छीन लिया जाएगा। सरकार किसी भी निषेध कानून या लाइसेंस कानून आदि के बिना निषेध लागू कर सकती है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे संविधान का उद्देश्य उन अधिकारों के समूह को कोई सुरक्षा देना नहीं है जो उपखंड *(ए)* से *(ई)* और *(जी)* में उल्लिखित अधिकारों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाते हैं। वास्तव में, मैं इसे हमारे संविधान का एक गुण मानता हूं कि यह प्रयास नहीं करता है

व्यापक रूप से और व्यक्तिगत अधिकारों की गणना करें, लेकिन अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक अभिव्यक्ति का उपयोग करें, और उन सभी की रक्षा करें।

यह बताया गया है कि मूल मसौदे में

*"*स्वतंत्रता*"* शब्द का उपयोग केवल अमेरिकी *297* में किया गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान लेकिन प्रारूपण समिति ने जोड़ा

द.

*"*व्यक्तिगत*"* शब्द यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या

था।

जो अब अनुच्छेद *21* है, उसके द्वारा संरक्षित किया जाना नहीं था

जो पहले से ही अब लेख द्वारा संरक्षित किया गया था

19. यदि प्रारूपण को संदर्भित करने की अनुमति थी

समिति की रिपोर्ट, यह एक और जवाब होगा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें कि

एक मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई थी

अनुच्छेद *19* द्वारा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि

प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर मेरा निर्णय और

इसकी स्वीकार्यता के बारे में मैं कोई राय व्यक्त नहीं करता। क्या*?* कभी भी प्रारूप समिति के इरादे हो सकते हैं

संविधान अंततः पारित हो चुका हैअनुच्छेद *21* में *"*व्यक्तिगत स्वतंत्रता*"* शब्दों का उपयोग किया गया है जो

इसका मतलब केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह है इसका अर्थ है स्वतंत्रता या व्यक्ति से जुड़े अधिकार (जस।

अभिव्यक्ति "जीवन की स्वतंत्रता" या

व्यक्तित्व)।

और यह अनुच्छेद *19* की भाषा को दबाने के लिए दबाव डाल रहा है उस लेख में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। किसी भी मामले में

मामला

जीवन के अधिकार को अनुच्छेद *19* में नहीं पढ़ा जा सकता है।

अनुच्छेद *19* को अपने संचालन में सी. आई. टी. तक सीमित किया जा रहा है।

केवल एक गैर-नागरिक को उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी

जिसे कहा गया है उसे छोड़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद *21* का प्रक्रियात्मक संरक्षण। अगर कोई नहीं है

मूल अधिकार प्रक्रिया किसकी रक्षा करेगी?

मैं समझता हूँ कि यह अनिवार्य नहीं है कि कोई विदेशी

उन्हें वही विशेषाधिकार होने चाहिए जो किसी शहर को दिए गए हैं

ज़ेन, लेकिन अगर अनुच्छेद *21* को मेरे तरीके से समझा जाता है

सुझाव दिया कि एक विदेशी को भी समान सुरक्षा मिलेगी

हमारे कानूनों के समक्ष अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए

हमारे संविधान के तहत देश। मैं असमर्थ हूँ, वहाँ

ऊपर दिए गए सभी कारणों से, इस बात से सहमत होना कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ अनुच्छेद *19* या उस का परिणाम हैं।

उस लेख का उद्देश्य उन सभी की रक्षा करना है।

इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत"

स्वतंत्रता "स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का पर्याय है।

और, इसलिए, सीधे अनुच्छेद *19 (1)* (डी) के तहत आता है।

रिपोर्ट न किए गए असहमत निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है

विविध मामला सं. में कलकत्ता के सेन जे.*166 1950* का उस मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित करते हुए।

298

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

सेन जे. ने अपने फैसले में निम्नलिखित अंश का हवाला दियाः

ब्लैकस्टोन की टिप्पणियों सेः

" व्यक्तिगत सुरक्षा के बाद इंग्लैंड का कानून

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान, दावा और संरक्षण

व्यक्तियों। इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है

गति की शक्ति, बदलती स्थिति, या चलने की शक्ति

व्यक्ति का अपना झुकाव किसी भी स्थान पर हो।

बिना कारावास या संयम के निर्देश दे सकते हैं, जब तक कि

देय द्वारा

कानून का पाठ्यक्रम "। *[* जॉर्ज चेज़ का पृष्ठ *73*

ब्लैकस्टोन का संस्करण *(*चौथा संस्करण*),* पुस्तक *1,* अध्याय *1।]*

उपरोक्त परिच्छेद के अधिकार पर विद्वान

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भीतर आती है

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)*। मैं विद्वानों से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ

न्यायाधीश का निष्कर्ष।

पुस्तक के प्रथम अध्याय के अवलोकन पर

ब्लैकस्टोन की टिप्पणियों में से यह प्रतीत होगा कि

विद्वान टिप्पणीकार ने संबंधित अधिकारों को विभाजित किया

व्यक्ति *(*जस पर्सनारम*)* को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात्, "व्यक्तिगत सुरक्षा" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता"। के तहत प्रमुख "व्यक्तिगत सुरक्षा" ब्लैकस्टोन में सात अधिकार शामिल थे, अर्थात्, जीवन, अंग, शरीर के अधिकार,

स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा, और सिर के नीचे "व्यक्तिगत

स्वतंत्रता "उन्होंने केवल स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार रखा। उन्होंने सबसे पहले अपने द्वारा वर्गीकृत किए गए कई अधिकारों से निपटा।

"व्यक्तिगत सुरक्षा" शीर्षक के तहत और फिर आगे बढ़े

यह कहने के लिए कि उन अधिकारों के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता आई जो उनके वर्गीकरण के अनुसार केवल मुक्त आवागमन के अधिकार में शामिल थी। यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद *21* में अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का उपयोग उस सीमित अर्थ में किया गया है जिसमें ब्लैकस्टोन ने अपनी टिप्पणियों में इसका उपयोग किया है। यदि अनुच्छेद *21* में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का पर्याय थी जिसका उल्लेख अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में किया गया है, तो आश्चर्यजनक परिणाम यह होगा कि केवल अंतिम उल्लिखित अधिकार को ही अनुच्छेद *21* का प्रक्रियात्मक संरक्षण कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद *19 (1)* के अन्य उपखंडों में अन्य अधिकारों में से किसी को भी कोई प्रक्रियात्मक संरक्षण नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार अनुच्छेद *21* द्वारा फिर से मांगी गई प्रक्रिया में नोटिस और एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है। इसलिए, उसके अनुसार, एक आदमी के आंदोलन के अधिकार को उसे नोटिस दिए बिना और एक निष्पक्ष मुकदमे के बिना नहीं लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष लेकिन वह किसी भी प्रक्रिया की औपचारिकता के बिना अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अपनी संपत्ति या अपने किसी अन्य अधिकार से वंचित हो सकता है

सभी। प्रस्ताव को केवल अस्वीकार कहा जाना चाहिए। मेरे निर्णय में, अनुच्छेद *19* व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्वतंत्र अधिकारों के रूप में संरक्षित करता है और अनुच्छेद *21* में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति का उपयोग एक समग्र शब्द के रूप में किया गया है, जिसमें इसके अर्थ के भीतर सभी प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो पुरुषों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरा करते हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अगला तर्क दिया

कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निस्संदेह अर्थ है या इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य और उप रुख स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और इसके परिणामस्वरूप एक निवारक निरोध कानून जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट या निलंबित करता है, उसे अनिवार्य रूप से स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार को नष्ट या निलंबित करना चाहिए और आवश्यक रूप से अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* द्वारा नागरिक को दिए गए संरक्षण के खिलाफ अपराध करना चाहिए जब तक कि यह खंड *(5)* में निर्धारित तर्कसंगतता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है। तर्क आकर्षक है और सटीक उद्देश्य और दायरे के रूप में गंभीर विचार की आवश्यकता है।

अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंड *(*घ*)* का।

बहुत ही भाषा में संकेत हैं

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)* स्वयं कहता है कि इसका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं हैमुक्त आवाजाही का सामान्य अधिकार जो सामने आता है

व्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकिन इसके केवल एक विशिष्ट और सीमित पहलू से, अर्थात्, एक स्वतंत्र व्यक्ति का विशेष अधिकार।

पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए भारतीय नागरिक राज्यक्षेत्र, अर्थात, एक राज्य से दूसरे राज्य में

संघ। दूसरे शब्दों में, यह गारंटी देता है, एक्साम्पी के लिए,

कि आम तौर पर रहने वाला एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक

पश्चिम बंगाल राज्य पश्चिम से आने-जाने के लिए स्वतंत्र होगा

पंजाब बिना किसी छूट या बाधा के खंड *(5)* में उपबंधित। यह स्थानांतरण का विशेष अधिकार है।

इस विशिष्ट अर्थ में भारतीय नागरिक का विचार और

अनुच्छेद *19 (1) (*घ*)*। यह एक के अधिकार पर तर्क दिया जाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ का निर्णय

सुनील कुमार बनाम में सेन जे द्वारा अध्यक्षता की गई। द चीफ *300*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

पश्चिम बंगाल के सचिव *(1)* ने कहा कि शब्द "के माध्यम से"

उस उपखंड में आने वाले भारत के क्षेत्र से बाहर

केवल यह इंगित करता है कि हमारा संविधान गारंटी नहीं देता है

अपने नागरिकों को अंतर्ज्ञान में या अंतर्ज्ञान में मुक्त आवाजाही का अधिकार

विदेशी क्षेत्र और उन शब्दों को जोड़ा गया है

एक विदेशी देश में और यह पूरी तरह से अनावश्यक था संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, इसके लिए

बिना कहे चला गया होगा। इन शब्दों के माध्यम से

भारत के क्षेत्र से बाहर का उपयोग इस संबंध में नहीं किया जाता है

और अभिव्यक्ति, जैसे, पाकिस्तान में? क्या यह गारंटी देता हैइसके नागरिकों को इकट्ठा होने या संघ बनाने का अधिकार है।

या किसी विदेशी क्षेत्र में संघ? साफ तौर पर नहीं। इसलिए,

उपखंड *(घ)* में उन शब्दों का उपयोग करना आवश्यक नहीं था।

यह इंगित करने के लिए कि विदेशों में मुक्त आवाजाही

इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उपयोग सेउन शब्दों में से संविधान यह स्पष्ट करता है कि

नहीं।

इस संबंध में किसी भी नागरिक को गारंटी दी जा रही थी।बिना पासपोर्ट के भारत से पलायन करना और वह

भारत के क्षेत्र के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी। क्या उन शब्दों को छोड़ दिया जाता है?

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* से संकेत मिलता है कि भारत का नागरिक

बोलने की ऐसी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और पूर्वदबाव के रूप में वह एक प्रसारण स्थापित करने में सक्षम होगा

स्टेशन और उनके विचारों और अभिव्यक्तियों को प्रसारित करें

को

बिना लाइसेंस के विदेशी भूमि? साफ तौर पर नहीं। तर्क की इस पंक्ति को छोड़ते हुए और तर्क की एक पूरी तरह से नई पंक्ति को अपनाते हुए कहा जाता है कि "भारत के पूरे क्षेत्र में" शब्दों के उपयोग से संविधान में कहा गया है कि स्वतंत्र आवाजाही का व्यापक अधिकार जो वह संभवतः अपने नागरिकों को दे सकता था, दिया गया है। डॉक्स, फिर, अन्य उपखंडों से उन शब्दों को हटाने से संकेत मिलता है कि संविधान पीछे हट गया है। उन अधिकारों के कुछ भागों की सीमाओं से परे भीयोग्यता खंड जो आगे आते हैं? क्या वे अन्य अधिकार पूरे भारतीय क्षेत्र में प्रबल नहीं हैं? *(1) 54* सी. डब्ल्यू. एन. *394*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

301

एस सी आर। स्पष्ट रूप से वे करते हैं, उन शब्दों के बिना भी। इसलिए, उन शब्दों का उपयोग उपखंड *(घ)* में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया होगा। वह दूसरा उद्देश्य, जहाँ तक मैं इसे समझ सकता हूँ, यह इंगित करना है कि संघ के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र आवाजाही की रक्षा की जाती है ताकि संसद सूची *I* में प्रविष्टि *81* के तहत बनाए गए कानून द्वारा इसे निर्धारित सीमाओं से अधिक सीमित न कर सके।

इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने पढ़ा है

अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* द्वारा संपादित।

यह स्वतंत्र आवाजाही के सामान्य अधिकार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए भारतीय नागरिक के एक विशिष्ट और विशेष अधिकार को सुरक्षित करने के लिए है।

भारत के क्षेत्र जिन्हें एक स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता है

व्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न चलने-फिरने के सामान्य अधिकार के अलावा राष्ट्रीय अधिकार। यह पूरे भारतीय संघ में भारतीय नागरिक की मुक्त आवाजाही के मामले में अनुचित भेदभाव के खिलाफ एक गारंटी है। संक्षेप में, यह प्रांतवाद के खिलाफ एक सुरक्षा है। इसका व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेना-देना नहीं है। इसकी हर किसी को गारंटी है व्यक्ति, नागरिक या अन्यथा, अनुच्छेद *21* द्वारा तैयार किए गए तरीके और सीमा तक।

अनुच्छेद *19* का खंड *(5)* अनुच्छेद *19* के उपखंड *(*घ*)* को अर्हता प्रदान करता है।

खंड *(1)* जिसे इसलिए खंड *(5)* के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। अंतिम उल्लिखित खंड राज्य को इसके प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है - जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत के पूरे क्षेत्र में मुक्त आवाजाही का अधिकार। उचित प्रतिबंधों के अधिरोपण का स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अधिकार के कुछ हिस्से बने हुए हैं। यह उचित प्रतिबंध या तो लगाया जा सकता है

आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। अनुसूचित जनजाति आमतौर पर उन क्षेत्रों में रहती हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान

अनुसूचित जनजातियों के हित में नागरिकों का स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिबंध वास्तव में अनुसूचित क्षेत्रों में या उनके भीतर स्वतंत्र आवाजाही के उनके अधिकार पर है। इसका अर्थ यह है कि यदि अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक पाया जाता है तो नागरिकों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवेश करने या घूमने से रोका जा सकता है, हालांकि वे कहीं और जाने के लिए काफी स्वतंत्र हैं। यह संयम *[1950]* हो सकता है।

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धन-उधारदाताओं या अन्य लोगों के खिलाफ जो उनका शोषण करने के लिए बाहर हो सकते हैं। उन्हें संरक्षित करना पड़ सकता है। उनकी अपनी त्रुटिहीन आदतों के खिलाफ, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने चूल्हे और घरों को बेच या गिरवी रख सकते हैं। इसी तरह, नागरिकों के स्वतंत्र आवाजाही को आम जनता के हित में प्रतिबंधित करना पड़ सकता है। एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पूर्व हो सकता है

इधर-उधर जाने और बीमारी फैलाने से रोका और प्रकृति में उसके अलगाव के लिए नियम

संगरोध लागू करना पड़ सकता है। इसी तरह, स्वस्थ लोगों को रोका जा सकता है, के हित में

आम जनता को प्लेग-संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। ऐसे संरक्षित स्थान हो सकते हैं, जैसे कि किले या अन्य रणनीतिक स्थान, जहाँ तक पहुँच को आम जनता के हित में विनियमित या प्रतिबंधित भी किया जा

सकता है। हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब इस प्रकार मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे वह आम जनता के हित में हो या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए, तो इस तरह के प्रतिबंध का संदर्भ आम तौर पर एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र के लिए होता है जो निषिद्ध क्षेत्र बन जाता है, लेकिन संघ के अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार अप्रभावित छोड़ दिया जाता है। यह परिस्थिति कि खंड *(5)* केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्र को छीनने और इस प्रकार खंड *(1)* के उपखंड *(घ)* द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग के क्षेत्र को सीमित करने पर विचार करता है, मेरे मन में इंगित करता है कि उपखंड *(घ)* व्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्र आवाजाही के सामान्य अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा एक स्वतंत्र अधिकार माना जाता है। दूसरे शब्दों में, उपखंड *(घ)* में वास्तविक जोर "भारत के पूरे क्षेत्र में" शब्दों पर है। अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई राज्य बाधा नहीं होगी। यह प्रांतवाद के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसका व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेना-देना नहीं है।

अंत में, अधिकारों का दायरा और दायरा तय होता है।

अनुच्छेद *19 (1)* पर विचार किया जाना चाहिए।

करता है*?*

मुक्त आवाजाही के अधिकार और अन्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की रक्षा करना।

303

एस सी आर।

किसी भी अन्य विचार के बावजूद सभी परिस्थितियों में उल्लिखित व्यक्तिगत अधिकार*?* करता है*?*

नहीं।

अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता का प्रतिपादन करें*?* क्या इसका संरक्षण तब भी जारी रहता है जब नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से अपनी क्षमता खो देता है*?* उन व्यक्तिगत अधिकारों की निरंतरता व्यक्ति के वैध निरोध के साथ कैसे संगत हो सकती है*?* ये प्रति सोनल अधिकार और वैध निरोध एक साथ नहीं जा सकते हैं।

एक ऐसे व्यक्ति का मामला लीजिए जिसे ठीक से धोखा दिया गया है। की एक धारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया

जिसकी तर्कसंगतता के बारे में भारतीय दंड संहिता

कोई विवाद नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता का उनका अधिकार है

निश्चित रूप से अक्षम। खंड *(2)* के तहत राज्य कर सकता हैमानहानि, बदनामी, मानहानि, अवमानना से संबंधित कानून

न्यायालय या कोई ऐसा मामला जो शालीनता का उल्लंघन करता हो

या नैतिकता या जो सुरक्षा को कमजोर करती है, या

राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है। इनमें से किसी पर भी कोई कानून

इस खंड खंड द्वारा विचार किए गए ये मामले निश्चित रूप से

भाषण और अभिव्यक्तियों के लिए कुछ सीधा संदर्भ होना चाहिए

सायन। इसका मतलब है कि कानून सीधे तौर पर कटौती कर सकता है

बोलने की स्वतंत्रता ताकि नागरिक बात न कर सके

मानहानि करना या न्यायालय की अवमानना करना या व्यक्त करना

भाषण या अन्य द्वारा अभद्र या अनैतिक भावनाएँ

अभिव्यक्ति के रूप या राजद्रोही शब्द बोलना। कहने के लिए

कि प्रत्येक अपराध राज्य की सुरक्षा को कम करता है

चाहे इसमें भाषण का कोई संदर्भ होया अभिव्यक्ति, इस के अर्थ के भीतर एक कानून है

और बैठक के लिए एक स्पष्टीकरण खोजने का असफल प्रयास यह तर्क कि किसी न्यायालय द्वारा कोई दोषसिद्धि

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* का लगातार उल्लंघन करना चाहिए। हो सकता है।इस तथ्य से दूर नहीं जाना कि एक नजरबंदी के रूप में

एक दृढ़ विश्वास का परिणाम स्वतंत्रता को बाधित करता है

खंड *(2)* के तहत अनुमेय से कहीं अधिक भाषण

अनुच्छेद *19* का। इसी तरह वैध ठगों पर हिरासतविजय प्रत्येक अन्य व्यक्तिगत अधिकार पुरुषों को बाधित करती है।

उपखंड *(बी)* से *(ई)* और *(जी)* में उल्लिखित खंड *(3)* से *(6)* की सीमाएँ। तर्क है कि हर

भारतीय दंड संहिता की धारा भले ही

इसमें निर्दिष्ट किसी भी अधिकार का कोई संदर्भ है।

उपखंड *(बी)* से *(ई)* और *(जी)* में *304* लागू करने वाला कानून है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

यहां तक कि संभाव्यता की योग्यता भी नहीं। हो सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैध के परिणामस्वरूप एक नजरबंदी

कनविक

यह अनिवार्य रूप से मौलिक को बाधित करना चाहिए

व्यक्तिगत

अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा गारंटीकृत अधिकार

इससे परे

उसके खंड *(2)* से *(6)* के तहत क्या अनुज्ञेय है

लेख और फिर भी कोई भी सवाल करने के बारे में नहीं सोच सकता है

निरोध या धारा की वैधता

भारतीय दंड संहिता जिसके तहत सजा सुनाई गई थी। क्यों*?* क्योंकि उसके व्यक्ति की स्वतंत्रता है

कानूनी रूप से ले जाया गया, दोषी बंद हो जाता है

होना।

सायन या किसी अन्य व्यक्तिगत अधिकार द्वारा संरक्षित अनुच्छेद *19* का खंड *(1)*। तर्क की समानता पर वह, जब तक हिरासत बनी रहती है, किसी अन्य व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, उदाहरण के लिए, वह जो चाहता है या जब चाहता है वह नहीं खा सकता है, लेकिन उसे वही खाना पड़ता है जो जेल संहिता उसके लिए प्रदान करती है।

और उस समय जब वह जेल के नियमों द्वारा आवश्यक है

इसलिए यह निष्कर्ष अटूट है कि

खाने के लिए। अनुच्छेद *(19) (1)* द्वारा संरक्षित अधिकार, जहाँ तक वे व्यक्ति से जुड़े अधिकारों से संबंधित हैं, अर्थात उपखंड *(ए)* से *(ई)* और *(जी)* में निर्दिष्ट अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो केवल एक स्वतंत्र नागरिक को हैं, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त है।उसका व्यक्ति विकलांग है, व्यायाम कर सकता है।

यह इंगित किया गया है

उपरोक्त तर्कों के प्रतिवाद के रूप में, कि वैध दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप निरोध किसी व्यक्ति को उपखंड *(च)* में उल्लिखित अपनी संपत्ति प्राप्त करने या रखने या निपटाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं करता है। इसका उत्तर सरल है, अर्थात्, वह अधिकार व्यक्ति से जुड़ा अधिकार नहीं है, *(*जस पर्सनारम*)* और इसका अस्तित्व व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता का नुकसान, वहाँ

व्यक्ति को। इसके अलावा, संपत्ति के अधिकार को निलंबित नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद *31* के तहत अनिवार्य रूप से अर्जित की गई संपत्ति के कारण अपनी संपत्ति खो देता है, तो वह उस संपत्ति को रखने का अपना अधिकार खो देता है और ऐसा नहीं कर सकता है।

शिकायत है कि अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के उपखंड *(च)* के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। आईः इस प्रकार है कि अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित अधिकार मौजूद हैं जबकि नागरिक के पास उन्हें लागू करने की कानूनी क्षमता है। यदि अधिकारों *305* के संबंध में वैध दोषसिद्धि के कारण उनका प्रयोग करने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।उपखंड *(क)* से *(ग)* और *(छ)* में, या किसी विधि पूर्ण के कारण अधिकार के संबंध में अनिवार्य अधिग्रहण

उपखंड *(च)*, जब तक उसकी असमर्थता बनी रहती है, तब तक उसे वे अधिकार नहीं मिलते हैं। यह आगे बताता है कि यदि कोई नागरिक

व्यक्ति की स्वतंत्रता को कानूनी रूप से छीन लिया जाता है, अन्यथा किसी अपराध के लिए वैध दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, वह नागरिक, ठीक उसी कारण से, ऐसा नहीं कर सकता है। अपने व्यक्ति से जुड़े किसी भी अधिकार का उल्लेख करें, जिसमें शामिल हैं -

जिनका उल्लेख अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(ई)* और *(जी)* में किया गया है। मेरे निर्णय में एक वैध निरोध,

चाहे दंडात्मक हो या निवारक, अनुच्छेद *19 (1) (ए)* से *(ई)* और *(जी)* द्वारा प्रदत्त संरक्षण के खिलाफ अपराध नहीं करता है, क्योंकि उन अधिकारों को अनिवार्य रूप से तब समाप्त कर दिया जाना चाहिए जब व्यक्ति की स्वतंत्रता कानूनी रूप से छीन ली जाती है। संक्षेप में, वे अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जहां से वैध निरोध शुरू होता है। इस प्रकार समझा गया, अनुच्छेद *19* और अनुच्छेद *21*

हो सकता है,

आसानी से एक साथ जाएँ और वास्तव में, उनके बीच कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि निवारक निरोध की वैधता या अन्यथा अनुच्छेद *19* पर निर्भर नहीं है, और इसके द्वारा निपटा नहीं जाता है।

संक्षेप में, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है

अनुच्छेद *19* का परिणाम। अनुच्छेद *19* केवल कुछ विशेष अधिकारों से संबंधित है, जो अपनी उत्पत्ति और स्थापना में स्वतंत्रता या व्यक्ति के गुण हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण विशिष्ट और स्वतंत्र अधिकारों के रूप में माने जाते हैं। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद *19 (1) (डी)* स्वतंत्र रूप से चलने के अधिकार का एक विशिष्ट पहलू बताता है, अर्थात्, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार जिसे एक भारतीय नागरिक का विशेष विशेषाधिकार या अधिकार माना जाता है और इस तरह से संरक्षित

है। अनुच्छेद *19* का संरक्षण नागरिक की अधिकारों का प्रयोग करने की कानूनी क्षमता के साथ-साथ समाप्त होता है।

इस प्रकार, अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(ई)* और *(जी)* के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिनिर्धारित करता है जो केवल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि

अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता

संरक्षित

उन उपखंडों द्वारा। एक नागरिक जो

हार जाते हैं

कानूनी रूप से हिरासत में लिए जाने से उसके व्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप हो या

निवारक निरोध के परिणामस्वरूप उन अधिकारों का प्रयोग करने की उसकी क्षमता खो जाती है और इसलिए उसके पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं हैं जिनकी उपखंड *(ए)* से *(ई)* और *(जी)* रक्षा कर सकें।

[1950]

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेरे निर्णय में अनुच्छेद *19* का निवारक निरोध की वैधता या अन्यथा के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है और यह कि ऐसा खंड *(5)* होने के कारण, जो न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किए जाने के लिए तर्कसंगतता का एक परीक्षण परीक्षण निर्धारित करता है, इसका कोई आवेदन नहीं है।

इस प्रकार अनुच्छेद *19* मार्ग से बाहर है। मैं आता हूँ।

अनुच्छेद *20* जो संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है

उन कानूनों के खिलाफ, जिन्हें पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून, दोहरे खतरे और आत्म-दोषारोपण के रूप में जाना जाता है। यह अनुच्छेद पूर्ण विधायी शक्ति पर एक सीमा का गठन करता है, लेकिन इस अनुच्छेद के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा विधायी सूचियों के साथ पठित अनुच्छेद *246* के तहत प्रयोग किया जा सकता है। यदि विधायिका

अदालत निश्चित रूप से

द.

इस सीमा की अवज्ञा करता है

इसे रोकें।

अनुच्छेद *20* में कोई नहीं है

निवारक पर असर

निरोध कानून और मैं आगे बढ़ता हूँ।

अनुच्छेद *21* इस प्रकार है:

"21. कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से वंचित नहीं रहेगा।

प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता

या

कानून द्वारा स्थापित "।

पेट्टी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के लिए विद्वान वकील का तर्क

इसका तात्पर्य यह है कि इस अनुच्छेद द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, को केवल एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। तर्क के अनुसार, यह लेख

जीवन को या प्रति सोनल स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार के रूप में कोई सुरक्षा देने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन केवल एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसका पालन किसी व्यक्ति को करने से पहले किया जाना चाहिए।

मैं हूँ।

अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाए।

इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ। अनुच्छेद *21,*

के रूप में

"प्रो

सीमांत नोट में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। जैसा कि मैंने इसे पढ़ा है, यह मूल मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है जिसके लिए

संरक्षण दिया जाता है और इसका उद्देश्य किसी विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करना नहीं है। यह कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, वह उप-स्थायी मौलिक अधिकार है जिसे संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है। की घोषित वस्तु

लेख, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे को परिभाषित करने के लिए है।

इसे मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है। जीवन का अधिकार और

307

एस सी आर।अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं है।

लेकिन एक योग्य अधिकार है-एक अधिकार

निरपेक्ष

सही है।

खो जाने की संभावना या जोखिम से

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित होने की देयता सीमित शब्दों की प्रकृति में होती है। यह अनुच्छेद जबड़े द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अभाव के लिए अपने दायित्व के संदर्भ में अधिकार का परिसीमन करता है और इसी परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले एक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्य पर एक संबंधित दायित्व डालता है। वह प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यह निर्धारित करने या इंगित करने के लिए इस लेख के उद्देश्य या दायरे में नहीं है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का दावा है

वह अनुच्छेद *21* एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रक्रिया का अर्थ है प्रक्रिया के वे मौलिक अपरिवर्तनीय नियम जो सभी जलवायु और देशों में और हर समय स्वीकार किए जाने वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा स्वीकृत या अच्छी तरह से स्थापित हैं। इस सवाल के अलावा कि क्या प्राकृतिक प्रक्रिया का कोई नियम मौजूद है जो हर समय सभी मानव जाति के न्याय और निष्पक्ष खेल की धारणाओं के अनुरूप है, यह पता लगाना होगा कि क्या अनुच्छेद *21* की भाषा हमारे संविधान में इसकी शुरूआत के अनुरूप होगी। इसके बाद सवाल उठता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। अनुच्छेद *21* में "प्रक्रिया" शब्द को किसी कदम को इंगित करने के लिए लिया जाना चाहिए।

या जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए आगे बढ़ने की विधि या तरीका। के अनुसार

लेख में उपयोग की गई भाषा, इस प्रक्रिया को "कानून द्वारा स्थापित" किया जाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वॉल्यूम के अनुसार "स्थापित" शब्द। *III*, पी। *297* , इसका अर्थ है, अन्य बातों के अलावा, "स्थिर या दृढ़ बनाना; भौतिक समर्थन द्वारा मजबूत करना; ठीक करना, अधिनियम या समझौते द्वारा स्थायी रूप से निपटान, स्थापना या आदेश। डॉ. अन्नानडेल के न्यू ग्रेशम डिक्शनरी के संस्करण के अनुसार "स्थापित" शब्द,

इसका अर्थ है, अन्य बातों के अलावा, "स्थायी रूप से पाया जाना; स्थापित करना; अधिनियमित करना या डिक्री देना; आदेश देना; अनुसमर्थन करना; दृढ़ बनाना"। यह इस प्रकार है कि अपने सामान्य प्राकृतिक अर्थों में "स्थापित" शब्द का अर्थ है, अन्य बातों के अलावा, "अधिनियमित"। "कानून द्वारा स्थापित "इच्छा",

15-3 एस. सी. इंडिया/*58 308*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, इसका अर्थ है "कानून द्वारा अधिनियमित"। यदि "स्थापित" शब्द का यह अर्थ स्वीकार किया जाता है, तो "कानून" शब्द का अर्थ राज्य द्वारा बनाया गया कानून होना चाहिए और संभवतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को कभी भी उन सिद्धांतों द्वारा "अधिनियमित" नहीं कहा जा सकता है। जब भारतीय दंड संहिता की धारा *124*-ए "कानून द्वारा स्थापित सरकार" की बात करती है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब "प्राकृतिक न्याय द्वारा स्थापित सरकार" नहीं है।

इसलिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को,

आई.

यह राज्य द्वारा अधिनियमित प्रक्रिया होगी, जिसमें अनुच्छेद *12* में अपनी परिभाषा के अनुसार संसद शामिल है। यदि किसी कानून में उपयोग किए गए शब्दों को उनका सामान्य प्राकृतिक अर्थ देने के लिए निर्माण का मूल नियम लागू किया जाता है, तो इस स्थिति से कोई बच नहीं सकता है।

मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं, तो क़ानून का निर्माण था। द. प्रक्रिया के हिंदू या मुसलमान कानून

थे।

निरस्त और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रतिस्थापित

या दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए प्रो.

कानून द्वारा स्थापित सेडर काफी संगत है

ब्लिश्ड का अर्थ "स्वीकृत" या "व्यवस्थित" माना जाता है या "दृढ़" होने पर सवाल उठेगा कि

उस संदर्भ में "कानून" शब्द का अर्थ। संदर्भ लें

एंस को सैल्मंड के न्यायशास्त्र, *10* वीं ई. में बनाया गया है। टियोन, पी। *37* , यह दर्शाता है कि "कानून" शब्द का उपयोग किया जाता है

"कानून द्वारा स्थापित" अभिव्यक्ति का अर्थ है कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अमूर्त भावना। यह है।

के लिए सलाह

" "लेक्स" नहीं बल्कि "जस", लर्नड कहते हैं

द.

याचिकाकर्ता। यह बताया गया है कि दोनों अँग्रेजी

और कई मामलों में भारतीय कानून, जिनमें से कुछ हैं हमारे सामने उद्धृत किया गया है, मान्यता दी है और लागू किया है

हमारे कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने में भी ऐसा ही करें।व्यवस्था। मुझे प्रकृति के सिद्धांतों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

शब्द के अर्थ के भीतर होने के रूप में न्याय

" कानून ", इसके स्पष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए

अन्य लेखों में शब्द। अनुच्छेद *14* निश्चित रूप से

प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत जो एस. सी. एस. सी. आर. को सुनिश्चित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

309

प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। जब प्राकृतिक न्याय कानून के समक्ष समानता की बात करता है और आदेश देता है, तो उस कानून को बाहर की किसी चीज़ को संदर्भित करना चाहिए।

प्राकृतिक

न्याय, और इसका मतलब राज्य द्वारा बनाए गए कानून होना चाहिए। यह तभी होता है जब राज्य का कानून प्रत्येक व्यक्ति को समानता देता है

कि उस कानून को प्राकृतिक न्याय के अनुसार कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद *17* में "कानून के अनुसार" शब्द राज्य के कानून के संदर्भ में हैं। इसी तरह, अनुच्छेद *20 (1)* में "कानून" शब्द का अर्थ राज्य द्वारा बनाए गए कानून के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। द.

यही टिप्पणी अनुच्छेद *23,31* और *32* में "कानून के अनुसार" शब्दों पर लागू होती है। प्राकृतिक न्याय

कोई कर नहीं लगाता है और इसलिए, अनुच्छेद *265* और *286* में "कानून" शब्द का अर्थ राज्य द्वारा निर्मित होना चाहिए।

कानून। यदि यह "कानून" शब्द का सही अर्थ है तो अनुच्छेद *21* और "स्थापित प्रक्रिया" में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कानून के अनुसार "

इसका मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होना चाहिए

राज्य द्वारा बनाया गया जिसमें, जैसा परिभाषित किया गया है, पार्लिया शामिल है

राज्य और राज्यों के विधानमंडलों।

हमें कई पाठ्य पुस्तकों के लिए संदर्भित किया गया है

और अमेरिकी विकास को दर्शाने वाले निर्णय

"कानून की उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत और हम रहे हैं

उन सिद्धांतों को हमारे संविधान में अपनाने का आग्रह किया।

इस मामले को इसके ऐतिहासिक आधार के खिलाफ माना जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि. विभिन्न भागों में अंग्रेज बसने वाले

अमेरिका के लोग अपने साथ अंग्रेजी सामान ले गए थे।उनके अधिकारों को विनियमित करने वाले एक प्रकार के व्यक्तिगत कानून के रूप में कानून

और स्वतंत्रताएँ आपस में और साथ ही उनके बीच और

राज्य। स्वतंत्रता संग्राम के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित रूप में तैयार किए गए थे।

संविधान बनाने वालों में से अधिकांश

महान अंग्रेजी न्यायविद ब्लैकस्टोन का मेष, जो अपने प्रसिद्ध टिप्पणियों ने अलगाव की वकालत की थी

राज्य के तीन अंग, अर्थात्, कार्यपालिका,

विधायिका और न्यायपालिका। मोंटेस्क्यू की आत्मा

कानून पहले ही प्रकाशित हो चुके थे जिसमें उन्होंने एक

अरिस्टोट के लिए व्यापक और अधिक जोरदार अभिव्यक्ति शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दें। अनुभव.

संसद के दमनकारी कानूनों ने प्रभावित किया था

अमेरिकी संविधान *310* के निर्माताओं पर

यह विश्वास कि सभी विधायी निकायों की आदत थी कि वे उन शक्तियों को समझें और उनका प्रयोग करें जो उनकी नहीं थीं। कानून के साथ औपनिवेशिक राज्यपालों का हस्तक्षेप

और

न्यायपालिका भी वास्तविक थी। यह दुखद है।

अनुभव युग्मित

राजनीतिक दर्शन के साथ

समय ने फ्रेमर्स को प्रेरित किया

या अमेरिकी संविधान

न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी सुरक्षा उपाय अपनाना। *(* संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन पर मुनरो देखें, *5* वां संस्करण, अध्याय *IV*, पी। *53* इत्यादि।*)* . जज कूली अपनी संवैधानिक सीमाओं, छठे संस्करण, खंड में कहते हैं। *II*, अध्याय *XI*, पी। *755 :*

"अमेरिकी राज्यों के लोग, धारण करते हैं

अपने हाथों में संप्रभुता, व्यक्तिगत अधिकारों के उचित अवलोकन के लिए किसी से कोई प्रतिज्ञा करने का कोई अवसर नहीं है; लेकिन शक्ति की आक्रामक प्रवृत्ति ऐसी है कि उन्होंने इसे कोई छोटा महत्व नहीं माना है, कि, नीचे दिए गए उपकरणों को तैयार करने में

जिन्हें उनकी सरकारों को उनके एजेंटों द्वारा प्रशासित किया जाना है, उन्हें इस गारंटी को दोहराना और फिर से लागू करना चाहिए, और इस तरह इसे संवैधानिक सिद्धांत के रूप में अपनाना चाहिए।सुरक्षा "।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लोगों के

अमेरिका के विभिन्न राज्यों का इरादा विधायिका से भी अपने जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के बारे में कोई जोखिम नहीं लेना था। जैसा कि मुनरो ने इसे पीपी पर रखा है। *58-61 : —*

"संविधान निर्माताओं ने सीमाएं निर्धारित कीं

कांग्रेस की शक्तियों के लिए, और यह उनका इरादा था कि इन सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन अदालतों द्वारा इस तरह के पालन को कैसे लागू किया जाना था*? 1767* के राजनेताओं ने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया कि

सवाल "।

संविधान चुप था और कोई नहीं था

कांग्रेस द्वारा अपनी विधायी शक्तियों की सीमाओं को पार करने की स्थिति में किसे अंपायर के रूप में काम करना था, इस बारे में प्रावधान व्यक्त करें। *5* वें संशोधन द्वारा जिसे अब "नियत प्रक्रिया खंड" के रूप में जाना जाता है, संघीय संविधान में पेश किया गया था और *14* वें संशोधन द्वारा राज्य संविधानों में इसी तरह का खंड अपनाया गया था। कुछ राज्य संविधानों ने "कानून के उचित पाठ्यक्रम" शब्दों का उपयोग किया, कुछ ने मैग्ना चार्टा के शब्दों को दोहराया, अर्थात्, "देश का कानून" लेकिन अधिकांश सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट।

एस सी आर।

311

उन्होंने "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। सभी अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ था, अर्थात्, किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस खंड द्वारा संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का कार्य करने का अवसर दिया। और मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वोच्च

न्यायालय ने इस अवसर का लाभ उठाया और संवैधानिकता के प्रश्नों पर अंतिम शब्द कहने का अधिकार ग्रहण किया, और उसे यह अधिकार प्राप्त हैः *(* मुनरो, पी। *62)*।

अभिव्यक्ति "उचित प्रक्रिया या कानून" किया गया है

अमेरिकी न्यायालयों द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की गई। कार्ल ब्रेंट स्विशर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक शक्ति के विकास पर अपनी पुस्तक में पी। *107* उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के विकास के संदर्भ में कहते हैंः

" इसकी व्याख्या का अमेरिकी इतिहास नीचे आता है

तीन अवधियों में। संविधान के तहत सरकार की लगभग पहली शताब्दी को कवर करने वाली पहली अवधि के दौरान "उचित प्रक्रिया" की व्याख्या "प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में की गई थी-और मुख्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया-जिसके द्वारा सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती थी। दूसरी अवधि के दौरान, जिसे मोटे तौर पर *1936* तक बढ़ाया गया था, "उचित प्रक्रिया" का विस्तार न केवल प्रक्रिया पर बल्कि उन गतिविधियों के सार पर प्रतिबंध के रूप में किया गया था जिनमें सरकार संलग्न हो सकती है। *1936* से आज तक की तीसरी अवधि के दौरान, एक ठोस प्रतिबंध के रूप में "उचित प्रक्रिया" के उपयोग को काफी हद तक निलंबित या त्याग दिया गया है, जिससे यह मुख्य रूप से प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में अपनी मूल स्थिति में रह गया है।

"कानून की उचित प्रक्रिया" की व्याख्या करने की आड़ में

अमेरिकी अदालतें इससे बहुत आगे बढ़ गईं

यहाँ तक कि

लॉर्ड कोक ने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा। अमेरिकी अदालतों ने धीरे-धीरे सभी कानूनों को संशोधित करने की शक्ति को खुद पर हावी कर लिया। शुरुआत में वे किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता या या अधिकार से वंचित करने से पहले एक उचित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देने तक सीमित थे।

संपत्ति।

समय के साथ, "कानून की उचित प्रक्रिया" को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण, प्रक्रिया *312* के लिए लागू किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

अधिकारिता और मूल कानून के लिएः *(* विलिस, पी।

मुनरो के शब्दों में "कानून की उचित प्रक्रिया"

642) .

एक तरह का पैलेडियम बन गया जो हर तरह से ढकता है

वाक्यांश को परिभाषित करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे सक्षम करने के लिए इसका उपयोग कियाविधान के किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करता है जो

अनुचित सोचाः *(* विलिस, पी। *657)*। होल्डन वी.

हार्डी *(1)* हम निम्नलिखित टिप्पणियाँ पाते हैंः

" इस न्यायालय ने कभी भी परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है

'कानून की उचित प्रक्रिया' शब्दों को सटीक करें। यह.

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कुछ अपरिवर्तनीय हैं

न्याय के सिद्धांत जो इस विचार में निहित हैं

स्वतंत्र सरकार जो संघ का कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है

उपेक्षा करें। "

टेलर वी। पीटर *(2)* ब्रोंसन जे. ने कहाः

" देश के कानून द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द '

संविधान का अर्थ गलत काम करने के उद्देश्य से पारित कानून से नहीं है। वह निर्माण

प्रतिबंध को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा, और संविधान के इस हिस्से को केवल मूर्खतापूर्ण बना दें।

लोगों से दोनों सदनों से कहा जाएगाः

' आपको विधायी शक्ति प्रदान की जाएगी

राज्य, लेकिन किसी को भी नागरिक के किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित या वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि आप उस उद्देश्य के लिए एक क़ानून पारित नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनते, तब तक आप गलत नहीं करेंगे। "

यह इस प्रकार था कि संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय

राज्यों ने राज्य के अन्य दो अंगों, अर्थात् कार्यपालिका और कांग्रेस पर अपना वर्चस्व दृढ़ता से स्थापित किया। जॉन डिकिन्सन के शब्दों में मुनरो में पी। *61* , " आर्गन के न्यायाधीश। कानून को अलग करने के साथ शुरू हुआ और बनाने के साथ समाप्त हुआउन्हें "। और यह सब व्यापक विकास केवल एक छोटे से शब्द "देय" की उपस्थिति के कारण संभव हो सका, जो अपनी सामग्री में कोई सीमा नहीं जानता है और किसी निश्चित परिभाषा के अधीन नहीं है। जब भी

एक उप

स्थायी कानून या किसी भी कानून में निर्धारित कुछ प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत का समर्थन नहीं मिला, यह उचित नहीं था और इसलिए, यह "देय" नहीं था।

(1) 4 हिल *140,145*।

(1) 169 यू. एस. पी. *366* पर। *389 .*

एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

313

शब्द का बहुत बड़ा और अस्पष्ट महत्व

" न्यायाधीशों के अनुसार एक दिन जो "देय" नहीं था, उसके परिणामस्वरूप विसंगतियां होना तय था, फिर *20* साल बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन करना "देय" हो गया, नए न्यायाधीशों के अनुसार जो तब बेंच पर कब्जा करने के लिए आए थे, क्योंकि कोर्ट को संविधान को समाज की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करना था जो लगातार बदल रहे थे और बढ़ रहे थे। कानून की उचित प्रक्रिया की व्यापक सामग्री, जिसमें कानून की प्रक्रियात्मक और मूल उचित प्रक्रिया दोनों शामिल थीं, को संकुचित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सामाजिक हित को अन्य मामलों में सामाजिक हित को रास्ता देना था, जिन्हें माना जाने लगा।

समुदाय के लिए अधिक महत्वपूर्ण हित। यह था।

पुलिस शक्तियों के नए सिद्धांत को विकसित करना-एक विशिष्ट अमेरिकी सिद्धांत। पुलिस की शक्तियाँ कहीं भी नहीं हैं।

पूरी तरह से परिभाषित। शिकागो बी. एंड क्यू. राय में। वी.

जल निकासी आयुक्त *(1)* "पुलिस शक्ति" को "सार्वजनिक सुविधा या सामान्य समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए नियमों को शामिल करने" के लिए कहा गया है।

के रूप में

साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नैतिकता या सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए नियम। संदर्भ लें

इस संबंध में कूली को सूचित किया जा सकता है।

संवैधानिक सीमाएँ, *8* वां संस्करण, खंड। *II,* पी।

1223 और पी पर विलिस के अध्याय *XXVI* के लिए। *727 .*

शुद्ध परिणाम यह है कि सभी-समावेशी और स्वदेशी

अब एक की अपनी मूल स्थिति में वापस लाया गया घोषणा द्वारा विधि की प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया और

पुलिस शक्ति के नए सिद्धांत का अनुप्रयोगएंटीडोट या पूर्व के लिए उपशामक। कौन जानता है कब

पेंडुलम फिर से झूल जाएगा।

अब उस ओर मुड़ना जिसे प्रक्रिया कहा गया है

कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यह पाया जाएगा कि मामला अलग-अलग भाषाओं में वर्णित किया गया है

मामले। वेस्टरवेल्ट बनाम। ग्रेग *(2)* एडवर्ड्स जे परिभाषित

यह इस प्रकार हैः

" कानून की उचित प्रक्रिया का निस्संदेह अर्थ है,

उन नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही का उचित क्रम

(3) 12 एन. वाई. *202*

(1) 20 1 यू. एस. *561,592*।

314

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

और प्रपत्र जो रक्षक के लिए स्थापित किए गए हैं

निजी अधिकारों का हनन "।

अभिव्यक्ति की एक अधिक विशिष्ट परिभाषा "द

देश का कानून "जिसका अर्थ है प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया

वेबस्टर द्वारा वादी के वकील के रूप में प्रस्तुत किया गया

डार्टमाउथ कॉलेज बनाम के न्यासियों में त्रुटि। लकड़ी का वार्ड *(1):*

" देश के कानून के अनुसार सबसे स्पष्ट रूप से इरादा है।

सामान्य कानून; एक ऐसा कानून जो इसके समक्ष सुनता है और इसकी निंदा करता है;जो जाँच के बाद आगे बढ़ता है और निर्णय देता है

मुकदमे के बाद ही। मतलब यह है कि हर नागरिक

अपने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और उन्मुक्ति को बनाए रखेगा,

शासन करने वाले सामान्य नियमों के संरक्षण के तहत समाज। सब कुछ जो फॉर्म के तहत पारित हो सकता है

इसलिए किसी अधिनियम को देश का कानून नहीं माना जाना चाहिए।

च में विलिस। *XXIII,* पी। *661* , कहते हैंः

"एक मामले के रूप में कानूनी प्रक्रिया की गारंटी

प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई भी हिस्सा, जिसमें स्वामित्व भी शामिल है, उससे कुछ औपचारिकताओं के पालन के अलावा नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सामाजिक हित की रक्षा करना है।

पी. *662* विलिस आवश्यकताओं की गणना करते हैं -

विधि की प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया निम्नानुसार हैः *(1)* नोटिस, *(2)* सुनवाई का अवसर, *(3)* एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण और *(4)* प्रक्रिया का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम। संक्षेप में, प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिसे अपने जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित किया जाना है, उसका "अदालत में अपना दिन" रहा होगा। यह पी द्वारा विलो के अनुसार है। *736* , मतलबः

" *(1)* कि उसे उचित सूचना मिल गई होगी, जो

वह कार्यवाहियों की स्थापना का वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है, जिसके द्वारा उसके कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं; *(2)* कि उसे एक उचित अवसर दिया जाएगा।

को

उपस्थित होना और अपने अधिकारों की रक्षा करना, जिसमें स्वयं गवाही देने का अधिकार, गवाह पेश करना, और प्रासंगिक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य पेश करना शामिल है, *(3)* कि न्यायाधिकरण जिसमें या जिसके समक्ष उसके अधिकारों का निर्णय लिया जाता है, इस तरह से गठित किया गया है ताकि उसके अधिकारों का उचित आश्वासन दिया जा सके।

(1) पी पर *4* व्हीटन *518*। *79 ; 4* एल. एडन। *629* पी पर। *615 .*

315

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर। ईमानदारी और निष्पक्षता; और *(4)* कि यह सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है।

यह ध्यान दिया जाएगा कि विल की चौथी वस्तु

लौबी विलिस की चौथी फिल्म से अलग है। संक्षेप में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून की प्रक्रिया के सिद्धांत के विकास का इतिहास और उस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोर दिए जाने के अनुसार प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएं हैं।

हमसे पहले याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील

यह तर्क नहीं देते कि हमें कानून की उचित प्रक्रिया के इस अमेरिकी दस्तावेज़ को उसके पूर्ण गौरव में आयात करना चाहिए, लेकिन हमें इसके प्रक्रियात्मक हिस्से को अपनाना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय उन औपचारिकताओं के पालन के जो न्याय और निष्पक्षता के पालन की आवश्यकता है। तर्क

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकीलों के विचार आकर्षक हैं और पहली शर्मनाक टिप्पणी निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को आकर्षित करती है, लेकिन गंभीर चिंतन पर मुझे हमारे संविधान में कानून की प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के अमेरिकी सिद्धांत को लागू करने के लिए कई अक्षम्य तर्क मिलते हैं। यह सिद्धांत तभी फल-फूल सकता है और काम कर सकता है जब न्यायपालिका इस अर्थ में न्यायपालिका के अधीन हो कि न्यायपालिका निर्णय में बैठ सकती है और विधायिका के सभी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। इस तरह के सिद्धांत का उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं हो सकता है जहां विधायिका सर्वोच्च है। यही कारण है कि "कानून की उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत इंग्लैंड में काफी अलग है जहां संसद सर्वोच्च है। मैथ्यूज जे. ने इस अंतर को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है।

जोसेफ हुर्टाडो बनाम। कैलिफोर्निया के लोग *(1)* पी। *531 :*

"मैग्ना चार्टा की रियायतों को रद्द कर दिया गया था

राजा से उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी के रूप में

और

उसके विशेषाधिकारों का दुरूपयोग। बैरनों के दिमाग में यह नहीं आया कि वे संसद की शक्ति को सीमित करके अपने स्वयं के निकाय के खिलाफ या आम लोगों के पक्ष में सुरक्षा प्रदान करें, ताकि प्राप्तकर्ता के बिल, पूर्व-वास्तविक कानून, संपत्ति की ज़ब्ती की घोषणा करने वाले कानून और अन्य मनमाने कानून जो अंग्रेजी इतिहास में अक्सर होते हैं, उन्हें कभी भी देश के कानून के साथ असंगत नहीं माना गया, क्योंकि *(*बोनहैम में लॉर्ड कोक को जो जिम्मेदार ठहराया गया था, उसके बिना*)*

((1882) [10 यू. एस. *516*।

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मामला, *[8* कोक *115,118 (*ए*),]* पार्लिया की सर्वशक्तिमानता

सामान्य कानून पर विचार पूर्ण था, यहाँ तक कि इसके खिलाफ भी।

वास्तविक और व्यावहारिक

सामान्य अधिकार और कारण।विधायी अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा

एक स्वतंत्र जनमत की शक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया था

कॉमन्स द्वारा।

इस देश में लिखित संविधान माने जाते थे।

लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक

उन्हें सौंपी गई शक्ति के अतिक्रमण के खिलाफ

अधिकारों के बिलों में शामिल। वे सीमित थे। सरकार की सभी शक्तियों पर, विधायी के रूप में

साथ ही कार्यकारी और न्यायिक "।

दोनों प्रणालियों के बीच यह बुनियादी अंतर

कभी भी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए, अगर विचार का भ्रम है

बचने के लिए। हालाँकि हमारे संविधान ने लागू किया है

विधायी प्राधिकरणों पर सीमाएँ, अभी तक

कुछ इस तरह की सीमाओं के अधीन और बाहर हमारे संविधान

हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों को छोड़ दिया हैअपने संबंधित विधायी क्षेत्रों में सर्वोच्च। में

मुख्य रूप से, मैंने जिन सीमाओं का उल्लेख किया है, उनके अधीन, हमारे संविधान ने विधानमंडलों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी है

न्यायपालिका की प्रकृति। अंग्रेज़ी सिद्धांत

इसलिए, कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार अधिक है

अमेरिकी सिद्धांत की तुलना में हमारा संविधान जो

काफी अलग प्रणाली की सेवा के लिए विकसित किया गया है।

ऊपर उद्धृत ब्रोंसन जे. की सुरम्य भाषा,

जबकि यह अमेरिकी संविधान के लिए काफी उपयुक्त है जो सर्वोच्चता को मान्यता नहीं देता है।

कांग्रेस का, हमारे जैसे संविधान में पूरी तरह से स्थान से बाहर है, और इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है, जो केवल कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, अपने-अपने मामलों में विधानमंडलों की सर्वोच्चता को मान्यता देता है।

मैदान। इसके अलावा, यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर कानून की उचित प्रक्रिया के अनिश्चित और बदलते अमेरिकी सिद्धांत को अपनाने से इनकार कर दिया और "कानून की उचित प्रक्रिया को छोड़कर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जो मूल मसौदे में अधिक विशिष्ट अभिव्यक्ति द्वारा "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर" थे। इसके बावजूद या इस तथ्य के बावजूद अमेरिकी सिद्धांत को लाने की कोशिश करना होगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए संविधान के इरादे को कम करना।

एस सी आर।

अनुच्छेद *21.* तीसरे स्थान पर, उस अनुच्छेद की भाषा के स्पष्ट अर्थ को देखते हुए, जैसा कि ऊपर समझाया गया है और जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है, अमेरिकी द्वारा कानून की प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया में अपनाए गए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्वीकार करना असंभव है।

सुप्रीम कोर्ट। पुनः, यहां तक कि सर्वव्यापी छोटे शब्द "देय" को भी अनुच्छेद *21* में जगह नहीं मिलती है ताकि प्रक्रिया को योग्य बनाया जा सके। यह प्रक्रिया की बात करता है न कि "उचित" प्रक्रिया की और इसलिए, न्यायालय की "बौद्धिक यार्ड छड़ी" को निश्चित रूप से खारिज कर दिया जाता है। अंत में, कानून के उचित उपकर के सिद्धांत को इसके उपशामक, पुलिस शक्तियों के सिद्धांत के बिना आयात करना असंगत होगा। अंतिम उल्लिखित सिद्धांत को अनुच्छेद *21* में पढ़ना असंभव है।

इसे एक समझौते के रूप में भी सुझाया गया है

इस न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के लचीले सिद्धांतों के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए जैसा कि कानून की उचित प्रक्रिया के अमेरिकी सिद्धांत और केवल राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की कठोरता के बीच अपनाया गया है। यह कहा जाता है कि हमारे पास दंड प्रक्रिया संहिता है जो इसके कुछ प्रावधानों के अंतर्गत आती है

सलामी प्रिंसी

के तहत

प्रक्रिया के बारे में और हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि उन झूठ बोलने वाले सिद्धांतों को हमारे सकारात्मक कानून द्वारा समाप्त या तय की गई प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए। लेकिन कौन बताएगा कि वे बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? मैं किन सिद्धांतों को अनावश्यक बताकर अस्वीकार करता हूं और किन सिद्धांतों को मौलिक के रूप में अपनाऊंगा? क्या है बुनियादी बात

मुझे

हो सकता है कि आज एक दशक बाद किसी अन्य न्यायाधीश को ऐसा न लगे, क्योंकि बदलती सामाजिक स्थितियों के साथ सिद्धांत आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में यह सुझाव दिया गया था कि

विधि कानून की उचित प्रक्रिया को सामान्य कानून के सामान्य निकाय के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि यह तारीख में था।

संविधान से। बार्डवेल डब्ल्यू में। कोलिन्स *(1)*

यह था

निम्नलिखित शब्दों में नकारात्मकः

"कानून की उचित प्रक्रिया '

इसका मतलब यह नहीं है कि जनरल

कानून का निकाय, सामान्य और क़ानून, जैसा कि संविधान के प्रभावी होने के समय था; इसके लिए विधायिका को किसी विशेष रूप से कानून को बदलने या संशोधित करने की शक्ति से वंचित कर देगा।

हालाँकि, न्यायालय ने इन सिद्धांतों को लाया -

(1) 44 मिन, *97*।

318

सर्वोच्च न्यायालय। रिपोर्टें

[1950]

उचित प्रक्रिया खंड के तहत प्राकृतिक न्याय। स्नान करने के लिए

जिन बातों को मैं आज बुनियादी सिद्धांतों के रूप में मानता हूँ, उन्हें स्पष्ट करें।

दंड प्रक्रिया की हमारी संहिता के अंतर्गत होगा

उन्हें अपरिवर्तनीय बनाना और विधायिका को रोकना यहाँ तक कि उनमें सुधार करने के लिए भी। यह और कुछ नहीं बल्कि आई एम है।

विधायिका पर एक सीमा डालते हुए जो कॉन इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मुझे नहीं लगता कि यह एक

न्यायालय के लिए अनुज्ञेय साहसिक कार्य करना। यह एक खतरनाक साहसिक कार्य है, क्योंकि यह हाथी राष्ट्र लाएगा जिसका अर्थ है विनाश। हमें संविधान को स्वीकार करना चाहिए जो सर्वोच्च कानून है। संविधान ने अनुच्छेद *21* द्वारा एक प्रक्रिया की आवश्यकता की है और अनुच्छेद में प्रक्रिया की कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।

22. इन्हें जोड़ना संविधान की व्याख्या करना नहीं है। लेकिन इसे हमारे बौद्धिक मापदंड और हमारी अचेतन प्रवृत्तियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए कि क्या

एक आदर्श

संविधान होना चाहिए।

अनुच्छेद *21,* मेरे निर्णय में, केवल एक

जीवन और व्यक्तिगत जीवन का मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता जो अपनी सामग्री में एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक सीमित अधिकार है, जिसका दायरा एक प्रक्रिया का पालन करके इसे छीन लिए जाने के जोखिम से सीमित है।

उपयुक्त द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित

राज़ी। विधायी प्राधिकरण और निकटवर्ती उद्देश्य

अनुच्छेद *21* में कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस तारीख को संविधान लागू हुआ था, उस तारीख को भारतीय दंड संहिता ने विभिन्न अपराधों का निर्माण किया

था और उनमें से किसी के लिए भी दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर देगी। समवर्ती सूची की प्रविष्टि *1* के साथ पठित अनुच्छेद *246* के तहत, संसद या कोई भी राज्य विधानमंडल अधिक अपराध जोड़ सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए और साधन बना सकता है। लेकिन यह सब अभाव दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही की जा सकती है। पुनः, इस संविधान की तिथि पर लगभग हर प्रांत में निवारक निरोध कानून थे और उन कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता था। हालाँकि, उन कानूनों ने एक प्रकार की प्रक्रिया प्रदान की जिसका पालन किया जाना था। इसलिए, संविधान लागू होने से पहले, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लिया जा सकता था *319*

एस सी आर।

सुपर

अदालत की रिपोर्ट

केवल द्वारा अधिनियमित प्रक्रिया का पालन करके

दंडात्मक निरोध के मामले में या निवारक निरोध के मामले में विभिन्न सुरक्षा अधिनियमों द्वारा अधिनियमित प्रक्रिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता। हालाँकि, संसद और राज्य विधानमंडलों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि *2* के साथ पठित अनुच्छेद *246* के तहत दंड प्रक्रिया के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगर वह लेख अपने आप खड़ा रहा

द.

संसद या राज्य विधानमंडल पूरे आपराधिक मामले को निरस्त कर सकता है।

प्रक्रिया संहिता और यह भी करें

कंकाल के साथ भी दूर

में दी गई प्रक्रिया

सुरक्षा अधिनियम। यदि अनुच्छेद *246*

खुद खड़ा रहा तो

उपयुक्त विधायी प्राधिकरण

ले जा सकता था

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दूर करें

किसी के साथ भी

किसी भी प्रक्रिया से बाहर निकलें। यह विधायी प्राधिकरण की यह पूर्ण सर्वोच्चता है,

हालांकि,

काट दिया गया

अनुच्छेद *21* द्वारा जो एक प्रक्रिया के संदर्भ में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के दायरे और दायरे को सीमित करता है और अनुच्छेद *22* द्वारा जो न्यूनतम प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस स्थिति में न्यायालय की एकमात्र शक्ति है -

यह निर्धारित करना कि क्या विवादित कानून ने कुछ प्रक्रिया प्रदान की है और अनुच्छेद *22* की लघु आवश्यकताओं का पालन और पालन किया है और यदि किया है, तो यह नहीं है

न्यायालय द्वारा अधिक विस्तार पर जोर देने के लिए

अपनी धारणा के अनुसार प्रक्रिया या विधायी प्राधिकरण के विवेक पर सवाल उठाना

विशेष कानून। हालाँकि कठोर, अनुचित, पुरातन

उस कानून के प्रावधान घृणित हो सकते हैं।

यह कहा जाता है कि अगर यह सख्ती से तकनीकी व्याख्या है

यह अनुच्छेद *21* पर रखा जाता है तो यह एक मौलिक अधिकार का गठन नहीं करेगा और इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता विधानमंडल की दया पर होगी, जो किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रदान करके और अनुच्छेद *22* की कुछ आवश्यकताओं का पालन करके, किसी भी समय, किसी व्यक्ति को उसकी खुशी और इच्छा पर उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। इस तर्क के कई जवाब हैं। अनुच्छेद *21* जैसा कि मेरे द्वारा समझा गया है, यदि कुछ और नहीं, तो निश्चित रूप से होगा।

और के रूप में

कार्यपालिका के खिलाफ व्यक्ति

हर किसी की रक्षा करें यह उतना ही मौलिक अधिकार होगा जितना कि *320*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

मैग्ना चार्टा के प्रसिद्ध *39* वें अध्याय के रूप में संविधान में एक स्थान अंग्रेजी कानून में स्वतंत्रता का एक गढ़ था और है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद *32* के साथ पठित हमारे संविधान का अनुच्छेद *21* हमें विधायी प्राधिकरण के खिलाफ भी कुछ सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें एक व्यक्ति को केवल प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, जो इसके द्वारा अधिनियमित होने के बावजूद, कम से कम अनुच्छेद *22* की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इस सीमा के अधीन

हमारी संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल में

मई

अनुच्छेद *21* के तहत किसी भी कानून को लागू करना और किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई भी प्रक्रिया प्रदान करना। उस अनुच्छेद का ऐसा अर्थ और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का दायरा और विस्तार जो इस देश के लोगों ने खुद को दिया है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई भी कानून जो अनुच्छेद *246* के तहत उपयुक्त विधायी प्राधिकरण द्वारा बनाया जा सकता है और अनुच्छेद *22* की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है।

अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को कम करें, क्योंकि

उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार परिधि में है

इस तरह के कानून को उल्लंघन नहीं माना जा सकता हैअनुच्छेद *13 (2)* के प्रावधान; हमारा संविधान

एक है

संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता

में से

इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। जिन सीमाओं का मैंने उल्लेख किया है, जो निश्चित रूप से न्यायसंगत हैं, उनके अधीन रहते हुए हमारे संविधान ने विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया है।

प्राधिकरण और, ऐसा होने पर, हमें उस निकाय की सामयिक अनिश्चितताओं का सामना करने और अत्याचारी अंग्रेजी क़ानून की प्रकृति के अधिनियमों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बार-बार उल्लेख किया है, अर्थात्, कि रोचेस्टर के रसोइये के बिशप को मौत के घाट उतार दिया जाए। यदि संसद गर्दन से लटकाने का प्रावधान करके जीवन छीन सकती है, तो तार्किक रूप से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है यदि वह फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मारकर या गोली मारकर या बिजली की कुर्सी पर या तेल में उबालकर भी मौत की सजा का प्रावधान करती है। विधायिका द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया न्यायालय की न्याय की भावना और निष्पक्ष खेल के खिलाफ अपराध कर सकती है।

321

एस सी आर।

और विधायिका द्वारा प्रदान की गई सजा न्यायालय की दंडात्मक धारणाओं को आहत कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार है। न्यायालय संविधान का अर्थ और व्याख्या कर सकता है और इसके सही अर्थ का पता लगा सकता है, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद न्यायालय अपने विवेक या नीति पर सवाल नहीं उठा सकता है। संविधान सर्वोच्च है। न्यायालय को संविधान को वैसा ही लेना चाहिए जैसा वह पाता है,

भले ही वह एक आदर्श संविधान के बारे में अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के अनुरूप न हो। विधायी अत्याचार के खिलाफ हमारा संरक्षण, यदि कोई हो, एक स्वतंत्र और बुद्धिमान जनमत में अंतिम विश्लेषण में निहित है जिसे अंततः खुद को स्थापित करना चाहिए।

मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ वह परिचय नहीं है।

किसी भी नवीनता के लिए, क्योंकि कई अन्य संविधानों में विधायिका की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है

द.

किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता से वंचित करने का मामला

और

अंग्रेज़ी लोकतांत्रिक संविधान

है।

संपत्ति।

बिन्दु में एक। आयरिश फ्री स्टेट के संविधान को लीजिए। अनुच्छेद *40 (4) (i)* में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को कानून के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद *50 (5)* गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक का निवास अलंघनीय है और जबरन नहीं किया जाएगा।

कानून के अनुसार प्रवेश किया। उपरोक्त दोनों खंडों में "कानून के अनुसार" शब्द अनिवार्य हैं।

मतलब एक ही है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है

खंड *(5)* को पढ़ना कि इसका अर्थ है राज्य द्वारा बनाई गई कानून के अनुसार, क्योंकि हमें प्राकृतिक न्याय विनियमन द्वारा निर्धारित किसी भी नियम के लिए संदर्भित नहीं किया गया है।

आवासों की खोज, या उनमें प्रवेश। चेकोस्लोवाकियाई संविधान के अनुच्छेद *107 (2)* का उपयोग करता है "कानून के अनुसार" शब्द जो,

के साथ पढ़ें

उस अनुच्छेद के खंड *(1)* का स्पष्ट रूप से अर्थ है -

कानून को

जो इसका हिस्सा होगा

संविधान।

डैनजिग के मुक्त शहर के संविधान को लें।

उस संविधान का अनुच्छेद *74*, जो "मौलिक अधिकार और कर्तव्य" शीर्षक वाले भाग *II* में है, निम्नानुसार प्रदान करता है:

"स्वतंत्रता या व्यक्ति अलंघनीय होगा।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई सीमा या वंचितता सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू नहीं की जा सकती है, सिवाय किसी कानून के आधार पर।

322

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

"कानून" शब्द स्पष्ट रूप से, संदर्भ में, नहीं हो सकता है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अर्थ है। पुनः, उस संविधान का अनुच्छेद *75* स्वतंत्र शहर के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता और किसी भी स्थान पर रहने और बसने, वास्तविक संपत्ति हासिल करने और जीविकोपार्जन के अधिकार की रक्षा करता है। यह यह कहते हुए समाप्त होता है कि कानूनी प्रतिबंधों के बिना इस अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में कानूनी प्रतिबंधों का अर्थ केवल शहर के कानूनों के प्रतिबंध हो सकते हैं। वाइमर संविधान का अनुच्छेद *114*

यह उसी तर्ज पर है और लगभग उसी भाषा में व्यक्त किया गया है जैसे डैनजिग संविधान के अनुच्छेद *74* में किया गया है।

1946 के जापानी संविधान को लीजिए जिससे हमारा अनुच्छेद *21* लिया गया है। उस संविधान का अनुच्छेद *XXXI* कहता हैः

" किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य दंडात्मक दंड लगाया जाएगा।

निश्चित रूप से "प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर" शब्द

कानून द्वारा स्थापित "आपराधिक दंड के अधिरोपण के लिए उनके आवेदन में राज्य द्वारा बनाई गई कानून का अर्थ होना चाहिए और एक ही लेख में एक ही वाक्य में समान शब्द, सामान्य नियमों के अनुसार नहीं हो सकते हैं।

क़ानूनों का अर्थ, जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए उनके आवेदन में एक अलग बात है। मुझे पता है कि एक संविधान का दूसरे के आलोक में अर्थ लगाना सही नहीं है और जब मैं अन्य संविधानों का उल्लेख करता हूं तो यह मेरा उद्देश्य नहीं है; लेकिन मुझे लगता है कि अन्य लिखित संविधानों के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद।

संविधान बहुत स्पष्ट रूप से देखता है कि लिखित में लागू या अंतर्निहित कोई विशेष कारण नहीं है। संविधान जिनके आयात की आवश्यकता होती है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या हमारे संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया के अमेरिकी सिद्धांत। ऊपर उल्लिखित कई संविधानों ने उस अमेरिकी सिद्धांत को नहीं अपनाया है, लेकिन अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को अपनी विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की देखभाल के लिए छोड़ने से संतुष्ट हैं। अगर हमारे संविधान ने भी ऐसा ही किया है तो यह कोई नई बात नहीं है। इन सब के लिए

कारण, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के बहुत सक्षम और आकर्षक तर्कों के बावजूद, जिन्हें मैं स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं, मैं आश्वस्त नहीं हूं कि हमारे *323* के अनुच्छेद *21* में पेश करने की कोई गुंजाइश है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

आई. ए. डब्ल्यू. की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का संविधान

शायद पसंद न आएँ

प्रक्रिया के संबंध में भी।

हो सकता है या

लेकिन यह हमारा परिणाम है

संविधान जैसा कि मैं के तहत

खड़े हो जाओ।

विद्वान महान्यायवादी ने कुछ बातों का उल्लेख किया है

मूल पर संविधान सभा में बहस खंड जो अब अनुच्छेद *21* बन गया है, अनुच्छेद *21* की भाषा की व्याख्या में उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के रूप में नहीं

लेकिन के रूप में

ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना। बिनि।

उनका कहना है कि इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि हमारे संविधान के निर्माताओं को "कानून की उचित प्रक्रिया" और "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार" वाक्यांशों के अर्थ में आवश्यक अंतर था, जो उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया था, कि वे जानते थे कि पहला न्यायपालिका की सर्वोच्चता और दूसरा विधायिका की सर्वोच्चता को दर्शाता है और इस पूरे ज्ञान के साथ वे जानबूझकर पहली अभिव्यक्ति को अस्वीकार करने और दूसरी को अपनाने के लिए सहमत हुए। मेरी राय में,

विधियों की व्याख्या के सामान्य नियमों पर अनुच्छेद *21* की भाषा की व्याख्या करना संभव है, मुझे नहीं लगता कि बहसों को संदर्भित करना बिल्कुल भी आवश्यक है।

जैसा कि मैं बहसों का उल्लेख करने या उन पर भरोसा करने का प्रस्ताव नहीं करता,

इस मामले के उद्देश्यों के लिए, मैं कोई राय व्यक्त नहीं करता हूँस्वीकार्यता या अन्यथा का प्रश्न

बहसें।

अब मैं अनुच्छेद *22* की ओर जाता हूँ। का विवाद

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील यह है कि अनुच्छेद *21* द्वारा

अंतिम कुछ शब्दों का कारण, "प्रक्रिया के अनुसार

कानून द्वारा स्थापित "चार आवश्यकताओं को आकर्षित करता है

कानून की अमेरिकी प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया योग के रूप मेंविलिस द्वारा शादी की गई जिसका संदर्भ दिया गया है

पहले, और उन आवश्यकताओं को छोड़कर,

जिस हद तक उन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त या संशोधित किया गया है

अनुच्छेद *22* द्वारा, किसी व्यक्ति के समक्ष इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हो सकता है। आई.

ऊपर बताए गए कारणों के लिए पहले ही कहा जा चुका है कि

प्राकृतिक नियम लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।न्याय या कानून की अमेरिकी प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया

या हमारी आपराधिक संहिता का कोई अंतर्निहित सिद्धांत

उस लेख में प्रक्रिया। यह निष्कर्ष है

मैं उस प्रमुख आधार पर पहुँच गया हूँ जिसे मैंने मान लिया है

याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील गायब है और यह

16-3 एस. सी. इंडिया*/58 [1950]*

324

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तर्क की रेखा शुरू नहीं होती है और नहीं हो सकती है स्वीकार कर लिया।

दूसरी ओर विद्वान महान्यायवादी,

उन्होंने अपने तर्क के एक चरण में आग्रह किया है कि अनुच्छेद *21* का निवारक निरोध से कोई लेना-देना नहीं है और निवारक निरोध पूरी तरह से अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* के अंतर्गत आता है जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता का गठन करता है। मैं इस चरम सीमा को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं।

बिन्दु

भी देखें। असली स्थिति, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, दो चरम विचारों के बीच है। अनुच्छेद *21*, मेरे विचार से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उसमें उल्लिखित सीमा तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन अधिकार के दायरे और दायरे को सीमित करता है। पूर्ण अधिकार उस लेख की परिभाषा के अनुसार है जो इसे छीन लिए जाने के जोखिम से काट दिया गया है।

प्रक्रिया के साथ

के अनुसार

कानून द्वारा स्थापित। यह.

क्या यह सीमित अधिकार है

जो कि

मूल रूप से

कार्यपालक

संविधान के लिए विधानमंडल के साथ-साथ अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित है

स्वयं द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित एक प्रो सेडर की आवश्यकता के कारण अपने अभाव की शर्त रखी। . जबकि अनुच्छेद *19* के उपखंड *(2)* से *(6)* ने एक सीमा निर्धारित की है -

एक नागरिक के मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद *21* और *22* ने विधायी सूचियों के साथ अनुच्छेद *246* के तहत दी गई राज्य की शक्ति पर एक सीमा रखी है। हमारे संविधान के तहत हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद *19* में निर्धारित नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंधों और अनुच्छेद *21* और *22* द्वारा राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों द्वारा संतुलित है। निवारक निरोध किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उतना ही प्रभावी ढंग से वंचित करता है जितना कि करता है।

दंडात्मक निरोध और, इसलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि इसे छीन लिए जाने के जोखिम के कारण, दंडात्मक के साथ-साथ पूर्वनिर्धारित निरोध के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद *21* की भाषा काफी सामान्य है और सभी प्रकार के निरोध के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपनी सीमित सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त व्यापक है। यह किसी व्यक्ति को कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून की मंजूरी के बिना निवारक हिरासत से बचाता है।

यह विधायिका को लेने से रोकता है।

विधायिका। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना, हालांकि ऐसी *325*

एस सी आर। कानून अपने आप में होना चाहिए। अगर. जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा तर्क दिया गया है और मेरे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अनुच्छेद *19* केवल एक स्वतंत्र नागरिक के अधिकारों का समर्थन करता है जब तक कि वह स्वतंत्र है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पूर्ण अभाव से संबंधित नहीं है और यदि, जैसा कि विद्वान द्वारा तर्क दिया गया है

महान्यायवादी,

अनुच्छेद *21* किसी व्यक्ति को निवारक निरोध से सुरक्षा नहीं देता है तो जीवन के लिए सुरक्षा कहाँ है और प्रति व्यक्ति

मौलिक अधिकारों के रूप में सोनल स्वतंत्रता जो प्रक्रिया

अनुच्छेद *22* के उपबंध किसकी रक्षा कर सकते हैं*?* क्या बात है*?*

प्रक्रियात्मक संरक्षण का उपयोग यदि कोई मूल नहीं है

सही*?* मेरे निर्णय में अनुच्छेद *21* उप की रक्षा करता है।

एक प्रक्रिया और अनुच्छेद *22* की आवश्यकता के द्वारा स्थायी अधिकार

न्यूनतम प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद *22* के खंड *(1)* और *(2)* में उपबंध निर्धारित किए गए हैं।

जब एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो जिसका पालन करना पड़ता है।

गिरफ्तारी के ठोस आधार, *(*बी*)* परामर्श करने का अधिकार, औरअपनी पसंद के एक कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किया जाए, *(*सी*)*

24 तारीख के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार

घंटे और *(*डी*)* हिरासत से परे स्वतंत्रता

द्वारा को छोड़कर उक्त अवधि

मजिस्ट्रेट का आदेश।

ये चार प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ बहुत अधिक हैं।

प्रक्रियात्मक देय आवश्यकताओं के समान

ये स्वास्थ्यवर्धक संरक्षण भी हमारे जीवन में पाए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता। यदि प्रक्रिया है

पहले से ही अनुच्छेद *21* द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें शामिल है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, या अंतर्निहित सिद्धांत

अनुच्छेद *22* के खंड *(1)* और *(2)* में उन्हें दोहराना*?* यह अनावश्यक ओवरलैपिंग क्यों*?* सच तो यह है कि

अनुच्छेद *21* किसी विशेष प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है।लेकिन जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को परिभाषित करने में

स्वतंत्रता केवल आवश्यकता की परिकल्पना या संकेत करती है

द्वार या अनदेखी। यह अब तक दंडात्मक हिरासत के रूप में हैचिंतित हैं। अनुच्छेद *22* का खंड *(3)* स्पष्ट रूप से

यह प्रावधान करता है कि निर्धारित प्रक्रिया में से कोई भी नहीं खंड *(1)* और *(2)* किसी विदेशी दुश्मन या किसी विदेशी दुश्मन पर लागू होंगे।

वह व्यक्ति जिसे किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है

निवारक निरोध के लिए प्रयास करना। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से *[1950]* है

326

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट किया गया कि किसी बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है और उसे परामर्श के लिए या उसका बचाव करने के लिए किसी वकील की सहायता नहीं लेनी है। हमारे संविधान का ऐसा स्पष्ट प्रावधान होने के कारण कोई भी इसके विवेक पर सवाल नहीं उठा सकता है। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।

अनुच्छेद *22* के खंड *(4), (5), (6)* और *(7)* संदर्भ में

निवारक निरोध से संबंधित है। अनुच्छेद *246* उपयुक्त विधायिका को सूची *I* में प्रविष्टि *9* और/या सातवीं अनुसूची की सूची *III* में प्रविष्टि *3* के संदर्भ में निवारक निरोध के लिए एक कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। इस विधायी शक्ति पर अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* तक कुछ सीमाएँ लगाई गई हैं। इसके अनुसार विधायिका, चाहे वह संसद हो या राज्य विधानमंडल, को याद दिलाया जाता है कि

निवारक निरोध के लिए उसके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उपखंड *(ए)* और *(बी)* में उल्लिखित दो मामलों को छोड़कर किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा। उपखंड *(ए)* और उपखंड *(बी)* का परंतुक केवल द्वारा बनाए गए कानून को संदर्भित करता है

खंड *(7)* के अधीन संसद।

के तहत

खंड *(7)* यह है

केवल संसद और कोई राज्य विधानमंडल नहीं जो तीन उपमंडलों में निर्दिष्ट बातों को निर्धारित कर सके।उस खंड के खंड। यद्यपि राज्य विधानमंडल निवारक निरोध के लिए एक कानून बना सकता है।

प्रविष्टि संख्या *3.* सातवीं अनुसूची की सूची संख्या *3* मेंऐसा कानून तीन से अधिक लोगों को हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है।

महीनों तक जब तक

के प्रावधान

उपखंड *(ए)* और

(ख*)* खंड *(4)* की धारा इस तरह के निरोध को मंजूरी देती है। यहाँ तक कि एक

संसद द्वारा बनाया गया कानून हिरासत को अधिकृत नहीं कर सकता है।

तीन महीने से अधिक के लिए जब तक कि यह एक कानून नहीं है

खंड *(7)* के प्रावधानों के तहत। संक्षेप में, खंड *(4)*अनुच्छेद *22* विधायी पर एक सीमा प्रदान करता है

निवारक निरोध की अवधि के बारे में शक्ति। इसके अलावा

विधायी शक्ति पर सीमा अधिरोपित करने से,

खंड *(4)* निरोध की प्रक्रिया भी विहित करता है -

तीन महीने से अधिक की अवधि सलाहकार मंडल। फिर खंड *(5)* आता है। यह नीचे रखता है

प्रक्रिया जिसका पालन किया जाना है जब ए

व्यक्ति

निवारक प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है

निरोध, अर्थात्, *(*क*)* आदेश के आधार

बंदी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए

जैसा भी हो सकता है, और *(*बी*)* बंदी को वहन किया जाना चाहिए

एस. सी. आर. के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

327

आदेश दिया। पहली आवश्यकता नोटिस की जगह लेती है और दूसरी बचाव या सुनवाई की। ये हमारे संविधान द्वारा निर्धारित एकमात्र अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ हैं। विधानमंडल को विस्तृत जानकारी प्रदान करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।

निवारक निरोध को विनियमित करने वाली प्रक्रिया लेकिन यह नहीं है

ऐसा करने के लिए बाध्य। यदि कुछ प्रक्रिया के रूप में प्रदान की जाती है

अनुच्छेद *21* और अनिवार्य आवश्यकताओं द्वारा देखा गया

हमारे संविधान के तहत जैसा कि मैंने इसे पढ़ा, शिकायत की निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कानून।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि

प्रक्रियात्मक देय प्रक्रिया की चार आवश्यकताएँ

विलिस द्वारा उठाये जाने को उनकी ऐपली में संशोधित करना होगा

निवारक निरोध के लिए कैशन। इस प्रकार वह नहीं करता है

गिरफ्तारी से पहले पूर्व सूचना दें, क्योंकि वह पहचानता है

कि ऐसी आवश्यकता बहुत ही उद्देश्य को निराश कर सकती है

विचाराधीन व्यक्ति को भूमिगत जाना है। प्रोवीखंड *(5)* में आधारों की आपूर्ति के लिए एक अच्छा उपखंड है।

नोटिस के लिए अनुशासित। वह इस बात पर भी जोर नहीं देता कि

निरोध की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए न्यायाधिकरण

न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए। वह संतुष्ट होगा अगर

न्यायाधिकरण या सलाहकार बोर्ड, जैसा कि इसे लेख में कहा गया है *22* संविधान का, एक निष्पक्ष निकाय है और जाता है

निरोध के आदेश और उसके निर्णय के गुण-दोष में

सायन कार्यकारी सरकार के लिए बाध्यकारी है। वह अंदर ऐसा माना जाता है कि बंदी के पास एक उचित और प्रभावी प्रभाव होना चाहिए

अपना बचाव करने का शानदार मौका। वह नहीं करता।

वकील की सहायता पर जोर देना, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से है छीन लिया गया, संविधान द्वारा ही। लेकिन वह

जिस पर वे एक प्रभावी अवसर कहते हैं

में से

एक निष्पक्ष निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से सुना जाना

जो उसके आधारों की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा

दाग-धब्बे। दावा उचित हो सकता है लेकिन सवाल न्यायालय के समक्ष तर्कसंगतता या अन्यथा नहीं है

अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* के प्रावधान। वे प्रावधान

न्यायसंगत नहीं हैं, क्योंकि वे प्रावधान हैं

स्वयं संविधान, जो प्रत्येक निकाय पर सर्वोच्च है *328*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

न्यायालय केवल एक उचित समझौते पर पता लगाने की कोशिश कर सकता है।

निर्देश, वास्तव में क्या सुरक्षा प्रदान की गई है।

संविधान ने देने का प्रावधान किया है

हिरासत के आधार हालांकि तथ्य अलग-अलग हैं

खंड *(6)* के तहत आधारों को रोका जा सकता है और

निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अधिकार

यह। इसने नजरबंदी की अवधि के लिए प्रावधान किया है यह। वहाँ गारंटीकृत मौलिक प्रक्रियात्मक

अधिकार समाप्त होते हैं। किसी भी परीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है

कोई भी न्यायाधिकरण।

एक की शर्त को आयात नहीं किया जा सकता है

किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा इस तथ्य से मुकदमा चलाया जाता है कि

प्रतिनिधित्व दिया गया है। करने का अधिकार

प्रतिनिधित्व "दर्ज कराने" के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है।

डांजिंग संविधान द्वारा प्रदान की गई आपत्तियाँ

संविधान। प्रतिनिधित्व

और

वाइमर

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ऐसा कहा जाता है कि एक अभियोजक स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

आम तौर पर, हिरासत के आदेश एक बड़े पैमाने पर होंगे

अधिकांश मामले जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं।

या उप-मंडल अधिकारी या पुलिस आयुक्त।

बंदी का प्रतिनिधित्व सरकार के पास जाता है मन में। यह क्यों माना जाना चाहिए कि एक उच्च शासन

सरकार की सीट पर अधिकारी नहीं होगा

प्रतिनिधित्व पर निष्पक्ष रूप से विचार करें और न्याय करेंस्थानीय द्वारा किए गए निरोध के आदेश का औचित्य

वास्तव में खंड *(1)* के प्रावधानों का अपवर्जन और *(2)* परीक्षण या मौखिक बचाव के किसी भी विचार को नकारता है। द.

न्यायालय, स्वभाव और प्रशिक्षण से, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन वह संविधान की बुद्धिमत्ता या नीति पर सवाल नहीं उठा सकता है। निवारक निरोध कानूनों के संबंध में मेरे निर्णय में, एकमात्र सीमा रखी गई है

विधायी शक्ति यह है कि

देना होगा

न्यूनतम

कुछ प्रक्रिया और कम से कम शामिल करें

अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)*।

में निर्धारित आवश्यकताएँ मूल के संबंध में कोई सीमा नहीं है

कानून। इसलिए एक निवारक निरोध कानून जो कुछ प्रक्रिया प्रदान करता है और अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, उसे एक अच्छा कानून माना जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी घृणित क्यों न लगे।

अदालत होनी चाहिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

329

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि

विवादित अधिनियम अनुच्छेद *22 (4)* से *(7)* की केवल आवश्यकताओं का भी पालन नहीं करता है। यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा *3* में कोई प्रावधान नहीं है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षण लेकिन इसे परिभाषित करने और यह कहने के लिए प्राधिकरण पर छोड़ देता है कि क्या कोई विशेष व्यक्ति विधायी प्रमुखों के भीतर आता है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि संसद ने

बिल्कुल भी कानून नहीं बनाया है, लेकिन अपनी विधायी शक्तियों को कार्यकारी अधिकारियों को सौंप दिया है। आई.

यह मत सोचिए कि इस विवाद में कोई सार है। पहली बात यह है कि यह प्रक्रिया के रूप में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मूल कानून के लिए है जो इसके लिए खुला नहीं है।

अदालत की जांच। अगले स्थान पर यह विवाद कानून बनाने के लिए शक्ति के प्रत्यायोजन और एक अधिकार और विवेकाधिकार प्रदान करने के बीच बुनियादी अंतर को नजरअंदाज करता है।

उसके निष्पादन के बारे में

कानून के तहत और उसके अनुसरण में प्रयोग किया गया। विवादित अधिनियम ने विशेष रूप से एक सुनिश्चित मानक निर्धारित किया है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के आचरण का निर्णय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।

इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि अधिनियम की धारा *12* दो कारणों से अनुच्छेद *22* के खंड *(7)* की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है, अर्थात्

((i) वह खंड *(7)* उन परिस्थितियों को विहित करने वाली विधि पर विचार करता है जिनके अधीन, और वर्ग या

ऐसे मामलों के वर्ग जिनमें किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और फिर उसके बाद तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला एक अन्य कानून; और

((ख) कि खंड *(7)* के अधीन संसद को उन दोनों परिस्थितियों को विहित करना चाहिए जिनके अधीन, और मामलों का वह वर्ग या वर्ग जिसमें किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, मुझे समझ नहीं आता कि संसद को दो कानून क्यों बनाने चाहिए, एक लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए और दूसरा इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए। यह हो सकता है कि कोई राज्य संसद *330* तक लंबे समय तक नजरबंदी का प्रावधान नहीं कर सकता है।

उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि पार्लियामेंट एक ही अधिनियम द्वारा दोनों क्यों नहीं कर सकता है। वास्तव में, खंड *(4) (*बी*)* यह विचार करता है कि निरोध स्वयं खंड *(7)* के उपखंड *(*ए*)* और *(*बी*)* के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार है। इसलिए, हिरासत के तहत अच्छी तरह से हो सकता है

कानून जो संसद खंड *(7)* के उपखंड *(ए)* और *(बी)* के तहत बनाती है। जहाँ तक दूसरे बिंदु की बात है, तर्क यह है कि संसद को खंड के तहत विवेकाधिकार है।

(7) एक कानून बनाने के लिए और यह कोई कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जब हमारी संसद एक कानून बनाने का विकल्प चुनती है तो उसे दोनों परिस्थितियों को निर्धारित करना चाहिए जिनके तहत, और मामलों के वर्ग या वर्ग जिनमें कोई व्यक्ति कर सकता है।

तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाए। आई.

खंड *(7) (ए)* का अर्थ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिस तरह से लगाया गया है, उसे समझने में असमर्थ हूं। यह एक सक्षम प्रावधान है जो संसद को दो चीजें निर्धारित करने का अधिकार देता है। संसद कर सकती है

या तो निर्धारित करें

या दोनों।

अगर एक पिता अपनी नाजुक बात बताता है

बच्चा कि वह

खेल सकते हैं

टेबल टेनिस और बैडमिंटन लेकिन फुटबॉल का कठिन खेल नहीं, इसका स्पष्ट रूप से यह मतलब नहीं है कि अगर बच्चा खेलना चाहता है, तो उसे दोनों टेबल खेलना चाहिए।

बच्चा। इसी तरह, संविधान संसद को देता है दो चीजों को निर्धारित करने की शक्ति। संसद नहीं है

निर्धारित करने के लिए बाध्य लेकिन अगर यह निर्धारित करने का विकल्प चुनता है

यह या तो या दोनों निर्धारित कर सकता है। खंड *7 (ए),* मेरे में

राय को निम्नानुसार विभाजित रूप से पढ़ा जाना चाहिएः द.

संसद निम्नलिखित परिस्थिति निर्धारित कर सकती है -

जिसे किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

तीन महीने से अधिक और संसद निर्धारित कर सकती है

ऐसे मामलों का वर्ग या वर्ग जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है

तीन महीने से अधिक समय तक जकड़ना। वह एपीमुझे कॉन के ध्वनि नियमों के साथ व्यंजन होने के लिए नाशपाती

मामलों के वर्ग संभवतः एकजुट हो सकते हैं। वास्तव मेंकलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष *1950* का पूर्ण पीठ मामला संख्या *1*

न्यायालय *(*क्षितिंद्र नारायण बनाम। मुख्य सचिव*)* स्वयं

इंगित करता है कि एक ही प्रावधान पढ़ा जा सकता है

सरदार के रूप में

जटिलताएँ या एक वर्गीकरण के रूप में। उस मामले में सीखा वकील ने स्वीकार किया कि धारा *12* ने आदेश निर्धारित किया था

जटिलताएँ लेकिन उनकी शिकायत थी कि यह *331* नहीं था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्धारित किया गया। अधिकांश न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। हालाँकि, एक विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *12* ने मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्धारित किया था, लेकिन परिधि के रुख को निर्धारित नहीं किया था। अतः यह स्पष्ट है कि वर्गीकरण

परिस्थितियों को इंगित कर सकते हैं।

एक बार फिर,

स्वयं

यह विभिन्न आधारों पर हो सकता है। यह.

वर्गीकरणप्रांतों के अनुसार बंदी आ सकते हैं

से। यह बंदी की उम्र के अनुसार हो सकता है। यह उस उद्देश्य के अनुसार हो सकता है जो उनके सामने होना चाहिए या उन गतिविधियों के अनुसार हो सकता है जिनमें उनके शामिल होने का संदेह है। इस मामले में संसद ने छह विधायी प्रमुखों में से पांच को लिया है और उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया है। इस प्रकार बंदियों को उनके संदिग्ध उद्देश्य या गतिविधियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जो इसमें निर्दिष्ट कई मामलों को खतरे में डालते हैं।

अनुभाग। मुझे समझ नहीं आता कि वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है।

कुछ विधायी प्रमुखों में आने वाले निरोधकों के उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाए, क्योंकि प्रत्येक विधायी प्रमुख का एक विशिष्ट अर्थ होता है जिसे अच्छी तरह से समझा जाता है

कानून में। यदि मैं सही हूं कि एक वर्गीकरण किया गया है तो यह तथ्य कि कोई व्यक्ति एक या दूसरे वर्ग के अंतर्गत आता है, वे परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके तहत उसे अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

तीन महीने। मैं इसे सही नहीं मानता।

निर्माण का, किसी भी आगे की सीमा को पढ़ने के लिए अनुच्छेद *22* का खंड *7 (क)*। मेरे निर्णय में संसद

खंड *(7)* के तहत परिस्थितियों और वर्गों दोनों को निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं था, और किसी भी मामले में वास्तव में और सार दोनों को निर्धारित किया है।

मैं इस बात से अवगत हूं कि संसद द्वारा बनाया गया एक कानून

अनुच्छेद *22 (7)* के तहत लाभप्रद को समाप्त कर दिया जाएगा।

सलाहकार मंडल की राय की सुरक्षा। लेकिन

यह याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान ही यह विचार करता है कि कुछ परिस्थितियों में या

के लिए

बंदियों के कुछ वर्ग या वर्ग, यहाँ तक कि सलाहकार भीबोर्ड सुरक्षित नहीं हो सकता है और उसने संसद पर भरोसा किया है

उस उद्देश्य के लिए एक कानून बनाना। हमारी प्राथमिकताएँ

एक सलाहकार बोर्ड को हमें इस पहलू से अंधा नहीं करना चाहिए।मामले से। यह सच है कि परिस्थितियाँ आम तौर पर

दंगों, हंगामे, *332* जैसी बाहरी चीजों से संबंधित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1950]

राजनीतिक या सांप्रदायिक या किसी प्रकार की असामान्य स्थिति और यह कहा जाता है कि संविधान के निर्माताओं के दिमाग में ऐसी कोई स्थिति थी जब सलाहकार मंडल को समाप्त किया जा सकता था। यह भी आग्रह किया जाता है कि उनके दिमाग में था कि अधिक कठोर प्रकार के बंदियों को सलाहकार मंडल के विशेषाधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। मैं यह स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूं कि विशिष्ट परिस्थितियों का निर्धारण या वर्गों का अधिक कठोर और निश्चित विनिर्देश बेहतर और अधिक वांछनीय होता। लेकिन वह आदर्श के लिए रो रहा है। संविधान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है

परिस्थितियों या मामलों के वर्ग या वर्गों के संबंध में सीमा और इसके बारे में अटकलें लगाना बेकार है

संविधान निर्माताओं का इरादा, जो, वैसे,

न्यायालय का संविधान में सुधार करना या उसमें जोड़ना।यदि संसद द्वारा विधिवत बनाया गया कानून इसके प्रतिकूल है -

अच्छी समझ से, जनमत संसद को मजबूर करेगा

इसे उचित रूप से बदलें।

अंत में, एक आपत्ति ली जाती है कि धारा *14*

विवादित अधिनियम के अधिकार को छीन लेता है या कम कर देता है

उचित कार्यवाही द्वारा इस न्यायालय का रुख करने के लिए बंदी

इस न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए एक व्यक्ति को दिया जाता है जो इसके लिए नहीं है केवल स्थानांतरित करने के लिए लेकिन अदालत को स्थानांतरित करने के लिए

भाग *III* द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का प्रवर्तन और

इस न्यायालय को निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है या

इनमें से किसी के प्रवर्तन के लिए आदेश या रिट

अधिकार। इसलिए, आवेदन को आकर्षित करने के लिए

अनुच्छेद *32* के अनुसार, आवेदन करने वाले व्यक्ति को पहले संतुष्ट होना चाहिए।

कि उसे भाग *III* के तहत एक अधिकार मिला है जो होना चाहिए अनुच्छेद *32* के तहत लागू किया गया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि

अनुच्छेद *19* व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है।मैंने यह भी कहा है कि अनुच्छेद *21* और *22* पूर्व के लिए प्रावधान करते हैं

किसी प्रक्रिया पर जोर देकर टीक्शन। लेख के तहत

22 (5) निरोध का आदेश देने वाला प्राधिकारी है

आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके, संवाद करने के लिए

जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है, उन्हें रोकें।

इस प्रावधान का कुछ उद्देश्य है, अर्थात्

आधारों के प्रकटीकरण से एस. सी. आर. को हिरासत में लिया जा सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

333

आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर। मान लीजिए कि प्राधिकरण में निर्दिष्ट तथ्यों से अलग कोई आधार नहीं देता है।

खंड *(6)*। निश्चित रूप से बंदी एक मौलिक अधिकार खो देता है क्योंकि उसे प्रतिनिधि बनाने से रोका जाता है

निरोध के आदेश के विरुद्ध अभियोग। मान लीजिए कि अधिकारी बंदी को कागज का एक टुकड़ा सौंपता है

उस पर कुछ स्क्रिबलिंग के साथ जो राशि नहीं हैनजरबंदी के लिए कोई भी आधार। फिर बंदी भी

वैध रूप से शिकायत कर सकता है कि उसका अधिकार है

उल्लंघन किया गया। फिर वह अदालत में आ सकता है

अनुच्छेद *32* के तहत निवारण, लेकिन वह नहीं दिखा सकता है

कागज के टुकड़े को उस पर स्क्रिबलिंग के साथ कोर्ट करें

अधिनियम की धारा *14* के तहत और न्यायालय न्याय नहीं कर सकता है क्या उसे वास्तव में वे आधार मिले हैं जो वह है

अनुच्छेद *22 (5)* के तहत हकदार। ऐसे मामले में

बंदी अच्छी तरह से शिकायत कर सकता है कि दोनों उसके मूल अनुच्छेद *22 (5)* के तहत अधिकार के साथ-साथ

अनुच्छेद *32* के तहत संवैधानिक उपाय किए गए हैं

उल्लंघन किया गया। वह अपने उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।

अनुच्छेद *32* के तहत उपचारात्मक अधिकार, क्योंकि वह

नहीं कर सकते

दिखाएँ कि उसका उल्लंघन हुआ है

अनुच्छेद *22 (5)* के तहत मूल अधिकार। ऐसा प्रतीत होता है कि

अतः मैं अधिनियम की उस धारा *14* में जहाँ तक यह है

बंदी को अदालत को खुलासा करने से रोकता है

संविधान के भाग *III* के साथ और इसलिए है, अनुच्छेद *13 (2)* के तहत शून्य। हालाँकि, वह खंड है

स्पष्ट रूप से विच्छेद योग्य और पूरे अधिनियम को प्रभावित नहीं कर सकता है। उस पर

यह सवाल मेरेडिथ सी. जे. और दास जे. के विचारों पर है।

1950 के आपराधिक विविध सं. *124* में पटना का

(ललित कुमार बर्मन बनाम। राज्य*)* और बहुमत

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से

1950 का पूर्ण पीठ मामला संख्या *1 (*क्षितिंद्र नारायण*)*

वी. मुख्य सचिव*)* सही प्रतीत होते हैं और

ध्वनि।

ऊपर दिए गए कारणों से, मेरी राय में,

विवादित अधिनियम धारा को छोड़कर एक वैध कानून है।

14 जहाँ तक यह आधारों को प्रकट होने से रोकता है

अदालत में। हमारे सामने याचिकाकर्ता नहीं आता हैयह स्पष्ट है कि उन्हें उचित आधार नहीं मिला है। .

इसके अलावा,

विवादित अधिनियम जे. पी. आर. ई. एम. कोर्ट रिपोर्ट के तहत उनकी नजरबंदी की अवधि

[1950]

तीन महीने से अधिक और, परिधि में

आवेदन, मेरी राय में, खड़ा होना चाहिए

याचिका खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता - एस. सुब्रमण्यम।

: मद्रास राज्य और भारत संघः

पी. ए. मेहता

500